अभिमत

आधुनिक जीवनशैली जटिल व ऊर्जा गटकने वाली उपभोक्तावादी संस्कृति से जुड़ी है। उसमें तामझाम व दिखावा है। वह लोभ-लालच पर आधारित है, जिसकी सीमाएं आ चुकी हैं। प्राकृतिक संसाधन खत्म हो रहे हैं। कोयला व तेल खत्म होने वाले हैं। प्रदूषण से जलवायु बदलाव हो रहा है। ऐसे वैश्विक संकट के दौर में आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान, पुरखा संस्कृति, प्रकृतिप्रेमी सरल जीवन पद्धति से काफी कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन क्या हम आज के जलवायु बदलाव और वैश्विक संकट के दौर में आदिवासियों से कुछ सीखना चाहेंगे?

आदिवासियों से क्या सीख सकते हैं?

नवाचार

■ बाबा मायाराम

हाल ही मुझे छत्तीसगढ़ में जशपुर जिले के एक आदिवासी गांव में जाने का मौका मिला। इस दौरान मैंने उनके जीवन को देखने, समझने व करीब से जानने की कोशिश की।

यह गांव कुनकुरी के पास स्थित है। यहां उरांव आदिवासी रहते हैं। जिस घर में मैं ठहरा था, वह कच्चा मिट्टी का था, लेकिन सीमेंट व कांक्रीट के पक्के घरों की अपेक्षा ठंडा था। वहां हर चीज सुघड़ता से रखी हुई थी। गोबर व काली मिट्टी से लिपा-पुता यह घर अपना सौंदर्य बिखेर रहा था।

अंग्रेजी के यू आकार से बना यह घर काफी बड़ा था। मिट्टी की ऊंची दीवारें थीं। देसी खपरैल से छत ढकी थी। घर के आगे-पीछे काफी खुली जगह थी। शयन व अतिथियों के लिए अलग कमरा था। रसोई घर और कोठार (अनाज रखने के लिए) था। मवेशियों व बकरी के लिए अलग जगह थी, मुर्गी घर था। लम्बा-चौड़ा आंगन व खलिहान था।

इस घर को बनाने के लिए स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। आसपास के खेतों की मिट्टी, लकड़ी, बांस और देसी खपरैल से घर बनाया गया था। इसमें किसी भी तरह का खर्च नहीं है, जबकि आज पक्के घर बनाना बहुत ही खर्चीला हो गया है।

मिट्टी के घर टिकाऊ होते हैं, जिसमें बिना पंखे-कूलर के रहा जा सकता है। जबकि पक्के व कांक्रीट के घरों में बिना बिजली के रहना मुश्किल है।

सीमेंट के पक्के घर काफी नए हैं, जबकि मिट्टी के घर बनाकर लोग सदियों से रह रहे हैं। इनकी उम्र डेढ़-दो सौ साल तक होती है। जबकि सीमेंट के घरों की उम्र करीब 50 साल होती है। सीमेंट और मिट्टी के लिए, पहाड़ों को नष्ट किया जा रहा है। जंगलों को काटा जा रहा है। नदियों से रेत निकाली जा रही है, जिससे वे भी दम तोड़ रही हैं।

यहां घर के पीछे बाड़ी थी। एक कुआं था। जहां प्याज, लहसुन, मूली, मटर, गोभी, टमाटर, सेमी जैसी सब्जियां थीं। घर के सामने पुराना कटहल का पेड़ था, जो बड़े फलों से लदा था।

इसके अलावा, यहां बागान में बेर, आम, लीची और इमली जैसे फलदार पेड़ थे। इससे घर के लोगों को तो ताज़ी सब्जी व फल मिलते हैं, अतिरिक्त होने पर बेचते भी हैं।

घर के आंगन में महुआ सूखने पड़े हुए थे, जिनकी बिनाई का काम इन दिनों चल रहा है। जल्दी जागकर छोटे स्कूली बच्चे भी महुआ बीनने जाते हैं। ऐसे रिश्तेदार व पड़ोसी भी महुआ बिनाई के लिए आ जाते हैं, जिनके पास खुद के महुआ पेड़ नहीं हैं। एक दिन सभी पेड़ों के महुआ बकरियों और गाय को भी खिला दिए। पूछने पर बताया कि उनका भी इसमें हिस्सा है।

कुछ समय पहले तक यहां के कुओं से टेड़ा पद्धति से पानी खींचा जाता था। टेड़ा पद्धति देसज तकनीक है। इसमें बांस की लकड़ी के एक सिरे पर पत्थर बांध दिया जाता है और दूसरे सिरे पर बाल्टी। पत्थर के वजन के कारण पानी खींचने में ज्यादा ताकत नहीं लगती। इशारे से ही पानी से भरी बाल्टी ऊपर आ जाती है। सड़क के बैरियर या रेलवे गेट की तरह।

छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में इसी टेड़ा पद्धति से अब भी सिंचाई की जाती है। इससे पानी की रोज़ाना की जरूरत तो पूरी होती ही है, उसी पानी से सब्जियों की खेती भी हो जाती है। इसमें पानी की जितनी जरूरत होती है, उतना ही पानी निकाला जाता है, जिससे पानी का खत्म नहीं होता। भूजल भी नीचे नहीं जाता। कई सालों तक पानी बना रहता है। जबकि बिजली के मोटर पंपों से अकूत पानी उलीचा जाता है।

इस गांव में एक आम का बगीचा है, जहां बच्चों की टोलियां खेलती रहती हैं। गुलेल से निशाना साधकर आम गिराना इनके बाएं हाथ का खेल है। बेर और शहतूत के रसदार फल तोड़कर बच्चे खाते रहते हैं। जितने सारे लीची के फल खाने के लिए तो पूरे मोहल्ले के बच्चे आते थे और चिड़ियाओं का चहचहाता झुंड भी आता था।

खेती से लेकर घरेलू कामों में महिलाएं ज्यादा काम करती हैं। उनकी दिनचर्या जल्द शुरू हो जाती है। वे 4 बजे सुबह जाग जाती हैं। धान कूटती हैं, पानी लाती हैं। साफ-सफाई करती हैं। खेतों में धान का रोपा लगाना, निंदाई-गुड़ाई करना, कटाई करना, खलिहान तक फसलें ढोकर लाना इत्यादि। पुरुष कंधे पर ढोकर गोबर खाद डालते हैं। हलों से जुताई कर फसलें बोते हैं।

यहां महिलाओं पर उतनी पाबंदी नहीं है, जितनी देश के कुछ अन्य स्थानों में दिखाई देती है। यहां लड़कियां साइकिल चलाती हैं, जो उनकी आजादी की प्रतीक बन गई है। वे साइकिल की सवारी कर स्कूल जाती हैं। हाट-बाजार जाती हैं।

गांववालों के मुताबिक पहले यहां बहुत जंगल हुआ करता था। चार महीने खूब बारिश होती थी। हरे-भरे पेड़ थे। छोटे-छोटे नदी नाले थे। उनमें मछलियां खूब मिलती थीं। यहां एक साथ कई फसलें हुआ करती थीं। मक्का, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, उड़द, अरहर, कुलथी, जटगी, सरसों आदि फसलें बोई जाती थीं। खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन जंगल भी कम हो गए हैं और कुछ किसान रासायनिक खेती भी करने लगे हैं।

पहले यहां लोग खेतों में कपास बोते थे। चरखा से सूत कातते थे, और फिर उससे कपड़ा बनवाते थे। महुआ की डोरी (फल), मूंगफली व जटगी का तेल निकाला जाता था। गांव में देशज तरीके से तेल निकालते थे। यानी मिट्टी तेल व नमक को छोड़कर गांव में जरूरत की सभी चीजें होती थीं। कई मायनों में गांव आत्मनिर्भर हुआ करता था।

आदिवासियों ने ही हमें वन खाद्यों से परिचय कराया है। हरी पत्तीदार सब्जियां, मशरूम, कंद-मूलों से अवगत कराया है। उन्होंने इन्हें खोदने और पकाकर खाने की पद्धतियां भी बनाई हैं, और बताई हैं। जड़ी-बूटियों की पहचान, और गुणधर्मों की पहचान कराई है। इन सबको खाद्य पदार्थों में शामिल करवाने और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इनके इस्तेमाल का श्रेय उनको जाता है।

आम तौर पर आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने की बातें होती हैं, अपनी कल्पना और इच्छा के अनुसार उन्हें ढालने या रहन-सहन का अपना ढंग थोपने की कोशिश होती है। लेकिन आदिवासी समुदाय ही ऐसा है जिसका जलवायु बदलाव में कोई योगदान नहीं है। वे आज भी बहुत कम ऊर्जा इस्तेमाल कर व खुद ही मेहनत से जीवन जीते हैं। हालांकि यह भी जरूरी है कि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए।

वे काफी अनुशासित व मेहनती होते हैं और सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक भी, यहां परिवार के सभी की इच्छा का सम्मान होता है। आज जब हम जीवन के सौंदर्य से दूर होते जा रहे हैं, और उस आनंद को कृत्रिमता में तलाशते हैं, तब उनके गांवों में आज भी अखड़ा (सांस्कृतिक स्थल) है। जहां ढोल और मांदर की थाप पर गीत व नृत्य होता है।

यहां दूर-दूर घरों में रहने वाले लोगों में एक दूसरे के साथ करीबी रिश्ता है। उनमें समता और सादगी के मूल्य हैं। एक दूसरे की मदद करने, एक दूसरे का साथ देने के कई तरीके हैं। मिल-जुल घर बनाने व छत के खपरैल बदलने में इसे देखा जा सकता है। इन कामों के बदले पैसों का भुगतान नहीं किया जाता।

छत्तीसगढ़ व देश में कई जनजातियां हैं। अलग-अलग इलाकों में उनकी अलग-अलग जीवन पद्धतियां हैं। मैंने देश के कई हिस्सों में आदिवासियों की जीवनशैली को देखा है। छत्तीसगढ़ में कमार, बैगा, ओड़िशा में कोंध, मध्यप्रदेश में गोंड-कोरकू, भील और महाराष्ट्र में महादेव कोली के इलाकों में गया हूं।

आदिवासियों का देश-दुनिया को देखने का नजरिया हमसे भिन्न है। वे प्रकृतिपूजक हैं और उनकी श्रमप्रधान जीवनशैली है। पुरखा संस्कृति है, वे अपने पुरखों से सीखते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक परंपरा से पारंपरिक ज्ञान हस्तांतरित होता है। उनमें मिल जुलकर रहने, सामूहिकता, एकजुटता और मेल-जोल की संस्कृति है।

आदिवासियों की जीवनशैली अमौद्रिक होती है। वे प्रकृति के ज्यादा करीब हैं। प्रकृति के साथ उनका रिश्ता मां-बेटे का है। वे प्रकृति से उतना ही लेते हैं, जितनी उन्हें जरूरत है। अगर पत्ता चाहिए तो पत्ते लेते हैं और दातौन चाहिए तो दातौन ही। वे प्रकृति को नष्ट नहीं करते हैं, बल्कि बचाते हैं। वे खुद को भी प्रकृति का हिस्सा मानते हैं। लेकिन समय के साथ उनकी जीवनशैली में बदलाव भी आ रहा है।

मुख्यधारा की आधुनिक जीवनशैली जटिल व ऊर्जा गटकने वाली उपभोक्तावादी संस्कृति से जुड़ी है। उसमें तामझाम व दिखावा है। वह लोभ-लालच पर आधारित है, जिसकी सीमाएं आ चुकी हैं। प्राकृतिक संसाधन खत्म हो रहे हैं। कोयला व तेल खत्म होने वाले हैं। प्रदूषण से जलवायु बदलाव हो रहा है। ऐसे वैश्विक संकट के दौर में आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान, पुरखा संस्कृति, प्रकृतिप्रेमी सरल जीवन पद्धति से काफी कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन क्या हम आज के जलवायु बदलाव और वैश्विक संकट के दौर में आदिवासियों से कुछ सीखना चाहेंगे?

यहां लोग खेतों में कपास बोते थे। चरखा से सूत कातते थे, और फिर उससे कपड़ा बनवाते थे। महुआ की डोरी (फल), मूंगफली व जटगी का तेल निकाला जाता था। गांव में देशज तरीके से तेल निकालते थे। यानी मिट्टी तेल व नमक को छोड़कर गांव में जरूरत की सभी चीजें होती थीं। कई मायनों में गांव आत्मनिर्भर हुआ करता था। आदिवासियों ने ही हमें वन खाद्यों से परिचय कराया है। हरी पत्तीदार सब्जियां, मशरूम, कंद-मूलों से अवगत कराया है।

बीता सप्ताह

13 अप्रैल
- सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया के झूठी बातें फैलाने पर चिंता जाहिर की।
- लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी की गई।
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि देश में 45 फीसदी डॉक्टर अधूरी पर्ची लिख रहे हैं।
- वियतनामी अरबपति ट्रंग माई लैन को धोखाधड़ी के मामले में मौत की सजा सुनाई गई।

14 अप्रैल
- मुख्य न्यायाधीश वी वाई चंद्रचूड़ ने न्याय पालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परिवर्तनकारी भूमिका पर एक परिसंवाद में कहा जिनके पास संसाधन का कर रहे न्याय का दुरुपयोग।
- भारत व बंगलादेश के बीच 50 साल बाद जमीन की अदला बदली हुई। बंगलादेश के सीमावर्ती ठाकुरगांव के रानीसंकाई उपजिला की 56.86 एकड़ जमीन सौंपी गई और इसके जवाब में भारत को भी बंगलादेश से 14.68 एकड़ जमीन हासिल हुई।
- इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा देने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ सीबीआई केस दर्ज किया।
- कश्मीर में दो विदेशी पर्यटकों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई।

15 अप्रैल
- सुप्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान के आवास ग्लैक्सी रेसीडेंट पर दो अज्ञात युवक ने गोलियां चलाईं। जेल में बंद गैंगस्टर लारेंस विश्नोई के माफिया संगठन ने यह जिम्मेदारी ली है।
- नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा कि सरकार को अमीरों का ज्यादा ध्यान है। निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य व लैंगिक असमानता से विकास की गति धीमी है।
- 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के मुख्य ग्राफिक्स, रंग प्रणाली और खेल चिन्ह जारी किए गए।
- ईरान ने इजरायल पर किया ड्रोन व मिसाइल से हमला।

16 अप्रैल
- तमिलनाडु व केरल चुनाव प्रचार के दौरान राहुल के हेलिकॉप्टर की ली गई तलाशी।
- मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नही: मोदी
- केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस
- कश्मीर के चुनावी परिदृष्य में बेटे के लिए बाप व मां के लिए बेटी प्रचार में जुटी।
- भ्रष्टाचार अब अवसर का पासवर्ड नहीं बल्कि जेल जाने का रास्ता: धनखड़

17 अप्रैल
- कलपर के जंगलों में बीएसएफ-बीडीहारजी जवानों से मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए।
- कोल लेवी स्कैम मामले में आरोपी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज
- सरकार बनते ही रद्द करेंगे अग्निपथ योजना: राहुल
- सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पर बहस के दौरान कहा वोटो का वीवीपैट पर्चियों से हो मिलान।

18 अप्रैल
- अयोध्या में सूर्य की किरणों से रामलला का सूर्याभिषेक
- पंजाब में किसान आंदोलन जारी, ट्रैक पर बैठे।
- भाजपा समझ गई है कि वह देश की सत्ता में अब नहीं आएगी: शिवकुमार
- देश को कमजोर करने के लिए रची जा रही गहरी साजिश: राजनाथ सिंह

19 अप्रैल
- चुनावी प्रक्रिया में पवित्रता जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
- पूर्व आईपीएस मुकेश गुप्ता को हाईकोट से मिली राहत
- निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण
- सिद्दारमैया का दावा, कांग्रेस कर्नाटक में 20 लोकसभा सीटें जीतेगी
- केरल में मॉक पोल के दौरान भाजपा को मिले अतिरिक्त वोट, सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

18वीं लोकसभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण क्यों

■ नित्य चक्रवर्ती

भारत में 18वीं लोकसभा के चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को 102 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के साथ चुनाव शुरू हो गए। देश की लगभग 142 करोड़ आबादी में से 90 करोड़ मतदाताओं को कवर करने वाले सात चरण के चुनाव, 543 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के बाद 1 जून को समाप्त होंगे। परिणाम 4 जून को घोषित किये जायेंगे जिसके बाद यह स्पष्ट हो जायेगा कि सत्तारूढ़ भाजपा और एनडीए की ओर से प्रचार अभियान की कमान संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नयी लोकसभा में तीसरा कार्यकाल मिलेगा या नहीं।

इस लेखक को 1951-52 में हुए पहले लोकसभा चुनावों के बाद से सभी लोकसभा चुनावों को देखने का सौभाग्य मिला है - शुरुआत में दस साल की उम्र में कलकत्ता में एक वामपंथी पार्टी के स्वयंसेवक के रूप में। एक कार्यकर्ता के रूप में यह चरण 1969 तक कॉलेज और विश्वविद्यालय के दिनों तक जारी रहा। फिर 1969 से अब तक की भूमिका एक पत्रकार के रूप में लोकसभा चुनावों पर नजर रखने और देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर अभियान को कवर करने की रही है। इस बार भी, 82 वर्ष की आयु में, मैंने तमिलनाडु और पुडुचेरी की यात्रा की है और उसके बाद पश्चिमी जिलों को कवर करते हुए उत्तर प्रदेश की यात्रा की है। मैं कुछ दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 का लोकसभा चुनाव ऐसा होने जा रहा है जिसमें सत्तारूढ़ दल भाजपा की तुलना में विपक्षी दलों के लिए चुनाव मैदान में सबसे खराब असमान अवसर की स्थिति है। यहां तक कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भी, समान अवसर के मामले में विपक्ष बेहतर स्थिति में था।

सत्तारूढ़ शासन जिन तीन तरीकों से विपक्ष के समान अवसर को नष्ट कर रहा है, उनमें पहला है-विपक्ष के वित्तीय संसाधनों को निचोड़ना। कांग्रेस पार्टी को इसका मुख्य निशाना बनाया गया है। दूसरा है-विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों, जैसे ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का दुरुपयोग करते हुए महत्वपूर्ण विपक्षी नेताओं तथा उन्हें धन देने वाले दाताओं के विरुद्ध कार्रवाई करना। तीसरा है- प्रधानमंत्री और भाजपा के विचारों का प्रचार करने के लिए मीडिया, विशेषकर टीवी चैनलों पर पूर्ण नियंत्रण करना जो साथ-साथ विपक्ष के कार्यक्रमों और विचारों को बुरी तरह से दिखाये। यह रणनीति सोच-समझकर बनाई गई रणनीति है और इसका कार्यान्वयन 2019 के चुनावों के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से शुरू हुआ।

अभी, बड़ी आबादी वाले दो अन्य देशों-दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको में भी राष्ट्रीय चुनाव अभियान चल रहा है। दक्षिण अफ्रीका में 29 मई को और मैक्सिको में 2 जून को मतदान होने जा रहा है। तीन महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाले तीनों देशों में चुनाव परिणाम एक ही सप्ताह में सामने आयेंगे। इन दोनों देशों में अभियान चरम पर है लेकिन कहीं भी विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ सत्तारूढ़ शासन द्वारा किसी छापे का आरोप नहीं लगाया है। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष सिरिलरामाफोसा को रूढ़िवादी विपक्ष से बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वह लोकतंत्र के खेल के नियमों के तहत प्रचार कर रहे हैं।

मेक्सिको में भी यही स्थिति है। वामपंथी राष्ट्रपति ओब्राडोर, जिन्हें एएमएलओ के नाम से जाना जाता है, संविधान के अनुसार नये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को रास्ता देने के लिए पद छोड़ रहे हैं। एएमएलओ की स्वीकार्यता अपने चरम पर है। गठबंधन मोरेना आराम से जीतने की स्थिति में है। विपक्षी दलों को बड़ी पूंजी का समर्थन प्राप्त है लेकिन उन्होंने कभी भी एएमएलओ सरकार द्वारा किसी भी अलोकतांत्रिक कदम उठाये जाने की शिकायत नहीं की।

लोकसभा चुनाव और भारत में लोकतंत्र सूचकांक में गिरावट पश्चिम के साथ-साथ ब्रिक्स सदस्यों के बीच भी चर्चा का विषय है। 7अक्टूबर के युद्ध के बाद नरेंद्र मोदी को शुरू में उनके इजरायल समर्थक रुख के लिए ब्रिक्स सदस्यों से फटकार मिली। अब, उनके अभियान भाषणों और ईडी द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ-साथ चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की संपत्ति को निचोड़ने को ब्रिक्स देशों के राजनीतिक नेताओं द्वारा तिरस्कार के साथ देखा जा रहा है। भारत को 'लोकतंत्र की जननी' कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जा रहा है जो विपक्ष के लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश लगा रहा है।

कई पश्चिमी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव भारत में आखिरी स्वतंत्र चुनाव हो सकता है। वे सही नहीं हैं। निश्चित रूप से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोबारा आने से सत्तावादी प्रवृत्तियां मजबूत होंगी और भाजपा और संघ परिवार को हिंदू राष्ट्र के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है लेकिन यह आसान काम नहीं होगा। भारतीय लोगों के पास लोकतंत्र के पक्ष में अपनी पसंद का प्रयोग करने की अंतर्दृष्टि है। उन्होंने इसे 1977 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिखाया। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि विपक्षी इंडियागुट भाजपा के खिलाफ कितने प्रभावी ढंग से लड़ता है। उन्हें इस बार करो या मरो के नारे के साथ लड़ना है। खासकर यह बात कांग्रेस पर लागू होती है जो हिंदी पट्टी के ज्यादातर राज्यों में भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंद्वी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के रथ को रोकने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर है।

2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारत में भाजपा का रथ इतना बुलंद क्यों है और पीएम इस बार एनडीए का 400 पार और भाजपा का 370 पार के नारे की बात कर रहे हैं। भाजपा की प्रचार मशीन द्वारा बड़े राष्ट्रीय मीडिया की सहायता से यह नारा लगातार फैलाया जा रहा है। भाजपा के पास विशाल वित्तीय बाहुबल, सुगठित आरएसएस संगठन और प्रवासी भारतीयों का बड़ा समर्थन है, जिनमें से कई भाजपा चुनाव फंड में सक्रिय योगदानकर्ता हैं।

इसके विपरीत, कांग्रेस को भारतीय ब्लॉक पार्टियों में सबसे अधिक नुकसानदेह स्थिति में रखा गया है। हिंदी पट्टी में अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी के वित्तीय संसाधनों को पंगु बनाने के एक हिस्से के रूप में सत्तारूढ़ शासन द्वारा धन प्राप्त करने के लिए पार्टी के सामान्य माध्यमों को बंद कर दिया गया है। कांग्रेस के पास कई राज्यों में धन की कमी है और प्रति लोकसभा क्षेत्र में खर्च करने के मामले में उसकी क्षमता औसतन भाजपा की तुलना में दसवां हिस्सा है। इन दिनों चुनावों में डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। भारी फंड की जरूरत है। कांग्रेस उसक्षेत्र में भाजपा का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है।

यह 2024 के लोकसभा चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सबसे बड़ा झटका है। भाजपा ने समान अवसर को खत्म करने और मुख्य विपक्ष को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए सत्तारूढ़ सरकार और उसकी एजेंसियों का इस्तेमाल किया है। टीएमसी, डीएमके, एसपी और राजद जैसी अन्य क्षेत्रीय पार्टियां सीमित सीटों पर लड़ रही हैं। वे धन की व्यवस्था कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए, पार्टी द्वारा चुनाव लड़े जा रहे 300 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में धन की आपूर्ति करना एक कठिन काम बन गया है। यही वह कमजोरी है जिसे सत्तारूढ़ भाजपा 2024 के लोकसभा चुनावों में भुनाने की कोशिश कर रही है। इस प्रक्रिया में, भारतीय लोकतंत्र पीड़ित हो रहा है।

गार्जियन संवाददाता सही है जब अखबार लिखता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव भारतीय इतिहास में सबसे एकतरफा हो सकते हैं। हां, संसाधनों और मीडिया समर्थन के मामले में यह एकतरफा होगा लेकिन मतदाताओं के समर्थन के मामले में नहीं। नरेंद्र मोदी अपने अनूठे ब्रांड हिंदुत्व राष्ट्रवाद को क्रोनी पूंजीवाद और गरीब-समर्थक आर्थिक कार्यक्रमों के साथ मिलाकर बेच रहे हैं। इसमें एक प्रकार की विषैली अपील है। इंडिया गुट इसका मुकाबला केवल बेहतर आख्यान के साथ कर सकता है जो आम मतदाताओं के दिल और दिमाग से संबंधित हो सकता है। द्रमुक और टीएमसी जैसे क्षेत्रीय दल प्रभावी ढंग से ऐसा कर रहे हैं। कांग्रेस को उन राज्यों में भी ऐसा करना होगा जहां वह भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंद्वी है। केवल कांग्रेस, केवल कांग्रेस और केवल कांग्रेस ही अपने उच्च प्रदर्शन से भाजपा के रथ को रोक सकती है और भारत के लोकतंत्र सूचकांक को और नीचे गिरने से रोक सकती है।

कई पश्चिमी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव भारत में आखिरी स्वतंत्र चुनाव हो सकता है। वे सही नहीं हैं। निश्चित रूप से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोबारा आने से सत्तावादी प्रवृत्तियां मजबूत होंगी और भाजपा और संघ परिवार को हिंदू राष्ट्र के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है लेकिन यह आसान काम नहीं होगा। भारतीय लोगों के पास लोकतंत्र के पक्ष में अपनी पसंद का प्रयोग करने की अंतर्दृष्टि है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घातक है युद्ध की आहट

33 वर्षों में पहली बार एक विदेशी राष्ट्र ने 13 अप्रैल (शनिवार) को इज़रायल पर हमला किया। आखिरी बार 1991 में इराक ने इज़रायल पर क्रूज़ मिसाइलों से हमला किया था। यह ईरान था जिसने पिछले सप्ताह के अंत में इज़रायल में विभिन्न इलाकों पर 360 से अधिक मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपित किए थे। यह हमला धीमी गति से चलने वाले ड्रोन (जो ईरान से इज़रायल तक जाने में छह घंटे से अधिक समय लेते हैं), तेज क्रूज़ मिसाइलों और बहुत उच्च गति वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का एक संयोजन था जो ध्वनि की गति से भी तेज हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने इजरायल पर इस सुनियोजित हमले को लेकर पड़ोसी देशों को 72 घंटे की चेतावनी दी थी। उधर इज़रायल लगभग 99 प्रतिशत मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में कामयाब रहा और इसलिए उसका बहुत नुकसान नहीं हुआ। यह परिष्कृत मिसाइलरोधी रक्षा प्रणाली- आयरन डोम के कारण संभव हुआ जिसे इज़रायल ने अमेरिकी और ब्रिटिश मदद से बनाया था और इस बार जॉर्डन की धरती पर भी तैनात किया गया था।

रक्षा के उन कुछ घंटों के लिए अनुमानित खर्च लागत लगभग 1.1 बिलियन डॉलर थी। रक्षा आपूर्तिकर्ताओं, मुख्य रूप से अमेरिकी कंपनियों को इस तरह की तैनाती से लाभ होगा। बेशक, दो साल पहले शुरू हुए यूक्रेन युद्ध के कारण हथियार प्रणालियों के अमेरिकी निर्माताओं को पहले ही काफी फायदा हुआ है। ईरान द्वारा उस रात ड्रोन और मिसाइलों से किए हमले की लागत शायद एक अरब डॉलर के करीब है।

इज़रायल द्वारा 1 अप्रैल को सीरिया के दमिश्क में ईरानी दूतावास पर किए हमले के प्रतिशोध में ईरान ने यह हमला किया था। इस हमले में ईरान के दो वरिष्ठ जनरलों की मौत हो गई थी। बिना किसी उकसावे के किए इस हमले को इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अधिकृत क्यों किया, वह भी एक राजनयिक लक्ष्य पर? क्या इज़रायल हमास के साथ संघर्ष के दायरे को और विस्तारित करने की कोशिश कर रहा था तथा एक बढ़ते युद्ध में अन्य देशों को खींच रहा था? क्या उसे यह पता नहीं था कि ईरान के दूतावास पर उसकी कार्रवाई किसी जवाबी कार्रवाई को आमंत्रित करेगी? या इसने ईरान द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया को गलत समझा? इज़रायल के साथ सहानुभूति रखने वालों का तर्क होगा कि इज़रायल की कार्रवाई अकारण नहीं थी। यह इज़रायल के क्षेत्र के भीतर हमास का समर्थन करने वालों को दंडित करना था। सभी लोग जानते हैं कि इज़रायल के भीतर हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हौथिस को ईरान का मौन समर्थन है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को विफल करने और हमास तथा हिजबुल्लाह के समर्थन का बदला लेने के लिए इज़राइल ने पहले भी ईरान के बुनियादी ढांचे और सैन्य स्थलों पर हमले किये हैं। ईरान ने भी अपनी परमाणु हथियार क्षमता के निर्माण की गति को बनाए रखा है। इज़रायल निश्चित रूप से एक परमाणु सशस्त्र राष्ट्र है जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

ईरान द्वारा इज़रायल पर ड्रोन और मिसाइल के असफल हमले को कुछ टेलीविजन और सोशल मीडिया चैनलों ने तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत बताया। शेयर बाजारों में हड़बड़ाहट दिखाई दी। ईरान की जवाबी कार्रवाई की आशंका में शुक्रवार को ही न्यूयॉर्क का डाउ इंडेक्स 2.4 फीसदी गिर गया था। दुनिया भर में शेयरों में और गिरावट की आशंका है। सोने की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और 2400 डॉलर प्रति औंस के करीब है। भारत में जल्द ही दस ग्राम सोने का मूल्य 80,000 रुपये को पार कर सकता है। जोखिम से बचने वाले उन निवेशकों द्वारा सोने की उच्च मांग की सहज प्रतिक्रिया है, जिन्हें डर है कि अन्य सभी संपत्तियों की कीमतों में भारी गिरावट आएगी। यह संघर्ष मध्य पूर्व से तेल आपूर्ति को बाधित करेगा इसलिए तेल की कीमतें निश्चित रूप से बढ़ेंगी। माल ढुलाई दरों और हवाई कार्गो के लिए जोखिम प्रीमियम में भी बढ़ेगा जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार की लागत में वृद्धि होगी। इस सारे घटनाक्रम का भारत पर तिहरा दबाव पड़ता है। यह हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को कम करता है, विनिमय दर पर दबाव डालते हुए व्यापार घाटे को बढ़ाता है और चूंकि पेट्रोल व डीजल की कीमतें प्रभावित होंगी इसलिए मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण बन सकता है। मार्च में समाप्त होने वाली चौथी तिमाही में मंदी देखी गई थी तथा उस तिमाही के लिए जीडीपी विकास दर 6 प्रतिशत के करीब हो सकती है।

निवेशकों का बिगड़ता मिज़ाज जीडीपी वृद्धि को और भी धीमा कर सकता है हालांकि चुनाव खर्च आम तौर पर जीडीपी को ऊपर उठाए रखता है। यदि वैश्विक आर्थिक मिज़ाज का अंदाजा लगाया जाए तो व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक उसी तरह जैसे हौथियों के हमलों के कारण लाल सागर के व्यापार मार्ग में व्यवधान ने समुद्री व्यापार की लागत में वृद्धि की है। यह स्थिति भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नकारात्मक है। खुदरा महंगाई में वृद्धि की खबर भी राहत देने वाली नहीं है तथा तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण और खराब हो सकती है। यही कारण है कि भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती नहीं कर सकता है जिससे आवास और वाहन ऋण में मदद मिल सकती थी।

और अंत में, बेरोजगारी के बारे में आई रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित हालिया रिपोर्ट ने युवा बेरोजगारी, कौशल असंतुलन और श्रम शक्ति में अभी भी महिलाओं की कम भागीदारी की एक गंभीर तस्वीर चित्रित की है। भारत में वर्ष 2005 से श्रम बल की भागीदारी तथा पुरुषों और महिलाओं की मजदूरी दर में अंतर के संदर्भ में लैंगिक अंतर बढ़ता जा रहा है। यह अंतर कम नहीं हो रहा है, जैसा कि दुनिया के अन्य हिस्सों में देखा जा रहा है। इसके अलावा अनुमान है कि कोविड के बाद करीब 5 करोड़ श्रमिक कृषि क्षेत्र में वापस चले गए हैं जो कम उत्पादकता, कम गुणवत्ता वाली नौकरियों के साथ-साथ अल्प-रोजगार भी प्रदान करता है। रोजगार परिदृश्य में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की आवश्यकता है जो मुख्य रूप से निजी क्षेत्र से आएगा। इसके लिए निवेशकों के विश्वास और नए उद्यमों, व्यवसायों और उद्यमों में बड़े पैमाने पर फंड प्रवाह की आवश्यकता होती है। अकेले सरकार बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन नहीं कर सकती है।

मध्य-पूर्व में तनाव के कारण बढ़ी अनिश्चितता सिर्फ रक्षा आपूर्ति निर्माताओं के लिए अच्छी खबर है। अधिकांश लोगों के लिए यह बुरा आर्थिक समाचार है। सुरक्षा परिषद के दोनों सदस्यों-चीन या रूस ने ईरान के हमले की निंदा नहीं की है। इज़रायल को गाज़ा पर बमबारी बंद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में रखे प्रस्ताव को एकमात्र असहमत देश संयुक्त राज्य अमेरिका ने बार-बार वीटो किया है।

हमास द्वारा 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमले के लिए इज़रायल का प्रतिशोध अब अनुपात से ज्यादा लगता है। इज़रायल की बदले की कार्रवाई में अब तक 30,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है जिनमें ज्यादातर नागरिक हैं। इनमें अनेक महिलाएं एवं बच्चे शामिल हैं। जैसे यूक्रेन में बमबारी का कोई अंत नहीं दिख रहा है उसी तरह इज़रायल द्वारा गाज़ा पर हमलों की समाप्ति के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। युद्ध के बादल बस घने तथा और गहरे होते जा रहे हैं। शांति की गुहार लगाने वालों को युद्धोन्मादी लोगों ने बाहर कर दिया है। संघर्ष विराम या शांति वार्ता तो दूर की बात है, नेता कोई समझदारी का माहौल बनाने में नाकाम रहे हैं। यह सब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है जो पहले से ही महंगाई, स्थिर निजी निवेश, उच्च युवा बेरोजगारी दर और व्यापक असमानता की चुनौतियों से जूझ रही है।

(लेखक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। सिंडिकेट: द बिलियन प्रेस)

डॉ.अजीत रानाडे

हमास द्वारा 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमले के लिए इज़रायल का प्रतिशोध अब अनुपात से ज्यादा लगता है। इज़रायल की बदले की कार्रवाई में अब तक 30,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है जिनमें ज्यादातर नागरिक हैं। इनमें अनेक महिलाएं एवं बच्चे शामिल हैं। जैसे यूक्रेन में बमबारी का कोई अंत नहीं दिख रहा है उसी तरह इज़रायल द्वारा गाज़ा पर हमलों की समाप्ति के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। युद्ध के बादल बस घने तथा और गहरे होते जा रहे हैं।

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

दैनिक जलते दीप

जोधपुर, शनिवार 20 अप्रैल 2024

आतंक फैलाने की कोशिश

पिछले कुछ समय से जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों की बढ़ती सख्ती के बीच आतंकियों पर शिकंजा कसा है। इसकी वजह से आतंकवादियों के बीच हताशा की स्थिति साफ देखी जा सकती है। शायद यही वजह है कि अब आतंकियों ने पहचान तय करके किसी साधारण व्यक्ति को मार डालने की नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, ताकि सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। मगर उनकी ऐसी बर्बरता और अपनी मंशा को पूरा करने के लिए मानवीयता के खिलाफ हर हद को पार करने की हरकतों से उनकी हकीकत का पता चलता है। वरना क्या कारण है कि वहां अन्य राज्य से आकर कोई छोटा-मोटा काम करके गुजारा करने वाले गरीब लोगों या मजदूरों को भी मार डालने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती। हालांकि आतंकवाद की जिस दृष्टि के साथ वे काम करते हैं, उसमें उनकी इस तरह की अमानवीय हरकतों पर हैरानी नहीं होती। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों ने एक बार फिर लक्षित हत्या की घटना को अंजाम दिया। बुधवार को बिजबेहरा इलाके के जबलीपोरा में आतंकियों ने एक मजदूर को नजदीक से गोली मार दी। मारा गया व्यक्ति बिहार से वहां जाकर मजदूरी और अन्य काम करता था। केवल इस वर्ष निशाना बना कर किसी व्यक्ति को मार डालने की यह तीसरी घटना है। पिछले कुछ समय से सुरक्षा बलों की बढ़ती सख्ती के बीच हताश आतंकियों ने अब राज्य के बाहर से आकर गुजारा करने वाले लोगों की हत्या करना शुरू कर दिया है। इससे पता चलता है कि उनका मकसद राजनीतिक नहीं है, बल्कि हिंसा और निर्दोष या मासूम लोगों की हत्या के जरिए आतंक फैलाना ही उनकी राजनीति है। दरअसल, यह वारदात जिस अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में हुई, वहां सात मई को तीसरे चरण के तहत मतदान होना है और उम्मीद की जा रही है कि वहां लोग अपने मताधिकार का खुल कर प्रयोग करेंगे। जाहिर है, बिहार से जम्मू-कश्मीर जाकर मजदूरी करने वाले व्यक्ति की हत्या दरअसल स्थानीय लोगों के बीच भी दहशत फैलाने की कोशिश है, ताकि लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोका जा सके। समस्या यह है कि आए दिन सरकार आतंकवाद का सामना करने और उसका खात्मा करने के लिए हर स्तर पर सख्ती बरतने और आतंकियों का असर कम होने का दावा करती है। निश्चित रूप से आतंकियों पर नकेल कसने में मदद मिली है। आतंकवादी संगठनों को अब पहले के मुकाबले स्थानीय लोगों का संरक्षण भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसी हत्याओं से सुरक्षा व्यवस्था के चौकस होने के सरकार के दावों पर भी सवाल उठते हैं। लक्षित हत्याओं की नई रणनीति से आए दिन बाहरी या फिर स्थानीय लोगों को जिस तरह पहचान कर निशाना बना कर मार डालने की घटनाओं के जरिए लोगों के बीच आतंक फैलाने की कोशिशों में जिस तरह बढ़ोतरी हुई है, उससे साफ है कि अभी आतंकियों का असर खत्म नहीं हुआ है। किसी की पहचान तय करके उसे मार डालने का एक मकसद यह भी होता है कि अलग-अलग समुदायों के बीच आपस में दूरी और संदेह का माहौल पैदा किया जाए, ताकि असुरक्षाबोध से घिरे लोगों का इस्तेमाल मन-मुताबिक किया जा सके। जाहिर है, सुरक्षा बलों को अब हालात के मुताबिक नई रणनीति के तहत आतंकियों के खिलाफ मोर्चा लेना होगा।

आपदा को आमंत्रण

युक्त अरब अमीरात और खाड़ी के कुछ अन्य देशों में अचानक आई भारी व असामान्य बारिश ने इंसान को तमाम सबक दिए हैं। जिन देशों को अपनी समृद्धि व संपन्नता का दंभ था, वहां आई मूसलाधार बारिश ने सारी आधुनिक व्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी। दुनिया का सबसे ज्यादा आधुनिक व चहल-पहल वाला दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अराजकता का शिकार हो गया। सैकड़ों उड़ाने रद्द हो गईं। दुनिया के चोटी के हवाई अड्डों में शामिल जिस दुबई एयरपोर्ट में पिछले साल आठ करोड़ यात्रियों की आमद थी, एक मूसलाधार बारिश से उसकी सारी व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी थीं। इस दौरान ओमान में 19 लोगों की मौत के अलावा अन्य देशों में भी लोगों के हताहत होने की आशंका है। बताते हैं कि अभी भी कई निचले इलाकों में बारिश का पानी भरा हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात में पिछले 75 साल बाद रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में डूबे वाहन और बारह लेन वाले हाईवे पर लगा जाम बता रहा है कि कुदरत की माया के आगे मानव का विकास अभी भी बौना ही है। फिर मध्यपूर्व के रेगिस्तानी इलाकों में मूसलाधार बारिश का होना निश्चित ही अचरज की बात है। अचानक आई इस बारिश और बाढ़ को जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कहा जा रहा है। लेकिन वहीं लोग आरोप लगा रहे हैं कि यह घटना विशुद्ध रूप से प्रकृति से मानवीय छेड़छाड़ का नतीजा है। आलोचक इस असामान्य बारिश को क्लाउड सीडिंग का नतीजा बता रहे हैं। दरअसल, कृत्रिम तरीके से बारिश कराने की कोशिश को ही क्लाउड सीडिंग कहा जाता है, जिसमें बादल में बारिश के बीज बोने के लिये कृत्रिम तरीके से प्रयास किये जाते हैं। ऐसे कुछ प्रयास यूएई में किये जा रहे थे। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में बताया गया है कि रविवार व सोमवार को यूएई में क्लाउड सीडिंग की योजना बनायी गई थी और मंगलवार को भयावह बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं। आशंका जतायी जा रही है कि क्या कृत्रिम बारिश के प्रयासों के चलते यह स्थिति पैदा हुई है? बहरहाल, आने वाले वक्त के अध्ययन हमें बताएंगे कि इस आपदा के आने में क्लाउड सीडिंग की कितनी भूमिका थी। वैसे दुनिया के तमाम देशों में संकट के समय क्लाउड सीडिंग कराने के मामले सामने आते रहते हैं। किन्हीं देशों में सामरिक तो कहीं कृषि उद्देश्यों के लिये कृत्रिम बारिश का सहारा लिया जाता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते बदले हालात में यह संकट गहरा हो जाता है। उल्लेखनीय है कि कृत्रिम बारिश का सहारा तब लिया जाता है, जब हवा की नमी की कमी के चलते बारिश नहीं हो पाती। भारत में साठ के दशक में कृत्रिम बारिश का प्रयोग किया गया था। दरअसल, बारिश के बीजों के रूप में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड व सोडियम क्लोराइड जैसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिनका हवाई जहाज की मदद से बादलों में छिड़काव किया जाता है। इससे बर्फ के कण बादलों की नमी के साथ मिलकर बारिश होने की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। दरअसल, आधुनिक विकास के मोह में संयुक्त राज्य अमीरात अपने व्यापारिक उद्देश्यों व नागरिकों के लिये पानी की कमी को पूरा करने के लिये इस तकनीक का उपयोग करता रहा है। ऐसे ही भारत में नब्बे के दशक में तमिलनाडु में भयंकर सूखे से निपटने के लिये क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कई बार किया गया था। वहीं चीन ने भी बीजिंग में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पर्यावरण प्रदूषण दूर करने के लिये क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया था। बहरहाल, यूएई, ओमान व सऊदी अरब जैसे इलाकों में ऐसी भारी बारिश हमारे नीति-नियंताओं को विकास योजनाओं को लेकर नये सिरे से विचार करने को मजबूर कर रही है। इन देशों को अपनी सड़कों व अन्य विकास कार्यों को अब बारिश के ऐसे संकट को नजर में रखकर तैयार करना होगा। साथ ही मनुष्य को इस तथ्य को गंभीरता से स्वीकारना होगा कि प्रकृति के साथ अन्याय करने पर हमें उसका प्रतिकार सहने के लिये तैयार रहना होगा।

प्रसंगतः परोपकार की सीख

अरब के एक खलीफा बेहद ईमानदार और न्यायप्रिय थे। एक बार वह बीमार हो गए। उनका काफी इलाज कराया गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपना अंत समय जान खलीफा ने खजांची को बुलाया और उससे पूछा, 'बताओ, खलीफा बनने के बाद मेरी निजी संपत्ति कितनी बढ़ी है?' खजांची ने हिसाब लगाया और बोला, 'हुजूर, आपकी निजी संपत्ति में एक ऊंट, एक दुशाला और एक बकरी का इजाफा हुआ है।' खलीफा ने उन्हें गरीबों में बांट देने का हुक्म दिया। इसके बाद उन्हें यह भी पता चला कि उन्होंने राजकोष से पांच हजार दिरहम लिए थे। इस पर वह बोले, 'मेरा घर बेचकर पांच हजार दिरहम खजाने में जमा कर दिए जाएं और जो बचें उन्हें गरीब लोगों व अनाथ बच्चों में बांट दिया जाए।' इसके बाद वह अपने आसपास खड़े सभी लोगों से बोले, 'मेरी आखिरी यात्रा में सिर्फतीन कपड़े मेरे जिस्म पर हों, जिनमें से दो तो इस वक्त मेरे शरीर पर हैं ही। तीसरा कपड़ा खरीद कर मुझ पर डाल दिया जाए।' यह सुनकर उनके कुछ मित्र बोले, 'हम तीनों नए कपड़े खरीद ही सकते हैं और फिर अंतिम यात्रा में तो नए कपड़े लिए जाने चाहिए, भला पुरानों से काम क्यों चलाया जाए?' उन मित्रों की बात सुनकर खलीफा बोले, 'अरे भाई, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धरती पर नए कपड़ों की जरूरत मुर्दों के बजाय जिंदा लोगों को ज्यादा है। आप लोग कृपया जिंदा लोगों को ही नए कपड़े देने का प्रयास करें।' यह सुनकर सभी लोग खलीफा के प्रति श्रद्धा से भर उठे।

बुद्धिहीन उपभोक्तावाद की आसक्ति से नहीं मिलेगी खुशी

– अविजित पाठक

हालांकि हम लोग एक भयावह रूप से हिंसाग्रस्त विश्व में जी रहे हैं, वह जिसमें लगातार होने वाले युद्ध, सैन्यीकरण, नए किस्म का अधिनायकवाद, बढ़ती आर्थिक असमानता, पर्यावरण संकट और सामाजिक कारणों से बना मानसिक संताप इसका चरित्र बन गया है। और मानो इन सबके बीच 'खुशी' ढूंढ़ना एक अनन्त खोज बन गई है। आधुनिक काल में, हमें गुणा-भाग वाली सूक्ष्मता से प्यार हो गया कि तुर्रा यह कि खुशी जैसे उच्च गुणवत्तापूर्ण और आत्मनिष्ठ अनुभव को भी हमने नापने-तोलने की चीज़ बना डाला है। हर साल, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास उपाय नेटवर्क एक सूची जारी कर, विभिन्न मुल्कों का पदानुक्रम तय करता है जो उसके हिसाब से मापने लायक 'खुशी सूचकांक' पर आधारित हैङ्क इस निर्धारण में सकल घरेलू उत्पाद, आयु दीर्घता, राजकीय कामकाज दक्षता, स्वतंत्रता, सामाजिक संबल (परोपकारी व्यवहार) को गिना जाता है। जहां फिनलैंड पिछले सालों की भांति 'सबसे खुश' देश है वहीं विश्व खुशी रिपोर्ट-2024 में भारत का स्थान 143 देशों में 126वां है।

खैर, मैं इस किस्म की रिपोर्ट के गुण-दोषों को पूरी तरह खारिज भी नहीं करता। बेशक, एक उचित मात्रा में सामाजिक सुरक्षा, राज्य द्वारा चलाई जाने वाली सामाजिक भलाई नीतियां, अच्छी मेडिकल सुविधाएं, रोजगार उपलब्धता, संवाद की मौजूदगी वाला समाज और राजनीतिक स्वतंत्रता रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ हद तक संतोष पैदा करते हैं। तथापि, यहां यह अहसास भी उतना ही जरूरी है कि 'शुद्ध खुशी' जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि उल्लास के हमारे सबसे बढ़िया लम्हे और संतोष भी कुछ हद तक आशंका से जुड़े होते हैं, मसलन, जो कुछ हमारे पास है उसे खोने का डर, चाहे यह भौतिक संपदा, शरीर की तंदुरुस्ती हो या फिर प्रियजनों का साथ छूटने का भय। ताजिंदगी हम 'सम्पूर्ण खुशी' के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी यह हाथ नहीं आती। कोई हैरानी नहीं कि हमारे इस काल में जीवन जीने का ढंग सिखाने वाले, प्रेरणास्पद भाषणकर्ता और आध्यात्मिक बाबाओं की कोई कमी नहीं, जो बारम्बार हमें एक खास तकनीक पर चलने की सीख देते हैं, मसलन, समाधि अभ्यास, श्वास साधक व्यायाम, सचेतन होना इत्यादि ङ्क'खुश' व 'सफल' होने के मकसद हेतु। लेकिन फिर, यह समझना चाहिए कि खुशी की प्राप्ति कैप्सूल खाने जैसा एक त्वरित उपाय नहीं है, जिसकी खुराक किसी स्व-सहायता पुस्तक या आश्रम अथवा मठ के विशेष सत्रों में भाग लेकर मिले। तथ्य तो यह है कि यदि सच में हम एक आडम्बरहीन, शांतिपूर्ण और संतोष से परिपूर्ण दुनिया की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमें स्व और दुनिया अथवा राजनीति और अध्यात्म के बीच पुल बनाना होगा। उदाहरणार्थ, जरा सोच कर देखिए, जो व्यक्ति भूख, कुपोषण और सिर पर छत न होने से बेहाल है उसको संचेतना सिखाने की बेवकूफी (बुरे अनुभवों से बने संताप या अस्थिर भविष्य की आशंका को नज़रअंदाज कर वर्तमान में जीने की समर्था बनाए)। या फिर उस मानसिक हिंसा के बारे में सोचिए जो एक बेरोजगार युवा के मानस पर चोट करती है, जब नौकरी पाने में कंपनी दर कंपनी से अस्वीकृति झेलनी पड़े, तिस पर आप उसे सबसे अधिक बिकने वाली स्व-सहायता किताब 'मैं ठीक हूं-आप ठीक हैं' जैसी कोई पुस्तक पढ़ने को कहें ताकि 'अच्छा' और 'सकारात्मक' महसूस का भ्रम पाले। यह ठीक उतना ही बेवकूफाना है जब किसी बेघर को या जो पहले से झुग्गी में रह रहा है, उसे न्यूनतम साधनों में जीवन जीने का प्रवचन दिया जाए। राजनीतिक व आर्थिक असमानता की नींव को बदले बिना हम अ गैर-बराबर व शोषण करने वाली दुनिया को बदलकर संतोष की ओर नहीं बढ़ सकते।

इसी प्रकार जैसा कि 'भारत रोजगार रिपोर्ट 2024' बताती है कि भारतीय युवाओं में 83 प्रतिशत बेरोजगार हैं या जब 'द राइज़ ऑफ बिलिनियर्स राज' नामक शोध-पत्र कहे कि भारत के चोटी के 1 फीसदी अमीरों के हाथ में 40 प्रतिशत आम लोगों के बराबर सरमाया है, तो एक आम भारतीय को महसूस हो रहे संताप, भय और आशंका का अंदाजा लगाना कठिन नहीं। भले ही हमारे पास हज़ारों की संख्या में बाबा, गुरु और स्व-सहायता सिखाने वाले हों, जो मोक्ष प्राप्ति की जुगत के तौर हमें नाना किस्मों की घुट्टी पिलाते हैं, तथापि अलफ सच्चाई है कि हमारा देश नाखुश मुल्क है। संभवतः हमारे समाज में राजनीतिक-आर्थिक पुनर्संरचना किए बिना हम वैसा सामाजिक परिवेश नहीं बना सकते, जो यथेष्ट संतोष से परिपूर्ण लोगों की तरक्की अनुकूल हो।

ऐसा नहीं है कि मुझे अर्थपूर्ण, सतत और करुणामय जीवन के लिए आत्मविश्लेषण या अंदरूनी शांति के महत्व से इंकार है। जहां उचित मात्रा में आर्थिक सुरक्षा और राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे रोजमर्रा के जीवन को कुछ आरामदायक बनाती है वहीं हम एक अधिक अर्थपूर्ण और शांतिपूर्ण वजूद की ओर नहीं बढ़ सकते, जिसके बिना मैं जीवन को धर्मनिष्ठ नहीं कह सकता। उदाहरणार्थ, यह धर्मनिष्ठा जीवन जीने के ढंग में, गैर-उपभोक्तावाद अवस्था की कला विकसित करने के बारे में हैं। भोजन, आवास, जीवन-पुष्ट शिक्षा, राजनीतिक स्वतंत्रता और विरक्ति न बनाने वाले काम जैसी मूलभूत जरूरतों को लालच के वायरस के मोहपाश में जा फंसने से अलहदा कर पहचानना होगा वह लालच जिसका बाजार-चालित समाज ने सामान्यीकरण कर दिया है।

हां, उस समाज में कभी खुशी नहीं हो सकती जो नवउदारवादी बाजार द्वारा उत्पादित नित नए फैशनों या नई वस्तुओं के प्रति बुद्धिहीन उपभोक्तावाद या निरंतर बढ़ती आसक्ति के सिद्धांत को मान्यता दे। लालसा की यह प्रवृत्ति शांति और धीरज को भंग करती है । इसकी बजाय व्यक्ति में ईर्ष्या, अशांति और पीछे छूट जाने का भयंकर डर बनाती है। इसी प्रकार, दूसरों से जुड़े रहने वाले स्व को विकसित करने की कला भी उतनी ही महत्वपूर्ण है वह स्व जिसे दिखने में साधारण से कामों में भी बहुत आनंद मिलता हो जैसे कि दोस्तों से बिना स्वार्थ मिलना या पहाड़ी इलाके में सैर और प्रकृति की अनंतता की झलकी का अनुभव करना। यह बेशक साधारण लगे लेकिन फिर भी सर्जनात्मकता के अतिरेक से लबरेज होती है, वह जो हमें निरंतर ललचाने और बहकाने वाली बाजारीकरण संस्कृति से उपजी मिथकीय 'सफलता' या 'अति उत्तम और खुशी' वाली जिंदगी की मरीचिका से पीछे भागने की लालसा से मुक्त रहने में मददगार होती है।

जीवन की धर्मनिष्ठा को जरूरत है हमारे अस्तित्व में अंतर्निहित उदासी को अंगीकार करने के साहस की। यह 'सब कुछ हमारे बस में नहीं' को स्वीकार करने जैसा है। जो कुछ हम थामकर रखना चाहते हैं वह चलायमान और अस्थाई है। बिना पूर्व सूचना घटित अकल्पनीय दुर्घटनाएं और शोकाकुल प्रसंग हमारे अस्तित्व को झिंझोड़ सकते हैं, मौत की सच्चाई से कोई नहीं बच सकता जो कि हमारे फुलाए अहम की व्यर्थता की अंतिम परिणति है। संभवतः यह अहसास, हमें कटु बनाने की बजाय, आंसुओं से भरे इस लौकिक अस्तित्व से गुजरने में समर्थ बनाता है। **(लेखक समाजशास्त्री हैं।)**

कई आशंकाओं से भरा खतरनाक रास्ता!

हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कनीना में सड़क हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई। 15 से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। चूंकि माहौल चुनाव का है सो प्रधानमंत्री से लेकर विधायक तक सक्रिय हो गये। कुछ कार्रवाई होती भी दिख रही है। जो बस सड़क पर चल रही थी, उसका अनफ़िट होने के कारण एक महीने पहले भी 15 हजार का चालान हुआ था। सब जानते थे कि बस चलाने वाला शराब पिए है और उसकी ड्राइविंग बेलगाम थी, इसके बावजूद बस सड़क पर चलती रही। अभी इस दुर्घटना के बाद सड़कों पर बसों की जांच और चालान की औपचारिकता चल ही रही थी कि यमुनानगर में स्कूली बच्चों से भरा एक तिपहिया पलट गया, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। सात बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। जो वाहन महज तीन सवारी के लिए परमिट प्राप्त है, उसमें 12 से अधिक बच्चे भरे थे। सड़क पर चलने के लिए नाकाबिल वाहन, क्षमता से अधिक बच्चे, बेतहाशा गति, अकुशल चालकङ्क स्कूल जाने वाले बच्चों को लाने ले जाने में लिप्त वाहनों के मामले में सारे देश की यही एक-सी तस्वीर है।

दिल्ली के वजीराबाद पुल पर लुडलो केसल स्कूल की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 28 बच्चों की मौत के बाद सन्‌ 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूली बसों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके अनुसार स्कूल बस पीले कलर की होनी चाहिए। इसके साथ ही उस पर स्कूल बस जरूर लिखा होना चाहिए। बस में फर्स्ट-एड बॉक्स होना जरूरी है और बस की खिड़की में ग्रिल लगी होनी चाहिए। इसके साथ ही बस में आग बुझाने वाला यंत्र भी लगा होना चाहिए। स्कूल बस पर स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर भी होना चाहिए।

यही नहीं, दरवाजों पर ताले लगे हों और बस में एक अटेंडेंट भी हो। सबसे बड़ी बात कि अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। यह निर्देश दिल्ली में ही हवा-हवाई हैं। और अब तो स्कूल पहुंचने की राह में बड़ा खतरा ओमनी वैन हैं जिसमें अतिरिक्त सीटें लगा कर क्षमता से दोगुने नहीं तीन गुणा अधिक बच्चे बैठना, उनकी अंधाधुंध स्पीड और सबसे अधिक उसके चालकों का संदिग्ध व्यवहार नए किस्म का खतरा है। देश में आए रोज बच्चों के यौन शोषण में ऐसे वाहन चालकों की संलिप्तता सामने आती है। बसों के मामलों में तो स्कूल को जिम्मेदार बना दिया जा सकता है लेकिन वैन में ओवर लोडिंग, दुर्व्यवहार और दुर्घटना होने पर स्कूल हाथ झटक कर अलग हो जाते हैं। बीते कुछ सालों में बैटरी चालित रिक्शा स्कूल की राह का एक खतरनाक साथी बना है। इसमें बेशुमार संख्या में बच्चों को भरना, प्रतिबंधित या तेज गति के वाहनों वाली सड़क पर संचालन करना और अनाड़ी चालक होने के कारण इनके खूब एक्सीडेंट हो रहे हैं।

बीते कुछ सालों में विद्यालयों में बच्चों का पंजीकरण बढ़ा है। स्कूल में ब्लैक बोर्ड, शौचालय, बिजली, पुस्तकालय जैसे मसलों से लोगों के सरोकार बढ़े हैं, लेकिन जो सबसे गंभीर मसला है कि बच्चे स्कूल तक सुरक्षित कैसे पहुंचें? इस पर न तो सरकारी और न ही सामाजिक स्तर पर कोई विचार हो पा रहा है। इसी की परिणति है कि आए रोज देशभर से स्कूल आ-जा रहे बच्चों की जान जोखिम में पड़ने के दर्दनाक वाकिये सुनाई देते रहते हैं। परिवहन को प्रायः पुलिस की ही तरह खाकी वर्दी पहनने वाले परिवहन विभाग का मसला मान कर उससे मुंह मोड़ लिया जाता है। दरअसल बढ़ते पंजीकरण को देखते हुए बच्चों के सुरक्षित, सहज और सस्ते आवागमन पर जिस तरह की नीति की जरूरत है, वह नदारद है।

निजी स्कूलों में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, स्कूलों की अपनी बसों की संख्या सीमित हैं, औसतन 1000-1500 बच्चे इनसे स्कूल आते हैं। शेष का क्या होता है? यह देखना रोंगटे खड़े कर देने वाला होता हैं। पांच लोगों के बैठने के लिए परिवहन विभाग से लाइसेंस पाए वैन में 12 से 15 बच्चे ठुंसे होते हैं। बैटरी रिक्शे में दस बच्चे 'आराम' से घुसते हैं। दुपहिया पर बगैर हैलमेट लगाए अभिभावक तीन-तीन बच्चों को बैठाए रफ्तार से सरपट होते दिख जाते हैं। रोज एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि यही समय कालोनी के लोगों का अपने काम पर जाने का होता है।

ऐसा नहीं है कि स्कूल की बसें निरापद हैं, वे भी 52 सीटर बसों में 80 तक बच्चे बैठा लेते हैं। यहां यह भी गौर करना जरूरी है कि अधिकांश स्कूलों के लिए निजी बसों को किराए पर लेकर बच्चों की ढुलाई करवाना एक अच्छा मुनाफे का सौदा है। ऐसी बसें स्कूल करने के बाद किसी रूट पर चार्टेड की तरह चलती हैं। तभी बच्चों को उतारना और फिर जल्दी-जल्दी अपनी अगली ट्रिप करने की फिराक में ये बस वाले यह ध्यान रखते ही नहीं है कि बच्चों का परिवहन कितना संवेदनशील मसला होता है।

इस दिशा में सबसे पहले तो विद्यालय से बच्चे के घर की दूरी अधिकतम तीन से पांच किमी का फार्मूला लागू करना चाहिए। स्कूल का समय सुबह 10 बजे से करना, सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करना, प्रयुक्त वाहनों में ओवरलोडिंग या अधिक रफ्तार से चलाने पर कड़ी सजा का प्रावधान करना, असुरक्षित साधनों के लिए कड़े मानदंड तय करना समय की मांग है।

– पंकज चतुर्वेदी

जीवन पर्यन्त कला सृजन को समर्पित रहे प्रयोगधर्मी चित्रकार अब्बासी

जिनकी कलाकृतियों ने राजस्थान ही नहीं, देश दुनिया में बनाई अपनी अलग पहचान

पहली पुण्यतिथि पर विशेष

सैयद मेहर अली अब्बासी जोधपुर कला जगत की एक ऐसी बकमाल और बेमिसाल शख्सियत रही हैं, जिन्होंने जीवन पर्यन्त अपनी प्रयोगधर्मी चित्र व मूर्तिकला के माध्यम से जोधपुर का नाम सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश दुनिया में रोशन किया है। पिछले वर्ष 2023 में 75 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए अब्बासी धर्मनिरपेक्षता की अनूठी मिसाल थे। इस बात का प्रमाण यह है कि उन्होंने पांच हजार से ज्यादा भगवान गणेश की पेंटिंग्स का सृजन किया था। कला सृजन उनके लिए किसी इबादत से कम नहीं था। अब्बासी का यह गणेश प्रेम दर्शाता है कि वे धर्म की बंदिशों से दूर कला के प्रति पूरी तरह समर्पित थे।

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कला संकाय के असिसटेंट प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त अब्बासी ने करीब पचास वर्षों तक कला का सृजन किया। विश्वविद्यालय में कला संकाय स्थापित करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता हैं। अनेक राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पुरस्कारों का सम्मान देश व अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सैकड़ों कला प्रदर्शनियों में पेंटिग्स प्रदर्शित की गई। इसके अलावा मुंबई की जहांगिर आर्ट गैलरी सहित देश के प्रमुख महानगरों की स्थायी कला दीर्घाओं में उनकी पेंटिंग्स दर्शकों को लूभा रही है।

अब्बासी का गणेश प्रेम- विश्वविद्यालय से रिटायर होने के बाद अंतिम सांस तक प्रतिदिन करीब 18 घंटे कला की साधना की। उन्होंने 10, 000 से भी ज्यादा पेंटिंग और क्राफ्ट के काम किए हैं। राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय कला दीर्घाओं समेत कला जगत के कद्रदान भी उनके गणेश प्रेम के ही मुरीद हैं। इसके लिए उन्होंने हिंदू माइथोलॉजी का भी गहराई से अध्ययन किया।

गणेश की स्तुति में कला को माध्यम बना दर्शन के साथ हिंदू माइथोलॉजी को भी अब्बासी ने बखूबी दिखाया। उन्होंने अपनी कला में ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्किल को मिलाकर नया रूप दिया। कलर संयोजन का भी कमाल का इस्तेमाल किया।

अब्बासी ने अपना चित्र-संसार, बहुरंगी, बहुआयामी और बहुमाध्यमी से रचा। लोक देवता, लोक प्रतीक और ढाल-तलवार, त्रिसूल सूर्य, सर्प, हथेली अब्बासी के चहेते प्रतीक रहे हैं। इन चित्रों के बीज जोधपुर की महासतियों की छतरियों, देवी-देवताओं की मर्तियों तथा आदिवासी वस्त्र-विधान के चटख रंगों में है। राजस्थानी चटकीला-चमकीला लैंण्डस्केप कलाकार अब्बासी की तूलिका से धूसर और मटमैला भी बन गया। उनकी कलाकृतियों में लाल का प्रयोग धूसर पीले और काले के पार्श्व में प्रभावी लगता है। रूपायन की विविधता कलाकार की विशेषता कही जा सकती है। उनके चित्रों में अमूर्त संयोजन, रेखांकन, छापे, कोलाज, इलेक्ट्राप्लांट, वुडकैट, लीनोकट, लीथोग्राफ आदि का मिलान जुला संसार है। प्रतीकों के सहारे उन्होंने जहां शौर्य, सेक्स और गति के बिम्ब बनाए हैं, वहीं नारी के आदर्श और उत्सर्ग के प्रति भी आग्रह रहा है जो लोकरूपों के माध्यम से समकालीन संदर्भ में सृजनात्मक स्तर पर चित्रित हुए हैं। लोकरूपों को बुनते वक्त कलाकार अब्बासी की रचनादृष्टि, रचना प्रक्रिया जीवंत और संवेदनशील है। चाक्षुष नवीनता एवं अभिव्यक्ति की दृष्टि से मोटीफ्स व रंगों का प्रयोग, संयोजन व स्पेस डिजाइन का निजि तर्कशास्त्र उनकी नई कलाकृतियों में देखा जा सकता है। उनके चित्रों, में हैण्ड एण्ड स्नेक, हैण्ड एण्ड नेचर आदि में औरत और सर्प के प्रतीकों का इस्तेमाल विविध फार्म और ताजी अभिव्यक्ति के आकर्षक प्रयोग रहे हैं। कहा जा सकता है कि अब्बासी ने विषयगत दबाव से मुक्त हो कर निरपेक्ष भाव से अपने आसपास का कला संसार रचा है।

– सैयद मुनव्वर अली

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सम्पादकीय

उदासीन मतदाता, लोकतंत्र की कमजोरी का प्रतीक

लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने कई प्रयास किए लेकिन नतीजा फिर भी कोई खास नहीं मिला। राजस्थान की बारह लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ। लेकिन पोलिंग बूथों में जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के दौरान लाइनें लगी मिली थी, वह स्थिति आज लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को नहीं मिली। कई पोलिंग बूथों पर तो चुनाव कर्मचारी उंघते दिखाई दिए। राजस्थान की बारह लोकसभा सीटों के लिए शुक्रवार सुबह सात बजे से मतदान शुरू हुआ और कुछ एक स्थानों को छोड़कर शाम छह बजे तक मतदान हुआ लेकिन अधिकांश मतदान बूथों पर भीड़भाड़ देखने को नहीं मिली। इस मामले में अल्पसंख्यक इलाकों की स्थिति दूसरी थी। अल्पसंख्यक इलाकों में फिर भी मतदान बूथों पर अच्छी खासी भीड़ देखी गई। निर्वाचन आयोग ने इस बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के खूब नवाचार किए थे। जयपुर शहर (नगर निगम एरिया के) के सभी बूथों पर पहले 50 वोटर्स को इस बार निर्वाचन विभाग स्क्रेच कूपन दिए, जिसमें कोई न कोई इनाम वोटर्स को दिया गया। स्क्रेच कार्ड का इनाम जयपुर शहर के 10 इलाकों में गया। सुबह 7 से 11 बजे तक पहुंचने वाले लोगों को पार्किंग भी फ्री मिली। इस बार निर्वाचन आयोग का लक्ष्य इन लोकसभा सीटों पर 70 फीसदी से ज्यादा वोटिंग का है। जयपुर जिले की दोनों लोकसभा सीट जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण में 44 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। इनमें जयपुर शहर सीट पर कुल 22,87,350 वोटर्स हैं। वहीं, ग्रामीण सीट पर 21,84,987 वोटर्स हैं। जयपुर में सभी 2 हजार 166 बूथों पर मतदान दिवस पर पहले मतदान करने वाले 50 मतदाताओं को स्क्रेच कार्ड दिया गया। कार्ड को स्क्रेच करने पर कार्ड पर अंकित इनाम देकर मतदाताओं को सम्मानित किया गया। ये स्क्रेच कार्ड जयपुर नगर निगम शहरी सीमा के बूथों पर दिए गए। इसमें आमेर विधानसभा क्षेत्र में 34, हवामहल क्षेत्र में 240, विद्याधर नगर क्षेत्र में 326, सिविल लाइन्स क्षेत्र में 221, किशनपोल क्षेत्र में 170, आदर्श नगर क्षेत्र में 220, मालवीय नगर क्षेत्र में 187, सांगानेर क्षेत्र में 341, बगरू क्षेत्र में 201 और झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 226 मतदान केन्द्रों पर स्क्रेच कार्ड जारी किए गए। दरअसल प्रदेश की गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझूनूं, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ है। पहले चरण की इन 12 सीटों पर कुल 114 उम्मीदवार मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। बहरहाल मतदाता को खुद ही समझना होगा कि उसके लिए सरकार चुनने का मौका आता है तो वह उदासीन क्यों रहता है और इसके उसको क्या नुकसान है।

भगवान महावीर की जन्म जयन्ती पर विशेष

भगवान महावीर हैं सार्वभौम धर्म के प्रणेता

ललित गर्ग

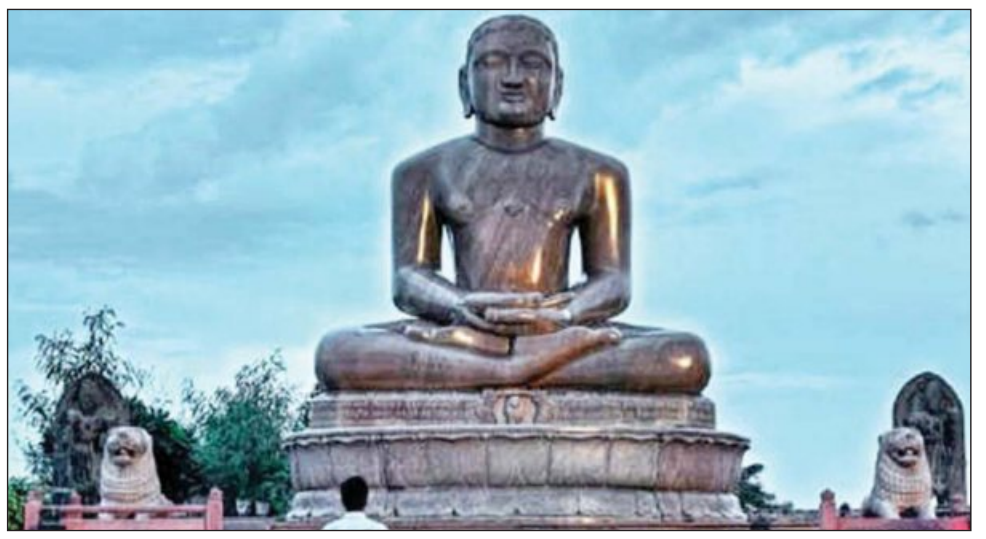

सदियों पहले महावीर जनमे। वे जन्म से महावीर नहीं थे। उन्होंने जीवन भर अनगिनत संघर्षों को झेला, कष्टों को सहा, दुख में से सुख खोजा और गहन तप एवं साधना के बल पर सत्य तक पहुंचे, इसलिये वे हमारे लिए आदर्शों की ऊंची मीनार बन गये। उन्होंने समझ दी कि महानता कभी भौतिक पदार्थों, सुख-सुविधाओं, संकीर्ण सोच एवं स्वार्थी मनोवृत्ति से नहीं प्राप्त की जा सकती उसके लिए सच्चाई को बटोरना होता है, नैतिकता के पथ पर चलना होता है और अहिंसा की जीवन शैली अपनानी होती है। महावीर का संपूर्ण जीवन स्व और पर के अभ्युदय की जीवंत प्रेरणा है। लाखों-लाखों लोगों को उन्होंने अपने आलोक से आलोकित किया है। वे सार्वभौम धर्म के प्रणेता थे, उनके मन में संपूर्ण प्राणिमात्र के प्रति सहअस्तित्व की भावना थी। इस वर्ष भगवान महावीर की 2550 वां निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है, उनकी जन्म जयन्ती एवं निर्वाण महोत्सव न केवल जैन धर्म के अनुयायियों के लिये बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिये उन्नत जीवन का आधार है, निर्वाण महोत्सव का भव्य आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम् सभागार में 21 अप्रैल, 2024 को चारों जैन सम्प्रदायों के आचार्यों, मुनिराजों एवं श्रद्धालुओं की उपस्थिति में करेंगे।

भगवान महावीर की मूल शिक्षा है- 'अहिंसा'। सबसे पहले 'अहिंसा परमो धर्मः' का प्रयोग हिन्दुओं का ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के पावन ग्रंथ 'महाभारत' के अनुशासन पर्व में किया गया था। लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलवायी भगवान महावीर ने। भगवान महावीर ने अपनी वाणी से और अपने स्वयं के जीवन से इसे वह प्रतिष्ठा दिलाई कि अहिंसा के साथ भगवान महावीर का नाम ऐसा जुड़ गया कि दोनों को अलग कर ही नहीं सकते। अहिंसा का सीधा-साधा अर्थ करें तो वह होगा कि व्यावहारिक जीवन में हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएं, किसी प्राणी को अपने स्वार्थ के लिए दुःख न दें। 'आत्मानः प्रतिकूलानि परेषाम् न समाचरेत्'' इस भावना के अनुसार दूसरे व्यक्तियों से ऐसा व्यवहार करें जैसा कि हम उनसे अपने लिए अपेक्षा करते हैं। इतना ही नहीं सभी जीव-जन्तुओं के प्रति अर्थात् पूरे प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा की भावना रखकर किसी प्राणी की अपने स्वार्थ व जीभ के स्वाद आदि के लिए हत्या न तो करें और न ही करवाएं और हत्या से उत्पन्न वस्तुओं का भी उपभोग नहीं करें। एक बार महावीर और उनका शिष्य गोशालक एक घने जंगल में विचरण कर रहे थे। जैसे ही दोनों एक पौधे के पास से गुजर रहे थे। शिष्य से दुश्मन बन चुके गोशालक ने महावीर से कहा, यह पौधा देखिए, क्या सोचते हैं आप, इसमें फूल लगेंगे या नहीं लगेंगे? महावीर आंख बंद करके उस पौधे के पास खड़े हो गए, और कुछ देर बाद आंखें खोलते हुए उन्होंने कहा, फूल लगेंगे। गोशालक ने महावीर का कहा सत्य न हो, इसलिये तत्काल पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया, और जोर-जोर से हंसने लगा। महावीर उसे देखकर मुस्कराए। सात दिन बाद दोनों उसी रास्ते से लौट रहे थे। जैसे ही दोनों उस जगह पहुंचे, जहां गोशालक ने पौधा उखाड़ा था, उन्होंने देखा कि वह पौधा खड़ा है। इस बीच तेज वर्षा हुई थी, उसकी जड़ों को वापस जमीन ने पकड़ लिया, इसलिए वह पौधा खड़ा हो गया था। महावीर फिर आंख बंद करके उसके पास खड़े हो गए। पौधे को खड़ा देखकर गोशालक बहुत परेशान हुआ। गोशालक की उस पौधे को दोबारा उखाड़ फेंकने की हिम्मत न पड़ी। महावीर हंसते हुए आगे बढ़े। गोशालक ने इस बार हंसी का कारण जानने के लिए उनसे पूछा, आपने क्या देखा कि मैं फिर उसे उखाड़ फेंकूगा या नहीं? तब महावीर ने कहा, यह सोचना व्यर्थ है। अनिवार्य यह है कि यह पौधा अभी जीना चाहता है, इसमें जीने की ऊर्जा है, और जिजीविषा है। तुम इसे दूबारा उखाड़ फेंक सकते हो या नहीं-यह तुम पर निर्भर है। लेकिन पौधा जीना चाहता है, यह महत्वपूर्ण है। तुम पौधे से कमजोर सिद्ध हुए और हार गए। और जीवन हमेशा ही जीतता है। जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए जरूरी है, आशावादी रहना।

भगवान महावीर का जन्म दिवस एक दस्तक है। उन्होंने बाहरी लड़ाई को मूल्य नहीं दिया, बल्कि स्व कर सुरक्षा में आत्म-युद्ध को जरूरी बतलाया। उन्होंने जो कहा, सत्य को उपलब्ध कर कहा। उन्होंने सबके अस्तित्व को स्वीकृति दी। 'णो हीणे णो अइरित्ते'-उनकी नजर में न कोई ऊंचा था, न कोई नीचा। उनका अहिंसक मन कभी किसी के सुख में व्यवधान नहीं बना। उन्होंने अपने होने का अहसास जगाकर अहं को खड़ा नहीं होने दिया। इसीलिये उनकी शिक्षाओं एवं उपदेशों का हमारे जीवन और विशेषकर व्यावहारिक जीवन में विशेष महत्व है। हम अपने जीवन को उनकी शिक्षाओं के अनुरूप ढाल सकें, यह अधिक आवश्यक है लेकिन इस विषय पर प्रायः सन्नाटा देखने को मिलता है। हम महावीर को केवल पूजते हैं, जीवन में धारण नहीं करते हैं। हम केवल कर्मकाण्ड और पूजा विधि में ही लगे रहते हैं। महावीर का यह संदेश जन-जन के लिये सीख बने- 'पुरुष! तू स्वयं अपना भाग्यविधाता है।' औरों के सहारे मुकाम तक पहुंच भी गए तो क्या? इस तरह की मंजिलें स्थायी नहीं होती और न इस तरह का समाधान कारगर होता है। भगवान महावीर कितना सरल किन्तु सटीक कहा हैं- सुख सबको प्रिय है, दुःख अप्रिय। सभी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। हम जैसा व्यवहार स्वयं के प्रति चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार दूसरों के प्रति भी करें। यही मानवता है और मानवता का आधार भी। मानवता बचाने में है, मारने में नहीं। किसी भी मानव, पशु-पक्षी या प्राणी को मारना, काटना या प्रताड़ित करना स्पष्टतः अमानवीय है, क्रूरतापूर्ण है। हिंसा-हत्या और खून-खच्चर का मानवीय मूल्यों से कभी कोई सरोकार नहीं हो सकता। मूल्यों का सम्बन्ध तो 'जियो और जीने दो' जैसे सरल श्रेष्ठ उद्घोष से है।

एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या सुख को स्थायी बनाया जा सकता है? क्या दुःख को समाप्त किया जा सकता है? इसका सीधा उत्तर होगा कि भौतिक जगत में ऐसा होना कभी संभव नहीं है। जब तक भौतिक जगत में जीएंगे तब तक यह स्वप्न लेना दिवास्वप्न है, कल्पना करना आकाश कुसुम जैसा है। आकाश में कभी फूल नहीं लगता। यह असंभव बात है कि इंद्रिय जगत में आदमी जीए और वह सुख या दुःख एक का ही अनुभव करे, यह द्वंद्व बराबर चलता रहेगा। तब व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि ऐसा कोई उपाय है जिससे सुख को स्थायी बनाया जा सके? इसका समाधान है स्वयं का स्वयं से साक्षात्कार। इसके लिये जरूरी है हर क्षण को जागरूकता से जीना। उसको जीने के लिये भगवान महावीर ने कहा था-'खणं जाणाहि पंडिए', जो क्षण को जानता है, वह सुख और दुःख के निमित्त को जानता है।

आज मनुष्य जिन समस्याओं से और जिन जटिल परिस्थितियों से घिरा हुआ है उन सबका समाधान महावीर के दर्शन और सिद्धांतों में समाहित है। जरूरी है कि हम महावीर ने जो उपदेश दिये उन्हें जीवन और आचरण में उतारें। हर व्यक्ति महावीर बनने की तैयारी करे, तभी समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। महावीर वही व्यक्ति बन सकता है जो लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित हो, जिसमें कष्टों को सहने की क्षमता हो। जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समता एवं संतुलन स्थापित रख सके, जो मौन की साधना और शरीर को तपाने के लिए तत्पर हो। जो पुरुषार्थ के द्वारा न केवल अपना भाग्य बदलना जानता हो, बल्कि संपूर्ण मानवता के उज्ज्वल भविष्य की मनोकामना रखता हो।

आज का इतिहास

20 अप्रैल की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- जहांदर शाह 1712 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा।
- न्यूयॉर्क ने 1777 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में नया संविधान अपनाया।
- उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 1888 में ओले गिरने से 246 लोगों की मौत।
- अलबामा और मिसीसीपी में 1920 में आये तूफान से 220 लोगों की मौत।
- जर्मनी में तानाशाह एडोल्फ हिटलर के 50वें जन्मदिन को 1939 में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया।
- सन 1940 में आरसीए द्वारा पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाया गया था।
- कोरिया और संयुक्त राष्ट्र सेना के बीच 1953 में बीमार युद्ध बंदियों का आदान प्रदान हुआ था।
- एयर इंडिया के बेड़े में 1960 में पहला जेट विमान बोइंग 707 शामिल हुआ।
- भारत ने 1971 में अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच जीता।
- अपोलो-16 अभियान 1972 में छह घंटों तक संकट से जूझने के बाद चंद्रमा पर उतर गया। जॉन यंग और चार्ल्स ड्यूक की टीम चंद्रमा पर उतरने वाली इतिहास की पांचवीं टीम बनी।
- कनाडा का एएमआईके ए-2 1973 में पहला व्यावसायिक उपग्रह बना।
- सोवियत वायुसेना ने 1978 में दक्षिण कोरियाई यात्री विमान संख्या 902 पर गोलीबारी करके उसे गिराया।
- दुनिया का सबसे बड़ा मेला 1992 में एक्सपो '92, सेविले, स्पेन में खोला गया।
- श्री इन्द्र कुमार गुजराल 1997 में भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने।
- जर्मनी के पूर्व चांसलर हेल्मुट कोल को 1999 में अमेरिकी सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम' से सम्मानित।
- 1999 में अमरीकी नगर डेनवर के कोलंबाइन स्कूल में हाई स्कूल के दो छात्रों ने अंधाधुँध गोलीबारी में 25 लोगों को मार दिया था।
- भारत ने 2006 में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा ताजिकिस्तान में स्थापित करने की घोषणा की।
- महाराष्ट्र भाजपा के नेता व राष्ट्रीय महासचिव गोपीनाथ मुण्डे ने 2008 में अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था।
- अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नौ दिन बिताने के बाद 2008 में पहले दक्षिण कोरियाई अंतरिक्ष यात्री यीसोयओन पृथ्वी पर सकुशल लौटे।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के उपग्रह प्रक्षेपण यान 'पीएसएलवी' ने 2011 में तीन उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया।
- अमेरिकी मीडिया ने 2012 में भारत के अग्नि-5 मिसाइल के सफल परीक्षण पर कहा है कि इससे भारत को उसके पड़ोसी देश चीन के बराबर में खड़ा कर दिया है।

20 अप्रैल को जन्मे व्यक्ति

- अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि जॉन इलियट का जन्म 1592 में हुआ।
- उर्दू के जनक मौलवी अब्दुल हक का 1878 में जन्म।
- जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का 1889 में जन्म हुआ।
- उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार गोपीनाथ मोहंती का जन्म 1914 में हुआ।
- प्रसिद्ध भजन गायिका जुथिका रॉय का जन्म 1920 में हुआ।

विशेष आलेख

'लाल आतंक' पर प्रहार से कांग्रेस को पीड़ा-किस बात की ?

रामस्वरूप रावतसरे

भारत दशकों से 'लाल आतंक' से त्रस्त रहा है। बिहार-झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक, नक्सलियों ने लगातार खून बहाए। बिहार में तो एक दौर ऐसा था जब लोगों को रात-रात भर जाग कर हथियारों के साथ घर-परिवार की सुरक्षा करनी शुरू कर दी थी। छत्तीसगढ़ में तो नक्सलियों ने कॉन्ग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का ही खात्मा कर दिया, नरसंहार के जरिए। अब उसी छत्तीगसढ़ में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सलियों के खिलाफ ये सबसे बड़े ऑपरेशन्स में से एक है। जानकारी के अनुसार आश्चर्य की बात है कि मृतकों में एक दर्जन से भी अधिक महिलाएँ हैं, जो खतरनाक हथियारों के साथ पुरुष नक्सलियों की सुरक्षा में आगे रहती थीं। राज्य पुलिस के 'डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (डीआरजी)' और 'बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स (बीएसएफ)' ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक तरह से देखा जाए तो ये पिछले एक दशक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है नक्सलियों के खिलाफ, क्योंकि अभी भी तलाशी अभियान जारी है। इससे पहले 2016 में 30 और 2021 में 25 नक्सली मारे गए थे। लेकिन, इस बार खास बात ये है कि सुरक्षा बलों की तरफ से कोई क्षति नहीं हुई है। ये ऑपरेशन काँकेड़ जिले के छोटेबेठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चलाया गया। एके-47 से लेकर राइफल और गोला-बारूद के अलावा कई हथियार बरामद किए गए। बस्तर के आईजी सुंदर राज पी ने स्पष्ट कर दिया है कि कुल 30 हथियार बरामद हुए हैं, नक्सलियों के साहित्य भी बड़ी मात्रा में मिले हैं। जो 2 बड़े नक्सली मारे गए हैं, वो हैं शंकर राव और ललिता। बस्तर में इस साल 79 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है।

पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि मारे गए लोगों में सभी नक्सली हैं, किसी के ग्रामीण होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वालों का काम ही यही है। उन्होंने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है, नक्सलियों का सफाया जारी रहेगा और आगे भी सुरक्षा बल बढ़त बनाए रहेंगे। पुलिस का मानना है कि वो सही दिशा में जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे बड़ी सफलता करार देते हुए कहा है कि जबसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से नक्सलवाद-आतंकवाद में कमी आई है और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद नक्सल विरोधी अभियान में गति आई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 3 महीने में ही 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं और 150 से अधिक ने आत्म-समर्पण किया है। उन्होंने नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने का प्रण भी दोहराया। जहाँ एक तरफ भाजपा नक्सलवाद पर प्रहार की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग्रेस पार्टी ये साबित करने में लगी है कि ये एक फर्जी मुठभेड़ था। वैसे ये कॉन्ग्रेस की पुरानी फितरत है। जब वो पाकिस्तान में भारत की सर्जिकल या एयर स्ट्राइक पर देश की सेना के खिलाफ जाकर बयान दे सकते हैं तो फिर नक्सलियों का समर्थन कौन सी बड़ी बात है उनके लिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्हें हाल के चुनाव में करारी हार मिली है, उन्होंने काँकेड़ मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भाजपा के शासनकाल में फर्जी एनकाउंटर होते हैं। उन्होंने अपनी सरकार में नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक कदम उठाए जाने का दावा करते हुए भाजपा सरकार पर जनजातीय समाज के लोगों की फर्जी गिरफ़्तारी का आरोप भी मढ़ दिया। उन्होंने दावा किया कि कवर्धा में ही लोगों को धमकाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने पूर्ववर्ती के आरोपों का कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा सलाह दी कि हर चीज पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ये घटना किसी भी तरह से फर्जी है तो भूपेश बघेल ये प्रमाणित करें। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने चुनौती दी कि भूपेश बघेल इस मुठभेड़ को फर्जी साबित करें, या फिर जवानों से माफ़ी माँगें। असल में भूपेश बघेल एक तो कॉन्ग्रेस नेता हैं उपर से हाल ही में उनकी हार हुई है, शायद इसी कारण वो उलूल-जलूल बयान दे रहे हैं। सुरक्षा बलों ने अभी 17 नक्सली कमांडरों की सूची बनाई है जिनके खिलाफ तलाशी अभियान तेज़ की जाएगी। पिछले 15 दिनों में ही छत्तीसगढ़ में 42 नक्सली मारे जा चुके हैं। अब सामने आ रहा है कि 'ऑपरेशन प्रहार' चलाया जाएगा, जिसके जरिए उन नक्सलियों को निशाना बनाया जाएगा जो युवकों का ब्रेनवॉश कर उन्हें हथियार उठाने के लिए उकसाते हैं। मांडवी हिड़मा इस 17 सदस्यीय सूची में सबसे ऊपर है, जिसके सुकमा के जंगलों में छिपे होने की आशंका है। इसी तरह मुपल्ला लक्ष्मणा राव माड़ के घने जंगलों में छिपा हुआ है। 51 वर्षीय हिड़मा एके-47 चलाने में दक्ष बताया जा रहा है। नक्सलियों की धर-पकड़ और उन्हें ढेर करने के लिए हमारे जवान अब आधुनिक तकनीक का भी सहारा ले रहे हैं। उन्हें जंगलों में ख़ाक छाननी होती है, अपनी जान खतरे में डालनी होती है, परिवार से दूर रहना पड़ता है तब जाकर नक्सल वारदातें कम होती हैं और आम लोग चैन से सोते हैं। लेकिन, भूपेश बघेल जैसे नेता सुरक्षा बलों पर ही सवाल उठाते हैं।

मेनका गांधी की माने तो आमूल दूध नहीं पीना चाहिए?

रामस्वरूप रावतसरे

भाजपा सांसद मेनका गाँधी ने आमूल पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने नकार दिया है। सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में एक इंटरव्यू के दौरान वो इससे सहमति नहीं जताती हुई दिख रही हैं कि आमूल किसानों की मदद करता है, उनका कहना है कि वो सिर्फ गायों को बड़ा करने और उन्हें बेचने व उनकी हत्या में किसानों की मदद करता है। साथ ही उन्होंने आमूल पर कई गायों की हत्या का आरोप मढ़ते हुए कहा कि जैन समुदाय की सबसे अधिक जनसंख्या गुजरात में है, अमूल भी गुजरात में स्थित है और सबसे ज्यादा गोहत्या भी गुजरात में ही होती है। लोकसभा चुनाव 2024 में सुल्तानपुर से भाजपा प्रत्याशी मेनका गाँधी कहती हैं, प्रतिदिन कई ट्रकों में भर कर गायों को महाराष्ट्र के अलाना (बीफ कंपनी) में ले जाया जाता है। इन सभी को मार डाला जाता है। ये गाये डेयरी से ले जाई जाती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भारत में पहला बूचड़खाना आमूल ने ही स्थापित किया था। उन्होंने गोवा में ऐसा किया, क्योंकि वो गुजरात में ये नहीं कर सके। डेयरी वाले जानते हैं कि वो मीट इंडस्ट्री के लिए एक बिचौलिए हैं। मेनका गाँधी ने ये भी कहा कि अगर आप दूध पीते हैं तो आप गोहत्या में हिस्सा ले रहे हैं, आप समझिए कि मीट खा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर मेनका गाँधी के इस वीडियो में आमूल के टैगलाइन से छेड़छाड़ करते हुए 'अमूल खून पीता है इंडिया' लिख कर शेयर किया गया। हालाँकि, आमूल ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए सच्चाई बताई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कहा है कि गोवा में उसके द्वारा बूचड़खाना स्थापित किए जाने की फर्जी खबर सोशल मीडिया व व्हाट्सएप्प में फ़ैल रही है। आमूल ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि ये एक फर्जी खबर है, इस वीडियो में कई अन्य आधारहीन दावे किए गए हैं जो गलत हैं, फर्जी हैं। आमूल ने कहा कि ऐसा कर के वो लोग उन लाखों महिला किसानों के योगदान का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने पिछले 77 वर्षों में कई पीढ़ियों को पोषण दिया है, भारत में फ़ूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की है। भारत के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादन होने का जिक्र करते हुए आमूल ने कहा कि डेयरी इंडस्ट्री में हमारा देश आत्मनिर्भर है। आमूल ने कहा, डेयरी इंडस्ट्री ने हमारी महिला किसानों को सम्मान दिया है, रोजगार दिया है और उनके लिए नियमित आय की व्यवस्था की है। गुजरात के 36 लाख किसान जिनके पास आमूल का स्वामित्व है, हम आश्वासन देते हैं कि ये लोग पशुओं का अपने परिवार के सदस्यों की तरह ख्याल रखते हैं। उन्हें प्यार मिलता है, उनका ध्यान रखा जाता है और हर उम्र में उनके लिए अच्छे इलाज की व्यवस्था की जाती है। इस वीडियो का इस्तेमाल भ्रामक सूचनाएँ फैलाने व ग्राहकों में गैर-ज़रूरी डर और चिंता बिठाने के लिए किया जा रहा है। आमूल ने अंत में अपने बयान में निवेदन किया है कि उसके इस सन्देश को रिश्तेदारों-दोस्तों तक फैलाएँ और उन्हें आश्वस्त करें कि आमूल एक जिम्मेदार ब्रांड है और इसके 36 लाख किसान अपने पशुओं से प्यार करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। 'गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन' की स्थापना गुजरात के आणंद में दिसंबर 1946 में हुई थी।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, अपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारम्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताप और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष

स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोपहर के बाद पारिवारिक जीवन में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा। आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। पिता से आपको लाभ होगा। ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बनी रहेगी।

वृष

आज के दिन बौद्धिक काम, नए सृजन और साहित्यिक गतिविधि में आप उलझे रहेंगे। किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है। आज आपको कार्यालय और व्यापार में थोड़ा संभलकर चलना होगा। आज कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले पाएंगे।

मिथुन

व्यापार में किसी तरह का लाभ होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पूंजी निवेश में सावधानी बरतें। धार्मिक काम के पीछे धन खर्च हो सकता है। कोर्ट-कचहरी के विषय में संभलकर चलें।

कर्क

मित्रों का सहयोग भी आप को प्राप्त होगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए निरर्थक वाद-विवाद न करें। आप की रचनात्मकता में सकारात्मक वृद्धि होगी। मित्रों और प्रियपात्र के साथ मुलाकात सुखद होगी।

सिंह

आज का आपका दिन लाभकारी है। पारिवारिक और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर-परिवार में आनंद का वातावरण आप को खुश रखेगा। बहुत दिनों से अटके सरकारी कामों में सफलता मिलेगी।

कन्या

आज वाणी पर संयम रखें. स्नेहीजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा। किसी उलझन में दिन गुजरेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। आप नए काम का आरंभ कर सकेंगे। धन और प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है।

तुला

दोस्तों के साथ मुलाकात होगी। किसी तरह का आर्थिक लाभ भी हो सकता है। हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर उतार-चढ़ाव बना रहेगा। संतान सम्बंधी शुभ समाचार आप को मिलेंगे। पुराने और बचपन के दोस्तों से मुलाकात हो सकती है।

वृश्चिक

मानसिक रूप से आप में भावुकता की मात्रा अधिक रहेगी। किसी बात को लेकर ज्यादा विचलित ना हों। अपनी कल्पनाशक्ति से साहित्य-सृजन में आप नवीनता ला पाएंगे। सुख-शांति बनी रहेगी। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी।

धनु

अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखना आपके ही हित में रहेगा। आज आपकी नौकरी और व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा। संतान की चिंता आपको हो सकती है।

मकर

सुबह का समय दोस्तों के साथ घूमने-फिरने, खान-पान एवं मनोरंजन में बीत सकता है। पार्टनरशिप काम में ध्यान रखें। व्यापार में ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं है। दोपहर के बाद आप को प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है।

कुंभ

स्वभाव में उग्रता हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। दोपहर के बाद आप आप मनोरंजन की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। मित्रों और स्नेहीजनों के साथ प्रवास या पर्यटन का योग है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रह पाएंगे।

मीन

दवाई खरीदने या अस्पताल की फीस पर आकस्मिक खर्च हो सकता है। आज दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ हर काम को आसानी से बना पाएंगे। गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। स्नेहीजनों के साथ घनिष्ठता बढ़ेगी।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

रावण ने किया कौशल्या हरण, पश्चात दशरथ कौसल्या विवाह

– आत्माराम यादव

अमरता का वरदान पाकर अतुल्य बलशाली राक्षसराज रावण दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के पश्चात अहंकार से चूर धरती पर ही नहीं अपितु देवलोक के देवताओं पर हमला कर अपनी जीत की पताका फहराता रहा ओर सृष्टि की संपूर्ण व्यवस्थाओं पर अपना अधिकार मानता रहा। एक समय देवर्षि नारद रावण से मिले ओर मधुर स्वर में बोले, ᳐राक्षसराज! आप जैसा परम तपस्वी, तेजस्वी और पराक्रमी राक्षस संसार में दूसरा नहीं है। आपकी शक्ति के समक्ष देवगण भी भयभीत हैं। निसंदेह आपके बाद राक्षस- कुल में कोई दूसरा पराक्रमी नहीं होगा।᳐ हालांकि आप वह्माजी के प्रपौत्र हैं, लेकिन उन्होंने आप से छल किया है। याद कीजिए राजन उन्होंने वर दिया था कि आपकी मृत्यु मनुष्य के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा नहीं होगी। फिर यह सृष्टि का नियम भी है कि जो जनमा है, एक-न-एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य होगी। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो ब्रह्माजी से पूछ लें।

रावण ने ब्रह्मासे पूछा - हे ब्रह्मन् ! मेरा किसके हाथों मरण होगा ? यह आप स्पष्ट कहिये, ब्रह्मा जी ने कहा कि अयोध्या के राजा दसरथ की पत्नी कौसल्या से साक्षात जनार्दन भगवान राम आदि चार पुत्रों के रूप में उत्पन्न होंगे। उनमें से राम तुम को मारेंगे । राजा दशरथ के लग्न का आज से पाँचवाँ दिन निश्चित किया है। ब्रह्माका यह वचन सुना तो रावण बहुत से राक्षसों को साथ लेकर शीघ्र अयोध्या नगरी को चल पड़ा। वहाँ जा और घोर युद्ध करके उसने नौका पर बैठे राजा दशरथको पराजित किया और पाद प्रहार से नाव को तोड़कर सरयू के जल में डुबो दिया! आनंद रामायण के सारकाण्ड प्रथम सर्ग में इसका यूं उल्लेख मिलता है कि - इक्ष्वाकुवंशप्रवरः क्षत्रियो लोकविश्रुतः । बलवान् सरयुतोरेऽग्योध्यायां पार्थित्रोत्तमः ॥३०॥ नाम्ना दश्शरथः श्रीमान् जम्बूद्वीपपतिर्महान । शशास राज्यं धर्मेण सैन्येन महताऽऽश्रुतः ॥३१॥ अयोध्यायास्तु सान्निध्ये देशे श्रीकोसलाह्वये । कोसलायां महापुण्यः कोसलाख्यो नृपो महान् ॥३२॥ तस्यासीदुहिता रम्या कौसन्या पतिकामुका । तस्या दशरथेनैव विवाहो निश्चितो सुदा ॥३३॥ लग्नार्थं तं समानेतुं दूता दशरथं नृपम् । ययुत्रिनिश्चयं कृत्वा विवाहदिवसस्य च ॥३४॥ तदा दशरथश्चापि साकेते सरयूजले । नौकास्थो जलजा क्रीडां चक्रे वे मंत्रिबंधुभिः ॥३५॥

आनंद रामायण के प्रसंग के अनुसार अयोग्या की सीमाओ के पास ही कोसलदेश था जहा कोसल नाम का एक बड़ा पुण्यात्मा राजा राज्य करता था ॥३२॥ उसकी विवाहके योग्य एक सुन्दरी कौसल्या नाम की पुत्री थी। उसका उसके पिता कोसल ने अयोध्या के राजकुमार दशरथके साथ विवाह निश्चित किया। अति प्रसन्नता एवं आनंद से अतिरेक राजा कौसल ने विवाह के दिन का निश्चय करके उन्होंने लग्न के निमित्त राजा दशरथ को आमंत्रिक करने दूत को भेजा तब उस समय राजा दशरथ सरयू नदी के बीच नौका पर बैठकर इष्टमित्रों तथा मन्त्रियोंके साथ जलक्रीड़ा कर रहे थे। रात्रि का समय था, चारों ओर सैनिक खड़े थे, चारणगण स्तुति कर रहे थे और रत्नों के दीप के प्रकाश से समस्त नाव जगमगा रही थी। वाराङ्गनायें नानाप्रकारके नृत्य-गान कर रही थीं ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

रावण ने इस किसी भी प्रकार राजा दशरथ ओर कौशल्या के विवाह को रोककर विधि का विधान बदलने का निश्चय कर यह आक्रमण किया था। इधर अयोध्या में राजा दशरथ पर आक्रमण के बाद वह सीधा कौशल देश जा पहुंचा। उस समय आधी रात थी। सभी सैनिक निद्रावस्था में थे। उपयुक्त अवसर पाकर रावण ने सोती हुई कौशल्या को उसके महल से सोते हुये ही अपहरण कर एक संदूक में बंद किया और उन्हें ले जाकर तिमिंगल नामक देत्य जो रावण का परम मित्र था को सौंप कहा की इस सन्दुक को किसी समुद्री टापू पर छोड़ आए देखते ताकि कौशल्या भूख प्यास से मर जाये । तिमिंगल ने उस संदूक को गंगा सागर के द्वीप पर जहा कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था वह छोड़ आए। इस प्रसंग के अनुसार राजा दशरथ की नौका पर रावण के द्वारा प्रहार करने पर उनकी नौका सीधे गंगा सागर के उस टापू पर पहुँच गई जहा राजकुमारी कौसल्या को रावण का मित्र दैत्य भूखा मरने की नियत से छोड़ गया था, जहा दशरथ जी ओर कौशल्या का मिलन हुआ।

एक अन्य प्रसंग के अनुसार राजा दसरथ रावण से युद्ध से बचने के बाद अपनी बारात को जल-मार्ग से कौशल देश की और जा रहे थे। उस समय दैवयोग से भारी वर्षा होते लगी। जल की लहरें आकाश को चूमने लगीं। चारों और भयंकर चक्रवात उत्पन्न हो गया। इस तूफान में सभी नावे डूब गई। राजा दशरथ और उनका मंत्री सुमंत किसी तरह एक टूटी हुई नाव को पकड़कर गंगासागर जा पहुँचे, जहाँ तिमिंगल ने संदूक छिपाया था। द्वीप पर एक विशाल संदूक देखकर राजा दशरथ विस्मित रह गए। उत्सुकतावश जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें से कौशल्या बाहर निकल आई। दोनों में परिचय का आदान-प्रदान हुआ। भावी पति को अपने समक्ष देखकर कौशल्या लज्जा और संकोच से भर उठीं। दशरथ भी एकटक उन्हें देखते रह गए। तदन्तर सुमंत्र के परामर्श से राजा दशरथ राजकुमारी कौशल्या ने विवाह के मुहूर्त में गंधर्व विवाह कर कौशल्या को अयोध्या ले आए और उनसे विधिवत विवाह कर लिया। इस प्रकार रावण के अनेक रुकावट करने पर भी राजा दशरथ और कौशल्या का विवाह संपन्न हो गया।

आखिर यूपी में क्या सियासी गुल खिलाएगी राहुल-अखिलेश की जोड़ी,इसे ऐसे समझिए

राहुल गांधी से पहले संवाददाता सम्मेलन की शुरूआत करते हुए अखिलेश यादव का यह कहना कि ᳐मुझे खुशी है आज हम मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बेहद अहम है।᳐ उन्होंने तो साफ कहा कि यूपी में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक भाजपा का सफाया होने जा रहा है।

उत्तरप्रदेश में पहले चरण के मतदान से दो दिन पहले यानी गत बुद्धवार को दिल्ली से सटे गाजियाबाद महानगर के कौशांबी स्थित फाइव स्टार होटल रेडिसन ब्लू सभागार में, गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र की इंडिया गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया, उसके सियासी मायने स्पष्ट हैं। यहां के शानदार मंच से दोनों नेताओं ने भाजपा की मोदी सरकार के प्रति जो तल्खी दिखाई, उससे यह सवाल उभरकर सामने आया कि आखिर यूपी में क्या सियासी गुल खिलाएगी राहुल-अखिलेश की जोड़ी,

आपको पता होना चाहिए कि यूपी में कांग्रेस-सपा गठबंधन होने के बाद पहली बार दोनों नेता एक साथ, एक मंच पर दिखाई दिए और पत्रकारों के लाख कुरेदने के बावजूद भी संतुलित और सधे हुए अंदाज में जो बातें कहीं, उसके राजनीतिक मायने स्पष्ट हैं।

पहला यही कि कांग्रेस-सपा की यह युगलबंदी लंबी चलेगी। क्योंकि पीएम पैदा करने वाले इस प्रदेश से यदि भाजपा और एनडीए गठबंधन को खदेड़ना है, तो पीएम के हवा-हवाई मुद्दों की बजाए राहुल गांधी-अखिलेश यादव के जमीनी मुद्दों यानी कांग्रेस की गारंटी (जिसमें इंडिया गठबंधन के मुद्दों को समाविष्ट किया गया है) की बात पर जोर देना होगा। कांग्रेस की गारंटी का मतलब समाज के समस्त दबे-कुचले लोगों के परवरिश और उत्थान की बात, जैसा कि उसमें समाविष्ट किया हुआ है। साफ शब्दों में कहें तो किसान-मजदूर-कारीगर, युवा, महिलाएं, कुटीर-लघु कारोबारी आदि के हित।

दूसरा, रामनवमी के दिन ही इंडिया गठबंधन के पहले संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन होने और इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा नेता अखिलेश यादव द्वारा देशवासियों और पत्रकारों को रामनवमी की बधाई देने का स्पष्ट मकसद है कि इंडिया गठबंधन सनातन मयार्दाओं की उपेक्षा अब नहीं करेगा। क्योंकि 2014 और 2019 का नजीर उसके सामने है। लिहाजा, 2024 में पुरानी गलतियों से सबक लेने की कोशिश की गई है। शुरूआत भी अच्छी है।

तीसरा, इस प्रेस वार्ता में राहुल गांधी का यह कहना कि ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है, काफी अहम है। उनके शब्दों में, 'एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस नीत इंडिया गठबंधन देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है।᳐ इससे साफ है कि कांग्रेस अपने पुराने मुद्दे पर अडिग है और सावधानी पूर्वक नए मुद्दों से खुद को जोड़ रही है, जो अच्छी बात है।

– कमलेश पांडे

दूसरे चरण की आठ सीटों के लिये फिर सज गई है बिसात, हेमामालिनी और अरूण गोविल सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव

– अजय कुमार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का मतदान होने के बाद ही तमाम दलों के नेताओं ने दूसरे चरण के लिये अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रथम चरण के मतदान को सभी दल अपने-अपने पक्ष में बात रहे हैं,लेकिन हकीकत 04 जून को ही सामने आयेगी। आज अमरोहा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बड़ी रैली की। अपने आप को अमरोहा से कनेक्ट करने के लिये वह तेज गेंजबाज शमी की तरीफ करने से भी नहीं चूकें। शमी अमरोहा के ही रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गााजियाबााद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ व मथुरा आठ सीटों पर चुनाव होंगे।दूसरे चरण में फिल्म अभिनेत्री और सांसद हेमामालिनी,रामायण सीरियल में प्रभु श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरूण गोविल,दानिश अली इन सीटों पर 91 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। सभी सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है, क्योंकि बसपा ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का एलान चुनाव में रोमांच ला दिया है। वहीं जानकारों की माने तो वोटों का बंटवारा होने से बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। इन सीटों पर 91 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। इनमें से 42 यानी 46 प्रतिशत प्रत्याशी करोड़ पति है। वहीं 18 प्रत्याशियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

इस चरण में मेरठ सीट सबसे हॉट सीट बन चुकी है। मेरठ में बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद राजेन्द्र अग्रवाल का टिकट काट कर धारावाहिक रामायण में प्रभु श्री राम का रोल करने वाले अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है। उधर, समाजवादी पार्टी ने मेरठ सीट पर दो बार अपना प्रत्याशी बदला है। पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया। बाद में भानु का टिकट काट कर सपा विधायक अतुल प्रधान को टिकट थमा दिया था, लेकिन अतुल के नामांकन करने के बाद ही उनका टिकट काटकर पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को उम्मीदवार घोषित कर दिया। बसपा ने देववृत त्यागी को कैंडिडेट बनाया है। सपा को इस सीट पर अंदरूनी कलह भारी पड़ सकती है। मुकाबला कांटे का होने की संभावना है।

मथुरा सीट पर बीजेपी ने फिर से हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है। हेमा मालिनी मुकाबला कांग्रेस के मुकेश धनगर और बसपा के सुरेश सिंह से होने जा रहा है। सपा के साथ आने से कांग्रेस इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दे सकती है। हालांकि एकला चलो की राह पर चली बसपा को किसी भी सीट पर हल्के में लेने वाला नहीं है। बसपा अपने चुनावी नतीजों से सबको आश्चर्यचकित कर सकती है।

वहीं अलीगढ़ सीट पर बीजेपी ने दोबारा सतीश कुमार गौतम को उम्मीदवार बनाया दिया है। सपा ने चौधरी बिजेंद्र सिंह और बसपा ने हितेंद्र कुमार बंटी को प्रत्याशी घोषित किया है। इसके अलावा बुलंदशहर सीट पर बीजेपी के डॉ. भोला सिंह का मुकाबला कांग्रेस के शिवराम वाल्मीकि और बसपा के गिरीश चंद से होने की उम्मीद है। इन दोनों ही सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है।

गौतमबुद्धनगर सीट पर भी सपा के टिकट बदलने से ये सीट हॉट सीट बन चुकी है। सपा ने इस सीट डॉ. महेंद्र सिंह नागर को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन डॉ. महेंद्र का सपा ने टिकट काटकर राहुल अवाना को टिकट थमा दिया था। बाद में फिर डॉ. महेंद्र सिंह नागर पर भरोसा जताया है।

उधर बीजेपी ने डॉ. महेश शर्मा को फिर से प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि बसपा ने राजेंद्र सिंह सोलंकी को मैदान में उतारा है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। 2019 में इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अन्य दलों की तुलना में बीजेपी का पलड़ा भारी है।

गठबंधन होने से कांटे की टक्कर मिल सकती है।

ऐसे ही अमरोहा सीट पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने मौजूदा सांसद कुंवर दानिश अली को उम्मीदवार बनाया है। दानिश 2019 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। हाल ही में कुंवर दानिश कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इस सीट पर बीजेपी कंवर सिंह तंवर को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बसपा ने एक बार फिर अमरोहा सीट पर मुस्लिम कार्ड खेला है। बसपा ने मजाहिद हुसैन को कैंडिडेट घोषित किया है। बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है जबकि बीजेपी को इससे फायदा होने के आसार है। बीजेपी 2019 में अमरोहा सीट पर चुनाव हार गई थी इसलिए बीजेपी के लिए इस सीट से चुनाव जीतना चुनौती भरा होने वाला है। दूसरे चरण के चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस के चार में से तीन प्रत्याशियों के अलावा बसपा, भाजपा, सपा, जय हिन्द नेशनल पार्टी और समाज विकास क्रांति पार्टी के सभी प्रत्याशी करोड़पति हैं। उप्र इलेक्शन वॉच के अनुसार मथुरा से भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी हैं सबसे अमीर प्रत्याशी हैं।

इनकी संपत्ति लगभग 278 करोड़ है। वहीं दूसरे नंबर पर अलीगढ़ से भाजपा प्रत्याशी सतीश कुमार गौतम की संपत्ति 16 करोड़ और तीसरे नंबर पर मेरठ से बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी की संपत्ति पांच करोड़ के आसपास हैं। नौ महिला प्रत्याशी भी दूसरे चरण के चुनावी मैदान में उतरी हैं। प्रत्साशियों की शिक्षा की बात की जाये तो 91 प्रत्याशियों में से 33 प्रत्याशी 12 वीं पास भी नहीं हैं। यानी 36 प्रतिशत प्रत्याशी बारहवीं पास भी नहीं है। इन्होंने अपनी शैक्षिक योग्यता पांचवीं से 12 वीं के बीच घोषित की है। वहीं 52 प्रत्याशी स्नातक और इससे ज्यादा पढे हैं। जबकि दो डिप्लोमा, दो साक्षर और दो अनपढ़ हैं।

– अजय कुमार

उन्नत जीवन का आधार है हनुमान भक्ति

– ललित गर्ग

भगवान हनुमानजी को हिन्दू देवताओं में सबसे शक्तिशाली माना गया है, वे रामायण जैसे महाग्रंथ के सह पात्र थे। वे भगवान शिव के ग्यारवें रूद्र अवतार थे जो श्रीराम की सेवा करने और उनका साथ देने त्रेता युग में अवतरित हुए थे। उनको बजरंग बलि, मारुतिनंदन, पवनपुत्र, केशरीनंदन आदि अनेकों नामों से पुकारा जाता है। उनका एक नाम वायुपुत्र भी है, उन्हें वातात्मज भी कहा गया है अर्थात वायु से उत्पन्न होने वाला। इन्हें सात चिरंजीवियो में से एक माना जाता है। वे सभी कलाओं में सिद्धहस्त एवं माहिर थे। वीरो में वीर, बुद्धिजीवियों में सबसे विद्वान। इन्होंने अपने पराक्रम और विद्या से अनेकों कार्य चुटकीभर समय में पूर्ण कर दिए है। वे शौर्य, साहस और नेतृत्व के भी प्रतीक हैं। समर्पण एवं भक्ति उनका सर्वाधिक लोकप्रिय गुण है। रामभक्त हनुमान बल, बुद्धि और विद्या के सागर तो थे ही, अष्ट सिद्धि और नौ निधियों के दाता और ज्योतिष के भी प्रकांड विद्वान थे। वे उन्नत जीवन के आधार है। उनसे सफल एवं सार्थक जीवन के प्रबंधन की शिक्षा मिलती है। वे हर युग में अपने भक्तों को अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं और उनके दुःखों को हरते हैं। वे मंगलकर्त्ता एवं विघ्नहर्त्ता हैं।

मंगलवार को हनुमानजी का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। भिन्न-भिन्न लोगों ने इस महान् आत्मा का मूल्यांकन भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से किया है। हनुमान का चरित्र एक लोकनायक का चरित्र है और उनके इसी चरित्र ने उन्हें सार्वभौमिक लोकप्रियता प्रदान की है। तैंतीस करोड़ देवी-देवताओं में मात्र हनुमान ही ऐसे हैं जिनकी आधुनिक युग में सर्वाधिक पूजा की जाती है और जन-जन के वे आस्था के केन्द्र हैं। उनके चरित्र ने जाति, धर्म और सम्प्रदाय की संकीर्ण सीमाओं को लांघ कर जन-जन को अनुप्राणित किया है। हनुमान का चरित्र बहुआयामी हैं क्योंकि उन्होंने संसार और संन्यास दोनों को जीया। वे एक महान् योगी एवं तपस्वी हैं और इससे भी आगे वे रामभक्त हैं। हनुमान-भक्ति भोगवादी मनोवृत्ति के विरुद्ध एक प्रेरणा है संयम की, पवित्रता की। यह भक्ति एक बदलाव की प्रक्रिया है। यह भक्ति प्रदर्शन नहीं, आत्मा के अभ्युदय का उपक्रम है। इससे अहं नहीं, निर्दोष शिशुभाव जागता है। क्रोध नहीं, क्षमा शोभती है। कष्टों में मन का विचलन नहीं, सहने का धैर्य रहता है।

उत्कृष्ट विलक्षणताओं के प्रतीक हनुमान पूर्ण मानव थे। कहते हैं कि ब्रह्मा ने जब मनुष्य का निर्माण किया तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि उन्हें यह अनुभूत हुआ कि उनके द्वारा सृष्ट मानव ईश्वर का साक्षात्कार करने में समर्थ है। मानव न केवल संपूर्ण प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, प्रत्युत वह अपनी साधना के द्वारा ब्रह्मपद को भी प्राप्त कर सकता है। त्रेतायुग के सर्वाधिक शक्तिशाली मानव हनुमान जिन्हें भ्रमवश अनेक देशी-विदेशी विद्वान पेड़ों पर उछल-कूद करनेवाला साधारण वानर मानते रहे हैं, अपने अलौकिक गुणों और आश्चर्यजनक कार्यों के बल पर कोटि-कोटि लोगों के आराध्य बन गये।

भारत ही नहीं, विश्व के इतिहास में किसी ऐसे मानव का उल्लेख नहीं मिलता, जिसमें शारीरिक बल और मानसिक शक्ति का एक साथ इतना अधिक विकास हुआ हो जितना हनुमान में हुआ था। प्राचीन भारत में ब्रह्मतेज से युक्त अनेक महामानव हुए। इसी प्रकार इस पावनभूमि में ऐसे विशिष्ट व्यक्ति भी हुए जो शारीरिक बल में बहुत बलशाली थे, परन्तु ब्रह्मतेज के साथ-साथ शास्त्र-बल का जो आश्चर्यजनक योग हनुमान में प्रकट हुआ, वह अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ता। शुद्ध आचार, विचार और व्यवहार से जुड़ी हनुमान की ऐसी अनेक चारित्रिक व्याख्याएं हैं जिनमें जीवन और दर्शन का सही दृष्टिकोण सिमटा हुआ है।

हनुमान को बुद्धिमानों में अग्रगण्य माना जाता है। ऋग्वेद में उनके लिए ह्यविश्ववेदसम्ह्ल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अभिप्रेत अर्थ है- विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ। हनुमान अपने युग के विद्वानों में अग्रगण्य थे। उनकी गणना सामान्य विद्वानों में नहीं, बल्कि विशिष्ट विद्वानों में की जाती थी। वाल्मीकि रामायण में हनुमान को महाबलशाली घोषित करते हुए ह्यबुद्धिमतां वरिष्ठह्ल कहना पूर्ण युक्ति संगत है। ह्यरामचरितमानसह्ल में भी उनके लिए ह्यअतुलित बलधामह्ल तथा ह्यज्ञानिनामग्रगण्यमह्ल इन दोनों विशेषणों का प्रयोग द्रष्टव्य है। ब्रह्मचारी हनुमानजी महान् संगीतज्ञ और गायक भी थे। इनके मधुर गायन को सुनकर पशु-पक्षी एवं सृष्टि का कण-कण मुग्ध हो जाता था।

हनुमान की विद्वता के साथ-साथ तर्क-शक्ति अत्यंत उच्च कोटि की थी। ऐसे अनेक प्रसंग है जब हनुमान ने अपनी तर्क-शक्ति से अनेक जटिल स्थितियों को सहज बना दिया। उनकी अलौकिक साधना एवं नैसर्गिक दिव्यता का ही परिणाम था कि वे भय और आशंका से भरे वातावरण में भी निःशंक और निर्भीक बने रहते थे। संकट की घड़ी में भी शांतचित्त होकर अपने आसन्न कर्तव्य का निश्चय करना उत्तम प्रज्ञा का प्रमाण है। हनुमान इस सर्वोत्कृष्ट प्रज्ञा से युक्त थे।

प्राचीन भारत की सर्वश्रेष्ठ भाषा संस्कृत और व्याकरण पर हनुमान का असाधारण अधिकार था। हनुमान ने सूत्र, वृत्ति, वार्तिक, महाभाष्य तथा संग्रह का भली-भांति अध्ययन किया था। अन्यान्य ग्रंथों तथा छंद-शास्त्र के ज्ञान में भी उनकी समानता करनेवाला कोई नहीं था। संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान में उनकी तुलना देवताओं के गुरु बृहस्पति से की गयी है। महर्षि अगस्त्य के अनुसार हनुमान नवों व्याकरणों के अधिकारी विद्वान थे। नोबेल पुरस्कार विजेता आक्टाभियो पाज का भी यह सुनिश्चित मत है कि हनुमान ने व्याकरण शास्त्र की रचना की थी।

मारुति नंदन, परमवीर, श्रीराम भक्त हनुमानजी की पवित्र मन से की गयी साधना और भक्ति चमत्कारपूर्ण परिणाम देने वाली है। हनुमानजी शिव के अवतार माने जाते हैं और ग्यारहवें रुद्र के रूप में इनकी मान्यता है। कहते है-मयार्दा पुरुषोत्तम राम की सार्वकालिक सेवा करने एवं रावण-वध में उनका सहयोग करने के लिए भगवान राम का अवतार लेने से पूर्व ही त्रेतायुग में शिवजी ने अपने ग्यारहवें रुद्र के रूप में अवतार लिया था। वह ह्यहनुमानजीह्ल के पवित्र लोकोपकारी नाम से विख्यात हुए। महादेव का हनुमान के रूप में अवतरण लेने के सन्दर्भ में कहा जाता है कि भगवान विष्णु महादेव के इष्ट देव हैं। वे उनके श्रीचरणों के शाश्वत पुजारी हैं। त्रेतायुग में रावणादि राक्षसों का सकुल संहार करके उनका उद्धार करने के लिए ही भगवान विष्णु अयोध्या के महाराज दशरथ के यहां अपनी सोलह कलाओं सहित पुत्र रूप में अवतरित हुए। अतः उनकी सेवा करने के लिए महादेव ने हनुमान के रूप में अवतार लिया।तंत्र शास्त्र के आदि देवता और प्रवर्तक भगवान शिव हैं। इस प्रकार से हनुमानजी स्वयं भी तंत्र शास्त्र के महान पंडित हैं। समस्त देवताओं में वे शाश्वत देव हैं। परम विद्वान एवं अजर-अमर देवता हैं। वे अपने भक्तों का सदैव ध्यान रखते हैं। उनकी तंत्र-साधना, वीर-साधना है। वे रुद्रावतार और बल-वीरता एवं अखंड ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। अतः उनकी उपासना के लिए साधक को सदाचारी होना अनिवार्य है। उसे मिताहारी, जितेन्द्रिय होना चाहिए। हनुमान साधना करने के लिए हर व्यक्ति उसका पालन नहीं कर सकता, इसलिए इस चेतावनी का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हनुमानजी को सिद्ध करने का प्रयास भौतिक सुखों की प्राप्ति या चमत्कार प्रदर्शन के लिए कभी नहीं करना चाहिए। उनकी भक्ति के माध्यम से भगवान राम के दर्शन तथा उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। यह भक्ति हृदय की पवित्रता से ही संभव है और इसी से व्यक्ति घर और मन्दिर दोनों में एक-सा होता है। कहा जाता है की श्री हनुमानजी का जन्म ही राम भक्ति और उनके कार्यो को पूर्ण करने के लिए हुआ है। उनकी सांस-सांस में, उनके कण-कण में और खून के कतरे-कतरे में राम बसे हैं। एक प्रसंग में विभीषण के ताना मारने पर हनुमानजी ने सीना चिरकर भरी सभा में राम और जानकी के दर्शन अपने सीने में करा दिए थे।हनुमान की भक्ति या उनको पाने के लिये इंसान को इंसान बनना जरूरी है। जब तक भक्ति की धारा बाहर की ओर प्रवाहित रहेगी तब तक भगवान अलग रहेंगे और भक्त अलग रहेगा। हनुमान भक्ति के लिये जरूरी है उनके जीवन से दिशाबोध ग्रहण करो और अपने में डूबकर उसे प्राप्त करो। ह्यजिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठह्ल- यही है सच्ची हनुमान भक्ति की भूमिका। भक्ति का असली रूप पहचानना जरूरी है, तभी मंजिल पर पहुंचेंगे, अन्यथा संसार की मरुभूमि में ही भटकते रह जायेंगे।

– ललित गर्ग

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आखिर कब थमेगी अपने ही युवाओं से खून की होली

छत्तीसगढ़ में पिछले 14 सालों के भीतर 1582 नक्सली मुठभेड़ हुई है। इन मुठभेड़ के दौरान 1452 नक्सली मारे गए हैं।इस बीच 1002 आम नागरिकों की भी मौत हुई है। वहीं इन हमलों में 1222 जवान शहीद हो चुके हैं।

छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षाबलों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन के लिए सुरक्षाबलों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। जवान नक्सलियों के अड्डे तक पहुंचने के लिए 20 घंटे तक पैदल चले हैं। नक्सलियों के समूह को देखने के बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू की थी। जब बंदूकें शांत हुईं, तो जंगल के फर्श पर सूखे पत्तों के बीच 29 माओवादी मृत पड़े थे। इनमें ललिता, शंकर और दूसरे कमांडर विनोद गावड़े के शवों की पहचान सबसे पहले की गई। मृतकों में पंद्रह महिलाएं भी थीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खिलाफ मिली सफलता को केन्द्र और राज्य में भाजपा सरकार की उपलब्धि बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बहुत कम समय में देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंका जाएगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद से इस अभियान को गति मिली है। नक्सली इलाकों में सुरक्षा बल कैंप लगाए जा रहे हैं। 19 के बाद इनकी संख्या 250 हो गई है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में छत्तीसगढ़ पुलिस से भी मदद मिल रही है। राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद तीन महीने में 80 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। 125 गिरफ्तार हुए हैं और 150 ने आत्मसमर्पण किया है। देश के 10 राज्यों में 70 जिलों में नक्सलवाद का प्रभाव है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य झारखंड जहां 16 जिले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित 14 जिले शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में पिछले 14 सालों के भीतर 1582 नक्सली मुठभेड़ हुई है। इन मुठभेड़ के दौरान 1452 नक्सली मारे गए हैं। इस बीच 1002 आम नागरिकों की भी मौत हुई है। वहीं इन हमलों में 1222 जवान शहीद हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद नक्सलियों को आशंका थी कि सरकार उनके खिलाफ अभियान तेज करेगी और हुआ भी ऐसा ही। राज्य की नई सरकार ने शान्ति का प्रस्ताव भी सामने रखा था लेकिन नक्सल नेताओं की तरफ से इस प्रस्ताव पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और सुरक्षाबलों को बस्तर में फ्री हैण्ड कर दिया गया हैं। ऐसे में पिछले तीन महीनों में नक्सलियों को कई बड़े नुकसान उठाने पड़े हैं। अब तक जहां माओवादियों के बटालियन स्तर के नेता ही ढेर हुए थे तो इस बार शंकर राव जैसे डिवीजन लेवल का नेता पुलिस के गोली का शिकार हुआ हैं। ऐसे में नक्सली प्रदेश में पूरी तरफ से बैकफुट में हैं। अब लगातार सवाल किये जा रहे हैं कि आखिर कब तक छत्तीसगढ़ को इस नक्सल दंश से छुटकारा मिल पायेगा और बस्तर में खून की होली थमेगी। सरकार, सुरक्षा बलों एवं स्थानीय लोगों की संयुक्त कोशिशों का परिणाम है कि पिछले एक

दशक में वामपंथी अतिवाद संबंधी घटनाओं, मौतों और उनके भौगोलिक प्रसार में काफी कमी आई है। जहाँ वर्ष 2010 में वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 96 थी वहीं वर्ष 2018 में प्रभावित जिलों की संख्या 60 रह गई है। वर्ष 2009 में जहाँ नक्सलवाद की घटनाओं और इन घटनाओं में मरने वालों की संख्या क्रमश 2258 व 1005 थी वहीं वर्ष 2018 में यह संख्या घटकर क्रमश 833 एवं 240 रह गई। देश के जिन 8 राज्यों के लगभग 60 जिलों में यह समस्या बनी हुई है उनमें ओडिशा के 5, झारखंड के 14, बिहार के 5, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 10, मध्य प्रदेश के 8, महाराष्ट्र के 2 तथा बंगाल के 8 जिले शामिल हैं। वर्ष 2015 के बाद से नक्सलियों के 90 प्रतिशत हमले लगभग चार राज्यों- छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और ओडिशा में हुए हैं।

माओवादियों के थिंक-टैंक और प्रथम पंक्ति के नेता या तो मारे जा चुके हैं या इस विचारधारा को छोड़ चुके हैं। भारत में नक्सली हिंसा की शुरूआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी नामक गाँव से हुई और इसीलिये इस उग्रपंथी आंदोलन को 'नक्सलवाद' के नाम से जाना जाता है। जमींदारों द्वारा छोटे किसानों के उत्पीड? पर अंकुश लगाने के लिये सत्ता के खिलाफ चारू मजूमदार, कानू सान्याल और कन्हाई चटर्जी द्वारा शुरू किये गए इस सशस्त्र आंदोलन को नक्सलवाद का नाम दिया गया। यह आंदोलन चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग की नीतियों का अनुगामी था। आंदोलनकारियों का मानना था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिये सरकारी नीतियाँ जिम्मेदार हैं। ये लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ हैं और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म करने के लिये हिंसा का सहारा लेते हैं। ये समूह देश के अल्प विकसित क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं और लोगों को सरकार के प्रति भड़काने की कोशिश करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें माओवादी हिंसा को मुख्यत कानून-व्यवस्था की समस्या मानती रही हैं, लेकिन इसके मूल में गंभीर सामाजिक-आर्थिक कारण भी रहे हैं। नक्सलियों का कहना है कि वे उन आदिवासियों और गरीबों के लिये लड़ रहे हैं, जिनकी सरकार ने दशकों से अनदेखी की है। वे जमीन के अधिकार एवं संसाधनों के वितरण के संघर्ष में स्थानीय सरोकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माओवाद प्रभावित अधिकतर इलाके आदिवासी बहुल हैं और यहाँ जीवनयापन की बुनियादी सुविधाएँ तक उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इन इलाकों की प्राकृतिक संपदा के दोहन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ न सड़कें हैं, न पीने के लिये पानी की व्यवस्था, न शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ और न ही रोजगार के अवसर। नक्सलवाद के उभार के आर्थिक कारण भी रहे हैं।

नक्सली सरकार के विकास कार्यों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं। वे आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं होने देते और उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काते हैं। वे लोगों से वसूली करते हैं एवं समांतर अदालतें लगाते हैं। प्रशासन तक पहुँच न हो पाने के कारण स्थानीय लोग नक्सलियों के अत्याचार का शिकार होते हैं। अशिक्षा और विकास कार्यों की उपेक्षा ने स्थानीय लोगों एवं नक्सलियों के बीच गठबंधन को मजबूत बनाया है। नक्सलवादियों की सफलता की वजह उन्हें स्थानीय स्तर पर मिलने वाला समर्थन रहा है, जिसमें अब धीरे-धीरे कमी आ रही है। सरकार नक्सली चरमपंथ से निबटने के लिये बहुआयामी रणनीति अपना रही है। इसमें सुरक्षा एवं विकास से संबंधित उपाय तथा आदिवासी एवं अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाने से संबंधित उपाय शामिल हैं। सरकार वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे, कौशल विकास, शिक्षा, ऊर्जा और डिजिटल संपर्कता का यथासंभव विस्तार करने के भी प्रयास कर रही है।

सरकार की इस नीति के परिणामस्वरूप नक्सलियों के हौसले कमजोर हुए हैं तथा उनके आत्मसमर्पण की संख्या लगातार बढ़ रही है। विमुद्रीकरण ने भी नक्सलियों को पहुँचने वाली वित्तीय सहायता पर लगाम लगाई है और इसके बाद से अब तक 700 से अधिक माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरकार वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है और वर्ष 2022 तक 48877 किमी. सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में संचार सेवाओं को मजबूत बनाने के लिये सरकार बड़ी संख्या में मोबाइल टावर लगाने का काम कर रही है। इसके तहत कुल 4072 टावर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। निश्चित तौर पर पुलिस की दवाब बनाने की सक्रिय कार्रवाई और विकास बहुआयामी योजनाओं से नक्सली समस्या जड़मूल से समाप्त हो सकेगी।

– योगेन्द्र योगी

भारत का सकल घरेलू उत्पाद अगले 50 वर्षों में 52 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो जाने की सम्भावना

गोल्डमेन सेच्स नामक अंतरराष्ट्रीय निवेश संस्थान ने अपने एक रिसर्च पेपर में बताया है कि आगे आने वाले 50 वर्षों में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 52 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा। इस प्रकार भारत इस संदर्भ में अमेरिका को भी पीछे छोड़ते हुए विश्व में प्रथम स्थान पर आ जाएगा। वर्तमान में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक आदि विभिन्न वित्तीय संस्थानों ने भी आगे आने वाले समय में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को 7.2 प्रतिशत रहने की प्रबल संभावनाएं जताई हैं। जबकि, आज विश्व के कई देश, विशेष रूप से ब्रिटेन, जर्मनी आदि, आर्थिक संकुचन के दौर से गुजर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कई विकसित देश ऊर्जा की कमी के संकट से जूझ रहे हैं। भारत के विदेशमंत्री, डॉक्टर एस जयशंकर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व के लगभग समस्त सशक्त देशों के साथ अच्छे सम्बंध बनाने में सफल रहे हैं। आज रूस को भी भारत की आवश्यकता है तो अमेरिका को भी। रूस, भारत को कच्चे तेल एवं सुरक्षा के लिए भारी मात्रा में शस्त्र उपलब्ध कराता है। वर्ष 2022 में भारत ने रूस से 4,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का सामान आयात किया था। वर्ष 2023 में यह बढ़कर 5,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर होने की प्रबल सम्भावना है। वहीं अमेरिका, भारत को अपना स्ट्रेटेजिक सहयोगी मानता है। आज विश्व की समस्त बड़ी शक्तियां भारत के साथ सौहार्द पूर्ण सम्बंध चाहती हैं। रूस, अमेरिका, यूरोपीयन देश एवं अरब देश भारत के साथ अपने व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं। रूस भी भारत के साथ अच्छे सम्बंध चाहता है तो यूक्रेन भी। उधर इजराईल भी भारत के साथ अच्छे सम्बंध चाहता है तो ईरान भी। भारत जी-20 समूह का सदस्य है तो भारत यू2आई2 एवं ब्रिक्स का भी सदस्य है। इस प्रकार कुल मिलाकर भारत का डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। आज भारत के पास विश्व की चौथी सबसे बड़ी फौज है। पश्चिमी बॉर्डर पर चीन से युद्ध की स्थिति में भारत आज इससे निपटने को पूर्णतः तैयार है। भारत के पास आज युवा जनबल है। भारत की 66 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष की कम आयु की है। 40 प्रतिशत जनसंख्या 13 से 35 वर्ष के बीच में है। भारत के पास 35 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। इसके विपरीत चीन, जापान, इटली, फ्रान्स आदि कई देशों की जनसंख्या अब धीमे धीमे कम हो रही है। इन देशों में आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए आज युवाओं की सख्त आवश्यकता है जो पूरे विश्व में केवल भारत ही उपलब्ध करा सकता है। वर्ष 2064 तक भारत की जनसंख्या बढ़ती रहेगी, ऐसी सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इस प्रकार वैश्विक स्तर पर भारत विश्व में विकास के इंजन के रूप में अपनी भूमिका लम्बे समय तक निभाता रहेगा। उक्त संदर्भ में दूसरा सबसे बड़ा कारण बताया गया है, भारत में हाल ही के समय में किया गया डिजिटलीकरण। इससे देश के ग्रामीण इलाकों में भी नागरिकों की दक्षता एवं उत्पादकता बढ़ गई है। भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की वित्तीय एवं बैंकिंग संस्थानों द्वारा भरपूर आर्थिक सहायता की जा रही है इससे यह उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं एवं देश में रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित कर रहे हैं। पूर्व में केवल बड़े उद्योगों को ही बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती रही है परंतु भारत में अब यह ट्रेंड बदला है। कोविड महामारी के बाद से तो इस सम्बंध में बड़ा बदलाव देखने में आया है। डिजिटलीकरण के कारण छोटे छोटे व्यवसाईयों की क्रेडिट हिस्ट्री निर्मित हो रही है जिसके कारण बैंकों को इन छोटे छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में आसानी हो रही है। 'आधार' ने तो देश के समस्त नागरिकों की एक अलग पहचान ही बना दी है। यूपीआई प्लेटफोर्म ने भी इस संदर्भ में ग्रामीण इलाकों में भी रोकड़ के उपयोग को कम कर डिजिटल प्लेटफोर्म पर वित्तीय व्यवहारों को हस्तांतरित किया है। छोटे छोटे व्यवसाईयों, किसानों, सामान्य नागरिकों को भी वित्तीय प्लेटफोर्म पर लाने में यह डिजिटलीकरण बहुत सफल रहा है। इससे वित्तीय समावेशन का कार्य भी आसान बन पड़ा है। भारत में डिजिटल व्यवहारों की संख्या आज संयुक्त रूप से अमेरिका, चीन एवं यूरोप से भी अधिक है। जबकि अमेरिका, चीन एवं यूरोप के देश भारत से अधिक विकसित देश हैं। इससे यह झलकता है कि भारत ने डिजिटलीकरण के मामले में पूरे विश्व को पीछे छोड़ दिया है। अब तो भारत का यूपीआई सिस्टम अमेरिका के स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को भी पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर डिजिटलीकरण के मामले में अपनी धाक जमाने की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत का यूपीआई सिस्टम सिंगापुर, फ्रान्स, श्रीलंका एवं यूएई में लागू किया जा चुका है। भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रान्स में भारतीय यूपीआई सिस्टम का उद्घाटन किया था, ताकि फ्रान्स में जाने वाले पर्यटक यूपीआई सिस्टम के माध्यम से फ्रान्स में वित्तीय व्यवहार कर सकें। न्यूजीलैंड में भी यूपीआई को लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। उक्त संदर्भ में तीसरा सबसे बड़ा कारण है चीन के, विस्तारवादी नीतियों के चलते, विश्व के अन्य देशों के साथ लगातार खराब होते सम्बंध। आज विश्व के कई देश चीन के साथ आर्थिक व्यवहार करने से कतराने लगे हैं। यह स्थिति भारत के आर्थिक विकास को गति दे सकती है क्योंकि चीन+1 की नीति का अनुपालन विश्व के कई विकसित देश आज करने लगे हैं एवं ये देश भारत में विनिर्माण के क्षेत्र में अपनी इकाईयों को स्थापित करते जा रहे हैं। ताईवान आदि देशों पर चीन की नीति की पूरे विश्व में भर्त्सना हो रही है। चीन के अपने बॉर्डर पर लगने वाले लगभग समस्त देशों के साथ चीन के सम्बंध अच्छे नहीं हैं।

बढ़ने लगी है सरकारी योजनाओं तक वंचित समुदाय की पहुंच

आरती कुमारी

"हमें हर महीने की पहली से तीन तारीख के बीच राशन मिल जाता है. यदि कभी लेट होता है तो मेरे पोता और पोती राशन डीलर से नहीं मिलने का कारण पूछते हैं. मुझे तो कुछ नहीं पता है लेकिन मेरे घर की नई पीढ़ी बहुत जागरूक है. बच्चों ने राशन से संबंधित सभी दस्तावेज जमा करा रखा है. इसलिए हमारा राशन नहीं रुकता है. अब तो मेरी पेंशन भी समय पर मिलने लगी है. सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ इन बच्चों के कारण मिलने लगा है. वह योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं और फिर पंचायत कार्यालय में जाकर उसे शुरू कराने का आवेदन देते हैं." यह कहना है 76 वर्षीय अम्बा बाई का, जो राजस्थान के उदयपुर जिला स्थित लोयरा गांव की रहने वाली है.

ऐतिहासिक नगरी उदयपुर से मात्र 8 किमी की दूरी पर आबाद यह गांव बड़गांव तहसील के अंतर्गत आता है. अनुसूचित जनजाति बहुल इस गांव की जनसंख्या करीब 2500 है. गांव में 550 मकानों में कुछ ओबीसी से जुड़े डांगी समुदाय के साथ साथ कुछ घर लोहार, जाट, सुथार और उच्च जातियों की भी है. उदयपुर शहर से करीब होने का प्रभाव गांव में साफ़ नजर आता है. कुछ कच्चे मकानों को छोड़कर अधिकतर मकान पक्के बनने लगे हैं. हालांकि आर्थिक रूप से अभी भी यह गांव कमजोर नजर आता है. ओबीसी और सामान्य जातियों के लोग जहां कृषि, व्यवसाय और पशुपालन करते हैं वहीं अनुसूचित जनजातियों से जुड़े अधिकतर परिवार के पुरुष सदस्य उदयपुर शहर के आसपास संचालित मार्बल फैक्ट्रियों में लेबर वर्कर के रूप में काम करते हैं. कुछ दैनिक मजदूर के रूप में भी काम करते हैं. वहीं कुछ परिवार के पुरुष सदस्य अहमदाबाद, सूरत और बेंगलुरु के फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं. जबकि घर की महिलाएं शहर के बड़े घरों में घरेलू सहायिका के रूप में काम कर परिवार की आर्थिक सहायता करती हैं. आर्थिक रूप से लोयरा गांव भले ही कमजोर हो, लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से यह गांव पहले की अपेक्षा अधिक विकसित होने लगा है. यही कारण है कि गांव में सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी है और वह इसका अधिक से अधिक लाभ भी उठाने लगे हैं. गांव की नई पीढ़ी में शिक्षा का स्तर बढ़ा है. अनुसूचित जनजाति समुदाय के लड़के और लड़कियां भी 12वीं तक शिक्षा प्राप्त करने लगी हैं. शिक्षा के बढ़ते स्तर ने गांव में जागरूकता को बढ़ाने का भी काम किया है. इसकी मिसाल खाद्य सुरक्षा के तहत गांव में मिलने वाली जन वितरण प्रणाली का लाभ है. इस संबंध में 45 वर्षीय शिवलाल कहते हैं कि वह स्वयं 12वीं पास हैं और बेंगलुरु जाकर मार्बल फैक्ट्री में काम करते हैं. लेकिन गांव में सरकार द्वारा दी जाने वाली लगभग सभी योजनाओं की न केवल उन्हें जानकारी है बल्कि उनका परिवार इसका लाभ भी उठाता है. वह बताते हैं कि "पहले के समय में राशन डीलर कुछ बहाना करके हमें राशन से वंचित कर देता था. लेकिन अब शिक्षा और जागरूकता के कारण ऐसा संभव नहीं है. अब राशन नहीं मिलने पर हम उससे सवाल करते हैं. पंचायत कार्यालय जाकर जानकारियां प्राप्त करते हैं. मैं जब घर पर नहीं होता हूं तो मेरे बच्चे यह काम करते हैं. इसलिए अब समय पर हमारा राशन मिल जाता है." गांव की 70 वर्षीय बुजुर्ग तारु बाई कहती हैं कि "अब हमारे समुदाय की 55 प्रतिशत लड़कियां 12वीं तक पढ़ने लगी हैं. इसीलिए उन्हें सभी योजनाओं की जानकारियां हैं. घर में बच्चों के पढ़ने के कारण ही मेरी वृद्धा पेंशन शुरू हो सकी है. उन्होंने ही मेरे सारे कागज़ात जमा कराये. जबकि हमारे समय में लड़कियों के पढ़ने का कोई रिवाज नहीं था. इसलिए हमें किसी सरकारी योजनाओं के बारे में कुछ पता नहीं होता था. कभी किसी से किसी योजना का नाम सुना और जब उसके बारे में पंचायत में पता भी किया तो कोई ठोस जवाब नहीं मिलता था. लेकिन अब नई पीढ़ी सभी योजनाओं के बारे में जानने लगी है. उन्हें यह भी पता है कि इसका लाभ उठाने के लिए कौन सा फॉर्म भरने की आवश्यकता है." तारु बाई बताती है कि "गांव का अधिकतर अनुसूचित जनजाति परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है. अधिकतर परिवारों के पास इतने पैसे नहीं है कि वह कोई व्यवसाय कर सकें और न ही इतनी ज़मीन है कि वह उस पर खेती या सब्ज़ी उत्पादन कर सकें. नई पीढ़ी पढ़ने तो लगी है लेकिन नाममात्र लोग ही नौकरी करते हैं. इसीलिए इस समुदाय के ज़्यादातर सदस्य मज़दूरी या फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं. लेकिन इसके बावजूद शिक्षा के प्रति नई पीढ़ी में उत्साह है."

55 वर्षीय सुंदर बाई बताती हैं कि "मेरे 5 बच्चे हैं और सभी स्कूल जाते हैं. बड़ी बेटी पिछले वर्ष 12वीं पास की है और अब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही है. मुझे अपनी बेटी के माध्यम से पता चला कि सरकार हमारे समुदाय के उत्थान के लिए बहुत काम करती है. ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ उठा कर हम अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग विकास कर सकते हैं. मेरी बेटी ने भी इसका लाभ उठाते हुए स्कॉलरशिप प्राप्त किया है. मैं और मेरे पति पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए पहले राशन डीलर किसी न किसी कागज़ की कमी बता कर हमारा राशन रोक देता था. लेकिन जब मेरी बेटी ने जाकर उससे बात की और खुद से सरकारी वेबसाइट पर सारे कागज़ात भरे, इसके बाद से हमारा राशन कभी नहीं रुका है. हमें ख़ुशी है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर जागरूक हो गए हैं और अपने अधिकारों को पहचानने लगे हैं. इसीलिए समुदाय के अधिकतर लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने लगे हैं. हालांकि हमारे समुदाय के नाममात्र बच्चे ही सरकारी नौकरियों में हैं. लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार बच्चों में पढ़ने लिखने का रुझान बढ़ा है और उनमें जागरूकता आई है, उससे वह भी जल्द ही सरकारी नौकरी में भर्ती होने लगेंगे."हालांकि इसी गांव में मांगी लाल और तुलसीराम का परिवार भी है जो खाद्य सुरक्षा के तहत जन वितरण प्रणाली का लाभ उठाने से वंचित है. मांगी लाल के पुत्र भूपेंद्र 12 वीं पास है. उनका कहना है कि उनके परिवार में 7 सदस्य हैं. पिछले वर्ष उनका राशन BPL से APL में कर दिया गया. जिससे उन्हें राशन मिलना बंद हो गया है. इसके लिए वह लगातार ई-मित्र से बात कर रहे हैं. वहीं तुलसीराम कहते हैं कि कुछ दस्तावेज़ की कमी के कारण उनके परिवार को राशन नहीं मिल रहा है. जिसे वह जल्द ठीक कराने का प्रयास कर रहे हैं. बहरहाल, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के बढ़ते प्रसार ने लोयरा गांव के अनुसूचित जनजाति समाज को भी जागरूक बना दिया है. जिसका परिणाम है कि पिछड़ा समझे जाने वाले इस समुदाय की भी सरकारी योजनाओं तक पहुंच बढ़ने लगी है.

उन्नत जीवन का आधार है हनुमान भक्ति

ललित गर्ग

भगवान हनुमानजी को हिन्दू देवताओं में सबसे शक्तिशाली माना गया है, वे रामायण जैसे महाग्रंथ के सह पात्र थे। वे भगवान शिव के ग्यारवें रूद्र अवतार थे जो श्रीराम की सेवा करने और उनका साथ देने त्रेता युग में अवतरित हुए थे। उनको बजरंग बलि, मारुतिनंदन, पवनपुत्र, केशरीनंदन आदि अनेकों नामों से पुकारा जाता है। उनका एक नाम वायुपुत्र भी है, उन्हें वातात्मज भी कहा गया है अर्थात् वायु से उत्पन्न होने वाला। इन्हें सात चिरंजीवियो में से एक माना जाता है। वे सभी कलाओं में सिद्धहस्त एवं माहिर थे। वीरो में वीर, बुद्धिजीवियों में सबसे विद्वान। इन्होंने अपने पराक्रम और विद्या से अनेकों कार्य चुटकीभर समय में पूर्ण कर दिए है। वे शौर्य, साहस और नेतृत्व के भी प्रतीक हैं। समर्पण एवं भक्ति उनका सर्वाधिक लोकप्रिय गुण है। रामभक्त हनुमान बल, बुद्धि और विद्या के सागर तो थे ही, अष्ट सिद्धि और नौ निधियों के दाता और ज्योतिष के भी प्रकांड विद्वान थे। वे उन्नत जीवन के आधार है। उनसे सफल एवं सार्थक जीवन के प्रबंधन की शिक्षा मिलती है। वे हर युग में अपने भक्तों को अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं और उनके दुःखों को हरते हैं। वे मंगलकर्त्ता एवं विघ्नहर्त्ता हैं। मंगलवार को हनुमानजी का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। भिन्न-भिन्न लोगों ने इस महान् आत्मा का मूल्यांकन भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से किया है। हनुमान का चरित्र एक लोकनायक का चरित्र है और उनके इसी चरित्र ने उन्हें सार्वभौमिक लोकप्रियता प्रदान की है। तैंतीस करोड़ देवी-देवताओं में मात्र हनुमान ही ऐसे हैं जिनकी आधुनिक युग में सर्वाधिक पूजा की जाती है और जन-जन के वे आस्था के केन्द्र हैं। उनके चरित्र ने जाति, धर्म और सम्प्रदाय की संकीर्ण सीमाओं को लांघ कर जन-जन को अनुप्राणित किया है। हनुमान का चरित्र बहुआयामी हैं क्योंकि उन्होंने संसार और संन्यास दोनों को जीया। वे एक महान् योगी एवं तपस्वी हैं और इससे भी आगे वे रामभक्त हैं। हनुमान-भक्ति भोगवादी मनोवृत्ति के विरुद्ध एक प्रेरणा है संयम की, पवित्रता की। यह भक्ति एक बदलाव की प्रक्रिया है। यह भक्ति प्रदर्शन नहीं, आत्मा के अभ्युदय का उपक्रम है। इससे अहं नहीं, निर्दोष शिशुभाव जागता है। क्रोध नहीं, क्षमा शोभती है। कष्टों में मन का विचलन नहीं, सहने का धैर्य रहता है। उत्कृष्ट विलक्षणताओं के प्रतीक हनुमान पूर्ण मानव थे। कहते हैं कि ब्रह्मा ने जब मनुष्य का निर्माण किया तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि उन्हें यह अनुभूत हुआ कि उनके द्वारा सृष्ट मानव ईश्वर का साक्षात्कार करने में समर्थ है। मानव न केवल संपूर्ण प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, प्रत्युत वह अपनी साधना के द्वारा ब्रह्मपद को भी प्राप्त कर सकता है। त्रेतायुग के सर्वाधिक शक्तिशाली मानव हनुमान जिन्हें भ्रमवश अनेक देशी-विदेशी विद्वान पेड़ों पर उछल-कूद करनेवाला साधारण वानर मानते रहे हैं, अपने अलौकिक गुणों और आश्चर्यजनक कार्यों के बल पर कोटि-कोटि लोगों के आराध्य बन गये। भारत ही नहीं, विश्व के इतिहास में किसी ऐसे मानव का उल्लेख नहीं मिलता, जिसमें शारीरिक बल और मानसिक शक्ति का एक साथ इतना अधिक विकास हुआ हो जितना हनुमान में हुआ था। प्राचीन भारत में ब्रह्मतेज से युक्त अनेक महामानव हुए। इसी प्रकार इस पावनभूमि में ऐसे विशिष्ट व्यक्ति भी हुए जो शारीरिक बल में बहुत बलशाली थे, परन्तु ब्रह्मतेज के साथ-साथ शास्त्र-बल का जो आश्चर्यजनक योग हनुमान में प्रकट हुआ, वह अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ता। शुद्ध आचार, विचार और व्यवहार से जुड़ी हनुमान की ऐसी अनेक चारित्रिक व्याख्याएं हैं जिनमें जीवन और दर्शन का सही दृष्टिकोण सिमटा हुआ है। हनुमान को बुद्धिमानों में अग्रगण्य माना जाता है। ऋग्वेद में उनके लिए 'विश्ववेदसम्' शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अभिप्रेत अर्थ है- विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ। हनुमान अपने युग के विद्वानों में अग्रगण्य थे। उनकी गणना सामान्य विद्वानों में नहीं, बल्कि विशिष्ट विद्वानों में की जाती थी। वाल्मीकि रामायण में हनुमान को महाबलशाली घोषित करते हुए 'बुद्धिमतां वरिष्ठं' कहना पूर्ण युक्ति संगत है। 'रामचरितमानस' में भी उनके लिए 'अतुलित बलधामं' तथा 'ज्ञानिनामग्रगण्यम' इन दोनों विशेषणों का प्रयोग द्रष्टव्य है। ब्रह्मचारी हनुमानजी महान् संगीतज्ञ और गायक भी थे। इनके मधुर गायन को सुनकर पशु-पक्षी एवं सृष्टि का कण-कण मुग्ध हो जाता था। हनुमान की विद्वता के साथ-साथ तर्क-शक्ति अत्यंत उच्च कोटि की थी। ऐसे अनेक प्रसंग है जब हनुमान ने अपनी तर्क-शक्ति से अनेक जटिल स्थितियों को सहज बना दिया। उनकी अलौकिक साधना एवं नैसर्गिक दिव्यता का ही परिणाम था कि वे भय और आशंका से भरे वातावरण में भी निःशंक और निर्भीक बने रहते थे। संकट की घड़ी में भी शांतचित्त होकर अपने आसन्न कर्तव्य का निश्चय करना उत्तम प्रज्ञा का प्रमाण है। हनुमान इस सर्वोत्कृष्ट प्रज्ञा से युक्त थे। प्राचीन भारत की सर्वश्रेष्ठ भाषा संस्कृत और व्याकरण पर हनुमान का असाधारण अधिकार था। हनुमान ने सूत्र, वृत्ति, वार्तिक, महाभाष्य तथा संग्रह का भली-भांति अध्ययन किया था। अन्यान्य ग्रंथों तथा छंद-शास्त्र के ज्ञान में भी उनकी समानता करनेवाला कोई नहीं था। संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान में उनकी तुलना देवताओं के गुरु बृहस्पति से की गयी है। महर्षि अगस्त्य के अनुसार हनुमान नवों व्याकरणों के अधिकारी विद्वान थे। नोबेल पुरस्कार विजेता आक्टाभियो पाज का भी यह सुनिश्चित मत है कि हनुमान ने व्याकरण शास्त्र की रचना की थी। मारुति नंदन, परमवीर, श्रीराम भक्त हनुमानजी की पवित्र मन से की गयी साधना और भक्ति चमत्कारपूर्ण परिणाम देने वाली है। हनुमानजी शिव के अवतार माने जाते हैं और ग्यारहवें रुद्र के रूप में इनकी मान्यता है। कहते है-मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सार्वकालिक सेवा करने एवं रावण-वध में उनका सहयोग करने के लिए भगवान राम का अवतार लेने से पूर्व ही त्रेतायुग में शिवजी ने अपने ग्यारहवें रुद्र के रूप में अवतार लिया था। वह 'हनुमानजी' के पवित्र लोकोपकारी नाम से विख्यात हुए। महादेव का हनुमान के रूप में अवतरण लेने के सन्दर्भ में कहा जाता है कि भगवान विष्णु महादेव के इष्ट देव हैं। वे उनके श्रीचरणों के शाश्वत पुजारी हैं। त्रेतायुग में रावणादि राक्षसों का सकुल संहार करके उनका उद्धार करने के लिए ही भगवान विष्णु अयोध्या के महाराज दशरथ के यहां अपनी सोलह कलाओं सहित पुत्र रूप में अवतरित हुए। अतः उनकी सेवा करने के लिए महादेव ने हनुमान के रूप में अवतार लिया। तंत्र शास्त्र के आदि देवता और प्रवर्तक भगवान शिव हैं। इस प्रकार से हनुमानजी स्वयं भी तंत्र शास्त्र के महान पंडित हैं। समस्त देवताओं में वे शाश्वत देव हैं। परम विद्वान एवं अजर-अमर देवता हैं। वे अपने भक्तों का सदैव ध्यान रखते हैं। उनकी तंत्र-साधना, वीर-साधना है। वे रुद्रावतार और बल-वीरता एवं अखंड ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। अतः उनकी उपासना के लिए साधक को सदाचारी होना अनिवार्य है। उसे मिताहारी, जितेन्द्रिय होना चाहिए। हनुमान साधना करने के लिए हर व्यक्ति उसका पालन नहीं कर सकता, इसलिए इस चेतावनी का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हनुमानजी को सिद्ध करने का प्रयास भौतिक सुखों की प्राप्ति या चमत्कार प्रदर्शन के लिए कभी नहीं करना चाहिए। उनकी भक्ति के माध्यम से भगवान राम के दर्शन तथा उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। यह भक्ति हृदय की पवित्रता से ही संभव है और इसी से व्यक्ति घर और मन्दिर दोनों में एक-सा होता है। कहा जाता है की श्री हनुमानजी का जन्म ही राम भक्ति और उनके कार्यो को पूर्ण करने के लिए हुआ है। उनकी सांस-सांस में, उनके कण-कण में और खून के कतरे-कतरे में राम बसे हैं। एक प्रसंग में विभीषण के ताना मारने पर हनुमानजी ने सीना चिरकर भरी सभा में राम और जानकी के दर्शन अपने सीने में करा दिए थे। हनुमान की भक्ति या उनको पाने के लिये इंसान को इंसान बनना जरूरी है। जब तक भक्ति की धारा बाहर की ओर प्रवाहित रहेगी तब तक भगवान अलग रहेंगे और भक्त अलग रहेगा। हनुमान भक्ति के लिये जरूरी है उनके जीवन से दिशाबोध ग्रहण करो और अपने में डूबकर उसे प्राप्त करो। 'जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ'- यही है सच्ची हनुमान भक्ति की भूमिका। भक्ति का असली रूप पहचानना जरूरी है, तभी मंजिल पर पहुंचेंगे, अन्यथा संसार की मरुभूमि में ही भटकते रह जायेंगे।

मेष राशि : आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। अपना व्यवहार लचीला रखें और दूसरों की बातें समझने का मन बनाकर चलें। आज कोई बुजुर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति आपको सही सलाह दे सकता है। व्यापारिक मामलों में जवाबदारी बढ़ सकती है। आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी। आज खुद पर किसी तरह की उलझन को हावी न होने दें साथ ही आपको अपने व्यवहार पर कंट्रोल करना पड़ेगा।

वृष राशि : आज व्यवसाय में आपको फायदा हो सकता है। ऑफिस में किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए सहकर्मी की मदद मिलेगी। कोर्ट-कचहरी के मामलों से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की जरूरत है। लवमेट कहीं घूमने की प्लानिंग करेंगे। शाम को परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर सकते हैं।

मिथुन राशि : आज कोई काम पूरा होने से आपको ख़ुशी मिलेगी। शाम तक आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिससे घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा। आसपास के लोग आपके व्यक्तित्व से प्रसन्न होंगे। आप ताजगी से परिपूर्ण रहेंगे। लवमेट के साथ आपका दिन बेहतर गुजरेगा। आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। सोचे हुए कार्यों की गति मजबूत होगी।

कर्क राशि : आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। परिवार की सलाह आज आपके लिए फायदेमंद होगी। आज आपके कोई खास रिश्तेदार आपसे हेल्प लेंगे। आज आपका मन पूजा-पाठ में अधिक लगा रहेगा। परिवार के साथ किसी मंदिर में दर्शन करने जायेंगे। इस राशि के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के लिए कॉल आएगी।

सिंह राशि: आज का दिन आपके लिए अच्छा होने वाला है। आज पास की किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल होने के योग बन रहे हैं। आज किसी मामले में दूसरों के साथ बातचीत या सलाह करने से फायदा होगा। जरूरी काम और रिश्ते के बारे में विचार करेंगे और योजना बनाएंगे। परिवार से जुड़ी कोई परेशानी खत्म होने के योग हैं। आज नए सिरे से कोशिश करेंगे तो आप सफल हो सकते हैं।

कन्या राशि: आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है। आज आप जिस भी काम को पूरा करना चाहेंगे, वो काम पूरा हो जाएगा। किसी दोस्त से मिलने आप उसके घर जा सकते हैं। अधिकारी वर्ग आपके काम से प्रसन्न होंगे। आप किसी सोच-विचार में डूबे रह सकते हैं। आप नए लोगों के संपर्क में आने की कोशिश करेंगे, इससे आपको फायदा होगा। घर पर बच्चों के लिए पार्टी का आयोजन कर सकते हैं।

तुला राशि : आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज काम में माता-पिता की हेल्प मिलने से वह जल्दी ही पूरा होगा। नेगेटिव विचारों से दूरी बनाएं रखें। आपको आज उधार के लेन देन से बचना चाहिए। आज आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स का दिन आज अच्छा रहेगा। आप समाज सेवा से जुड़कर अच्छे कामों को गति देंगे। आपके सरकारी नौकरी में चयनित होने के योग बन रहे हैं।

वृश्चिक राशि : आज आपका दिन रोज की अपेक्षा लाभ देने वाला रहेगा। आपकी मुलाकात आज अपने बचपन के मित्र से होंगी। साथ ही बचपन की यादें ताजा हो जाएगी। आपका रुका हुआ कार्य आज पूरा होगा। इस राशि के जो युवा खेल कूद में इंटरेस्ट रखते है, उनका दिन आज अच्छा रहेगा। कोई शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी।

धनु राशि : आपके लिए दिन शुभ कहा जा सकता है। आज आप जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे। कामकाज निपटाने में आप बहुत हद तक सफल भी रहेंगे। अपनी तरफ से हर मामले पर आपको सकारात्मक रहना होगा। धैर्य और विनम्रता रखें। आज किसी पुरानी समस्याओं पर दोस्तों से बातचीत हो सकती है, इससे आपको अच्छा समाधान भी मिल सकता है। आपकी सलाह से दूसरों को फायदा होगा। आज आपको नए इनकम सोर्स मिल सकते हैं। कामकाज में आपकी रुचि बढ़ सकती है। बिजनेस अच्छा रहेगा। फालतू खर्चे कम हो सकते हैं।

मकर राशि: आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज शांति से कामकाज निपटाने की कोशिश करें। आज पुरानी देनदारी भी निपटा सकते हैं। आज जीवनसाथी की भावनाओं को समझने में बहुत हद तक आपको सफलता मिल सकती है। धैर्य और समझदारी रखें। आज परिवार के कामों में आपका पैसा लग सकता है। बड़े लोगों से मुलाकात के योग बन रहे हैं। आज आप कोई नया काम शुरू करने का प्लान बनायेंगे।

कुंभ राशि : आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अपने से बड़े या किसी अनुभवी से सलाह लेकर ही आगे बढने की कोशिश करेंगे। आज किसी कठिन काम को मेहनत, धैर्य और समझदारी से निपटा लेंगे। आज आपके पास बहुत-सी जिम्मेदारियां हो सकती हैं। संतान, परिवार के सदस्य और दोस्तों के साथ समय बीत सकता है।

मीन राशि: आज का दिन आपके लिए अच्छा है। ट्रांसफर या प्रमोशन के लिए किसी से बात हो सकती है इसमें आपको सफलता मिलेगी। काम पूरे होने के योग हैं। आज आप करियर में सक्सेस होने के लिए प्लानिंग करेंगे जिसका फायदा आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आपको आज नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है।

द. भारत में भाजपा को भरोसा योगी और प्रमोद सावंत पर

आर.के. सिन्हा

भाजपा इस बार दक्षिण भारत की जंग में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए जी-जान लगा रही है। वह इस चुनावी जंग में अपने प्रतिद्वंदियों को किसी भी सूरत में कोई स्पेस देने के मूड में नहीं है। जिनको लगता है कि भाजपा का दक्षिण भारत में कोई वजूद ही नहीं है, वे घोर मुगालते में हैं। भाजपा इस बार इन राजनीतिक अल्प-ज्ञानियों को पूरी तरह से गलत साबित करना चाहती है। दक्षिण भारत के राज्य भाजपा के लिए अबतक कठिन चुनौती वाले प्रदेश रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है । लेकिन, अब परिस्थितियाँ बदली हैं। इस बार पार्टी ने दक्षिण भारत में चुनावी स्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने का मन ही नहीं बनाया, बल्कि दृढ़ संकल्प किया हुआ है। वास्तव में 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के संबंध में दक्षिण की धारणा को पूरे समाज, मीडिया और समीक्षकों की राय बदलने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। भाजपा ने अपने दो बेहद तेज – तर्रार मुख्यमंत्रियों क्रमशः योगी आदित्यनाथ और प्रमोद सावंत को दक्षिण भारत में सघन चुनाव अभियान की जिम्मेदारी सौंपी है। ये दोनों ही अपने कुशल नेतृत्व के चलते उत्तर प्रदेश और गोवा को विकास की बुलंदियोंपर लेकर जा रहे हैं। प्रमोद सावंत कर्नाटक में भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में जमकर कैंपेन कर रहे हैं। वे कर्नाटक में अपना भाषण कन्नड़ में ही देते हैं। जाहिर है, इस वजह से वे तुरंत स्थानीय जनता से संबंध स्थापित कर उन्हें प्रभावित करते हैं। योगी आदित्यनाथ को भी दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में प्रचार करना है। योगी आदित्यनाथ और प्रमोद सावंत की अखिलभारतीय छवि बन चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ पूर्व में कर्नाटक में कैंपेन करते रहेहैं। उन्हें कर्नाटक का युवा, मेहनतकश और महिलाएं बहुत ध्यानसे सुनती हैं। उन्होंने बीमारू उत्तर प्रदेश को देश के सबसे विकसित होते राज्य कीश्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि चुस्त-सख्तप्रशासन से गुंडे मवाली भाग खड़े होते हैं। अगर बात प्रमोद सावंत की करें तो वे गोवाकी स्थापित छवि को बदल रहे हैं। वे चाहते है कि गोवा को उसके समुद्री तटों, गिरिजाघरों के अलावा उसके समृद्ध अतीत के रूप में भी जाना जाए। गोवा को लेकर एक खास तरह की भ्रांति पूर्ण धारणा बना दी गई है, जबकि सच्चाई यह है कि गोवा एक प्राचीन सनातन भूमि है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पर्यटन संग आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से गोवा कोविकसित बनाने का संकल्प लिया है। बेशक, प्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ-साथ यह दोनों भी दक्षिण भारत में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में अहम रोल निभाने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपनेगृह प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और बिहार में भी बड़ी सभाओं कोसंबोधित कर चुके हैं। वे जिधर भी जाते हैं वहां पर उनका अभूतपूर्व स्वागत होता है । इस बीच,तमिलनाडु उन अनूठे राज्यों में से एक है, जहाँ 87 फीसद से अधिक हिंदू आबादी है। यह उन राज्यों में एक है जहांराष्ट्रीय दलों यानी भाजपा और कांग्रेस की उपस्थिति अबतक काफ़ी कमजोर रही है। हाँ भाजपा कोयंबटूरऔर कन्याकुमारी में जरूर अच्छे वोट जुटाती रही है। तमिलनाडु में भाजपा मजबूत नहीं हुईं इसका सबसे बड़ा कारण राज्य में नेतृत्व का अभाव रहा, कई भाजपा नेता विवादास्पद बयान के लिए जाने जाते रहे । लेकिन, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस धारणा को बदल दिया है।और फिर पूर्व आईपीएस अधिकारी के. अन्नामलाई को तमिलनाडु भाजपा का अध्यक्ष बनाएजाने के बाद दक्षिणी राज्य में भाजपा कीसंभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। अन्नामलाई राज्य में पार्टी के लिए जमीन तैयार करने मेंकाफी हद तक सफल भी हुए हैं। मोदी और अमित शाह लगातार अन्नामलाई के नेतृत्व को अपनासमर्थन दे रहे हैं। भाजपा ने इसी आधार पर तमिलनाडु में अकेले 23 सीटों पर चुनाव लड़ने का साहस दिखाया। तमिलनाडू में 19 अप्रैल को मतदान हुआ। भाजपा को लगता है कि वह इस बार तमिलनाडु और केरलजैसे राज्यों में भी चौंकाने वाले नतीजे देगी। दक्षिण भारत में लोकसभा की कुल मिलाकर 130 सीटें हैं।इसमें तमिलनाडु (39), कर्नाटक (28), आंध्रप्रदेश (25), तेलंगाना (17), केरल(20) और पुदुचेरी (1) शामिलहैं। कांग्रेस ने 2019 में दक्षिण से 28 लोकसभासीटें जीतीं थीं। इसमें केरल में 15, तमिलनाडुमें 8, तेलंगानामें तीन, कर्नाटक में एक और पुदुचेरी में एक, जबकिभाजपा ने कर्नाटक में 25 और तेलंगाना में 4 सीटें जीतीथीं। तमिलनाडु में भाजपा का खाता नहीं खुला था जबकि उसका जे. जयललिता की पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके)से इसका गठबंधन था। केरल और आंध्र प्रदेश में भी हाल यही रहा। खास बात है किदक्षिण भारत में सबसे ज्यादा सीटेंतमिलनाडु में ही हैं। मोदी- शाह के साथ भाजपा के चुनावी रणनीतिकार इस राज्य में हीखाता खोलने पर पूरा फोकस करते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी सेभी तमिलनाडु का रिश्ता जोड़ा गया है और सफलतापूर्वक आयोजित की गई तमिल संगम इसकी बानगी है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

मतदान प्रतिशत बढ़े पर वोटर भी संकीर्णता छोड़ें

चुनाव आयोग ने हाल ही में देश के 11 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लंबी बैठक में मतदान प्रतिशत बढ़ाने का अभियान शुरू करने के लिए कहा। आंकड़ों में पाया गया कि पिछले चुनाव में इन 11 राज्यों (बिहार, यूपी, महाराष्ट्र आदि) में मतदान प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से काफी कम था, जबकि पश्चिम बंगाल, असम और आन्ध्र में ये ज्यादा रहा। चुनाव में ज्यादा भागीदारी प्रजातंत्र की गुणवत्ता का एक सर्वमान्य पैमाना है। आयोग इस बात से भी चिंतित था कि शहरी वोटर्स में उदासीनता बढ़ रही है। लेकिन क्या हम दावा कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल और असम के वोटर्स में प्रजातंत्र के प्रति आस्था बिहार या यूपी के वोटर्स से ज्यादा है? तमाम ऐसे राज्य जहां मतदान का प्रतिशत ज्यादा है, वहां सामाजिक तो छोड़िए, आर्थिक अस्तित्व के लिए भी लोगों का राजनीतिक तौर पर किसी न किसी पार्टी से जुड़ना और सक्रिय रहना मजबूरी बन गई। एक राज्य जो भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता के लिए बदनाम हो, अगर वहां मतदान का प्रतिशत अपेक्षाकृत ज्यादा हो तो क्या यह प्रजातंत्र की मजबूती कही जा सकती है? लिहाजा चुनाव आयोग को जहां एक तरफ प्रतिशत बढ़ाने के उपक्रम करने चाहिए, वहीं मतदाताओं को अपने संवैधानिक अधिकारों, संवैधानिक कर्तव्यों के साथ ही वैज्ञानिक और तार्किक सोच बढ़ाकर सही प्रत्याशी चुनना चाहिए।

प्रेरणा

छोटी-छोटी बातों में विश्वास रखें क्योंकि इनमें ही आपकी शक्ति निहित है। यही आगे ले जाती हैं। - **मदर टेरेसा**

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
ptvijayshankarmehta.com

दो तरह के दोस्तों से ही अकेलापन दूर होगा

क्या बहुत ज्यादा दोस्त बनाने से आप अकेलेपन से बाहर आ जाएंगे? बहुत लोगों से संबंध रखने पर क्या आप खुश रह सकेंगे? जिन लोगों की मित्रता का दायरा बहुत बड़ा होता है, वो लोग और अधिक अशांत पाए जाते हैं। और फिर सोशल मीडिया के युग में तो यारी-दोस्ती की बाढ़ आ गई है। यदि आपको दोस्ती ही करना है तो दो लोगों से दोस्ती करिए। एक अपनी संतानों से और दूसरा, अपनी आत्मा से। आत्मा की बात यहां इसलिए कही जा रही है क्योंकि सारी दुनिया ने एकता का आधार रंग, चमड़ी, भाषा, आमदनी, जाति पर बनाया है। लेकिन हमारी संस्कृति में आत्मा को बताया है। हम कहते हैं, जो हमारे भीतर है, वही सबके भीतर है। लेकिन चूंकि हम लोग शरीर पर जीते हैं, इसलिए आत्मा से संबंध बना ही नहीं पाते। इसलिए पहला मित्र आत्मा और फिर अपनी संतानों से दोस्ती करें। हम संतान तैयार करने में मेहनत करते हैं। मां गीतकार होती है, पिता संगीतकार होते हैं और संतान गायक। ये त्रिवेणी संगम मित्रता में बड़ा काम आएगा। दोस्ती होने से अकेलापन नहीं मिटता। अकेलापन मिटता है, अपनी आत्मा और आत्मा रूपी संतानों को उनसे जोड़कर।

• Facebook: Pt. Vijayshankar Mehta

विश्लेषण • 'मोदी की गारंटी' ही बुनियादी एजेंडा बना

व्यक्ति-केंद्रित राजनीति के एक नए दौर में है देश

राजदीप सरदेसाई
वरिष्ठ पत्रकार
rajdeepsardesai52@gmail.com

543 निर्वाचन क्षेत्रों, 10 लाख से अधिक बूथों, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 96 करोड़ से अधिक मतदाता- लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ एक नाम पर लड़ा जा रहा है : नरेंद्र दामोदरदास मोदी। 2024 का यह लोकसभा चुनाव सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा संसदीय लोकतंत्र के नाम पर लड़ी जा रही प्रेसिडेंशियल-शैली की लड़ाई है। हर दूसरे राज्य में मानो केवल एक ही उम्मीदवार मैदान में है, और उन्होंने इस चुनाव को अपने नेतृत्व पर एक जनमत-संग्रह बना दिया है।

यहां तक कि भाजपा का घोषणा-पत्र भी एक व्यक्ति को बाकी सभी चीजों से ऊपर रखने के बारे में है। 'मोदी की गारंटी' की कैच लाइन घोषणा-पत्र के लगभग हर पृष्ठ पर प्रधानमंत्री की तस्वीरों के साथ मौजूद है। 'एक राष्ट्र, एक नेता' के ढिंढोरे के आगे पार्टी का आकार छोटा हो गया है। 1970 के दशक के मध्य में कांग्रेस के शिखर के दिनों के बाद से- जब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरूआ ने 'इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया' कहा था- यह पहली बार है जब राष्ट्रीय चुनाव पूरी तरह से एक व्यक्ति पर केंद्रित हो गए हैं। 2014 का चुनाव 'अच्छे दिन' के आश्वासन पर लड़ा गया था, 2019 का चुनाव पुलवामा और बालाकोट के आसपास बनी व्यापक राष्ट्रवादी अपील पर, लेकिन इस बार तो चुनाव को नौकरियों, महंगाई, आर्थिक विषमता आदि के आधार पर लड़ने का दिखावा तक नहीं किया जा रहा। न ही बीते दस वर्षों की खूबियों-खामियों पर बात की जा रही है। यहां तक कि अब तो हिंदुत्व भी भाजपा के कोर-वोटरों के लिए एक सीमा के बाद कोई मायने नहीं रखता। 'विकसित भारत' का बहुप्रचारित नैरेटिव इस मान्यता के इर्द-गिर्द बुना गया है कि केवल एक ही नेता भारत को भविष्य में ले जा सकता है। वर्ष 2036 में देश में ओलिम्पिक खेल कराने का वादा भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के आसपास स्थायित्व की आभा बनाने पर ही केंद्रित है।

वैसे 'गारंटी' का विचार सबसे पहले 2020 में दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी द्वारा गढ़ा गया था। बाद में कांग्रेस ने हिमाचल और कर्नाटक में इसका उपयोग किया। अब यह प्रधानमंत्री की यूएसपी है। यह बताता है कि मतदाताओं को भले ही अपने स्थानीय नेतृत्व पर संदेह हो, लेकिन मोदी जैसे लार्जर-देन-लाइफ राष्ट्रीय नेता पर भरोसा करने के लिए वे तत्पर हैं, फिर भले ही यह 'गारंटी' उम्मीदों पर ज्यादा आधारित क्यों न हो। खुद प्रधानमंत्री थर्ड पर्सन में 'मोदी की गारंटी' शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।

कर्नाटक को देखें तो समझ आता है कि यह व्यक्ति-केंद्रित राजनीति जमीन पर कैसे काम कर रही है। जो कभी 'अलग तरह की पार्टी' कहलाती थी, वही भाजपा अब 'हर कीमत पर जीत' के सिद्धांत में विश्वास रखने वाली चुनाव-मशीन बन गई है। आधे मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया गया है, जिनमें कई वरिष्ठ और वफादार कार्यकर्ता रहे थे। पार्टी ने एचडी देवगौड़ा की जेडीएस के साथ गठबंधन कर लिया है, जबकि केवल एक साल पहले भाजपा विधानसभा चुनावों में उसके खिलाफ जमकर प्रचार कर रही थी और उस पर भ्रष्टाचार में डूबी पिता-पुत्र की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने का आरोप लगा रही थी। दक्षिण बेंगलुरु में युवा सांसद तेजस्वी सूर्या रविवार सुबह 'रन फॉर नमो' कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। उत्साही भीड़ को प्रधानमंत्री के चेहरे वाली टी-शर्ट और मास्क बांटे जा रहे हैं। जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों के

भाजपा द्वारा मोदी के नाम पर प्रचंड जनादेश मांगा जा रहा है। फिलहाल भले ही यह रणनीति काम कर जाए, लेकिन आज नहीं तो कल जब भाजपा मोदी के बाद किसी नेता को खोजने की कोशिश करेगी, तब उसका क्या होगा?

बीच 'मोदी-मोदी' का नारा भी चरम पर पहुंच गया है। हर क्षेत्र में ब्रांड-मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है।

विडम्बना यह है कि संघ परिवार ने हमेशा से ही 'व्यक्ति' से अधिक 'संगठन' के महत्व पर जोर दिया था। याद करें कि 1999 और 2004 के चुनाव अभियानों में अटल बिहारी वाजपेयी के कट-आउट्स देखकर आरएसएस ने किस तरह से उस पर नाराजगी व्यक्त की थी। लेकिन अब लगता है कि उसने भी 'आएगा तो मोदी ही' के प्रचार-अभियान को स्वीकार कर लिया है। शायद उसे लगता हो कि मोदी 3.0 में भगवा-भाईचारे के मूल वैचारिक एजेंडे को लागू किया जा सकेगा। सांसद-प्रत्याशियों का चेहरा कहीं नजर नहीं आता। केंद्रीय मंत्रियों तक को हाशिए पर धकेल दिया गया है। विपक्ष लस्त-पस्त है और मीडिया चीयरलीडर्स की भूमिका निभा रहा है। केवल और केवल मोदी के नाम पर प्रचंड जनादेश मांगा जा रहा है। फिलहाल भले ही यह रणनीति काम कर जाए, लेकिन आज नहीं तो कल जब भाजपा मोदी के बाद किसी नेता को खोजने की कोशिश करेगी, तब उसका क्या होगा?

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

दूरदृष्टि • यह इजराइल-अमेरिका दोनों के हित में

ईरान को अलग-थलग करने के लिए वैश्विक पहल जरूरी

थॉमस एल. फ्रीडमैन
तीन बार पुलित्ज़र अवॉर्ड विजेता एवं 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' में स्तंभकार

जिस तरह से इजराइल, अमेरिका और उनकी अन्य सहयोगी सेनाओं ने इजराइल पर लॉन्च किए गए लगभग हर ईरानी ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया, उससे चकित होना आसान है। हम यह निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि ईरान ने सीरिया में कार्यरत अपने शीर्ष अधिकारी की हत्या का बदला ले लिया है और इसी के साथ झगड़ा यहीं खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अगर पश्चिम ऐसा मानता है तो यह उसकी बड़ी भू-राजनीतिक गलती होगी। ईरान को अलग-थलग करने के लिए अब एक व्यापक, निरंतर और वैश्विक पहल करने की जरूरत है- केवल इसलिए नहीं कि वह दोबारा ऐसा करने की हिमाकत न करे, बल्कि इसलिए भी कि इजराइल को उस पर जवाबी कार्रवाई करने के और कारण न मिलें। ईरान के पास एक क्षेत्रीय नेटवर्क है, और लंबे समय तक उस पर लगाम लगाए रखना है तो इजराइल को भी अमेरिका के साथ मिलकर एक क्षेत्रीय गठबंधन बनाना होगा।

लेकिन ईरान को अब इसके लिए बड़े कूटनीतिक और आर्थिक परिणाम भुगतना होंगे। जब तेहरान ने उन सभी ड्रोन और मिसाइलों को दागा तो उसे नहीं पता था कि उनमें से सभी को इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा। कुछ को ऐन यरूशलेम के ऊपर मार गिराया गया था। एक मिसाइल तो इस्लाम के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक अल-अक्सा मस्जिद को निशाना बना सकती थी। दूसरा रॉकेट इजरायली संसद या किसी ऊंचे अपार्टमेंट पर हमला कर सकता था, जिससे बड़े पैमाने पर लोग हताहत हो सकते थे। दूसरे शब्दों में, हम ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से चल रहे शैडो वॉर के अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ जाने की बात कर रहे हैं। अभी तक इतना ही होता था कि इजराइल लेबनान और सीरिया में ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की यूनिट्स पर टारगेटेड हमले करता था, क्योंकि उन यूनिट्स को वहां होना ही नहीं चाहिए था। ईरान भी हिजबुल्ला की ओर से इजराइल पर रॉकेट से जवाबी कार्रवाई करवाता था। हमने ईरान को सीरिया से जॉर्डन, गाजा और वेस्ट बैंक में हथियारों की तस्करी करते देखा है, और हमने देखा है कैसे मोसाद ने ईरान में एक वैज्ञानिक की हत्या की थी।

लेकिन इजराइल और ईरान ने कभी सीधे तौर पर एक-दूसरे पर बड़ा हमला नहीं किया था। दरअसल, 33 साल पहले सद्दाम हुसैन के इराक द्वारा स्कड मिसाइलों से किए गए हमले के बाद से किसी भी देश ने सीधे तौर पर इजराइल पर हमला नहीं किया है। अगर अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाने और उसे विश्व मंच पर अलग-थलग करने की सक्रिय पहल नहीं की तो ईरान की हरकत को सामान्य मान लिया जाएगा, और ऐसी स्थिति में इजराइल को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। वैसा हुआ तो हमारा सामना मध्य-पूर्व में एक बहुत बड़े युद्ध से होगा और तेल की कीमतें 250 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। जब तक ईरान को अलग-थलग करने के लिए वैश्विक कदम नहीं उठाए जाएंगे, इजराइल असुरक्षित महसूस करता रहेगा। वैसा करने से अमेरिका भी एक ऐसे युद्ध में फंसने से बच जाएगा, जिसमें वह शामिल नहीं होना चाहता।

ईरान ने जो किया है, उसके राजनीतिक-सैन्य मायनों को चाहकर भी कम करके नहीं आंका जा सकता। मिसाइल हमलों के बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हमने अपने दुश्मन को सबक सिखा दिया है। लेकिन हो सकता है

अगर अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाने और उसे विश्व मंच पर अलग-थलग करने की सक्रिय पहल नहीं की तो ईरान की हरकत को सामान्य मान लिया जाएगा, और ऐसी स्थिति में इजराइल को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी।

इजराइल ने इससे कुछ और ही सबक लिया हो। ईरान ने जाने-अनजाने पूरी दुनिया को बता दिया कि उसकी सरकार पश्चिमी खुफिया एजेंसियों से इतनी प्रभावित है कि जो बाइडन एक दिन पहले ही हमले के सटीक समय की भविष्यवाणी करने में सक्षम थे। और पूरी दुनिया को भी यह पता चल गया है कि इजराइल और उसके पश्चिमी सहयोगियों की एंटी-मिसाइल क्षमताएं ईरान की मिसाइल क्षमताओं से कहीं बेहतर हैं। हमें मानना होगा कि इससे ईरान और उसके सहयोगी निराश और हताश हुए होंगे। ईरान अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करना चाहता था। उसका इरादा दक्षिण इजराइल स्थित नेवातिम हवाई अड्डे पर प्रहार करने का था, जहां अमेरिका द्वारा भेजे गए उन्नत एफ -35 लड़ाकू विमान मौजूद थे। लेकिन ईरान उनको खरोंच भी नहीं लगा पाया। इतने बड़े पैमाने पर हमला करने के बावजूद ईरान 7 साल की एक मुस्लिम लड़की को जख्मी भर ही कर पाया। जब ईरान के आक्रमण की यह हालत थी तो अब उसके नेता सोच रहे होंगे कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करने का मन बना लिया तो उनके डिफेंस का क्या होगा? **(द न्यूयॉर्क टाइम्स से)**

The Economist
20 अप्रैल के अंक से
विशेष अनुबंध के तहत सिर्फ दैनिक भास्कर में
इकोनॉमिस्ट ने इस हफ्ते जेन ज़ी के साथ बच्चों पर स्मार्टफोन के बढ़ते असर और इसके दुष्प्रभावों की पड़ताल की है।
दैनिक भास्कर
अब आप द इकोनॉमिस्ट के सभी आर्टिकल DB एप पर हर शनिवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

बिजनेस ब्रीफ

इस वर्ष 3.2 फीसदी से बढ़ेगी वैश्विक जीडीपी

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के नए अनुमान के अनुसार वैश्विक जीडीपी इस वर्ष 3.2 फीसदी की दर से बढ़ने की राह पर है। आईएमएफ ने कहा कि विश्व की अर्थव्यवस्था मजबूत और लचीली बनी हुई है। महामारी से जितना सोचा था, उससे कम आर्थिक नुकसान होगा। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो अमेरिका के लिए बेहतर खबर है, जहां आईएमएफ के अनुसार जीडीपी में 2.7 फीसदी की वृद्धि होगी। वहीं रूस में 3.2 फीसदी की वृद्धि का अनुमान जताया गया है।

माइक्रोसॉफ्ट ने एआई कंपनी जी42 में निवेश किया

माइक्रोसॉफ्ट ने अबू धाबी में एआई मॉडल बनाने वाली कंपनी जी42 में 1.5 अरब डॉलर निवेश की घोषणा की है। इस निवेश को यूएई की सरकार का समर्थन प्राप्त है, वहीं बाइडेन सरकार ने भी इसे सपोर्ट किया है, जिसने जी42 को चीन से अलग होने और अमेरिका पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया था।

यूरोप की सबसे मूल्यवान टेक कंपनी की बिक्री गिरी

यूरोप की सबसे मूल्यवान टेक्नोलॉजी कंपनी 'एएसएमएल' की बिक्री में गिरावट आई है। कंपनी लिथोग्राफी मशीन सप्लाई करती है, जो चिप निर्माण में एक आवश्यक टूल है। पहली तिमाही में कंपनी की सेल 3.8 अरब डॉलर तक गिर गई, जो 2023 की अंतिम तिमाही में 9.8 अरब डॉलर थी। एएसएमएल को उम्मीद है कि वर्ष की दूसरी छमाही चिप बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित होगी।

टेस्ला अपनी वर्कफोर्स में 10 फीसदी तक छंटनी कर रही

टेस्ला अपनी वैश्विक वर्कफोर्स को 10% तक घटा रही है। यह लगभग 14 हजार नौकरियों के बराबर है। इलॉन मस्क की कंपनी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कंपनी के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वे कंपनी छोड़ रहे हैं। इस साल की पहली तिमाही में टेस्ला की डिलीवरी में गिरावट आई थी। वहीं चीन की ईवी कंपनियां मुनाफे में हैं। इस साल इसके शेयर की कीमत में 37% की गिरावट भी आई थी।

© 2024 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

स्मार्टफोन

अमेरिका में स्मार्टफोन के चलते बच्चों में 150% तक तनाव बढ़ा, फ्रांस में टीनएजर्स के लिए फोन बैन, ब्रिटेन में भी चर्चा

फ्लोरिडा में बच्चों के लिए सोशल मीडिया तो नीदरलैंड्स में स्कूलों में फोन बैन

विश्व भर में बच्चों पर पड़ रहे स्मार्टफोन के दुष्प्रभाव पर बहस तेज हो गई है। ब्रिटेन-अमेरिका जैसे देशों में तो इस समस्या से निजात पाने के लिए नियम तक बनाने की बात हो रही है। दरअसल, ब्रिटेन में 12 साल के छोटे बच्चे तक के पास खुद का स्मार्टफोन है। यह समस्या कितनी बड़ी है, इसे एक उदाहरण से समझिए। दो महीने पहले ब्रिटेन की डेजी ग्रीनवेल और क्लेयर फर्नीहॉफ ने अपने बच्चों में स्मार्टफोन की लत कम करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस मुहिम के बारे में पोस्ट किया, तो उनकी इस पहल में ब्रिटेन के 60 हजार पैरेंट जुड़ गए। ऐसे में इन लोगों ने मिलकर 'स्मार्टफोन-फ्री चाइल्डहुड' नामक ग्रुप बनाया। इस समूह का लक्ष्य बच्चों में स्मार्टफोन एडिक्शन को समाप्त करना है।

पिछले महीने अमेरिका में भी इस तरह की मुहिम चली थी। जब फ्लोरिडा राज्य ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पारित किया था। अब ब्रिटेन की सरकार भी एक नए कानून पर विचार कर रही है, जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्मार्टफोन बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस बहस से दो बातें साफ होती हैं। पहली- स्मार्टफोन टीनएजर्स के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। गैलप सर्वे के अनुसार अमेरिकी टीनएजर्स दिन के 5 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं।

दूसरी बात है कि पिछले कुछ सालों में समृद्ध देशों के टीनएजर्स में मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन की समस्याएं बढ़ी हैं। 2010 के मुकाबले अमेरिका में डिप्रेशन के मामलों में 150 फीसदी की वृद्धि हुई है। 17 अमीर देशों में टीनएजर्स में आत्महत्या के मामले भी बढ़े हैं। यह इसलिए भी ध्यान देने योग्य है क्योंकि 2010 के बाद से ही स्मार्टफोन के चलन की शुरुआत हुई थी। कुछ रिसर्च सोशल मीडिया और खुशी के बीच सीधे संबंध की भी बात करते हैं। 2018 में स्टैनफोर्ड और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने फेसबुक से एक महीने दूर रहने का प्रयोग किया था। जिन लोगों ने खुद को प्लेटफॉर्म से दूर रखा, उन्होंने अधिक खुशी महसूस की। इन यूजर्स ने परिवार और दोस्तों को ज्यादा समय दिया।

हालांकि स्मार्टफोन बैन पर विशेषज्ञ बंटे नजर आते हैं। 'अनलॉक्ड' बुक के लेखक पीट एटचेल्स कहते हैं, सोशल मीडिया बैन करना सार्थक नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता कि किसी भी तरह के प्रतिबंध में क्या-क्या शामिल किया जाएगा।' वहीं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉ. मैथ्यू गेंट्जको कहते हैं, 'बच्चों को कुछ हद तक स्मार्टफोन इस्तेमाल करने देना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो चैट जैसी गतिविधियों से उनमें कम्युनिकेशन भी बेहतर हो सकती है।'

© 2024 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

भारत में 10 से 14 आयु वर्ग के 83 फीसदी बच्चे स्मार्टफोन उपयोग करते हैं

2022 में जारी मैकाफी के ग्लोबल कनेक्टेड फैमिली अध्ययन के अनुसार, 10-14 वर्ष की आयु वर्ग के 83 फीसदी भारतीय बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय औसत 76% से 7% अधिक था। इसके अलावा यूनेस्को ने भी टीनएजर्स के लिए ग्लोबल बैन की बात कही थी। यूएन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल एजेंसी की रिपोर्ट ने कहा था कि स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने टीनएजर्स के लिए स्मार्टफोन बैन किया है। फ्रांस ने 2018 में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्मार्टफोन बैन किया था। इसी साल नीदरलैंड्स ने भी स्कूलों में हर तरह के मोबाइल फोन बैन किए थे।

बिजनेस

अगर ट्रम्प चुनाव हारे, तो उनकी कंपनी ट्रुथ सोशल दिवालिया हो सकती है

इस साल 26 मार्च से, जब से डोनाल्ड ट्रम्प की मीडिया फर्म ट्रुथ सोशल के शेयर्स की ट्रेडिंग शुरू हुई है, तब से इसके शेयर्स का मूल्य आधे से अधिक गिर चुका है। फिलहाल कंपनी के शेयर 26 डॉलर पर हैं। सुस्त प्रदर्शन के बावजूद निवेशक ट्रुथ सोशल की वैल्यू उसकी क्षमता से ज्यादा लगा रहे हैं। निवेशक यह भूल रहे हैं कि ट्रुथ सोशल लगातार घाटे से जूझ रही है। 2023 के लिए कंपनी का अनुमान था कि वह 144 मिलियन डॉलर का बिजनेस करेगी, लेकिन ट्रुथ सोशल केवल 4.1 मिलियन डॉलर का ही बिजनेस कर पाई। इस बीच कंपनी को 58.2 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। ट्रम्प की कंपनी का दावा है कि वह फेसबुक-अमेजन जैसे दिग्गजों की जगह लेनी आई है। लेकिन एनालिटिक्स फर्म सिमिलरवेब ने पाया कि ट्रुथ सोशल पर लगभग 77 लाख विजिटर्स थे, जो फेसबुक के ट्रैफिक का लगभग 0.05% हिस्सा है।

ट्रम्प के पास ट्रुथ सोशल के 57 फीसदी शेयर

शायद निवेशकों का मानना है कि ट्रम्प नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव जीतेंगे और इसके बाद वे ट्रुथ सोशल का विस्तार करेंगे। ट्रम्प के इरादे जो भी हों, वास्तविकता कुछ और है। ट्रुथ सोशल पर ट्रम्प के सिर्फ 70 लाख फॉलोअर्स हैं, वहीं एक्स पर उनके 8.7 करोड़ फॉलोअर्स हैं। ट्रम्प के पास कंपनी में 78.8 मिलियन शेयर हैं, जो लगभग 57% है। लॉकअप समझौते के तहत ट्रम्प 25 सितंबर तक इन शेयर्स की बिक्री नहीं कर सकते, जब तक कि कंपनी का बोर्ड उन्हें प्रतिबंध से मुक्त नहीं कर देता। ट्रम्प जीते तो ट्रुथ सोशल के साथ क्या होगा यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन अगर वे चुनाव हारे, तो हो सकता है कि इससे ट्रुथ सोशल का स्टॉक क्रैश हो जाए।

स्वास्थ्य

बुजुर्ग हो रही चीन की आबादी ; इसी वजह से यहां अल्जाइमर- डिमेंशिया जैसी बीमारियां बढ़ रहीं

2050 तक 50 करोड़ लोग 60 से ज्यादा उम्र के होंगे

चीन में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। 2050 तक यहां 50 करोड़ लोग 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले होंगे। अब चीन में बुजुर्गों के सामने एक चुनौती पनपी है। यह अल्जाइमर का खतरा है। दरअसल, चीन के 1 करोड़ लोगों को यह बीमारी है। वहीं 5 करोड़ से ज्यादा चीनी लोगों को दिमागी समझ से जुड़ी बीमारी है। 90 वर्षीय झांग चीन के हांग्जो प्रांत में रहते हैं। उन्होंने दो बार कैंसर को मात दी है। वे बताते हैं, 'पिछले बार जब मुझे कैंसर हुआ था, तब डॉक्टर ने कहा था कि मेरे पास सिर्फ 18 महीने का समय बचा है। वो अलग बात है कि इस बात को ही अब 16 साल पूरे हो गए हैं।' झांग के स्वस्थ रहने के पीछे दो चीजें थीं। 'नो एक्सरसाइज एंड नो स्मोकिंग।' लेकिन अब झांग के सामने एक नया डर अल्जाइमर का है। झांग आगे कहते हैं, 'जिस व्यक्ति को यह बीमारी होती है वह अपने परिवार-दोस्तों सभी को भूल जाता है। अंत में थक हारकर अकेले रहने लगता है। आजकल मुझे भी भूलने की समस्या होने लगी है। हर रोज अल्जाइमर का डर लगा रहता है।'

हालांकि, झांग के लिए समस्याएं कम हैं क्योंकि हांग्जो चीन के सबसे अमीर शहरों में से एक है। और झांग के होमटाउन गोंगशू में डिमेंशिया के लिए बेहतर उपचार उपलब्ध हैं क्योंकि यहां सरकारें ही डिमेंशिया के चेक-अप व उपचार के लिए सक्रिय हैं। अकेले गोंगशू में 16 हजार डिमेंशिया के मरीज हैं। यहां की औसत उम्र (83) भी चीन की राष्ट्रीय औसत उम्र से ज्यादा है। लेकिन गोंगशू सही मायने में एक अपवाद है। क्योंकि चीन के अन्य शहरों में दिमाग से जुड़ी बीमारियों के लिए बेहतर इलाज की सुविधाएं नहीं हैं। गोंगशू में जो रेजिडेंशियल केयर सेंटर हैं, वो एक मरीज पर 5 हजार युआन तक चार्ज करते हैं। लेकिन सरकारी पेंशन स्कीम के अनुसार चीन में रिटायर्ड कर्मचारियों को सबसे अधिक 3600 युआन की राशि ही मिलती है। वहीं श्रमिकों और किसानों को तो सिर्फ 200 युआन तक की ही पेंशन दी जाती है। इसी वजह से कई बुजुर्ग रेजिडेंशियल केयर सर्विस से बाहर हो जाते हैं।

© 2024 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

जीवनशैली भी जिम्मेदार

चीन की लाइफस्टाइल भी डिमेंशिया जैसी बीमारियों को दावत देती हे। चीन के आधे वयस्क धूम्रपान करते हैं। हाई बीपी, डिप्रेशन और डायबिटीज सहित कई बीमारियां आम हैं। ये सभी डिमेंशिया के लक्षण हैं। मरीजों के लिए बीमा कवरेज खराब है। मौजूदा बीमा कवरेज अमूमन डिमेंशिया-अल्जाइमर जैसी बीमारियों को नहीं जोड़ते। डिमेंशिया का पता लगाने वाले ब्रेन-इमेजिंग स्कैन महंगे हैं। इस जनवरी में अमेरिका और जापान के बाद चीन तीसरा देश बन गया, जिसने अल्जाइमर के नए इलाज लेकेनमैब को मंजूरी दी। लेकिन इसके इलाज में सालाना 28 हजार डॉलर खर्च आता है।

© 2024 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From The Economist, translated by DB Corp, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.com

भारत की जनसंख्या

लगातार वृद्धि

भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। यदि इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया जाता है तो यह 77 वर्ष में दूनी हो सकती है। भारत अपनी जनसंख्या यात्रा में महत्वपूर्ण मोड़ पर है। उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है और अब 1.44 बिलियन लोगों का देश बन गया है। 77 साल के भीतर संख्या दूनी होने की संभावना भयंकर चुनौती पेश करती है। यह सच है कि भारत की बढ़ती जनसंख्या एक महत्वपूर्ण 'जनसंख्या लाभांश' का अवसर भी देती है। यदि युवा कार्यबल को उपयुक्त कौशल और अवसरों से लैस किया जाए तो यह आर्थिक प्रगति, खोज एवं उत्पादकता के लिए संचालक शक्ति बन सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्यरक्षा तथा रोजगार अवसरों में समुचित निवेश कर भारत में आर्थिक महाशक्ति बनने की क्षमता मौजूद है। लेकिन अवसरों के साथ ही भारत को तेजी से हो रही जनसंख्या वृद्धि के कारण अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। संसाधनों तथा ढांचागत संरचना पर दबाव बहुत है, जबकि स्वास्थ्यरक्षा, शिक्षा, आवास तथा परिवहन पहले से ही जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जनसंख्या अधिक होने के कारण भोजन, पानी, ऊर्जा और आवास की मांग बढ़ जाती है जिससे पर्यावरण क्षरण तथा सामाजिक-आर्थिक असमानतायें बढ़ती हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है। सबसे पहले 'मानव पूंजी' में निवेश के सुनियोजित प्रयास होने चाहिए। अर्थव्यवस्था में सार्थक सहभागिता के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान कर लोगों को सशक्त बनाने हेतु शिक्षा व स्वास्थ्यरक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सौभाग्य से हमारी जनसंख्या वृद्धि दर में धीमी होने की प्रवृत्ति है। इसकी वृद्धि रोकने के लिए समग्र जनसंख्या रणनीति की तत्काल आवश्यकता है, लेकिन देश के पास ऐसी कोई योजना नहीं है।

लेकिन जनसंख्या नियंत्रण का कोई प्रयास अत्यधिक अलोकप्रिय हो सकता है। श्रीमती इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने इसका प्रयास 1970 के दशक में किया था जिसका नतीजा अंतत: उनकी सत्ता से विदाई था। इससे सभी राजनीतिक पार्टियों ने सबक सीखा। निश्चित रूप से हम चीन नहीं हैं और दबाव डालने वाले कोई कदम नहीं उठाए जाने चाहिए, लेकिन सरकार को सचेतन रूप से परिवार नियोजन को पुरस्कृत करने तथा बड़े परिवारों को दंड देने के प्रयास करने चाहिए। व्यक्तियों व खासकर महिलाओं को प्रजनन स्वास्थ्य व गर्भनिरोध के बारे में सशक्त बनाने के समग्र कार्यक्रम जनसंख्या वृद्धि स्थिर करने में सहायक हो सकते हैं।

इसके साथ ही बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए स्वास्थ्यरक्षा, सफाई, परिवहन और आवास जैसे क्षेत्रों में ज्यादा निवेश आवश्यक है। पर्यावरण क्षरण की भरपाई के लिए टिकाऊ विकास व्यवहार अपनाए जाने चाहिए। जनसंख्या वृद्धि के प्रभावी प्रबंधन के लिए रोजगार सृजन भी महत्वपूर्ण है। उद्यमिता को बढ़ावा देने, निवेशों को आकर्षित करने तथा छोटे एवं मझोले उद्यमों के विकास में सहायता के लिए नीतियां बनाई जानी चाहिए। इनसे रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। जेंडर समानता तथा महिला सशक्तीकरण की ऐसी पहलों की आवश्यकता है जो शिक्षा, स्वास्थ्यरक्षा तथा आर्थिक अवसरों को प्रोत्साहन दें। सशक्त महिलायें परिवार नियोजन के बारे में सूचनाओं के आधार पर पसंद निर्धारित करती हैं जिनसे परिवार छोटा रखने तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य बेहतर रखने में सहायता मिलेगी। इस बारे में समाधानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सवाल है कि इनको लागू कौन करेगा?

मजबूत भारत-ईरान संबंध

भू-राजनीतिक जटिलताओं के बीच भारत ईरान, इज़राइल तथा अपने देश की आवश्यकताओं के बीच नाजुक संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है।

भूपिंदर सिंह
(लेखक, सेवानिवृत्त सेनाधिकारी हैं)

भारत और ईरान के बीच मजबूत ऐतिहासिक संबंध हैं। वर्तमान समय में भारत भू-राजनीतिक जटिलताओं के बीच भारत ईरान, इज़राइल तथा अपने देश की आवश्यकताओं के बीच नाजुक संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है। फारस और हिंदुस्तान, यानी भारत के बीच बहुत प्राचीन काल से सभ्यतामूलक संबंध बने हुए हैं। ईरान में 1979 में हुई 'इस्लामी क्रांति' तथा उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला रोहुल्ला खुमैनी के शासनकाल में भी भारत के साथ मजबूत संबंध बने रहे। खुमैनी के परदादा सैयद अहमद मुसावी 'हिन्दी' का जन्म लखनऊ के निकट किंतूर में हुआ था। हालांकि, कुछ कारणों से सैयद अहमद मुसावी ने अवध छोड़ दिया और वे खुमैन में बस गए, पर फारस में वे 'हिन्दी' के नाम से लोकप्रिय बने रहे। बाद में रोहुल्ला खुमैनी ने 'हिन्दी' तखल्लुस से कवितायें लिखीं जो बहुत लोकप्रिय हुईं। भारत में भी अनेक शिया वंश-परिवार फले फूले जो शरणार्थी के रूप में यहां आए थे। अरब-सुन्नी शासकों के उत्पीड़न से स्वयं को बचा कर भारत आने वाले शिया परिवार दकन, रामपुर, अवध और बंगाल, आदि स्थानों पर बसे और खूब फले-फूले।

उस समय लखनऊ भारतीय शियाओं के गढ़ के रूप में विकसित हुआ था। मध्यपूर्व से एकदम उलट भारत में नस्ली तनाव तुलनात्मक रूप से बहुत कम थे। गिलगिट एजेंसी के गजेटियर के अनुसार, 'सुन्नी और शिया जहां एकसाथ रहते थे, वे परस्पर सहिष्णुता की भावना अपनाते थे जो अन्य इस्लामी समुदायों में बहुत विरल चीज थी। चिलाज़ और सिंधु घाटी के अलावा आमतौर से यहां कट्टरता का पूर्ण अभाव है।'
लेकिन बाद में समय बदलने के साथ कट्टर नस्लवादियों के लेखन से समाज में कट्टरपंथ का उदय हुआ। इस कारण खूनी टकराव तथा ध्रुवीकरण ने जन्म लिया। जल्द ही भारत में भी संख्याबल में कम होने के कारण शिया लोगों को काफी अधिक संख्या वाली सुन्नी जनसंख्या से उत्पीड़न झेलना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप केवल लखनऊ व कारगिल जैसे क्षेत्रों में शिया बहुसंख्य रहे, जबकि अन्य क्षेत्रों में सुन्नियों ने उन पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया।

पड़ोसी पाकिस्तान में भी 'शियाफोबिया' को बहुत बढ़ावा मिला। इसके साथ ही सुन्नी-शिया विभाजन जल्द ही पूरी दुनिया में फैल गया। इसने उस समय राजनीतिक-संप्रभु रंग भी धारण कर लिया, जब ईरान ने विश्व स्तर पर शियाओं की संवेदनाओं तथा उनके अनेक देशों में उत्पीड़न को अपना स्वर दिया। इस व्यापक उथलपुथल के कारण 'उम्मा' या मुस्लिम दुनिया नस्ली आधार पर दो 'समूहों' में विभाजित हो गई। इसके साथ ही शिया-सुन्नी मिश्रित जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ईरान बनाम अरब शेख शासनों की अंतर्निहित भावनाओं ने खुलेआम हिंसक झड़पों का रूप लेना शुरू कर दिया। इन क्षेत्रों में लेबेनान, यमन, सीरिया, बहरीन, पाकिस्तान तथा यहां तक कि भारत भी शामिल हो गया। हालांकि, भारत में शिया-सुन्नी नस्ली तनाव व टकराव अन्य देशों की तुलना में ज्यादा तीखे नहीं हो पाए। भारत में तुलनात्मक रूप से अधिक सुरक्षा, स्वतंत्रता तथा शियाओं के फलने-फूलने पर ईरान की जनता तथा तेहरान के शासकों ने भी गौर किया। हालांकि, भारत में भी अन्य इस्लामी देशों की तरह सुन्नी जनसंख्या की तुलना में शिया बहुत छोटे अल्पसंख्यक हैं, लेकिन भारत में उनको पूर्ण स्वतंत्रता तथा विकास और अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक व्यवहारों के पालन के अवसर मिले हैं। आधुनिक समय में भारत शियाओं के लिए एक 'विरल स्वर्ग' बना रहा। इस कारण ईरान ने अक्सर आर्गेनाइजेशन आफ इस्लामिक कोआपरेशन-ओआईसी जैसे अनेक मंचों पर भारत-समर्थक दृष्टिकोण अपनाया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक शियाओं का भविष्य खासकर संकट में है। इसे तेहरान ने स्वाभाविक रूप से भू-राजनीतिक स्तर पर दिल्ली-समर्थक दृष्टिकोण अपनाया है। 'शीत युद्ध' के दौरान अरब शेख खासकर पाकिस्तान के निकट थे, ऐसे में ईरान ने प्रतिक्रिया में भारत के साथ गहरे संबंध स्थापित किए। लेकिन 'ईरानी क्रांति' के अपरिहार्य परिणाम के रूप में ईरान ने ज्यादा शुद्धतावादी दृष्टिकोण अपनाया तथा उसने सऊदी-नीत शेख शासनों समेत मुस्लिम उम्मा के नेतृत्व से संबंध सुधारने के प्रयास किए।
इसके कारण कभी-कभी कश्मीर जैसे मुद्दों पर ईरान के दृष्टिकोण में विरोधाभास दिखाई पड़े। लेकिन वैश्विक स्थितियों तथा शिया-सुन्नी सबंधों की जटिलता ने सुनिश्चित किया कि अनेक संवेदनशील मुद्दों पर ईरान और भारत एक ही पाले में खड़े दिखे। इनमें अफगानिस्तान प्रमुख है जहां दोनों देशों ने पाकिस्तान-नीत तालिबानी बलों का विरोध किया। लेकिन इसी समय भारत अमेरिका और इज़राइल के साथ अपने संबंध सुधार कर उनको रणनीतिक संबंधों में विकसित कर रहा था। वाशिंगटन और तेलअबीब के साथ दिल्ली के बढ़ते संबंधों के कारण भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया जिसके पीछे अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए प्रतिबंध भी थे। इसके साथ ही चाबहार बंदरगाह जैसी रणनीतिक परियोजनायें भी प्रभावित हुईं। इसके बावजूद दिल्ली और तेहरान के बीच एक अघोषित समझदारी हमेशा बनी रही है जिसके कारण द्विपक्षीय विश्वास तथा इरादों पर कभी सवाल नहीं उठे हैं।

भारत में 'बहुसंख्यकवादी' राजनीति के उभार से स्वाभाविक रूप से उम्मा में चिन्ता पैदा हुई, हालांकि शेख शासक विश्व मंच पर भारत के उभरने का स्वागत करते हुए उससे संबंध मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ ही शियाओं के लिए स्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है क्योंकि सत्तारूढ़ राजनीतिक अवस्थापना सक्रिय रूप से शियाओं को अपने साथ जोड़ रही है। 2014 व 2019 के आम चुनाव में लखनऊ के प्रमुख शिया नेताओं ने सक्रिय रूप से विजेताओं का समर्थन किया। ईरान ने इस परिघटना पर भी अच्छी तरह गौर किया क्योंकि वह दुनिया भर में शियाओं के प्रति अति-संवेदनशील है। जहां तक शियाओं के साथ व्यवहार का सवाल है, भारत एक 'सम्माननीय अपवाद' बना हुआ है। इस असंदिग्ध यथार्थ ने नई दिल्ली को शेख शासकों की राजधानियों तथा तेलअबीब के साथ समानान्तर व अभूतपूर्व संबंध बनाने में सहायता की है। हालांकि, आज जब इज़राइल-फिलिस्तीन युद्ध ईरान को भी अपने दायरे मे घसीट रहा है तब नई दिल्ली के लिए अपना पक्ष चुनना कठिन हो सकता है। हालांकि, रूस-यूक्रेन युद्ध की तरह इस मामले में भी 'रणनीतिक स्वतंत्रता' का दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। इससे भारत नैतिक रूप से टकराव से दूर रह कर व्यावहारिक रूप से एक सौम्य-बयानबाजी वाली स्थिति अपना सकता है। इससे कोई आहत नहीं होगा और वास्तव में शांति की तलाश की संभावनायें बनी रहेंगी।

दिल्ली अच्छी तरह जानती है कि इस टकराव के प्रति भारतीय मुसलमानों व खासकर ईरान का मामला आने पर शियाओं की भावनायें क्या हैं। चुनावी दृष्टिकोण से अवस्थापना शियाओं व पसमांदा मुसलमानों को साथ लेना चाहता है, लेकिन इज़राइल के कारण पूरे मामले में जटिलता पैदा होती है। इससे 'बहुसंख्यकवादी' सोच भी प्रभावित होती है जो वैचारिक रूप से वैश्विक-इस्लामवाद का मुकाबला कर रही है। इज़राइल का अक्सर जरूरत से ज्यादा समर्थन किया जाता है तथा उसकी प्रशंसा की जाती है। लेकिन अब यह नैतिक रूप से अप्रासांगिक होता जा रहा है। मजेदार बात है कि इज़राइल और ईरान, दोनों के तर्कों और विमर्शों में अनेक ऐसे तथ्य हैं जो भारत की 'व्यापक मजबूरियों' को उचित ठहराने के काम आ सकते हैं। भारत ने ईरान, फिलिस्तीन तथा इज़राइल के साथ औपचारिक राजनयिक संबंधों के अलावा शक्तिशाली 'बैक चैनल' या परोक्ष संबंध भी स्थापित किए हैं। इन शक्तिशाली बैकडोर चैनलों तथा भारत-ईरान के बीच गहरे ऐतिहासिक सभ्यतामूलक संबंधों का लाभ उठाते हुए सुनियोजित ढंग से राजनयिक प्रयास करने की आवश्यकता है। विश्व मंच पर भारत के कद तथा उसकी भावी रणनीति के साथ ही भारत-ईरान संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है कि भारत विभिन्न पक्षों के साथ संबंधों के बजाय विश्व शांति को प्राथमिकता दे।

भ्रष्टाचार और राजनीतिक पालाबदल

> धार्मिकता के सिद्धांतों के बजाय चुनावी अंकगणित, अक्सर राजनीतिक निर्णयों की दिशा तय करती है।

अतुल सहगल
(लेखक, प्रबंध सलाहकार हैं)

पिछले सप्ताह, भारत के एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र की सामग्री पढ़ते समय, एक दिलचस्प लेख ने मेरा ध्यान खींचा और इसे पूरे समय पढ़ने के लिए बाध्य किया। लेख का शीर्षक था - 2014 के बाद से, भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेता भाजपा में शामिल हो गए, उनमें से 23 को राहत मिली। निस्संदेह, यह लेख हमारे देश में प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था की खामियों पर एक स्पष्ट टिप्पणी थी। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट तथ्य का एक शर्मनाक विवरण था कि सभी रंगों और रंगों के राजनीतिक दल हमारी राजनीतिक प्रणाली में दोष रेखाओं द्वारा उत्पन्न ज्वार के साथ बहने के लिए मजबूर हैं और वह भी कभी-कभी केवल राजनीतिक अस्तित्व के लिए।

उपरोक्त विवरण की बारीकियों में गहराई से जाना और पवित्र राजनीतिक दलों और व्यक्तित्वों के बारे में बेशर्मी से आलोचना करना उचित नहीं होगा। भारत में मौजूदा व्यवस्था की कमियों पर ध्यान देना और अफसोस के साथ यह कहना उचित प्रतीत होता है कि चुनावी अंकगणित हमारी राजनीतिक व्यवस्था का सबसे बड़ा अभिशाप है। मायावी बहुमत जुटाने के लिए राजनीतिक दलों को खामियों से भरी कानूनी व्यवस्था के तहत स्थिर सरकारें बनाने और यहां तक कि सुचारु रूप से शासन कर सकने वाली मजबूत सरकारें बनाने के लिए संख्याएं जुटाने के लिए ऐसे हथकंडों का सहारा लेना पड़ता है।

हमारे लोकतंत्र में निश्चित कमियाँ हैं। बल्कि यह बिल्कुल सही नहीं है। बहुदलीय लोकतंत्र को लोकतंत्र के गैर-आदर्श, कमजोर रूप के रूप में वर्णित करना बेहतर है, खासकर हमारे जैसे सांस्कृतिक रूप से भिन्न समाज में। लोकतंत्र का सबसे शुद्ध रूप हमारे प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति में उल्लिखित है। मनुस्मृति का उल्लेख करते समय यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि इस अवलोकन को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, भले ही इस प्राचीन ग्रंथ से कोई विवाद जुड़ा हो। बेईमान व्यक्तियों द्वारा ऐतिहासिक व्याख्याओं के कारण वह विवाद अपने विकृत संस्करण से उत्पन्न हुआ। मनुस्मृति का मूल, अभ्रष्ट संस्करण एक आदर्श शासन व्यवस्था का दिव्य खाका है। धर्मग्रंथ लोकतंत्र की बात करता है जो लोकतंत्र (प्रजातंत्र) की निम्नलिखित तीन विशिष्ट विशेषताओं का संकेत देता है- चुनाव और शासन की दलविहीन प्रणाली, मतदाताओं द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार, धार्मिकता या धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप। यहां यह बताना भी प्रासंगिक होगा कि उपरोक्त आदिम, ईश्वरीय ग्रंथ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए एक संरचनात्मक ढाँचा भी प्रदान करता है। यह तीन सभाओं की बात करता है - राजर्यसभा (कार्यकारी सभा), विद्यार्यसभा (विषय विशेषज्ञ सभा) और धर्मार्यसभा (धार्मिक विशेषज्ञों की सभा)। अंतिम उल्लिखित सभा या परिषद प्रतिष्ठित नैतिक प्रतिष्ठा और त्रुटिहीन चरित्र वाले व्यक्तियों से बनी है जो कार्यकारी परिषद के कामकाज पर एक प्रकार के नैतिक अधिकार के रूप में सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। यह देखना आसान है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मौजूदा राजनीति और शासन संरचना उपर्युक्त आदर्श राजनीति और शासन प्रणाली से कितनी दूर है। एक दलीय कम लोकतांत्रिक राजनीति में, चुनावी अंकगणित की सभी समस्याएं और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली बुराइयां गायब हो जाएंगी। कोई बड़ी चुनावी रैलियां नहीं होंगी, चुनावों पर कोई भारी खर्च नहीं होगा, कोई खरीद-फरोख्त नहीं होगी, कोई पार्टी नहीं बदलेगी, कोई दलबदलू नहीं होगा, भ्रष्ट और अपराधी राजनेताओं पर मुकदमा चलाने में कोई देरी नहीं होगी और बहुसंख्यकवाद या अल्पसंख्यकवाद की कोई मूर्खतापूर्ण अवधारणा नहीं होगी।

कोई अल्पसंख्यक-केंद्रित शासन नहीं होने जा रहा है। यह समझना भी मुश्किल नहीं है कि अगर हम पवित्र ग्रंथ मनुस्मृति के सिद्धांतों को अपनी राजनीति और शासन में शामिल कर लें तो हमारे देश में मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था की कितनी माध्यमिक बुराइयां खत्म हो जाएंगी। यह उम्मीद करना दूर की कौड़ी हो सकती है कि हम वर्तमान प्रणाली से उपरोक्त यूटोपियन संरचना के अनुरूप कुछ बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें अपने देश में पार्टी रहित लोकतांत्रिक प्रणाली जैसी एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताओं को शामिल करते हैं, तो भी हमारे शासन को बहुत लाभ हो सकता है। .ऊपर जो कहा गया है, उसके आलोक में, हमें निश्चित रूप से अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है जो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देती है।

तदनुसार, हम आशा करते हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार व्यापक संवैधानिक, चुनावी और नौकरशाही सुधार लाएगी ताकि हमारा देश कंगारू छलांग लगाकर प्रगति कर सके, जिसमें वह सक्षम है। विश्व के नैतिक और आध्यात्मिक पथप्रदर्शक के रूप में अपने प्राचीन कद को बनाए रखते हुए, भारत विश्व का अग्रणी वैश्विक राष्ट्र-राज्य बनने के लिए दैवीय रूप से नियत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत संतों, संतों और द्रष्टाओं की भूमि है जो इस ग्रह पर अपने लंबे और उतार-चढ़ाव वाले ऐतिहासिक अस्तित्व के दौरान मानवता के लिए प्रकाशस्तंभ रहे हैं।

आप की बात

गहलोत की समझ

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा के संकल्प पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि 2019 और 2014 में जो स्थितियां थीं वे अब बदल गई है, भाजपा विश्वसनीयता खो चुकी है, वे कब तक पीएम मोदी के नाम पर राजनीति करते रहेंगे? गहलोत को समझना चाहिए कि मोदी काल को अभी 10 बरस हुए हैं, कांग्रेस जैसे 70 साल नहीं जिसने परिवारवाद के नाम पर इतने बरस राज करते-करते निकाल दिए। लेकिन अब इसी परिवारवाद के चलते कांग्रेस की हलात लगातार खराब होती जा रही है। कांग्रेस के अच्छे-अच्छे सूरमां पार्टी छोड़ कर अन्य पार्टियों में किस्मत आजमाने जा रहे हैं। भाजपा परिवारवादी नहीं, सुधारवादी दृष्टिकोण वाली पार्टी है। भाजपा के प्रति जनता की विश्वसनीयता बढ़ी है, जबकि कांग्रेस की घटती जा रही है। कांग्रेसियों को अपने आप से पूछना चाहिए कि देश की आजादी की लड़ाई से जन्मी कांग्रेस आखिर लगातार अविश्वसनीय क्यों होती जा रही है? कांग्रेस को अब क्षेत्रीय दल भी कुछ नहीं समझते हैं। इसी कारण इस बार कांग्रेस ऐतिहासिक रूप से सबसे कम लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। गहलोत को यह भी समझ लेना चाहिए कि अब आम जनता उनके जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के बयानों पर भी जल्दी से विश्वास करने नहीं जा रही है।

-**शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

ईवीएम पर विवाद

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा कि मतपत्रों द्वारा वोटिंग किए जाने की मांग के पीछे छिपी असलियत वे जानते हैं। पिछली बार जब ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग पर दबाव बनाया गया तो चुनाव आयोग ने सभी विपक्षी दलों को चुनौती दी थी कि वे किसी भी विशेषज्ञ को लाकर ईवीएम हैक कर कर दिखाएं। तब किसी भी दल ने यह चुनौती स्वीकार नहीं की थी। जाहिर है ईवीएम शत-प्रतिशत दोष रहित आधुनिक वोटिंग मशीन है। जिस देश में 97 करोड़ मतदाता हों वहां पर मतदान में यदि अपनी आसन्न पराजय को देखकर कुछ राजनीतिक दल ईवीएम और वीवीपैट पर्ची के शत-प्रतिशत मिलान की मांग करते हैं तो वह भी अव्यावहारिक है। चुनाव आयोग कुछ स्थानों की मशीनों से वीवीपेट का मिलान करके उसकी प्रामाणिकता जांच लेते हैं। शत-प्रतिशत वीवीपैट से मिलान की मांग वैसी ही है। जैसे कोई चावल पकने के परीक्षण के लिए पतीले के सभी चावलों की परीक्षा की बात करे। चुनाव परिणाम में पराजय को मतदाताओं का आदेश न मानकर ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ना और जीतने पर चुपचाप सत्ता भोगना अतार्किक और अनुचित है।

- **सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

राहत की बात

मतदान से पहले छत्तीसगढ़ में हमारे सुरक्षा वालों ने जिस तरह से नक्सलियों का सफाया किया वह बड़ी राहत देने वाली बात है। अक्सर चुनाव के समय नक्सली न केवल चुनाव बहिष्कार का आह्वान करते हैं, बल्कि दूसरों को आम चुनाव में वोटिंग नहीं करने देते हैं। छत्तीसगढ़ में कांकेर जिला नक्सलियों का बड़ा गढ़ कहलाता है। इस आपरेशन की सफलता के बाद देश के अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी ऐसे ही अभियान फौरन चलाए जाने चाहिए ताकि नक्सली किसी प्रकार मतदान को प्रभावित न कर सकें। विश्वास है कि लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर एक बड़ा अभियान नक्सलवाद के खिलाफ अवश्य चलाएंगे। नक्सलवादी हमेशा ही इस क्षेत्र के विकास में बड़ी बाधा बनते हैं एवं क्षेत्र की आम जनता को भी दहशत में रखते हैं। अक्सर चुनाव के समय नक्सलवादी मतदान में बाधा डाल कर अपना लोकतंत्र-विरोधी विमर्श आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। स्थानीय स्वशासी संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, शिक्षकों, राजस्व कर्मचारियों तथा आम जनता को विकास संबंधी मुद्दों में पारदर्शिता बरतने तथा उनको विचार-विमर्श में शामिल कर नक्सलियों की कमर तोड़ने के कदम स्थाई रूप से उठाए जाने चाहिए।

- **एमएम राजावत,** शाजापुर

नक्सल समस्या

नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद देश की तीन बड़ी समस्याएं हैं जो आए दिन सिर उठाती रहती है। कदम-कदम पर मौत बिछी होने के बावजूद हमारे जवान नक्सली आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। लगातार जवाबी कार्यवाही से नक्सली घटनाओं में कमी अवश्य आई है, तथापि दहशत अभी भी कायम है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में कई बड़े ईनामी नक्सलियों के साि 29 नक्सलियों का सफाया कर दिया है। यह नक्सल-विरोधी अभियान में मारे जाने वाले नक्सलियों की संख्या के दृष्टिकोण से दूसरा सर्वाधिक सफल आपरेशन है। हालांकि, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सुरक्षा बलों के नौजवानों की प्रशंसा की श लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनके पिछले पांच साल के शासनकाल में राज्य में नक्सली आंदोलन फला-फूला तथा नक्सल समस्या और गंभीर हुई। नक्सल समस्या समाप्त करने के लिए जमीनी स्तर पर आदिवासियों में विकास और प्रगति के प्रति विश्वास मजबूत करना भी जरूरी है। विकास को जमीन तक पहुंचाना जरूरी हो गया है।

-**अमृतलाल मारू,** इन्दौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 55

बहुतायत की समस्या

जानकारी के मुताबिक वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद एक पैनल के गठन पर विचार कर रही है ताकि डेरिवेटिव (वायदा एवं विकल्प) कारोबार की अधिकता से उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों का अध्ययन किया जा सके। वायदा एवं विकल्प या फ्यूचर और ऑप्शन कारोबार में तेज उछाल और इसमें खुदरा भागीदारी में इजाफे ने शायद व्यवस्था के लिए जोखिम बढ़ा दिया हो और अगर बड़े स्तर के उतार-चढ़ाव हुए तो इसके संक्रामक प्रभाव भी हो सकते हैं। हालांकि जो थोड़ी-बहुत जानकारी है, उसके मुताबिक पैनल शायद खुदरा डेरिवेटिव कारोबारियों और उनकी मार्जिन फंडिंग के संभावित स्रोत पर ध्यान दे सकता है। वह इस संभावना की भी जांच करेगा कि क्या लोग व्यक्तिगत ऋण का इस्तेमाल इस प्रकार की ट्रेडिंग में मार्जिन की रकम के लिए कर रहे हैं। डेरिवेटिव ट्रेडिंग के मामले में भारत अन्य देशों से अलग नजर आता है। देश में न केवल वायदा एवं विकल्प में सबसे ज्यादा कारोबार होता है बल्कि यहां डेरिवेटिव कारोबार की मात्रा का अनुपात भी नकद इक्विटी कारोबार की मात्रा की तुलना में खतरनाक रूप से बढ़ा हुआ है। भारतीय बाजार का सांकेतिक कारोबार नकद इक्विटी बाजार का 400 गुना से अधिक है। यह दूसरे बड़े उन वित्तीय बाजारों के उलट है जहां यह अनुपात आमतौर पर 10 से 15 गुना है।

वॉल्यूम का अधिक आकार खुदरा कारोबारियों की बढ़ती संख्या की वजह से है। इससे यह संभावना बनती है कि कारोबार का रिश्ता असुरक्षित ऋणों से हो सकता है। अगर यह सही है तो इससे भारी जोखिम की स्थिति बनती है और व्यापक वित्तीय क्षेत्र में संक्रमण फैल सकता है। 2023-24 में वायदा एवं विकल्प कारोबार का टर्नओवर एक साल पहले की तुलना में दोगुना हो गया। 2023 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक 10 में से नौ खुदरा निवेशकों को वित्त वर्ष 2022 में पैसा गंवाना पड़ा। यह नुकसान प्रति कारोबारी 1.1 लाख रुपये का रहा। चूंकि खुदरा भागीदारी बढ़ी है और कारोबार का आकार 2022 से दोगुना से अधिक हो चुका है इसलिए अब प्रति व्यक्ति नुकसान भी अधिक होने की संभावना है। नियामक को संदेह है कि कई खुदरा कारोबारी ऊंची ब्याज दर पर असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण लेते हैं ताकि फ्यूचर और ऑप्शन कारोबार के लिए जरूरी मार्जिन दिया जा सके। यह चलन खासतौर पर उन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में हो सकता है जिनकी अपनी ब्रोकरेज शाखा होती है और कई मामलों में ऐसी कंपनियां बैंकों से ऋण लेती हैं। यदि ऐसा मामला है तो जब कभी फ्यूचर और ऑप्शन में भारी उतार-चढ़ाव हुआ तो पूरे वित्तीय तंत्र के लिए बड़ा जोखिम खड़ा हो सकता है।

फ्यूचर कारोबार में जहां कोई संपति निर्मित या नष्ट नहीं होती है वहीं ऑप्शन कारोबार के साथ ऐसी बात नहीं है। ऑप्शन विक्रेता को असीमित नुकसान हो सकता है। यह भी संभव है कि औसत खुदरा विक्रेता नुकसान का बचाव करने में बहुत कुशल न हो। अगर खुदरा कारोबारी ऊंची ब्याज दर पर मार्जिन फंडिंग के लिए ऋण लेते हैं तो उन्हें अधिक नुकसान होगा। इसका कर्जदाताओं पर भी बुरा असर होगा। बहरहाल, सेबी ने जोखिम के स्तर का आकलन करने की कोशिश की लेकिन वह उपाय कारगर नहीं रहा। इसे निजता का उल्लंघन भी माना गया। नियामक ने खुदरा डेरिवेटिव कारोबारियों की कुल संपत्ति का आकलन करने का प्रयास किया ताकि व्यवस्थागत जोखिम के स्तर का आकलन करके व्यक्तिगत कारोबारियों की विशुद्ध संपत्ति के आधार पर उनकी सीमा तय की जा सके। भले ही यह विचार कारगर नहीं रहा हो लेकिन प्रस्तावित पैनल जोखिम कम करने के लिए बेहतर तरीके निकाल सकता है। वह वायदा एवं विकल्प क्षेत्र में अत्यधिक कारोबार की वजह का भी पता लगा सकता है। इस क्षेत्र के बारे में और अधिक आंकड़े तथा समग्र विश्लेषण मददगार साबित होगा। नियामक के लिए भी बेहतर होगा कि वह जागरूकता कार्यक्रम चलाए।

मानव विकास को प्राथमिकता जरूरी

केंद्र सरकार मानव विकास को बढ़ावा देना चाहती है तो उसे संघात्मक ढांचे को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने देना चाहिए। बता रहे हैं नितिन देसाई

संभावना जताई जा रही है कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित देशों की सूची में जगह बना लेगा। इस विषय पर चर्चा भी जमकर हो रही है। परंतु, विकसित देश बनने की प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए भारत को विकास से संबंधित अपनी नीतियों में कई बदलाव करने होंगे। विकास नीति के अंतर्गत जिन दो प्रमुख खंडों में बड़े बदलावों की आवश्यकता है वे हैं मानव विकास – विशेषकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य- और तकनीकी नवाचार। कुछ मायनों में दूसरा खंड काफी हद तक पहले खंड पर निर्भर है और इसलिए मैं यहां मानव विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की हिस्सेदारी साधारण थी। सकल मूल्य वर्द्धन में इनका हिस्सा क्रमशः 4 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत था। अगर हम भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं तो यह स्थिति बदलनी होगी। शिक्षा एवं स्वास्थ्य न केवल आर्थिक वृद्धि लिए आवश्यक हैं बल्कि विकास लक्ष्यों का आवश्यक हिस्सा भी हैं। विकास के लक्ष्यों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता भी शामिल की जानी चाहिए।

आर्थिक वृद्धि दर और मानव विकास के कुछ मानकों के बीच आपसी संबंध यह नहीं बताता है कि ऊंची आर्थिक वृद्धि बेहतर मानव विकास सुनिश्चित करती है या फिर मानव विकास बेहतर होने से आर्थिक वृद्धि की गति तेज हो जाती है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए अधिक सावधानी पूर्वक आंकड़ों के विश्लेषण की आवश्यकता होगी।

जनक राज, वृंदा गुप्ता और आकांक्षा श्रवण ने हाल में अपने एक आलेख में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा निर्धारित मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) और 1990-2019 के दौरान राज्य स्तरीय आर्थिक विकास के बीच संबंध का विश्लेषण किया गया है। उनके विश्लेषण में एचडीआई और भारत में आर्थिक विकास के बीच दीर्घ अवधि के संबंध का जिक्र किया गया है। परंतु, कारण एवं प्रभाव के संदर्भ में यह संबंध दो दिशाओं वाला है। इसका अभिप्राय यह है कि त्वरित वृद्धि के लिए उच्च मानव विकास जरूरी है और मानव विकास के स्तर में सुधार के लिए आर्थिक वृद्धि भी उतनी ही आवश्यक है। वे शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय से एचडीआई पर होने वाले प्रभाव का स्पष्ट आकलन नहीं कर पाए। शिक्षा के प्रभाव के विश्लेषण से पता चलता है कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार का अंतर-राज्यीय स्तर पर वृद्धि में भिन्नता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। मगर माध्यमिक शिक्षा में सुधार का असर क=षि एवं विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि पर पड़ता है। इसके अलावा, उच्च शिक्षा में सुधार का सेवाओं पर भी व्यापक असर होता है।

तो क्या सार्वजनिक व्यय अधिक कारगर नहीं रहने का कारण पर्याप्त वित्त पोषण की कमी हो सकता है? विश्व बैंक के विकास सूचकांकों के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में शिक्षा पर खर्च सरकार के कुल व्यय का 14.7 प्रतिशत रहा था। यह आंकड़ा निम्न मध्यम-आय वाले देशों से मेल खाता है। हालांकि, 2018 में स्वास्थ्य पर खर्च सरकार के कुल व्यय का 3.5 प्रतिशत था। यह निम्न मध्यम-आय वाले देशों के 5.1 प्रतिशत से कम रहा था। शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च केंद्र एवं राज्य सरकारों के व्यय पर कितना निर्भर है? राष्ट्रीय लेखा क्षेत्र द्वारा चिह्नित 'अन्य सेवाओं' में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की लगभग 80 प्रतिशत भागीदारी होती है। 'अन्य सेवाओं' में सार्वजनिक क्षेत्र की सकल नियत पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में 17 प्रतिशत भागीदारी थी और 83 प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्र एवं परिवारों से आया। सरकार की तरफ से की गई अनदेखी इस बात से झलकती है कि वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के जीएफसीएफ में 'अन्य सेवाओं' की हिस्सेदारी केवल 5.9 प्रतिशत थी।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में दिखे नतीजे निराशाजनक रहे हैं। 'एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन' शीर्षक से 'प्रथम' की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 से 18 वर्ष के उम्र दायरे में आने वाले लगभग 25 प्रतिशत छात्र कक्षा 2 की पुस्तक ठीक ढंग से अपनी क्षेत्रीय भाषा में नहीं पढ़ पाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार लगभग आधे बच्चे भाग (तीन अंकों की संख्या को एक अंक की संख्या से भाग) देने में कठिनाई महसूस करते हैं। कम उम्र के छात्रों में गुणवत्ता से जुड़ी समस्या दयनीय है। यह रिपोर्ट 14-18 वर्ष के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करती है।

जहां तक स्वास्थ्य क्षेत्र में दिखे प्रभावों की बात है तो कुछ सकारात्मक असर दिखे हैं, मसलन शिशु मृत्यु दर में कमी इसका एक उदाहरण है। परंतु बच्चों में पोषण में कमी और संक्रामक बीमारियों का प्रसार लगातार जारी रहना चिंता के दो प्रमुख कारण हैं। गरीब लोगों के लिए अपर्याप्त सार्वजनिक प्रावधान एक गंभीर त्रुटि है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान स्वास्थ्य व्यय में परिवारों को अपनी जेब से 52 प्रतिशत हिस्से का भुगतान करना पड़ता है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर निःशुल्क दवाओं का पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है। उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर हाल में किए गए एक ताजा अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि 2011-12 में लगभग 4.6 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य मद में भारी भरकम रकम खर्च करनी पड़ी। यह रकम उनके कुल खर्च का 10 प्रतिशत या इससे अधिक हो गई। ये खर्च गंभीर बीमारियों के इलाज पर हुए। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में लोगों को उत्पादक परिसंपत्तियां बेचनी पड़ीं और रकम उधार लेनी पड़ी। इतना ही नहीं, उन्हें बच्चों की शिक्षा पर खर्च में कटौती तक करनी पड़ी। मानव विकास में व्यापक सुधार ऊंचे एवं अच्छी तरह संगठित सार्वजनिक व्यय और शिक्षा एवं स्वास्थ्य विकास में निजी गतिविधियों के संवर्द्धन एवं नीति नियमन पर निर्भर करेगा।

लोक नीतियों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं पर व्यय का मुख्य लक्ष्य लोगों के जीवन में बदलाव लाने पर होना चाहिए न कि आर्थिक प्रभाव पर। मुख्य ध्यान गरीब परिवारों की जेब से होने वाले खर्च में कमी करने पर होना चाहिए। वास्तव में गरीबों की हालत तब और तंग हो जाती है जब उन्हें इलाज के लिए अपने गांव या छोटे शहरों से दूर जाना पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति एक ऐसे व्यापक दृष्टिकोण के आर्थिक प्रभाव भी दिखेंगे जो पर्यावरण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। मुझे स्मरण है कि एक पोषण विशेषज्ञ ने योजना आयोग (अब नीति आयोग) को सलाह दी थी कि पूरक खाद्य आपूर्ति की तुलना में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति पोषण में सुधार का अधिक विश्वसनीय जरिया हो सकती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तो इसके सकारात्मक आर्थिक प्रभाव भी दिखेंगे। पंजाब के एक मशहूर अर्थशास्त्री ने तर्क दिया था कि राज्य में कृषि के विकास में मलेरिया उन्मूलन का बड़ा योगदान रहा है।

देश में स्कूल और कॉलेज तेजी से स्थापित हो रहे हैं। अब इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा के तेजी से प्रसार की आवश्यकता है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की चुनौती जरूर है मगर राजनीतिक कारणों से पाठ्यक्रमों में बदलाव की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए सार्वजनिक एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों के प्रदर्शन की समीक्षा की जरूरत होगी। अगर प्रथम जैसी गैर-सरकारी संस्था प्रदर्शन की समीक्षा की दिशा में काम कर सकती है तो सरकार क्यों नहीं इसके लिए एक व्यापक प्रणाली स्थापित कर सकती है? उच्च शिक्षा में सुधार के लिए लीक से हटकर एक कदम यह हो सकता है कि हम संस्थाओं को अनुदान देने की प्रणाली से हटकर छात्रों को अनुदान या ऋण देने की पद्धति अपनाएं (और विशेष अधिकार प्राप्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को समाप्त किया जाए)। हम छात्रों को पढ़ाई की गुणवत्ता के आधार पर शिक्षण संस्थान चुनने की स्वतंत्रता दी जाए।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर अधिक जोर दिए जाने के लिए राज्यों के द्वारा बड़े एवं भिन्न नवाचार उपाय किए जाने की जरूरत है क्योंकि कमजोर प्रदर्शन का मूल कारण अलग-अलग हो सकता है। वैसे भी शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर केंद्र सरकार का व्यय राज्यों की तुलना में काफी कम है, विशेषकर तब जब वर्तमान एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर होने वाला व्यय घटा दिया जाए। इसे देखते हुए केंद्र सरकार को संघात्मक ढांचे को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने देना चाहिए। ऐसा करने से ही मानव विकास की रफ्तार तेज होगी जिससे सरकार दीर्घकालिक लक्ष्य प्राप्त कर पाएगी।

मनोरंजन खपत के विभिन्न आयाम

भारत के लोग मनोरंजन पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं या कम खर्च कर रहे हैं? इसका संक्षिप्त जवाब यह है कि शहरी इलाकों की तुलना में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन के खर्च में थोड़ा इजाफा हुआ है जबकि शहरों में यह कम हुआ है।

यह जानकारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए जारी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण से मिली है। यह सर्वेक्षण खाद्य और गैर-खाद्य दोनों तरह की चीजों से जुड़े खर्च पर भी नजर रखता है।

देश के ग्रामीण क्षेत्र में मनोरंजन पर हर महीने किए जाने वाला प्रति व्यक्ति खर्च (एमपीईसी) लगातार बढ़ रहा है और यह 1999-2000 के 0.42 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 0.99 प्रतिशत हो गई। इसके बाद के दशक में यह वर्ष 2022-23 में 1.09 प्रतिशत हो गई। यह इन सालों में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि है।

शहरी क्षेत्रों में एमपीसीई में मनोरंजन का अनुपात वर्ष 1999-2000 में 1.16 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 1.61 प्रतिशत हो गया। इसके बाद से यह घटकर 2022-23 में 1.58 प्रतिशत हो गया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन सहित विविध चीजों पर औसतन 234 रुपये मासिक खर्च किया जाता है जबकि देश के शहरी इलाकों में इस मद में 424 रुपये मासिक खर्च किए जाते हैं।

दरअसल राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने 261,746 घरों का सर्वेक्षण किया जिसमें यह बात स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है कि इस तरह के 'मनोरंजन' में क्या शामिल है। फिल्म, टेलीविजन या स्ट्रीमिंग जैसे अधिकांश मनोरंजन कारोबार में दो तरह से कमाई होती है। विज्ञापनदाताओं को दर्शकों का समय बेचकर विज्ञापन से कमाई की जाती है और इसके अलावा सीधे दर्शकों से शुल्क या सबस्क्रिप्शन शुल्क लेकर कमाई की जाती है।

सर्वेक्षण के आंकड़ों में स्पष्ट रूप से विज्ञापन समर्थित फ्री-टू-एयर या फ्री-टू-व्यू मनोरंजन उपभोग को शामिल नहीं किया जाता है। पिछले साल भारतीय मीडिया और मनोरंजन (एमऐंडई) कारोबार की 2.3 लाख करोड़ रुपये की कमाई में विज्ञापन राजस्व की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत है। यह सर्वेक्षण केवल भुगतान से होने वाली कमाई और संभवतः टेलीविजन, फिल्मों और स्ट्रीमिंग तक सीमित है।

मीडिया मंत्र
वनिता कोहली-खांडेकर

भारत में टेलीविजन सबसे बड़ा मीडिया माध्यम है। इसकी पहुंच लगभग 90 करोड़ लोगों तक है और इसने 2023 में (विज्ञापन और शुल्क मिलाकर) लगभग 69,600 करोड़ रुपये की कमाई की। इस दशक (और पिछले दशक में भी) में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टीवी पर सख्त मूल्य नियंत्रण किया है। इस नियंत्रण का मतलब यह है कि सामान्य महंगाई भी केबल या डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकती है और यह उपभोक्ता से जुड़े डेटा में भी दिखाई देता है।

अधिकांश टेलीविजन प्रसारक डीटीएच और केबल परिचालकों से मोल-तोल के जरिये बेहतर राजस्व हिस्सेदारी की बात कर भुगतान राजस्व बढ़ाते हैं। पिछले तीन वर्षों में, शुल्क वाले टीवी घरों की संख्या अनुमानतः 16.5 करोड़ से घटकर 9 करोड़ हो गई है। यह स्वाभाविक रूप से भुगतान वाली राजस्व वृद्धि को कम कर देता है। फिक्की-ईवाई (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री-अर्नस्ट ऐंड यंग) की रिपोर्ट का यह दावा है कि वर्ष 2023 में टेलीविजन राजस्व 2022 की तुलना में 1.8 प्रतिशत कम हो गया और यह एमपीसीई डेटा के अनुरूप है। इसके संदर्भ के लिए, सिनेमा पर गौर करें। विभिन्न सिनेमाघरों द्वारा दिन, समय, फिल्म आदि के अनुसार कीमतों में बदलाव करने की क्षमता का मतलब यह है कि टीवी के विपरीत, औसत टिकट कीमतें महंगाई के साथ बढ़ी हैं।

टीवी में उद्योग को प्रभावित करने वाले मूल्य नियमन के चलते देश का ग्रामीण क्षेत्र क्यों नहीं प्रभावित हुआ? ऐसा इसलिए है कि ग्रामीण भारत के अधिकांश हिस्सों में, खासतौर पर उत्तरी क्षेत्र की आबादी में, भुगतान वाले टेलीविजन का प्रसार (केबल या डीटीएच के माध्यम से) बहुत कम रहा है। केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में केबल का दखल सबसे अधिक है। इसे पहले से ही 1999-2000 और बाद के वर्षों के आंकड़ों में शामिल कर लिया गया है।

जिस चीज की पहुंच और खपत बढ़ी है वह है मुफ्त वीडियो। इसे पेश करने वाले दो सबसे बड़े मंच, डीडी फ्रीडिश और यूट्यूब हैं जिसने अभूतपूर्व वृद्धि देखी है।

पिछले दशक में, सरकारी मुफ्त डीटीएच सेवा, डीडी फ्रीडिश, टेलीविजन क्षेत्र में सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरी है। अब यह, हिंदी भाषी राज्यों में अनुमानित तौर पर 5 करोड़ घरों (24 करोड़ लोग) तक पहुंच रहा है। डीडी फ्रीडिश के किट में लगभग 1,000-1,200 रुपये का एकमुश्त खर्च शामिल है और इसमें कोई आवर्ती लागत नहीं है। यह पैसा संभवतः ग्रामीण क्षेत्र के मनोरंजन खर्च में नजर आता है।

कॉमस्कोर के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में इंटरनेट पर आने वाले 51 करोड़ अनूठे विजिटरों में से अधिकांश यूट्यूब (जो कि काफी हद तक मुफ्त स्ट्रीमिंग सेवा है) के उपभोक्ता थे। चूंकि यह एक विज्ञापन-समर्थित सेवा है इसलिए केवल डेटा पर पैसा खर्च किया जाता है और यह मनोरंजन के मद में दिखाई नहीं देगा।

आर्थिक विकास की धीमी गति और शहरी क्षेत्र के गरीब इलाके और देश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की फ्री टेलीविजन की सेवाएं लेने का रुझान भी अलग संकेत देता है। अगर इस पहुंच को मापने के लिए उपकरणों की दखल को आधार मानें, तो गरीब, छोटे शहरों और देश के ग्रामीण क्षेत्र का एक बड़ा वर्ग 2020 से शुरू होकर दो साल से ज्यादा समय से मुश्किल दौर में था। इस अखबार में पहले भी बताया गया है कि इसी दौर में इंटरनेट की पहुंच स्थिर हो गई थी।

ऐसा इसलिए हुआ कि महामारी के दौरान और बाद में, स्मार्टफोन की कीमतें चिप की कमी के कारण लगातार बढ़ती रहीं जो भारत में एक बड़े वर्ग के लिए इंटरनेट तक पहुंच बनाने का मुख्य माध्यम है। एक औसत फीचर फोन की कीमत 1,200 रुपये से कम होती है। वहीं सबसे सस्ता स्मार्टफोन भी 5,500 रुपये से अधिक कीमत पर मिलता है। लगभग 4,000 रुपये का यह अंतर भारत के कई क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ा रहा। यही कारण है कि फीचर फोन से स्मार्टफोन तक की स्वभाविक वृद्धि लगभग तीन सालों में धीमी हो गई है। ऐपल के आईफोन का प्रदर्शन अच्छा रहा, वहीं रियलमी और श्याओमी जैसे ब्रांड जो बाजार में किफायती और मध्यम श्रेणी के फोन की पेशकश करते हैं, उनकी बिक्री में भी कमी आई है।

आईडीसी के आंकड़े के मुताबिक 1.4 अरब लोगों वाले देश में लगभग 65 करोड़ यानी आधे लोगों के पास ही स्मार्टफोन है जिसका मतलब यह है कि उनकी इंटरनेट तक पहुंच बनी हुई है। वर्ष 2023 के अंत में, सेकंड हैंड स्मार्टफोन बाजार में कुछ तेजी आई। ट्राई के सितंबर 2023 के आखिरी उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या बेहतर रफ्तार से बढ़ी है। मनोरंजन से जुड़ी खपत के बेहतर स्थिति में पहुंचने में अभी कुछ समय लगेगा।

आपका पक्ष

दूर हों नई शिक्षा नीति की खामियां

कोरोना काल के कारण नई शिक्षा नीति को लागू करने में बहुत सी दिक्कतें आईं। प्राथमिक विद्यालयों को नई शिक्षा नीति में कई प्रावधान किए गए। इसमें नई शिक्षा व्यवस्था के तहत छात्रों को रोचक तरीके से अपनी वैदिक और प्राचीन शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा जाना प्रमुख था। प्राचीन काल में भारत में गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी जिसमें विद्यार्थी को न केवल शिक्षा अपितु नैतिक शिक्षा, अच्छे संस्कार और व्यवहार में आने वाले ज्ञान से रूबरू कराया जाता था जिसके कारण विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता था। प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के लिए नई शिक्षा नीति में कई प्रावधान हैं जिन्हें भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए अच्छा माना जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा का भी कलेवर बदला है अब कौशल विकास एवं नवाचार के साथ रचनाधर्मिता को आधार बनाकर छात्रों को तैयार किया जाना स्वागत योग्य कदम है। उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति का सबसे ज्यादा दखल है क्योंकि भारत में आज भी शिक्षा की अच्छी स्थिति नहीं है जिसका कारण गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्या है। आज भी 80 करोड़ भारतीयों को सरकार मुफ्त खाद्यान्न दे रही है जो कि स्थिति को बताने के लिए पर्याप्त है। उच्च शिक्षा में उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे आईआईएम एवं आईआईटी के अलावा राज्य एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जिसके तहत नई शिक्षा नीति 2020 में सेमेस्टर सिस्टम, कोई भी विषय पढ़ने की आजादी, किसी कारण से यदि कोई पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें तात्कालिक रूप से डिप्लोमा देकर उनके मनोबल को बढ़ाने का कार्य नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा संभव है। उच्च शिक्षा नीति को लागू हुए चार वर्ष बीत जाने के बाद इसके समीक्षा की भी जरूरत है जिससे इसमें व्याप्त विसंगतियों को दूर किया जा सके। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षार्थी एवं शिक्षक महत्त्वपूर्ण घटक है। अतः इन्हें सकारात्मक दिशा देना आवश्यक है।

डॉ रसिकेश, जौनपुर

झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार को 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। रांची के एक स्कूल में खुशी मनाती छात्राएं

माइक्रो प्लास्टिक से शरीर को नुकसान

जर्नल 'एनवायरनमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव्स' के हाल के अध्ययन में कहा गया है कि प्लास्टिक प्रदूषण के महीन कण (माइक्रो प्लास्टिक) भोजन-पानी और हवा में घुल चुके हैं। ये हमारे पाचन तंत्र को तो प्रभावित कर रहे हैं और आंतों से होते हुए शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंच रहे हैं। यह पहली बार है जब माइक्रो प्लास्टिक के इतने घातक परिणाम उजागर हुए हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको ऐंड हेल्थ साइंसेज से जुड़े वैज्ञानिकों का यह अध्ययन है। एक अनुमान के मुताबिक हर भारतीय हर साल लगभग 11 किलो प्लास्टिक उत्पादों का विभिन्न रूपों मे उपभोग करता है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक के कण किसी न किसी रूप से मनुष्य के शरीर में आ ही रहे होंगे। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए भी चिंताजनक है। ऐसे में प्लास्टिक के प्रचलन रोकने के प्रयास ईमानदारी से होने चाहिए।

डॉ विकास पंडित, बड़वानी

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

जालंधर में शुक्रवार को भारी बारिश के बीच यातायात पुलिसकर्मी छाता लेकर सड़क पर यातायात संभालते हुए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संवाद
नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । मुंबई । शनिवार, 20 अप्रैल 2024

अच्छे संकेत

मामले को तूल नहीं दे रहे ईरान और इस्राइल

ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के छह दिन बाद शुक्रवार सुबह इस्राइल की ओर से ईरान पर जवाबी हमले की खबरों ने पूरी दुनिया को एकबारगी सकते में डाल दिया। लगा कि इस पूरे क्षेत्र में युद्ध फैलने की जो आशंका पिछले कुछ दिनों से बनी हुई थी, वह सच हो रही है। लेकिन हमले को लेकर इस्राइल और ईरान के शुरुआती रुख पर गौर करें तो पिछले दिनों चले अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयासों के पॉजिटिव असर भी दिख रहे हैं।

चिंता की वजहें | पिछले 13 अप्रैल को ईरान की ओर से इस्राइल पर हुए हमले के बाद जहां इस्राइल जवाबी कार्रवाई पर अड़ा हुआ था, वहीं ईरान बार-बार दोहरा रहा था कि अगर इस्राइल ने आगे कुछ भी किया तो उसका जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होगा। ऐसे में सभी प्रमुख देशों की कोशिश मामले को ठंडा करने की थी। लेकिन शुक्रवार सुबह आई ताजा इस्राइली हमले की खबरों से एकबारगी हालात बेकाबू होते से लगे।

इस्राइली मिसाइल अटैक

परमाणु केंद्र थे निशाने पर | मामला ज्यादा गंभीर इसलिए भी था कि इस्राइली ड्रोन और मिसाइल हमलों का मुख्य निशाना ईरान का इस्फहान शहर बताया गया, जो न केवल मिसाइल उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है बल्कि कई परमाणु केंद्रों का भी ठिकाना है। अच्छी बात यह रही कि इस हमले से जान-माल की क्षति की कोई खबर नहीं है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने इस बात की पुष्टि की है कि हमले में किसी परमाणु केंद्र को नुकसान नहीं हुआ है।

तूल नहीं दे रहे | खास बात यह कि इस्राइल और ईरान दोनों ही इस हमले को तूल देने के मूड में नहीं दिखते। इस्राइल की ओर से अमेरिकी अधिकारियों को कार्रवाई की पूर्व सूचना दे दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर ईरान ने इसकी घोषणा भी नहीं की। अमेरिकी अधिकारियों ने ही मीडिया को इस बारे में बताया। दूसरी ओर ईरान ने कुछ ड्रोन को मार गिराने की बात जरूर कही, लेकिन इसके लिए इस्राइल या किसी अन्य देश को जिम्मेदार नहीं ठहराया। इसे घुसपैठ की कोशिश कहा गया। स्वाभाविक ही ईरान की ओर से बदले की कार्रवाई का भी कोई संकेत नहीं है।

क्रू मेंबर्स पर प्रगति | इस बीच भारत के लिए अतिरिक्त राहत की एक खबर यह है कि ईरान द्वारा जब्त मालवाहक जहाज MSC Aries पर फंसे 17 भारतीय क्रू मेंबर्स में शामिल एकमात्र महिला सदस्य ऐन टेस्सा जोसफ स्वदेश लौट आई हैं। अन्य सदस्यों की रिहाई पर भी ईरानी अधिकारियों से पॉजिटिव बातचीत चल रही है।

कूटनीति की जीत | अगर शुरुआती संकेत सही साबित होते हैं और यह प्रकरण शांति से निपट जाता है तो यह हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की एक ऐसी जीत होगी, जो युद्ध के बजाय बातचीत से मसले हल करने की प्रेरणा को मजबूती देगी।

अंतर्दृष्टि

कैसे जिएं हम खुशियों भरी एक प्यारी जिंदगी

सुंदर चंद ठाकुर

जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज है। खूबसूरत इसलिए क्योंकि यह असीम संभावनाओं से भरी हुई है। आज आप जिस भी वजह से परेशान हैं, आपको जो भी तकलीफ है, आप सबकुछ धीरे-धीरे ठीक कर सकते हैं। आप विपरीत स्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, तो धीरे-धीरे उससे लड़कर दोबारा खुद पर भरोसा करना शुरू कर सकते हैं। दोबारा जिंदगी के बाग में खुशियों की तितलियों के पीछे भाग सकते हैं। जिंदगी का अपना कोई रंग नहीं होता। उसमें रंग हम भरते हैं। जिंदगी में स्थितियां होती हैं। सभी स्थितियां अपने में उदासीन होती हैं। उन्हें हम अपनी अपेक्षा से अच्छी और बुरी बनाते हैं। जो घटना हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप घटती है, उसे हम अच्छी कहते हैं और जो अपेक्षाओं के खिलाफ जाती है, उन्हें हम बुरी कहते हैं।

कुछ दिनों पहले बातचीत के दौरान मेरी बेटी ने मुझसे पूछा – पापा, क्या यह जरूरी है कि हर इंसान महान बनने की कोशिश करे, अपने पीछे अपना बड़ा नाम और बड़ा काम छोड़ जाए ताकि दुनिया उसे हमेशा याद करे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम छोटी-छोटी चीजों से मिलने वाली खुशियों को सहज ही जीते हुए पूरा जीवन गुजार दें। बेटी ने सहज ही यह बात मुझ से कही, पर उसकी बात मेरे जहन में बैठ गई। मेरे लिए यह जिंदगी को देखने का एक बिलकुल ही नया नजरिया था। मैंने जो जीवन जिया था, उसमें तो हमेशा ही कुछ बड़ा काम करते हुए महानता की ओर जाने की कोशिश करना और मरने के बाद अपना नाम और काम छोड़ जाना, यही बात मन की तहों में नीचे दबी रही थी। यही प्रेरित भी करती थी। लेकिन अपने जीवन को महान बनाने के दबाव के बिना जीने वाली बात मैंने कभी सोची ही नहीं थी। ऐसा नहीं कि मुझ पर किसी का दबाव था, पर मेरा परिवेश मुझे ऐसे सोचते हुए ही जीवन जीने की कोशिश करवा रहा था।

बेटी की बात जहन में ऐसी फंसी कि मैं सोचने लगा कि एक आदर्श जीवन कैसा हो सकता है। बिना खुशियों के जीवन आदर्श नहीं हो सकता था। जीवन में खुशियों का होना उसके आदर्श होने की पहली शर्त थी। लेकिन खुशियों को सुनिश्चित कैसे किया जाए। इस सवाल पर मंथन किया, तो कुछ बातें दिमाग में आईं। मुझे खुशियों भरे जीवन के लिए पांच बातें जरूरी लगीं।

1. माइंडफुलनेस – अज्ञान में सबसे ज्यादा दुख छिपा हुआ है। खुशी के लिए जागरूक होना, अवेयर होना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। माइंडफुलनेस आती है मेडिटेशन से। इसलिए ध्यान का अभ्यास जरूर करें।

2. ग्रेटिट्यूड – जब तक हमारे मन में परमात्मा के प्रति या कहें कि सुप्रीम शक्ति के प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं कि हमें उससे ऐसा अद्भुत जीवन मिला, हेल्दी शरीर मिला, माता-पिता, घर, भाई-बहन, दोस्त मिले, तब तक हमारे पास खुशी नहीं आ सकती।

3. स्वयं से प्रेम – अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते, तो आप किसी और से भी प्रेम नहीं कर सकते और बिना प्रेम के जीवन में खुशी की कल्पना नहीं की जा सकती।

4. प्रकृति से जुड़ाव- हम जिन पंचतत्वों से मिलकर बने हैं, सब हमें प्रकृति से ही प्राप्त हुए हैं। एक तरह से प्रकृति ही हमारी जननी है। जैसे एक बच्चा अपनी मां से जुड़े रहकर ही खुश रहता है, पोषित होता है, वैसे ही खुश रहने और पोषित होने के लिए हमारा प्रकृति से जुड़े रहना जरूरी है।

5. छोटी बातों में खुशियां- खुश होने के अगर बड़ी बातों का इंतजार करोगे, तो जिंदगी निकल जाएगी। सुबह उठकर आंख खोलने, पहली सांस लेने, एक फूल को देखने, एक चिड़िया का गीत सुनने, पैदल चलने, धूप में जाने, बारिश को देखने, दोस्त से मिलने, मां-बाप के साथ चाय पीने, सूर्यास्त देखने जैसी बहुत छोटी-छोटी बातों पर खुश होना आ गया, तो जिंदगी को आप सहज ही खुशियों से लबरेज कर लोगे।

ऑफ दि ट्रैक

डॉक्टर से आगे AI

दिलीप लाल

AI लैंग्वेज मॉडल GPT-4 आंखों के इलाज में भी मददगार हो सकता है। कैंब्रिज स्कूल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन के अध्ययन में GPT-4 की तुलना जूनियर डॉक्टर, प्रशिक्षु नेत्र विशेषज्ञ और अनुभवी नेत्र विशेषज्ञों के साथ की गई। सभी को आंखों की समस्या से जुड़े 87 मामलों पर अपनी राय देने को कहा गया। GPT-4 ने जूनियर डॉक्टरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया और अनुभवी नेत्र विशेषज्ञों के बराबर स्कोर प्राप्त किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ज्यादा अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ थे, उन्होंने GPT-4 से अधिक अंक प्राप्त किए। इससे यह स्पष्ट होता है कि AI अभी भी मानव विशेषज्ञता को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। इसके बावजूद GPT-4 की क्षमता चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। यह मॉडल रोगियों को प्राथमिक उपचार, निदान और मैनेजमेंट में सहायता प्रदान कर सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। इस अध्ययन के प्रमुख लेखक डॉ. अरुण थिरुनावुकरसु का कहना है कि AI मॉडल को और विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर चिकित्सा डेटा की जरूरत है। इस दिशा में दुनिया भर में काम चल रहा है। यह अध्ययन पिछले अध्ययनों से अलग है क्योंकि इसमें AI की तुलना परीक्षा परिणामों से नहीं, बल्कि वास्तविक डॉक्टरों से की गई है। इससे AI की वास्तविक दुनिया में उपयोगिता का आकलन करने में मदद मिलती है। हालांकि AI के बावजूद, मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी डॉक्टरों के पास ही रहेगी। GPT-4 और अन्य AI मॉडल तेजी से विकसित हो रहे हैं जो आंखों के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन से दुनिया में कई जगहों पर मौसम में बदलाव आया है

दुबई के डूबने की वजह क्या है

Dubai

चंद्रभूषण

दुबई में जितनी बारिश डेढ़-दो साल में होती है (करीब 150mm), वह चौबीस घंटे में हुई। बाढ़ से पूरा शहर डूब गया है। गाड़ियां नाव की तरह तैर रही हैं। दुबई एयरपोर्ट से बहुत सी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कुछ का मानना है कि UAE के क्लाउड सीडिंग के चलते बाढ़ आई है तो कुछ कह रहे हैं कि बाढ़ का कारण क्लाइमेट चेंज है। वहीं कुछ अन्य का कहना है कि दुबई का इन्फ्रास्ट्रक्चर बारिश को ध्यान में रखते हुए तैयार नहीं किया गया था, इसलिए वहां बाढ़ आई है। आइए समझते हैं कि इस मामले का सच क्या है।

AP

भारी बारिश के बाद गुरुवार को दुबई में गाड़ियां सड़कों पर डूबती दिख रही थीं

नकली बारिश | यह सही है कि दुबई पिछले कई सालों से क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशल रेनफॉल कराता रहा है। क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशल रेन वह तकनीक है, जिसमें आप विमान से बादलों में कुछ केमिकल स्प्रे करते हैं, ताकि उनमें जो बूंदें हैं, वे इकट्ठी हों और बारिश बनकर बरसें। संयुक्त अरब अमीरात में तो ऐसा ही हो रहा है, चीन में भी बड़े पैमाने पर क्लाउड सीडिंग की जाती है। यूरोप में भी यह प्रयोग होता रहा है।

ओमान में भी बारिश | स्टडी में पाया गया है कि क्लाउड सीडिंग से 20-25% बारिश बढ़ सकती है। लेकिन दुबई में जिस दिन यह घनघोर बारिश हुई, उस दिन वहां क्लाउड सीडिंग नहीं हुई थी। दूसरी बात यह कि बारिश सिर्फ दुबई में नहीं, पूरे मिडल ईस्ट में हुई है। ओमान में तो दुबई से ज्यादा बारिश हुई। वहां काफी मौतें भी हुई हैं। यह जानना जरूरी है कि इतने बड़े इलाके में बारिश क्लाउड सीडिंग के कारण नहीं हो सकती। क्लाउड सीडिंग का थोड़ा-बहुत योगदान हो सकता है, पर दुबई का एक्सट्रीम रेन फॉल इसके चलते नहीं हुआ है।

अत्यधिक वर्षा | दूसरी बात है क्लाइमेट चेंज की। मार्च-अप्रैल मिडल ईस्ट में बारिश का सीजन होता है। मिडल ईस्ट में इतनी भयानक बारिश पहली बार नहीं हुई है। पिछले कुछ सालों से एक्सट्रीम रेन फॉल मिडल ईस्ट में सामान्य बात होती जा रही है। अभी जो बारिश हुई है, इसकी भी चेतावनी दो-तीन दिन पहले दे दी गई थी। बताया गया था कि एक बहुत बड़ा वेदर सिस्टम फॉर्म हो रहा है, जिसके कारण तेज बारिश हो सकती है।

क्लाइमेट चेंज | हमने भारत में भी देखा है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ा है। पिछले साल हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि कितनी तेजी से बारिश हुई और कितना भयावह नुकसान हुआ। हमने सिक्किम में बांध टूटता देखा। माना जाता है कि वह भी बारिश के कारण टूटा। दिल्ली में किसी-किसी दिन तेज बारिश हो जाती है तो पूरा शहर पानी के कारण रुक जाता है। मुंबई में भी ऐसे हालात पहले बन चुके हैं। मेरा मानना है कि दुबई की भयावह बारिश भी क्लाइमेट चेंज के कारण हुई है। मिडल ईस्ट में UAE, सऊदी अरब और ओमान के रेगिस्तानों में भी इस तरह के एक्सट्रीम रेन फॉल की घटनाएं बढ़ रही हैं।

दुबई की मुश्किल
- रेगिस्तान में बदलने लगा बारिश का पैटर्न
- बढ़ रही है भारी बारिश की फ्रीक्वेंसी
- इन्फ्रास्ट्रक्चर भी नहीं हुआ डिवेलप

गलत इन्फ्रास्ट्रक्चर | अब आते हैं इन्फ्रास्ट्रक्चर पर। दुबई रेगिस्तान में बसा शहर है। जिन्होंने शहर को डिजाइन किया, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बारिश होगी कि शहर डूब जाएगा। दुबई में स्टॉर्म वॉटर ड्रेन है ही नहीं कि वह बारिश के पानी को बाहर निकाल सके। रेगिस्तान में इमारतें खड़ी कर दी गईं और सड़कें बनाई गईं। इतनी भयावह बाढ़ का कारण है दुबई का अनप्लांड सिटी डिवेलपमेंट। आज की तारीख में यह कंक्रीट और स्टील का शहर है। भारत में भी शहर अब कंक्रीट और स्टील के बन रहे हैं। पेड़-पौधे नहीं है, सड़कें बन रही हैं, स्टॉर्म वॉटर ड्रेन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा।

प्रकृति से खिलवाड़ | आज हमें वेदर मॉडिफिकेशन और जियो इंजीनियरिंग के बारे में चर्चा करने की जरूरत है। दुबई की बाढ़ के कारण इस पर बहुत चर्चा हुई है, और यह जरूरी है कि इसे समझा जाए। बहुत से देश बिना अपने पड़ोसी को बताए वेदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। आर्टिफिशल रेन ला रहे हैं, क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं। चीन का टारगेट 2025 तक 50 लाख वर्ग किलोमीटर में आर्टिफिशल रेन कराने का है। ध्यान रहे, यह इलाका भारत के कुल क्षेत्रफल का डेढ़ गुने से भी बड़ा है। इसका भारत पर क्या असर होगा? चीन के बाकी पड़ोसियों पर क्या असर होगा? इस पर बात करने की जरूरत है क्योंकि जैसे-जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा, सभी देश टेक्नॉलजी लाएंगे आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए, जियो इंजीनियरिंग करने के लिए।

जियो इंजीनियरिंग | आर्टिफिशल रेनफॉल तो लोकल लेवल पर होगा, लेकिन जियो इंजीनियरिंग ग्लोबल लेवल पर करने की बात हो रही है। किस तरह से सूर्य की किरणों को स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट किया जाए, इसकी बात हो रही है। अलग-अलग जियो इंजीनियरिंग टेक्नॉलजी को लेकर चर्चा चल रही है, मॉडिफिकेशन की बात हो रही है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली के पूंजीपति भी इसमें पैसा लगा रहे हैं। वहां की कुछ कंपनियां तो बिना बताए जियो इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट भी कर रही हैं।

भविष्य की समस्या | अब हमें जियो इंजीनियरिंग और वेदर मॉडिफिकेशन के लिए एक ग्लोबल गवर्नेंस पर बात करने की जरूरत है। अगर हम इस पर अभी से ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य में यह बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकता है। अमेरिका, चीन, यूरोप के पास इतना पैसा है कि वर्ल्ड लेवल पर जियो इंजीनियरिंग कर सकते हैं। लेकिन उसका असर जब एशिया और अफ्रीका के छोटे और अपेक्षाकृत कमजोर और गरीब देशों पर होगा, तो वे क्या करेंगे? दुबई में आई बाढ़ की बदौलत जब वेदर मॉडिफिकेशन और जियो इंजीनियरिंग पर चर्चा चल ही गई है तो यही सही मौका है इस चर्चा को और व्यापक रूप देने का।

(लेखक iForest के CEO हैं)

प्रस्तुति : राहुल पाण्डेय

यह प्रवास ज़रूरी क्यों

'चार पैसे कम कमाओ अच्छा है, लेकिन घर में रहो!' क्यों यह पुरानी सीख न तो आपके लिए सही है और न देश के लिए? क्या है माइग्रेशन का इकॉनमी से कनेक्शन?

Internal Migration क्या है

देश के भीतर ही एक से दूसरी जगह माइग्रेशन, जैसे यूपी-बिहार के किसी मूल वासी का महाराष्ट्र या दिल्ली में जाकर बसना या राज्य के भीतर ही एक से दूसरी जगह जाना। देश में सबसे ज्यादा इंटरनल माइग्रेशन होता है शादी के चलते, करीब 72%। फिर रोजगार और शिक्षा का नंबर है।

ऐसा माइग्रेशन जरूरी क्यों

इससे शहरी इकॉनमी को गति मिलती है। यह मुश्किल है कि एक जगह सारे कामों के लिए हुनरमंद लोग मिल जाएं। फिर, कम स्किल वाले कई काम हैं, जिनके लिए बड़े पैमाने पर लोगों की जरूरत होती है। जैसे – कंस्ट्रक्शन साइट्स और फैक्ट्रियों में लेबर, स्ट्रीट वेंडर, गार्ड।

AI image

आंकड़ों में कहां ठहरता है भारत

2021 के एक सर्वे के मुताबिक, 29% भारतीय migrants हैं यानी करीब 40 करोड़। इनमें केवल 12% मतलब लगभग 16 करोड़ ही दूसरे राज्य में जाकर बसे हैं। बाकी आंकड़ा उनका है जो अपने ही राज्य में एक से दूसरी जगह गए हैं। केवल 11% माइग्रेशन काम के सिलसिले में हुआ है, वह भी ज्यादातर पुरुषों का। महिलाओं का प्रतिशत केवल दो है।

कम माइग्रेशन का घाटा क्या

Internal Migration पर 2014 में 82 देशों पर स्टडी हुई थी। भारत नीचे से दूसरा रहा। इसका नतीजा है शहरीकरण की धीमी रफ्तार। World Bank के मुताबिक 35% भारतीय ही शहरों में रहते हैं। चीन में यह आंकड़ा है 63%। शहर जाकर काम करने वाला शख्स शहर को भी चलाता है और उसके भेजे गए पैसों से गांव की इकॉनमी भी चलती है।

घर न छोड़ने की वजह क्या

शहरों में जीवन कठिन है। कमाई का बड़ा हिस्सा घर के किराये में चला जाता है। भाषा, संस्कृति और खानपान में विविधता बहुत है देश में, तो लोगों के लिए नई जगह अडजस्ट करना मुश्किल होता है। श्रमिक वर्ग के लिए सुविधाओं की कमी है। बड़ी आबादी वापस अपने घर लौटना चाहती है। इससे उन इलाकों पर दबाव पड़ता है, जहां संसाधन कम हैं।

तब और अब की अवधी में काफी फर्क है

मधुकर उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं और गंभीर शोधार्थी भी। पिछले दिनों उनका रामचरितमानस पर एक शब्दकोश आया है- रामचरितमानस-अवधी-हिंदी कोश। इसमें उन्होंने मानस में मौजूद उन शब्दों का भी मतलब बताया है, जो आज अर्थ खो चुके हैं। मानस, अवधी और अवधी के इतिहास पर उनसे बात की ***राहुल पाण्डेय*** *ने। पेश हैं मुख्य अंश :*

सप्ताह का इंटरव्यू
मधुकर उपाध्याय

> देखने वाली चीज रामकथा की निरंतरता है जो लगातार बनी हुई है और समाज में उसका एक स्वरूप है। जो समझते हैं कि शास्त्र से लोक प्रभावित होता है, उन्हें मान लेना चाहिए कि उनसे गलती हुई है क्योंकि लोक शास्त्र बनाता है, लोक शास्त्र को प्रभावित करता है। अगर आप लोक को नहीं समझते तो आप शास्त्र नहीं समझते

■ रामचरितमानस के हिंदी में कई अनुवाद हैं, तो डिक्शनरी की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या अनुवाद उस मेयार तक नहीं पहुंचते, जहां तक अवधी पहुंचती है?

यह पांच सौ साल पहले की अवधी है, जिसमें मानस की रचना हुई है। उस अवधी के तमाम शब्द अगर बच भी गए हैं तो उनके अर्थ बदल गए हैं। एक थे करिया पंडित। वह अयोध्या में अवधी में राम की कहानी सुनाया करते थे। वह कहते थे कि अगर मानस पढ़कर सोचोगे कि तुम सब समझ रहे हो, तो गड़बड़ है। एक दिन मैं उनकी कथा सुन रहा था। गांव के एक बुजुर्ग उठे और बोले कि पंडित जी एक चौपाई का अर्थ समझ में नहीं आया। करिया पंडित एकदम उछलकर खड़े हुए उतर कर उनके पैर छुए। बोले, महाराज, आप धन्य हैं। आपको तो एक ही चौपाई का अर्थ समझ में नहीं आया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। एक और उदाहरण है- 'सुधार' शब्द। अवधी के सुधार का मतलब है बहुत तेज धार- सु+धार। जब तुलसी परशुराम के फरसे को सुधार कहते हैं तो वह धारदार फरसे की बात कर रहे हैं। एक दूसरा शब्द लीजिए- 'दिग्गज'। हम सब इसका रोज इस्तेमाल करते हैं कि बहुत दिग्गज व्यक्ति हैं। लेकिन अवधी में और गोस्वामी जी के यहां दिग्गज का मतलब होता है दिग+गज, यानी दिशाओं का हाथी। जब वह कहते हैं कि 'डगमगाहिं दिग्गज चिक्करहीं', तो वह हाथियों के चीत्कार की बात कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि इसका कोश बनना चाहिए। एक और शब्द ले लीजिए- 'लय'। आपको कभी कोई संदेह नहीं होगा लय के बारे में, क्योंकि लय या रिदम समझते हैं। लेकिन पांच सौ वर्ष पहले की अवधी में तुलसीदास जी के इस्तेमाल हुए लय का अर्थ है सत्यानाश। जब सीताजी लक्ष्मण से कहती हैं कि राम संकट में हैं, जाओ-जाओ। तो लक्ष्मण सीता से कहते हैं, 'सपनेहुं संकट परइ कि सोई। भृकुटि बिलास सृष्टि लय होई।' यानी, उस व्यक्ति को सपने में भी कैसे संकट आ सकता है, जिसकी पलकें घूम जाएं तो दुनिया तबाह हो जाए।

■ अवधी के राम का अवधी में बखान दूसरी भाषाओं से किस तरह अलग है?

राम कथा तो बहुत पहले से है। उदाहरण के लिए, गोस्वामी जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे, उसके पैंतीस साल पहले राम कथा पद्मावत में आती थी। मलिक मुहम्मद जायसी ने लिखी है रामकथा। राम की कथा तो निरंतर है। देखने वाली चीज रामकथा की निरंतरता ही है जो लगातार बनी हुई है और समाज में उसका एक स्वरूप है। जो लोग यह समझते हैं कि शास्त्र से लोक प्रभावित होता है, उनको मान लेना चाहिए कि उनसे गलती हुई है क्योंकि लोक शास्त्र बनाता है, लोक शास्त्र को प्रभावित करता है, लोक प्रमुख है। अगर आप लोक को नहीं समझते तो आप शास्त्र नहीं समझते।

■ ऐसा क्यों कि लगभग उसी अवधि में लिखी गई दूसरी चीजों की अवधी मानस की अवधी से अलग है? मसलन, मलिक मोहम्मद जायसी।

बहुत अंतर है। जायसी की अवधी ठेठ है। उस पर काम करना मानस की अवधी से भी ज्यादा जरूरी है। गोस्वामी जी का झुकाव और उनका ज्ञान संस्कृत में अद्भुत था, तो उसका असर भी रहा होगा। जायसी पर फारसी का असर था, लेकिन फारसी और संस्कृत के शब्दों को इन दोनों ने अवधी के व्याकरण में प्रयोग किया। बहुत सारे लोग हैरान होते हैं कि गोस्वामी जी के रामचरितमानस में एक हजार से ज्यादा शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, पश्तो और यहां तक कि फारसी से पहले जो भाषा बोली जाती थी, उसके भी हैं। तुलसी के यहां शब्द आता है- बिसाल। ऐसा लगता है कि वो विशाल को बिसाल कहते हैं। लेकिन बिसाल अरबी का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मिलन। तुलसी मिलन के अर्थ में ही बिसाल कहते हैं। नुक्ता आपको न तो तुलसी और न ही जायसी के यहां मिलेगा। तुलसी के राम गरीब नवाज हैं, ग़रीब नवाज़ नहीं होते। उनका गरीब होता है, ग़रीब नहीं होता है। ग में नुक्ता नहीं होता है। जायसी के यहां भी नुक्ता नहीं है। दोनों अवधी हैं।

■ अवधी भाषा का मूल आपको इतिहास में कहां दिखता है? कैसे बनी अवधी?

बहुत कठिन है इसकी जड़ तक पहुंचना। जो मुझे दिखाई देता है वह प्राकृत का प्रभाव है अवधी पर। इसके अलावा गोंडी और बैगानी का भी असर है। आदिवासियों की बैगा संस्कृति थी। जैसे, गोंडी में 'क' का अर्थ घर होता है। तमाम शब्द जो बने, जो हिंदी में भी आए बाद में, जैसे मायका- मां का घर। किवाड़- बाड़ करने वाला, घर रास्ता रोकने का जो उपाय हो, उसको कहते हैं। गोंडी और बैगानी मध्य भारत में कहीं से चलती हैं। फिर उन पर छत्तीसगढ़ी का प्रभाव दिखाई देता है, बुंदेली का असर दिखाई देता है, फिर आपको बघेली का असर दिखाई देता है। बघेल खंड के बाद आप क्रॉस करते हैं, विंध्य, और आ जाते हैं इलाहाबाद प्रयागराज। अवधी का एक रास्ता उधर से भी है। जिस समय तुलसीदास जी ने मानस की रचना की, उस समय तक यकीनन अवधी इतनी समृद्ध रही होगी कि वह रामचरितमानस लिख सके। और उनसे पहले जायसी पद्मावत लिख सके। यह इन दोनों के तीन-चार सौ साल पहले की बात होगी। अवधी का विकास लगभग उसी कालखंड में हुआ, जिसमें दक्षिण भारत की तेलुगु भाषा उभर रही थी, मलयालम स्वरूप ले रही थी, बंगला का आकार बन रहा था, तो यह उसी कालखंड की भाषा है। इसके विकास की शुरुआत हुए करीब आठ से नौ सौ वर्ष मान सकते हैं।

रोटी क्यों नहीं खाते हैं आप

खुद अपनी आंख से

अलका 'सोनी'

बात काफी पुरानी है। गरमी की छुट्टियां थीं और हम सब नानी के गांव आए हुए थे। गांव में अभी तक विकास की किरणें नहीं पहुंची थीं। न बिजली थी, न सड़कें। रोजगार के भी कुछ खास साधन नहीं। लेकिन वहां के लोग और प्राकृतिक दृश्य, दोनों अद्भुत थे। प्रकृति की वह सुंदरता हमने अपने शहर में पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे लिए गांव का वह पहला और अजूबा अनुभव था। नानी के घर में आज की तरह खाने की ढेर सारी चीजें नहीं थीं। पता चला कि जो फसल कट कर आती, वही अगली फसल तक लोग दोनों टाइम खाते हैं। हम लोग गर्मी की छुट्टी में वहां गए थे। उस वक्त हरी सब्जियां शायद ही किसी के घर देखने को मिलती थीं, क्योंकि खेती पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थी। यह सब जानकर, देखकर मुझे अजीब लगता।

वैसे मेरी नानी का घर इस दृष्टि से समृद्ध था कि घर में उगाई ताजी सब्जियां मिल जाती थीं। किसी चीज की कमी नहीं थी। नानाजी की दुकान थी, जिसमें रोजमर्रा की जरूरत की सारी चीजें बिकती थीं। गांव के सभी लोग वहीं से राशन-पानी लिया करते थे। कुछ लोग सब्जी के नाम पर सिर्फ आलू खरीदते थे। एक दिन मुझे जाने क्या सूझी कि मैं भी नाना जी के साथ उनकी दुकान पर बैठ गई। उन्हें मोलभाव करते देखना बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी मेरा ध्यान एक बात पर गया। मैं काफी देर से देख रही थी कि अधिकतर गांव वाले घट्टे खरीद रहे थे। आटा कोई नहीं खरीद रहा था। घट्टा मकई को दरदरा पीस कर पानी से तैयार किया जाने वाला एक खाद्य पदार्थ होता है। इसी बीच दुकान पर एक परिचित आए तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनसे पूछ बैठी, 'मैं बहुत देर से देख रही हूं कि जो भी आ रहे, सब घट्टे ही खरीद रहे हैं। आटा कोई नहीं खरीद रहा। आप सब रोटी नहीं खाते?'

उन्होंने जो जवाब दिया, वह मेरी उम्र के हिसाब से थोड़ा भारी था। उसका पूरा मतलब मुझे बड़े होने पर ही समझ आया। उन्होंने कहा था, 'बिटिया, गरम रोटियां तो सबको अच्छी लगती हैं। लेकिन हम ठहरे गांव के लोग। मेहनत-मजदूरी करते हैं तो सिर्फ दो रोटी खाकर किसी का पेट नहीं भरता। चार-पांच रोटियां तो बच्चे बनते-बनते रसोई में ही खा जाएंगे। फिर रात को भूख लगने पर हम क्या खाएंगे और घर में मौजूद और लोगों को क्या खिलाएंगे? इस घट्टे से ही पेट भरता है हम सब का। पाव या आध किलो में ही सब तृप्त हो जाते हैं। तरकारी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बस नमक- मिर्च ही बहुत है।'

मैं चुप हो गई थी तब। पर इतना तो समझ आ ही गया था कि उन्हें किलो भर आटे और सूप भर सब्जी की जगह आधा किलो घट्टा लेना सस्ता लगता है। बस इतने में ही पूरे परिवार का पेट भर जाता था। उनके पूरे दिन की मेहनत से थके शरीर और भूखे पेट को भरने की क्षमता घट्टे में ही थी। रोटी तो सुकुमार और सामर्थ्यवान का पेट ही भर सकती है। जिनकी मेहनत से शहर के हम जैसे लोगों का पेट भरता है, वे हाड़ तोड़ मजदूरी के बाद भी घट्टा ही खरीद सकते हैं। शाम के नाश्ते से भरे पेट पर दो रोटी खाते ही जिनका मन भर जाता है, वे उनकी मजबूरी शायद कभी समझ भी नहीं पाएंगे।

चलते-चलते...

भले ही CO_2 उत्सर्जन में भारी कटौती की जाए, जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को सालाना 38 ट्रिलियन डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। जलवायु परिवर्तन अगले 25 वर्षों में जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका जैसे विकसित देशों सहित लगभग सभी देशों में भारी आर्थिक नुकसान का कारण बनेगा। पॉट्सडैम इंस्टिट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च (PIK) के वैज्ञानिकों ने पिछले 40 वर्षों के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह दावा किया है।

रीडर्स मेल

■ लोकलुभावन वादे नहीं, शिक्षा है जरूरी

देश में चुनावी माहौल है। लोक - लुभावनों वादों के बीच महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी मुद्दा हैं, लेकिन शिक्षा जैसे बुनियादी सवाल पर नेता और जनता में चुप्पी है। शिक्षा का बजट तो बढ़ा है, लेकिन हकीकत में क्वॉलिटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मेरी जानकारी में ऐसा कोई मौका शायद ही आया हो, जब शिक्षा की बेहतरी के लिए या जर्जर स्कूल-कॉलेज को सुधारने के लिए कोई वोटर अड़ गया हो। बात चुनाव बहिष्कार की नहीं है, बल्कि लोगों में एकजुटता ऐसी होनी चाहिए कि राजनीतिक दल या सरकार उनकी बातें सुनने को मजबूर हो जाए। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के साथ ही सभी लोगों तक उसकी पहुंच भी सुनिश्चित कराने की पहल होनी चाहिए।

-दीपा सिन्हा (मुंबई), ईमेल से

■ धरती को बचाने की पहल

धरती को बचाने का आशय इसकी रक्षा से है। धरती के बिना जीवन संभव नहीं, सब जानते हैं, इस हकीकत को। लेकिन, अपने स्वार्थ के लिए पृथ्वी का भरपूर दोहन किया जा रहा है। इंसान धरती पर मौजूद संसाधनों का इतनी तेजी से उपयोग-उपभोग कर रहा है कि पृथ्वी चाह कर भी उसकी भरपाई नहीं कर सकती। धरती को बचाने के लिए हमें वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगानी होगी, अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाने होंगे, वायु प्रदूषण रोकना होगा।

-साजिद अली, ईमेल से

■ चुनाव में हिंसक झड़प और फायरिंग

21 राज्यों में फर्स्ट फेज की 102 सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ। सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज था। निर्वाचन आयोग की ओर से शांतिपूर्ण मतदान की अपील के बाद भी कई जगहों पर हिंसक झड़पें व पुलिस फायरिंग हुई। कूचबिहार की हिंसक घटना पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती है। छत्तीसगढ़ में ग्रेनेड ब्लास्ट की घटना से पता चला कि नक्सली बड़ी चुनौती देंगे। मणिपुर में भी हिंसक घटनाएं हुई हैं। नक्सली हिंसा से प्रभावित गढ़चिरौली में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए रथ में बैठाकर वोटिंग की व्यवस्था की गई। ऐसे में अगले चरण के चुनाव के लिए प्रशासन को और भी चुस्त होना होगा।

-कांतिलाल मांडोत, ईमेल से

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः(022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

https://t.me/NewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा

नई दिल्ली • शनिवार • 20 अप्रैल • 2024

www.rashtriyasahara.com

भरोसे का आधार

सर्वोच्च न्यायालय ने लोक सभा सभा के प्रथम चरण के मतदान से एक दिन पहले चुनावी मशीन की विश्वसनीयता के बारे में यही कहा। एडीआर और अन्य की तरफ से जारी जनहित याचिकाओं पर दूसरे दिन सुनवाई करते हुए ईलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पर संदेह जताने को सही नहीं बताया। इस पर फैसला अभी आना है। पर इन टिप्पणियों से ईवीएम पर न्यायालय के रुख का पता चलता है। स्वदेश निर्मित ईवीएम मशीन से चुनाव बीसवीं सदी के नौवें दशक से ही कराया जा रहा है। इसके पहले, 1982 में केरल की परवूर विधानसभा उपचुनाव में उसे कुछ बूथों पर आजमाया गया था। इसकी खामियों को दुरुस्त कर इसे प्रयोग-सक्षम बनाया गया। ईवीएम के जरिए यूपीए ने दो आम चुनाव जीते हैं और केंद्र में उनकी दो सरकारें बनी हैं। इसके पहले एनडीए की भी सरकार बनी है। विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव ईवीएम से ही हुए हैं।

इसके बावजूद हारे हुए दल या गठबंधन हर आम चुनाव के वक्त ईवीएम को हटाने या उसे वीवीपीएटी से लैस करने की मांग चुनाव आयोग से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक करते रहे हैं। आयोग की तरफ से हर चुनाव के पहले उनके समक्ष ईवीएम के फूलप्रूफ डेमो के जरिए चिंताओं के निराकरण के बावजूद सवाल उठाते रहना एक रस्मी कवायद है। उनका आरोप होता है कि इसमें डाले गए वोट भाजपा को मिलते हैं। पहले के कुछ उदाहरण इसकी तस्दीक भी करते थे पर यह तो मशीनी गड़बड़ी हो सकती थी। अब तो इसमें पर्याप्त सुधार किया गया है। तभी तो सर्वोच्च न्यायालय ने चार करोड़ टेस्टेड डेटा पर अपना भरोसा जताया है। यह सही भी है। ऐसा नहीं होता तो यूपीए ही लगातार जीतता होता या एनडीए का राज बदस्तूर रहता। दलों को चुनावों में इतना पैसा और पसीना नहीं बहाना पड़ता। ईवीएम अपने आका को तश्तरी में नतीजे परोस देती। न्यायालय ने रस्मी याचियों से स्पष्ट कर दिया है कि बैलेट पेपर और बक्से की झीना-झपटी वाले प्रतिगामी चुनावी दौर में भारत जैसे 'महादेश' को नहीं लौटाया जा सकता। यह जर्मनी नहीं है। अलबत्ता, इस मसले पर फिर उंगली न उठे इस लिहाजन हर वोट का हिसाब रखने के लिए ईवीएम को वीवीपीएटी के साथ जोड़ने पर विचार किया जा सकता है। अंतिम परिणाम में देरी के बावजूद। चुनाव बिल्कुल शुद्ध-पवित्र तरीके से होना चाहिए ताकि उसके जनादेश की 'गारंटी' हो। सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी में अवाम का मत है।

सब दिखाएं समझदारी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर प्रर्वतन निदेशालय ने गलत डाइट लेने का आरोप लगाया है। अदालत में ईडी ने कहा कि वह तिहाड़ जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए तथा उन्हें मेडिकल आधार पर जमानत मिल जाए। केजरीवाल को टाइप-2 डायबिटीज है। वह सुबह-शाम आलू पूड़ी, मिठाई और आम खा रहे हैं। चीनी वाली चाय भी पी रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि ईडी उनका घर का खाना बंद करना चाहती है। केजरीवाल रोज 56 यूनिट इंसुलिन लेते हैं। उनका ब्लड-शुगर लेवल ऊपर-नीचे होता रहता है। उन्हें लगातार कब्ज रहता है तथा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस (खांसी) बनी रहती है। जेल डिस्पेंसरी की तरफ से नियमित जांच होने के बावजूद वह ब्लड शुगर के लिए निर्धारित डाइट नहीं ले रहे हैं। उधर अदालत में याचिका दायर कर केजरीवाल की जेल में सुरक्षा को खतरे में बताया गया है। आप नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी लंबे समय से जेल में बंद हैं। केंद्र सरकार पर आरोप है कि यह जानबूझकर किया जा रहा है। वह आप सरकार के काम-काज के तरीकों और उसकी प्रसिद्धि से घबरा कर ऐन लोक सभा चुनाव के पहले यह कदम उठाया गया। आप नेता संजय सिंह ने इस कृत्य को तानाशाही कहा, जबकि केजरीवाल ने जेल से भेजे संदेश में कहा कि मैं आतंकवादी नहीं हूं।

हालांकि केजरीवाल को खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा कदम उठाने से बचना चाहिए। निश्चित रूप से इससे दुनिया भर में उचित संदेश नहीं जा रहा है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। यह तय है कि यदि केजरीवाल या उनके दल के अन्य नेताओं पर आरोप साबित होते हैं तो उन पर कानून शिकंजा कसेगा। भ्रष्टाचार को लेकर अपने यहां सिर्फ बातें ही बनाई जाती हैं। राजनीतिज्ञों के भ्रष्टाचारमुक्त होने पर जनता में संशय ही है। मोदी सरकार भी ऐसा कोई उदाहरण तय करने में सफल नहीं है, जिससे प्रतीत हो कि अपने नेताओं के भ्रष्टाचार को लेकर भी वह कड़े कदम उठा रही है। घातक संक्रमण की तरह फैलते भ्रष्टाचार से जूझना बड़ी चुनौती है, बदले की भावना से ऊपर उठ कर इससे मुक्त होने के सामूहिक प्रयास करने होंगे।

कटाक्ष/ कबीरदास

न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी!

भाई किस्मत हो तो आजमगढ़ वालों जैसी हो। वैसे तो सब यूपी वाले ही बहुत खुशनसीब हैं पर आजमगढ़ वालों की बात ही कुछ और है। दिनेशलाल यादव उर्फ निरहुआ जी जैसा जीनियस बाकी यूपी वालों को भी कहां नसीब है। पट्ठे ने न दिमाग पर जोर डालने की मुद्रा बनाई और किसी तरह के आंकड़ों-वांकड़ों की जरूरत बताई। नाचते-गाते चुटकियों में देश को बेरोजगारी की उस समस्या का परमानेंट समाधान बता दिया, जिसका समाधान राम जी झूठ न बुलाएं, महाराज मोदी जी भी नहीं खोज पाए थे। और समाधान भी एकदम सिंपल। मोदी जी, योगी जी आदि का दिखाया रास्ता अपनाओ, राजा निरबंसिया बन कर दिखाओ। न होगी औलाद और न उठेगी रोजगार की मांग!

वैसे शायद यह कहना भी पूरी तरह से सही नहीं होगा कि मोदी जी बेरोजगारी का निरहुआ जी वाला समाधान नहीं खोज पाए थे। वरना मोदी जी, योगी जी वगैरह खुद यह समाधान क्यों करते? फिर भी, जैसे न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज का क्रेडिट दिया जाता है, वैसे ही निरहुआ जी को बेरोजगारी के अपने बुनियादी समाधान की खोज का क्रेडिट तो देना ही होगा। अब सेब को पेड़ से गिरते तो न्यूटन से पहले भी न जाने कितने लोगों ने देखा होगा। पर बिना सोचे-समझे व्यवहार में कुछ समाधान करते रहना एक बात है, योगी जी, मोदी जी की तरह पहले भी बहुतों ने ऐसा किया होगा; और समाधान का सिद्धांत खोज कर निकालना और ही बात है। हां! यह दूसरी बात है कि यह मोदी जी के राज के दस साल का ही कमाल है कि निरहुआ जैसा जीनियस निकल कर सामने आ सका और बेरोजगारी जैसी असाध्य लगने वाली समस्या का, अपना परमानेंट समाधान पेश कर सका। अब मोदी जी से कोई साल के दो करोड़ रोजगार मांगने नहीं जाएगा। अब जवाब सब को पता है-दो करोड़ बच्चे पैदा मत करो, रोजगार का लफड़ा ही मिट जाएगा। और निरहुआ जी की महान खोज में सिर्फ बेरोजगारी ही नहीं, परिवारवाद जैसी और कई समस्याओं का भी समाधान है। जब परिवार ही नहीं होगा, तो परिवारवाद कहां से आएगा। यूपी के ही महेशचंद्र शर्मा इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो मोदी-योगी को अपना नहीं समझता, अपने बाप को भी अपना नहीं समझता। पिता हो तो परम पिता जैसा!

मुद्दों का मूल्यांकन जरूरी

आम चुनाव-24

अखिलेश आर्येन्दु

ताजा सर्वेक्षण बताते हैं कि इस बार के आम चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और विकास प्रमुख मुद्दे के रूप में हावी रहने वाले हैं। ये मुद्दे मतदाताओं के लिए अपना सांसद चुनने में काम में आएंगे। पिछले पांच साल में देश की हालत में कितना सुधार हुआ और जनता के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने जनता की बेहतरी के लिए कितनी जिम्मेदारी से कार्य किए, यह भी मतदाताओं पर असर डालेगा। इसी तरह 2019 में एनडीए सरकार ने किन घोषणाओं या वादों को पूरा किया और कौन-सी घोषणाएं एनडीए की केंद्र और राज्यों में उसकी सरकारें पूरा करने में नाकाम रहीं, इस बार के आम चुनाव में जनता द्वारा उन सारे मुद्दों पर गौर करके मतदान करने की बात ताजा सर्वेक्षण में सामने आई है।

ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक नौकरी और बेरोजगारी का मुद्दा लोगों के लिए सबसे अहम रहने वाला है। तमाम ऐसे लोगों की राय है कि अर्थव्यवस्था पर राज्य और केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा गौर करने की जरूरत है क्योंकि गैर-बराबरी बढ़ी है। वहीं पर सर्वेक्षण में महिलाओं को रोजगार के अवसर कम होने की शिकायत भी है। बेरोजगारी के अलावा महंगाई का मुद्दा सबसे अहम है। रोजमर्रा की वस्तुओं में बढ़ोतरी से भी आम लोगों में खासी नाराजगी है खासकर गरीब, ग्रामीण और मजदूरी करके परिवार पालने वाले मजदूरों में। निम्न मध्यम और मध्यम वर्ग की भी महंगाई को लेकर सबसे ज्यादा शिकायत है।

उज्ज्वला और मुफ्त राशन योजना से भारत का निम्न वर्ग राहत महसूस कर रहा है। गौरतलब है कि भाजपा के नये चुनाव घोषणापत्र में गरीबों को मुफ्त राशन की योजना को अगले पांच साल और बढ़ा दिया गया है। निश्चित ही इसका असर चुनाव परिणाम में दिखाई देगा क्योंकि 2019 में निम्न और माध्यम वर्ग ने केंद्र की मुफ्त राशन योजना को पसंद किया था। आयुष्मान योजना को विस्तार देते हुए गरीबों के अलावा सत्तर साल के बुजुर्गों को भी इसका लाभ देने की बात जरूर नई है, इससे करोड़ों बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। इसी तरह पिछले पांच सालों में विकास की अहमियत को 48 प्रतिशत जनता ने स्वीकार किया। सबसे दिलचस्प राय भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में देखने को मिली। महज 8 प्रतिशत लोगों ने भ्रष्टाचार को तवज्जो दी यानी 92 प्रतिशत लोगों ने भ्रष्टाचार को कोई खास तवज्जो ही नहीं दी, जबकि दस साल पहले भ्रष्टाचार सबसे गंभीर मुद्दा हुआ करता था। उस समय देश में बेरोजगारी की दर 5 प्रतिशत के आसपास थी, लेकिन अब यह 6.8 प्रतिशत के आसपास है। पिछले चुनाव में बेरोजगारी को लेकर लोग इतने

आक्रामक नहीं थे जितने आज हैं। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी, महंगाई और लगातार कीमतों में बढ़ोतरी है। महंगाई में कुछ कमी आई है, लेकिन पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को भी व्यावहारिक बनाना होगा।

इसी तरह करोड़ों गरीबों को शौचालय, सूर्य घर योजना से 300 यूनिट मुफ्त बिजली के अलावा स्टार्टअप के जरिए रोजगार देने की कवायद की गई। फिर भी नौकरी और बेरोजगारी का मुद्दा इस चुनाव में छा गया है, इसके पहले इस पर लोग इतने उग्र नहीं थे। इसलिए कोई भी गठबंधन सत्ता में आए उसके सामने करोड़ों युवाओं को रोजगार देने और महंगाई को कम और स्थिर बनाए रखने की चुनौती तो होगी ही।

भाजपा का घोषणापत्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जारी करते हुए कहा कि उन्हें यदि पांच साल और मिलते हैं तो वे भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पिछले दस वर्षों में देश में कई स्तरों पर बदलाव आए हैं। करोड़ों नये युवा मतदाता इस बार के चुनाव में अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इनका भरोसा जीतना चुनौती ही है। वे रोजगार चाहते हैं, और देश को आगे बढ़ता हुआ भी देखना चाहते हैं। केंद्र में सरकार बनाने वाले गठबंधन को इन युवा मतदाओं की चाहत को हर हाल में पूरा करना ही होगा। इसी तरह महिलाएं भी सुरक्षा के साथ नौकरी भी चाहती हैं। वे आगे बढ़ना चाहती हैं और इसमें केंद्र सरकार से अपनी बेहतरी के लिए उम्मीद भी लगाए हुए हैं। इसलिए भाजपा नीत एनडीए गठबंधन और कांग्रेस का 'इंडिया' गठबंधन, दोनों ही महिलाओं के आर्थिक हालात मजबूत करने की बात अपनी चुनावी घोषणाओं में करते दिखते हैं।

बेशक, देश की साख दुनिया में पहले से बेहतर हुई है। कश्मीर मुद्दा भी एक झटके में हल कर लिया गया है। मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक जैसे जघन्य कानून को खत्म कर दिया गया। अंग्रेजी शासन की गुलामी के तमाम प्रतीकों को बनाए रखने वाले कानूनों को खत्म या बदल दिया गया। यह आजादी के बाद 'मोदी है तो मुमकिन है' के तहत किया गया। इसी तरह से नई शिक्षा नीति 2019-20 में लागू की गई। इससे शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति के रूप में देखा गया।

इसी तरह विदेश नीति का मूल्यांकन करने वालों का मानना है कि आजादी के बाद पहली बार है जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी भारत के सामने नतमस्तक हुए। जी-20 की अध्यक्षता, हिन्दी, उर्दू और बंगला को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रायोगिक भाषा के रूप में मान्यता मिलने, भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी से ज्यादा महत्त्व दिलाने और चीन के आगे सीना तान के खड़े होने और रूस-यूक्रेन युद्ध में परोक्ष मध्यस्थता करने जैसी तमाम उपलब्धियां भारत की विदेश नीति का हिस्सा रही हैं। ये उपलब्धियां केंद्र सरकार की बेहतर और व्यावहारिक विदेश नीति का हिस्सा रही हैं। इसी तरह आतंकवाद से मुक्त भारत की छवि पहली बार पिछले दस वर्षों में दुनिया में चर्चा का विषय रही। पौराणिक और पर्यटक स्थलों को विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया। नये एम्स और आईआईएम जैसे संस्थानों को खोलने पर जिस तरह केंद्र सरकार ने अहमियत दी, उसका ही परिणाम है कि आज सेहत और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति दिखाई देने लगी है। इस तरह चुनाव में महज बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को विपक्ष द्वारा हवा देना न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। फिर भी चुनाव की हलचल में कौन मुद्दे असरदायक होंगे और कौन-सी उपलब्धियों को जनता अहमियत देती है, यह तो परिणाम आने पर पता चलेगा, लेकिन जनता इस समय निर्णायक की भूमिका में है, जो निर्णय लेगी अपना अच्छा-बुरा समझ कर ही लेगी।

चुनाव में महज बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को विपक्ष द्वारा हवा देना न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है। फिर भी चुनाव की इस हलचल में कौन मुद्दे असरदायक होंगे और कौन-सी उपलब्धियों को जनता अहमियत देती है, यह तो परिणाम आने पर ही पता चलेगा, लेकिन जनता इस समय निर्णायक की भूमिका में है, जो भी निर्णय लेगी अपना अच्छा-बुरा समझ कर ही लेगी

इस्पात की खपत बढ़ी

- देश में घरेलू तैयार इस्पात की खपत 2023-24 में सालाना आधार पर 13 फीसद की बढ़ोतरी के साथ 13.6 करोड़ टन (एमटी) हो गई है। गत वर्ष 2022-23 में यह 12 करोड़ टन थी
- यह वृद्धि महत्त्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत सरकार का लक्ष्य 2030 तक देश की वार्षिक इस्पात निर्माण क्षमता को 30 करोड़ टन और प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत को 160 किग्रा. तक बढ़ाना है

स्रोत : मीडिया इन्पुट्स

इस्राइल-ईरान संघर्ष से भले ही समूचे विश्व की जान सांसत में हो, लेकिन लगता है कि दोनों पक्ष युद्ध की नौबत से बच रहे हैं। इस्राइल के इसफाहान हमले और उससे पहले ईरान की ड्रोन और मिसाइल आक्रामकता में ज्यादा नुकसान पहुंचाने की नीयत नहीं थी और कोशिश इत्ती भर थी कि सामने वाले को कड़ा संदेश दिया जाए।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक
@Chellaney

धूम्रपान

रजनीश कपूर

हर लिहाज से खतरनाक है ये शगल

साल 1961 की बहुचर्चित फिल्म 'हम दोनों' का गाना 'हर फिक्र को धुएं में उड़ाता' सबने सुना होगा। धूम्रपान करने वालों ने भी इसे अवश्य सुना होगा। फिल्म में गाने के बोल इस तरह दर्शाए गए कि फिल्म का हीरो अपने सभी फिक्र और चिंताओं को धुएं के कश में उड़ा देता है और चिंता मुक्त हो जाता है, परंतु क्या यह सही है कि मात्र सिगरेट के कश भरने और धुआं उड़ाने से आपकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी? इसका उत्तर है नहीं। बल्कि यदि आपको धूम्रपान की लत लग जाए तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ जरूर जाएंगी।

आज जानते हैं कि ऐसा क्या है, इस चंद लम्हे की मामूली सी खुशी में, जो लाखों करोड़ों को इसकी लत लगा देती है। दरअसल, सिगरेट में मौजूद तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो कश लेते ही बड़ी तेजी से आपके फेफड़े में समा जाता है और कुछ ही क्षण में दिमाग तक पहुंच जाता है। दिमाग में पहुंचते ही इसका संपर्क 'नर्व सेल' से होता है और इसके असर से डोपामाइन नाम का रसायन बाहर आता है। यह रसायन आपके दिमाग को संकेत देता है कि कुछ अच्छा करने से आपको इनाम मिल सकता है। विशेषज्ञों की मानें तो, यह रसायन आपको ऐसा इशारा देता है कि आप एक बार दोबारा सिगरेट का कश भर लेते हैं। एक शोध के अनुसार सिगरेट की लत से प्रभावित लोगों, जिन्हें गले का कैंसर हुआ था, की गले की नली को काट कर अलग करना पड़ा। उपचार के बाद भी इस लत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और वे दोबारा धूम्रपान करने को मजबूर थे। विशेषज्ञों के अनुसार दिमाग के जिस हिस्से को 'एनिमल पार्ट' कहा जाता है, उससे ही निकोटीन की लत पर काबू पाया जा सकता है। नशीले पदार्थ हमारे दिमाग के 'एनिमल पार्ट' को इस कदर उकसाते हैं कि वो ऐसे संदेश भेजता है कि हम ऐसा बार-बार करें। वहीं दिमाग का दूसरा हिस्सा हमें ऐसा करने से रोकता भी है। नशे की लत की गिरफ्त में लोग अक्सर इस संघर्ष से जूझते रहते हैं।

इस लत का इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि आप कितने समझदार हैं, बल्कि आपका दिमाग निकोटीन

या अन्य नशीले पदार्थों पर किस तरह प्रतिक्रिया देता है। यदि समय रहते और सही संगति के चलते नशा या धूम्रपान रोक दिया जाए तो बेहतर हो परंतु ऐसा बहुत कम होता है। सिगरेट की लत के लिए केवल निकोटीन ही जिम्मेदार नहीं होती। इसके लिए एक प्रमुख भूमिका सिगरेट बनाने वाली कंपनियों और उनके द्वारा जारी किए भ्रामक विज्ञापन भी उतने ही जिम्मेदार हैं। पश्चिमी देशों में जैसे ही निकोटीन की लत को लेकर सवाल उठने लगे तो कुछ लोगों ने इसकी जड़ तक जाने की सोची। उन्होंने वैज्ञानिक तरीकों से साबित कर दिया कि सिगरेट के धुएं में कुछ भी लाभदायक नहीं होता। इतना ही नहीं, यह न केवल धूम्रपान करने वाले, बल्कि उसके आस-पास के लोगों के लिए भी काफी हानिकारक साबित हो सकता है। जैसे-जैसे यह अभियान तेजी पकड़ने लगा, धूम्रपान पर सार्वजनिक जगहों पर प्रतिबंध भी लगने लगा। सिगरेट पर अतिरिक्त और बढ़े हुए कर भी लगाए जाने लगे जिससे इसकी कीमत में भी बढ़ोतरी हुई। साथ ही, सिगरेट के डब्बों पर भी स्वास्थ्य संबंधित चेतावनियां भी छापी जाने लगीं परंतु इन सबके चलते भी पश्चिमी देशों की बड़ी-बड़ी सिगरेट कंपनियों ने हार नहीं मानी। ज्यादा मुनाफा कमाने की नीयत से इन कंपनियों ने विकासशील देशों और उन देशों का रुख करना शुरू कर दिया जहां नियम और कानून सख्त नहीं थे।

इन देशों में आम नागरिक धीरे-धीरे इन कंपनियों की मार्केटिंग के मायाजाल में बड़ी आसानी से फंस गए। देखते ही देखते इन कंपनियों की फिर से चांदी होने लगी। सोचने वाली बात यह है कि लोग धूम्रपान के आदी कैसे बन जाते हैं? कुछ लोग सिगरेट पीने को 'स्टेटस सिंबल' या सामाजिक स्थिति का संकेतक मानते हैं। समझते हैं कि धूम्रपान करना ऐसी आदत है जो किसी विशेष वर्ग में आपको बड़ी आसानी से स्थान देती है, परंतु इस स्थान पाने की होड़ में आप अपनी सेहत से खिलवाड़ कर लेते हैं। इस लत के चलते न सिर्फ आप अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, परंतु अपने घरेलू बजट का भी नुकसान कर रहे हैं। ज्यों-ज्यों आपकी यह लत बढ़ती जाएगी आपकी जेब पर भार भी बढ़ेगा। धूम्रपान करने से मिलने वाला आंशिक 'सुकून' बड़ी मात्रा में आपके स्वास्थ्य पर असर करता है, और यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए आप जब भी धूम्रपान करते किसी व्यक्ति को देखें या स्वयं अगला कश लगाने लगें तो यह सवाल अवश्य पूछें कि क्या वास्तव में धूम्रपान करने से फिक्र धुएं में उड़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं फिक्र उड़ने की बजाय और बढ़ रहे हों?

दिव्य चिंगारी

संत राजिन्दर

हम सभी के भीतर एक दिव्य चिंगारी छिपी हुई है। विस्मयकारी सौंदर्य के मंडल, अकल्पनीय दृश्य और ध्वनियां, असीम विवेक और पूर्ण रूप से आलिंगित करता प्रेम हमें अंतर में आमंत्रित करते हैं। दिव्य ज्योति निरंतर प्रकाशित रहती है। हम इसकी खोज अधिकतम दूरी पर स्थित क्वासारों में या एटम के न्यूनतम क्वार्कों में करते हैं। किंतु इसके रहस्य हमारे भीतर छिपे रह जाते हैं। मानव के उम को जानने हेतु, वैज्ञानिक दूरबीनों के जरिए समस्त ब्रह्मांड को निहारने पर या पार्टिकल एक्सीलिरेटर्स द्वारा परमाणु का खंडन करके 'परमात्मा-कण' ढूंढने पर विशाल धनराशि खर्च करते हैं। अन्य व्यक्ति विश्व के विभिन्न धर्मों के कर्मकांडों द्वारा प्रभु को पाने का प्रयास करते हैं। फिर भी, अधिकांश लोगों के लिए प्रभु एक रहस्य बना हुआ है। हमारे भीतर एक ज्वाला विद्यमान है, जो हमारे जीवन में कायाकल्प कर सकने की सामर्थ्य रखती है। एक ज्योति है, जो हमें विवेक, शाश्वत सुख, पूर्ण प्रेम, निर्भयता तथा अमरत्व दे सकती है। यह ज्वाला हमारे हृदय और मन को आलोकित करती है और ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिलाती है जिनसे मानवता युगों-युगों से जूझती आई है, जैसे कि हम यहां क्यों आए हैं? हम कहां से आए हैं? मृत्योपरांत हम कहां जाएंगे? वैज्ञानिकों की भांति हम इनके उत्तरों को तारों से भरे आसमान में और परमाणु के अंदर ढूंढते रहते हैं। हम इनके उत्तरों को धर्मस्थानों, धर्मग्रंथों और तीर्थ स्थानों में भी ढूंढते रहते हैं, परंतु इस ज्ञान को प्राप्त करने हेतु हमें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है; यह ज्वाला हम सबके भीतर विद्यमान है। जब हम उस धधकते अंगारे को खोज लेते हैं, तो हम अंतर के अचरजों को देखने वाले बन जाते हैं, और सौंदर्य, असीम प्रेम, अविरल आह्लाद तथा अकथनीय हर्षोन्माद का अनुभव करने लगते हैं। यह दात मात्र कुछेक के लिए नहीं है; वरन यह सभी के लिए उपलब्ध है। शाश्वत धूप का आनंद लेने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। ध्यानाभ्यास द्वारा हम आंतरिक ज्योति तथा श्रुति को देख और सुन सकते हैं। इस धारा में लीन होने पर हमें चेतनता के आत्मिक मंडलों का अनुभव होता है।

रीडर्स मेल

भारत के कदम का इंतजार

अब भारत क्या करेगा? ग्रेट ब्रिटेन से राजनीतिक संबंध को खत्म करेगा या भारत 'राष्ट्र-मंडल' देशों की सदस्यता को त्याग देगा? कब तक भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों से उठने वाली आवाजों को दबाता रहेगा कि भारत में धार्मिक आजादी को कोई खतरा नहीं है? कब तक हम झूठी दलील देते रहेंगे कि भारत में समाज में कोई धार्मिक विभाजन या तुष्टिकरण की स्थिति नहीं है। ब्रिटिश सरकार लगभग एक साल के भीतर ही, एक बार नहीं, बल्कि दो-दो बार मणिपुर में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ किया गया उन्माद एवं हमले को वहां के सदन में उठा रहा है। इसे सिर्फ विदेशी प्रोपेगंडा कह देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें अपनी अंतरात्मा में भी झांकना होगा कि क्या हम वाकई धर्मनिरपेक्ष देश बने हुए हैं?

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

खत्म हो शक की गुंजाइश

सर्वोच्च न्यायालय में ईवीएम से संबंधित वीवीपैट मशीन में 100 फीसद मिलान पर सुप्रीम कोर्ट में कोई 5 घंटे की मैराथन बहस की गई और बहस के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। भारत में जब से ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाने लगा तब से यह विवाद का विषय बना हुआ है। पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसके बाद भाजपा सत्ता में आ गई तो विपक्षी दल इस मुद्दे पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। ताजा मामला था कि वीवीपैट मशीन में वोटिंग का 100 फीसद मिलान सार्वजनिक किया जाए और मतदाताओं को स्लिप भी दी जाए। चुनाव आयोग और भारत सरकार के वकीलों ने इसका विरोध किया और अपने तर्क दिए। मेरा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखकर सही किया है। यदि अभी फैसला आ जाता तो चुनाव प्रक्रिया बाधित होती और यह किसी भी तरह से संभव नहीं था कि 100 फीसद वोटिंग का मिलान हो सके। भविष्य में जरूर इस संदर्भ में सरकार से कहा जा सकता है कि व्यापक रूप से इंतजाम किए जाएं क्योंकि मतदाताओं के मन मे ईवीएम के प्रति शक बना रहता है जिसका समाधान जरूरी है।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

विचार करे चुनाव आयोग

कुछ महीने पहले विधानसभा के चुनाव कई राज्यों में हुए थे। तब कई जगह पर वर्तमान सांसदों को सांसदी से इस्तीफा दिला कर विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया था। उस समय ये सांसद फिर विधायक का चुनाव जीत भी गए थे, परंतु दुख है कि अब इन्हीं विधायकों, जो अभी कुछ माह पूर्व अपना चुनाव जीत कर आए थे, को अब एक बार फिर से सांसदी का चुनाव लड़वाया जा रहा है। मेरा कहना है कि किसी भी पार्टी की कैसी सोच है कि हर बार चुनाव जीते व्यक्ति को ही बार-बार चुनाव के मैदान में क्यों उतारा जाता है, जबकि बार-बार एक ही व्यक्ति को चुनाव लड़ाने की इस प्रक्रिया के कारण जनता का काफी धन बर्बाद होता है। इस विषय में हमारा यही कहना है कि चुनाव आयोग को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस तरह से बार-बार एक ही व्यक्ति को चुनाव लड़ाने की प्रक्रिया को आगे से तुरंत बंद कराना चाहिए ताकि सार्वजनिक धन की बर्बादी न हो।

एमएम राजावत, शाजापुर, मप्र

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

https://t.me/AllNewsPaperPdf

राष्ट्रीय सहारा
राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

वर्ष-33, अंक 248

आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

पश्चिम एशिया के भयानक हालात

आखिर वही हुआ जिसका दुनिया को बड़ा डर था। इजराइल ने अमेरिका की सलाह को नजरअंदाज करते हुए ईरान के उत्तर पश्चिमी शहर इस्फहान पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर दिए हैं। इस्फहान में ईरान की सेना का बड़ा एयरबेस है और इस क्षेत्र में उसके परमाणु हथियारों से जुड़े ठिकाने हैं। इजराइल ने ईरान के सात शहरों पर हमला किया है। पिछले रविवार को ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइल और ड्रोन दागे थे। इसके बाद इजराइल की ओर से ऐलान कर दिया गया था कि वह सही समय आने पर ईरान पर जवाबी प्रहार करेगा। पिछले 6 महीनों से गाजापट्टी पर इजराइल की निरंकुश कार्रवाई और दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले की प्रतिक्रिया में इजराइल पर ईरान के हमले के बाद मध्यपूर्व का संकट गहरा गया था। यद्यपि अमेरिका इजराइल को संयम बरतने की सलाह दे रहा है लेकिन इजराइल के जवाबी हमले से अमेरिका की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब स्थिति यह है कि इस युद्ध का विस्तार दूर-दूर तक हो सकता है। डर इस बात का है कि जिस तरह की भूमिका अमेरिका और उसके दुमछल्ले मित्र देश रूस-यूक्रेन युद्ध में निभा रहे हैं, वैसी ही भूमिका रूस और चीन इजराइल-ईरान टकराव में निभा सकते हैं। इस समय चीन और रूस ईरान के साथ खड़े दिखाई देते हैं।

अमेरिका इस समय सीधे युद्ध में कूदना नहीं चाहता। वह केवल इजराइल का मददगार बने रहना चाहता है। सच तो यह है कि ईरान के इजराइल पर हमले से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को घरेलू राजनीति में लाइफ लाइन मिल गई है। इजराइली सरकार के अतिराष्ट्रवादी सहयोगी नेतन्याहू पर ईरान पर हमला करने का दबाव बनाए हुए थे। ईरान-इजराइल लड़ाई शुरू होने से पूरी दुनिया की निगाहें गाजापट्टी में हो रही मानवीय तबाही से हट गई है। इजराइली सेना वहां आज भी नरसंहार कर रही है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अपने देश में ही घिरते जा रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव इसी वर्ष हैं। पहले बाइडेन की अफगानिस्तान को लेकर काफी आलोचना हो चुकी है। गाजा की भयानक स्थिति को लेकर भी बाइडेन अमेरिकी मतदाताओं के निशाने पर हैं। अमेरिका इस समय युद्धों के पूरी तरह खिलाफ है। बाइडेन के विरोधी विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी ही नहीं बल्कि उनकी अपनी डैमोक्रेटिक पार्टी के अधिकतर नेता भी उनके खिलाफ हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पद के चुनावों में बाइडेन को नुक्सान होना तय है।

अमेरिका इस समय सीधे युद्ध में कूदना नहीं चाहता। वह केवल इजराइल का मददगार बने रहना चाहता है। सच तो यह है कि ईरान के इजराइल पर हमले से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को घरेलू राजनीति में लाइफ लाइन मिल गई है। इजराइली सरकार के अतिराष्ट्रवादी सहयोगी नेतन्याहू पर ईरान पर हमला करने का दबाव बनाए हुए थे। ईरान-इजराइल लड़ाई शुरू होने से पूरी दुनिया की निगाहें गाजापट्टी में हो रही मानवीय तबाही से हट गई है। इजराइली सेना वहां आज भी नरसंहार कर रही है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अपने देश में ही घिरते जा रहे हैं।

ईरान और इजराइल के बीच तनातनी और हिंसक कार्रवाइयों का इतिहास पुराना है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है, जब ईरान ने अपनी धरती से इजराइल पर सीधे हमले किये हैं। इससे पहले के हमले ईरान अपने समर्थक समूहों, जैसे हमास, हिजबुल्लाह, अंसारअल्लाह, पॉपुलर मोबिलाइजेशन आदि के जरिये कराता रहा है। अब तक वह सीधे इजराइल से लड़ाई से बचता रहा है। सीरिया में उसके दूतावास पर हुए हमले की जवाबी कार्रवाई में किये गये इन हमलों से यह संकेत मिलता है कि ईरान अपनी पुरानी रणनीति में बदलाव कर रहा है। ईरान ने दूतावास हमले को अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है। ईरान ने इन हमलों को सीमित हमला कहा है, जिसके कुछ निशाने तय थे। हमलों के बाद उसने यह भी कहा है कि उसका जवाब पूरा हो गया और वह आगे हमले नहीं करेगा। साथ ही, उसने यह भी चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने फिर हमला किया, तो वह ज्यादा ताकत के साथ जवाब देगा।

कुछ दिन पहले ईरान के खोलेश्नरी गार्ड ने हार्मूज जलडमरू मध्य में इजराइली मालवाहक जहाज को कब्जे में लिया है। उस पर 17 भारतीय चालक दल सवार हैं। चालक दल की एक महिला कैडिट की अभी भारत वापसी हो चुकी है। उम्मीद है कि भारतीय विदेश मंत्रालय अन्य 16 भारतीयों को भी ईरान के कब्जे से मुक्त कराने में सफल हो जाएगा। इस संघर्ष से अब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई का मार्ग बाधित हो सकता है। युद्ध की स्थिति में फारस की खाड़ी, लाल सागर, स्वेज नहर और अन्य समुद्री रास्ते बाधित होंगे। इससे तेल की कीमतें बढ़ेंगी और तेल की कीमतें बढ़ने से हर चीज के दाम बढ़ेंगे। पहले ही रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहुत नुक्सान पहुंचाया है। पश्चिम एशिया में अशांति से चीन का आयात-निर्यात भी प्रभावित हो सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी कोरोना महामारी की छाया से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई है। यहां तक भारत की स्थिति है। भारत के इजराइल और ईरान दोनों से अच्छे संबंध हैं। दुनिया इस समय एक और युद्ध झेल नहीं सकती। इजराइल को अपनी स्वतंत्रता की रक्षा का पूरा हक है, मगर उसकी निरंकुश आक्रामकता को सहन नहीं किया जा सकता। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि वह युद्ध रोकने के लिए दोनों देशों पर दबाव बनाए। क्योंकि युद्ध किसी भी तरह से हितकर नहीं है।

आदित्य नारायण चोपड़ा

Adityachopra@punjabkesari.com

भड़काऊ और ओछी बयानबाजियों...

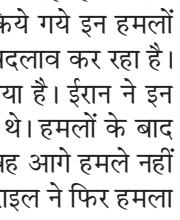

गीता पाढा

कृपा करके सभी दलों के अध्यक्ष अपने नेताओं की-
अभद्र भाषा व टिप्पणियों पर विराम लगाएं,
उचित-अनुचित के बारे में उनको ज्ञान कराएं,
भड़काऊ और ओछी बयानबाजियों से वह बाज आएं,
बेवजह न जनता के बीच मतभेद की दीवार बनाएं...!!!

गारंटियों का चुनावी महासंग्राम

राकेश कपूर

संसद से सड़क तक

kapurakesh@gmail.com

वर्तमान दौर के चुनावों में नया शब्द गारंटी निकल कर आया है जिसका अर्थ होता है कि मतदाताओं से जो वादा किया जाता है वह शर्तिया तौर पर राजनैतिक दल सत्ता में आने पर पूरा करेंगे। असल में यह विचारधारा से हट कर वादे पूरे करने का भी एक तरीका है हालांकि वादे विचारधारा के अनुसार ही राजनैतिक दल मतदाताओं से करते हैं। इन चुनावों में सत्तारूढ़ दल भाजपा भी गारंटी दे रही है और विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी गारंटी दे रही है।

दोनों की गारंटियों में मूल रूप से कोई बड़ा अंतर नहीं है क्योंकि जहां कांग्रेस पार्टी प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला को साल में एक लाख रुपए देने का वादा कर रही है तो वहीं भाजपा अगले साल पांच सालों के दौरान तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का दिलासा दे रही है। भाजपा और कांग्रेस के घोषणापत्रों में स्पष्ट अंतर यही है कि भाजपा राष्ट्रवाद को सर्वोच्च रख कर लोगों से वादे कर रही है और कांग्रेस लोक कल्याणकारी राज के वादे के साथ गांधीवाद के सिद्धान्त के अनुसार सीधे लोगों के हाथ में अधिकार देने का वादा करती लगती है। हालांकि भाजपा भी लोक कल्याणकारी राज की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध दिखती है मगर उसका लोगों को सशक्त बनाने का तरीका दूसरा है। वह वादा कर रही है कि युवा उद्यमियों को बिना बैंक गारंटी का 20 लाख रु. तक का ऋण अपना रोजगार शुरू करने के लिए दिया जायेगा जबकि कांग्रेस कह रही है कि केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में जो तीस लाख पद खाली पड़े हुए हैं उन्हें सत्ता पर पहुंचते ही तुरन्त भरा जायेगा।

भाजपा युवाओं को सीधे उद्यमी बनाना चाहती है जबकि कांग्रेस प्रत्येक शिक्षित युवा को प्रशिक्षु अधिनियम के तहत किसी व्यवसाय में पारंगत कर उसमें आगे नौकरी पाने का रास्ता खोलना चाहती है और एक साल के प्रशिक्षण के दौरान एक लाख रु. देने की गारंटी दे रही है। गौर से देखें तो केन्द्र सरकार ने फौज में भर्ती के लिए जो अग्निवीर योजना शुरू की वह इसी प्रशिक्षु स्कीम का विस्तारित रूप है जिसमें किसी नौजवान को चार साल तक सेना में सेवा में काम करने का अवसर दिया जाता है और उसके बाद 12 लाख रु. देकर उसे अपने विशेषज्ञ क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए स्वतन्त्र कर दिया जाता है। कांग्रेस का कहना है कि सेना के लिए यह प्रशिक्षु स्कीम अनुचित है और पुरानी प्रथा ही जारी रहनी चाहिए जिसमें किसी नौजवान को सेना से रिटायर होने के बाद पेंशन दी जाती थी।

युवा वर्ग के लिए यह मामला भावुकता का भी है मगर है यह कांग्रेस की प्रशिक्षु स्कीम के जैसा ही। यही वजह है कि कांग्रेस बेरोजगारी को बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। भाजपा ने इसका तोड़ तो निकाला है क्योंकि रक्षामन्त्री श्री राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि उनकी पार्टी की सरकार जरूरत पड़ने पर अग्निवीर स्कीम की समीक्षा करने के लिए तैयार है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भाजपा को अपने जन्म से लेकर ही बहुत पसन्द रहा है और 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव भी इसने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर ही जीते थे।

भाजपा की सबसे बड़ी गारंटी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी मानी जा रही है। भाजपा निश्चित रूप से यह कह सकती है कि राष्ट्रीय सन्दर्भों में उसने देशवासियों से जो वादे किये उन्हें पूरा किया। जैसे जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का उसका वादा 1953 से ही चला आ रहा था जब उसके संस्थापक डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान इसी उद्देश्य के लिए इसी राज्य की धरती पर हुआ था। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर का पृथक संविधान और प्रधानमन्त्री व ध्वज होता था।

1953 में डा. मुखर्जी ने यही नारा दिया था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चल सकते। हालांकि यह भी हकीकत है कि जब भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को जोड़ा गया था तो डा. मुखर्जी पं. जवाहर लाल नेहरू की ही सरकार में उद्योग मन्त्री थे। परन्तु उन्होंने दिसम्बर 1950 में पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री लियाकत अली खां के साथ पं. जवाहर लाल नेहरू का समझौता होने पर मन्त्रिमंडल से इस्तीफा दिया और 1951 में अपनी अलग भारतीय जनसंघ पार्टी बनाई। जनसंघ बनाने के बाद ही उन्होंने कश्मीर आन्दोलन में भाग स्व. पं. प्रेमनाथ डोगरा के निमन्त्रण पर 1952 के चुनावों के बाद लिया।

प. प्रेमनाथ डोगरा तब जम्मू-कश्मीर के प्रधानमन्त्री शेख अब्दुल्ला के विरुद्ध जबर्दस्त आंदोलन चला रहे थे। भाजपा ने दूसरा राष्ट्रीय वादा अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण का पूरा किया। हालांकि मन्दिर का निर्माण सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आने के बाद ही किया गया मगर भाजपा शुरू से ही देश के लोगों से यह वादा कर रही थी कि वह संवैधानिक दायरे में राम मन्दिर निर्माण करायेगी। इसके साथ ही भाजपा देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को महीने का मुफ्त राशन दे रही है जिसे अगले पांच साल भी जारी रखा जायेगा।

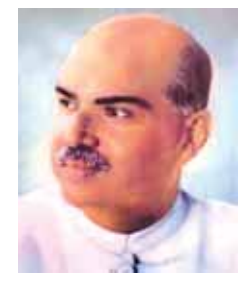

1953 में डा. मुखर्जी ने यही नारा दिया था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चल सकते। हालांकि यह भी हकीकत है कि जब भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को जोड़ा गया था तो डा. मुखर्जी पं. जवाहर लाल नेहरू की ही सरकार में उद्योग मन्त्री थे।

भाजपा ने संशोधित नागरिकता कानून को लागू करने का भी वादा किया था। उसने यह लागू कर दिया है। हम देखें तो कांग्रेस आम लोगों को उनके रोजमर्रा के मुद्दों पर फोकस कर रही है और बढ़ती महंगाई को भी एक चुनावी मुद्दा बना रही है। इसके साथ ही वह आर्थिक असमानता को भी एक मुद्दा बना रही है। जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस के राज 1991 से 1996 के दौरान ही इसके प्रधानमन्त्री स्व. पी.वी. नरसिम्हा राव ने ऐसी नीतियां चलाई थीं जिसकी वजह से भारत में आर्थिक असमानता बढ़ती चली गई।

बाजार मूल्क अर्थव्यवस्था की शुरुआत करके नरसिम्हा राव ने ही सरकारी दफ्तरों में ठेके पर कर्मचारी रखने की प्रथा शुरू की थी जिसमें बाद में आने वाली हर सरकार ने अपना और योगदान दिया। मगर अब राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं कि वे इस प्रणाली को बन्द कर देंगे। दरअसल राहुल गांधी आर्थिक मुद्दों पर देशवासियों को गारंटी देते लगते हैं और श्री मोदी राष्ट्रीय व सामाजिक मुद्दों पर। कुछ विशेषज्ञओं का मानना है कि राहुल गांधी भारत को नेहरू युग में ले जाना चाहते हैं जबकि मोदी विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं और उनकी गारंटियां इसी के अनुरूप हैं। यह देख कर मुझे 1967 के चुनावों की याद आ रही है जब प्रमुख विपक्षी पार्टी स्वतन्त्र पार्टी के नेता स्व. आचार्य एन.जी. रंगा ने नारा दिया था कि 'नेहरू का समाजवाद दम तोड़ रहा है' उस समय भी देश मे महंगाई व बेरोजगारी का आलम काबू से बाहर हो रहा था। मगर तब देश में गौहत्या विरोधी आन्दोलन भी शबाब पर था और जनसंघ का राजनैतिक पटल पर प्रभावशाली उदय हुआ था।

स्वतन्त्र पार्टी की इन चुनावों में 44 सीटें आयी थीं और जनसंघ की 33 अत: कोई भी चुनावी मुद्दा जनता के विमर्श में आ सकता है। अत: चुनावी गारंटियों का यह युद्ध पूरे चुनावों की दिशा तय करता दिखाई दे रहा है। मगर श्री मोदी की लोकप्रियता का तोड़ कांग्रेस के पास कोई नहीं है जो कि 1971 के चुनावों की याद दिला रहा है जिसमें इन्दिरा गांधी को भारी सफलता उनकी लोकप्रियता की वजह से ही मिली थी।

पहली बार कांग्रेस 400 से कम सीटों पर लड़ेगी ?

ताक-झांक

आर.आर. जैरथ

अपने इतिहास में पहली बार, कांग्रेस मौजूदा चुनावों में 400 से कम लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि उम्मीदवारों की पूरी सूची अभी घोषित नहीं की गई है, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी अपने राजनीतिक सहयोगियों के साथ समायोजन और गठबंधन के कारण 330 से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यह

उस पार्टी के लिए बहुत बड़ी गिरावट है जो कभी देश की राजनीति पर हावी थी और हर गांव में उसकी उपस्थिति थी। इसने हमेशा केरल जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर, जहां इसके क्षेत्रीय गठबंधन थे, लोकसभा की लगभग सभी 543 सीटों पर चुनाव लड़ा है। 2024 में कम आंकड़ा इस बात को रेखांकित करता है कि पार्टी ने पिछले तीन दशकों में कितनी राजनीतिक जगह खो दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को हराने की बेताब कोशिश में वह दूसरों को कितनी जगह देने पर सहमत हुई है। 2004 में कांग्रेस पहली बार गंभीर रूप से गठबंधन की राजनीति में उतरी। फिर भी, इसने तमिलनाडु में द्रमुक सहित कई अन्य दलों के साथ गठबंधन में वाजपेयी के शाइनिंग इंडिया अभियान से लड़ने के लिए खुद को सिकोड़ लिया। विडंबना यह है कि इसने एक बार डीएमके पर 1991 में राजीव गांधी की हत्या करने वाली ताकतों का समर्थन करने का आरोप लगाया था। 2004 में, कांग्रेस ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के हिस्से के रूप में 417 सीटों पर चुनाव लड़ा।

ठीक पांच साल बाद, जैसे ही यूपीए ने अपने साथी खो दिए, कांग्रेस ने 440 उम्मीदवार उतारे और वास्तव में 2019 में उसकी संख्या बढ़ गई। सबसे बड़ी गिरावट यूपी में हुई है जहां पार्टी ने 2019 में 67 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन इस बार अखिलेश यादव की सपा के साथ गठबंधन के कारण सिर्फ 17 सीटों पर लड़ रही है। कहने की जरूरत नहीं है कि 2019 में 67 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद, उसे सिर्फ एक सीट रायबरेली मिली थी। देखते हैं कि इस बार जब उसने केवल 17 उम्मीदवार उतारे हैं तो वह कितनों को जीतती है।

क्या राजपूतों को साध पाएगी भाजपा ?

यूपी में क्षत्रिय/राजपूतों के गुस्से को बढ़ाने वाले कई कारक हैं। इनमें से एक है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के साथ समुदाय के समझौते के बारे में केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला की टिप्पणियां, जिनमें अपनी बेटियों की शादी साम्राज्यवादियों से करना भी शामिल है। दूसरा कारण ओबीसी को लुभाने के लिए भाजपा द्वारा क्षत्रियों को दिए जाने वाले टिकटों की घटती संख्या है। भाजपा द्वारा अब तक मैदान में उतारे गए क्षत्रियों की संख्या केवल तीन है और यदि विवादास्पद पूर्व कुश्ती महासंघ प्रमुख बृजभूषण सिंह को टिकट दिया जाता है तो यह चार तक पहुंच सकती है। यह 2019 के मुकाबले करीब 50 फीसदी कम है। लेकिन यूपी में एक कानाफूसी अभियान शुरू हो गया है कि अगर पीएम मोदी 400 सीटों के साथ तीसरी बार जीत हासिल करते हैं, तो भाजपा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जगह किसी ओबीसी

नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी।

इस बार टिकट वितरण में क्षत्रियों को हाशिये पर धकेलने के साथ-साथ, समुदाय को युद्ध पथ पर ला खड़ा किया है। हाल के सप्ताहों में, पूरे पश्चिमी यूपी में क्षत्रिय जनसभाएं आयोजित की गई हैं, जहां प्रतिभागियों ने 2024 में भाजपा को वोट न देने की कसम खाई है। बीजेपी नेता डैमेज कंट्रोल मोड में हैं। रूपाला की टिप्पणियों के कारण गुजरात में क्षत्रियों के गुस्से को कम करने की कोशिश करने के बाद, उन्होंने अपना ध्यान पश्चिमी यूपी की ओर केंद्रित कर दिया है और समुदाय के नेताओं को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

आदित्य के उभार से खुश नहीं अखिलेश यादव

एक और राजनीतिक उत्तराधिकारी उभर रहा है। अखिलेश यादव के चचेरे भाई आदित्य यादव। वह इस बार यूपी की बदायूं सीट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव इस बात से ज्यादा खुश नहीं हैं। उन्होंने शुरू में इस सीट के लिए धर्मेंद्र यादव को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया था। जाहिर तौर पर, उनके चाचा शिवपाल यादव, जो आदित्य के पिता हैं को धर्मेंद्र यादव की उम्मीदवारी पर आपत्ति थी। अपने चाचा को संतुष्ट करने की उम्मीद में, अखिलेश यादव ने सीट के लिए पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उनके नाम की घोषणा की। लेकिन शिवपाल यादव ने कहा कि वह राज्य की राजनीति में ही रहना चाहते हैं और उन्हें लोकसभा में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। भारी सौदेबाजी के बाद, अखिलेश यादव अनिच्छा से चचेरे भाई आदित्य को टिकट देने पर सहमत हुए। ऐसा लगता है कि आदित्य अपने पिता की मदद कर रहे हैं लेकिन अब चुनावी राजनीति में

औपचारिक प्रवेश करना चाहते हैं।

सोनिया ही कांग्रेस की संकटमोचक ?

सोनिया गांधी कांग्रेस के लिए संकटमोचक के रूप में अपरिहार्य बनी हुई हैं। अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद, उन्होंने मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह और बेटे विक्रमादित्य को भाजपा में शामिल होने से रोकने के लिए कदम उठाया। सोनिया गांधी ने ही विक्रमादित्य सिंह को मंडी सीट से मैदान में उतारने की सलाह दी थी, जहां

उनके पिता दिवंगत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की जड़ें गहरी थीं और लोग आज भी उन्हें प्यार से याद करते हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस कदम को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन सोनिया अपनी बात पर अड़ी रहीं और आखिर में सोनिया की ही बात मानी गई। हिमाचल प्रदेश से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, मंडी में मुकाबला कड़ा हो गया है और बॉलीवुड अभिनेत्री और मोदी-शाह की पसंदीदा कंगना रनौत के लिए यह मुश्किल हो सकता है क्योंकि वह चुनावी राजनीति में प्रयोग कर रही हैं।

सपा : प्रत्याशी चयन में पीडीए को तवज्जो

राहिल नोरा चोपड़ा

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मर्तबा लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन में एक रणनीतिक बदलाव की अगुवाई की है। उनके इस प्रयास को मुस्लिम-यादव समर्थक पार्टी की छवि से दूर अपनी पार्टी की छवि को एक नया स्वरूप देने के तौर पर देखा

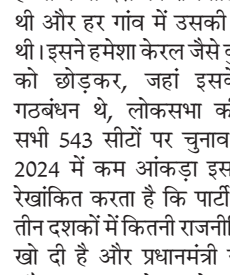

जा रहा है। पार्टी ने गैर-यादव अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को लुभाने के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन करते समय स्थानीय जाति समीकरणों और अपने 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के नारे को ध्यान में रखा, जो आबादी का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा है। सपा द्वारा अब तक घोषित 57 उम्मीदवारों में से केवल चार मुस्लिम हैं और चार यादव समुदाय से हैं। अधिकांश उम्मीदवार सामान्य, अनुसूचित जाति (एससी) और गैर-यादव अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) पृष्ठभूमि से हैं।

पार्टी ने रामपुर, कैराना, संभल और गाजीपुर से मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं, आजमगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद और मैनपुरी से यादव समुदाय के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इसने सामान्य श्रेणियों के नौ, अनुसूचित जाति के 15 और ओबीसी के 29 उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा है। इसमें जाट, गुर्जर और निषाद समुदाय के उम्मीदवारों को भी शामिल किया गया है। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि उनके तीन चचेरे भाई-धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और आदित्य यादव-क्रमशः आजमगढ़, फिरोजाबाद और बदायूं लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि, एसपी 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस के लिए 17 और टीएमसी के लिए एक सीट छोड़ी जाएगी।

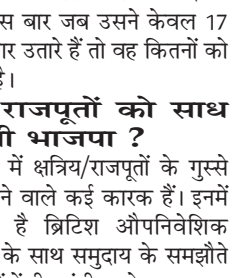

सहारनपुर में गरजी प्रियंका

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अपने पहले रोड शो में कृषि ऋण, चुनावी बाण्ड, बेरोजगारी और नोटबंदी को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। एक बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश पर शासन करने वाले लोग 'सत्य' या 'मां शक्ति' के नहीं, बल्कि केवल 'सत्ता' (शक्ति) के उपासक हैं। रोड शो में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के झंडे और बैनर लहराते हुए उत्साही कांग्रेस सदस्यों के साथ मार्च करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर प्रचार कर रही हैं और अगर पार्टी उन्हें अनुमति देती है तो अब वह रायबरेली सीट से लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसे होता है तो वह रायबरेली से चुनाव लड़ने वाली नेहरू-गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी होंगी।

भाजपा की रैलियों में नीतीश की अनुपस्थिति पर तंज

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग भाजपा के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के चुनाव अभियान में गायब है, जबकि विपक्षी महागठबंधन इस मांग को अपने अभियान के दौरान बार-बार उठा रहा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य यह दिखाना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे एक दशक पहले जनता से किए गए वादे को पूरा करने में विफल रहे हैं।

लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज होने के साथ ही जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार के दौरान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की अपनी दीर्घकालिक मांग पर पूरी तरह से चुप हैं, वहीं दूसरी ओर, राजद नेता तेजस्वी यादव ने राज्य में भाजपा की चुनावी रैलियों में नीतीश कुमार की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया है। नीतीश कुमार जी कहां हैं? भाजपा उन्हें अपनी रैलियों में क्यों नहीं बुला रही है? मंगलवार को पीएम की किसी भी रैली में

वह नजर नहीं आए। तेजस्वी यादव ने कहा, मेरे मन में अभी भी सीएम के लिए सम्मान है...बीजेपी, जो उनकी वर्तमान सहयोगी है, को इस मामले पर सफाई देने की जरूरत है।

भारत, बुल्गारिया के ऑडिट संस्थानों के बीच समझौता

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने बुल्गारिया के राष्ट्रीय लेखा परीक्षा कार्यालय 'एसएआई बुल्गारिया' के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

कैग ने यहां जारी एक बयान में कहा कि दोनों देशों के शीर्ष ऑडिट संस्थानों ने इस आशय के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच ऑडिटिंग के क्षेत्र में सहयोग और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान बढ़ाना है।

- ऑडिटिंग के क्षेत्र में सहयोग और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान बढ़ाना है

एमओयू के जरिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग और ऑडिट कार्यों में परस्पर सहयोग से ऑडिटिंग पेशेवरों और तकनीकी टीमों के बीच ज्ञान और अनुभव के आदान-प्रदान के लिए एक मंच स्थापित किया जाएगा। एमओयू पर हस्ताक्षर के समय बुल्गेरियाई राष्ट्रीय लेखा परीक्षा कार्यालय की कार्यवाहक अध्यक्ष गोरिट्सा ग्रैनचारोवा- कोजोरेवा भी मौजूद रहीं।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83

पंजाब केसरी

दिल्ली कार्यालय :

फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

युद्ध की भड़कती आग

ईरान और इजरायल जिस राह पर निकल पड़े हैं, वह युद्ध और विनाश की ओर ही जाता है। इस महीने की शुरुआत से ही दोनों देशों से 'हमला' और 'बदला' जैसे शब्द सुनाई दे रहे हैं। 1 अप्रैल को सीरिया के दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला हुआ, तो इसका आरोप इजरायल के मत्थे मढ़ा गया। दो हफ्ते बीतने से पहले ही ईरान ने उसका बदला लेने के लिए हमला बोल दिया। उसने इजरायल पर करीब 300 मिसाइलें दागीं। हालांकि, इजरायल ने दावा किया कि उसने ज्यादातर मिसाइलें लक्ष्य तक पहुंचने से बहुत पहले ही नष्ट कर दीं। नुकसान शायद बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन यह उसके सम्मान पर बहुत बड़ी चोट थी। पिछले तीन दशक में किसी देश ने पहली बार इजरायल की धरती पर इस तरह से बमबारी की जुर्रत की थी। इस शुक्रवार को इजरायल ने इसका बदला ले लिया। इजरायल के वमवर्षक ड्रोन ईरान की ओर उड़े और उसके सैन्य शहर इशफाहान पर बम बरसाए। इशफाहान के बारे में कहा जाता है कि इसी जगह पर ईरान अपना परमाणु बम विकसित कर रहा है। इसके अलावा, यह ईरानी फौज का सबसे बड़ा बेस भी है।

यह हमला कितना बड़ा था, इसके बारे में फिलहाल बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ खबरों में तीन बड़े धमाकों की आवाज सुनाई देने की बात कही गई है। हालांकि, ईरान और इजरायल, दोनों ने ही इसे कमतर दिखाने की कोशिश की है। तेहरान ने कहा है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जबकि इजरायल ने आश्वस्त किया है कि यह हमला ईरान के परमाणु केंद्र पर नहीं था। वैसे मामला हमले के बड़े या छोटे होने का नहीं है, मामला पश्चिम एशिया में और खासकर इन दोनों देशों के बीच उस तनाव का है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। अतीत में भी इजरायल एक बार ईरान के इसी शहर पर हमला कर चुका है, लेकिन इस बार तनाव बहुत ज्यादा है, इसलिए आशंकाओं की भरमार भी दुनिया को सिहरन दे रही है। अभी ईरान की तरफ से एक बयान यह भी आया है कि फिलहाल इस हमले का बदला लेने का उसका कोई इरादा नहीं है, लेकिन आम धारणा यही है कि बदला देर-सवेर लिया ही जाएगा। अगर इसी तरह से बदला-दर-बदला बात चलती रही, तो पश्चिम एशिया का यह तनाव कब पूर्ण युद्ध में बदल जाएगा, कहा नहीं जा सकता। पिछले चंद रोज में गाजा में जिस तरह का मानवीय संकट खड़ा हुआ है, इजरायल इन झड़पों के चलते उससे दुनिया का ध्यान हटाने में जरूर कामयाब रहा है।

अगर इसी तरह से बदला-दर-बदला बात बढ़ती रही, तो ईरान-इजरायल का यह तनाव कब पश्चिम एशिया में पूर्ण युद्ध में बदल जाएगा, कहा नहीं जा सकता।

पिछले कुछ महीनों से पश्चिम एशिया में जैसे तनाव दिख रहे हैं और जिस तरह के खतरे खड़े हो रहे हैं, उसके सामने पूरी दुनिया महज तमाशबीन बनी दिख रही है। खासकर जिनको हम महाशक्तियां कहते हैं, वे मौन हैं। रूस यूक्रेन के साथ लड़ाई में उलझा हुआ है। चीन अपनी सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है। अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव है और ऐसे मौके पर कोई यह मानने को तैयार नहीं कि वह पश्चिम एशिया में निष्पक्ष भूमिका निभा सकेगा। संयुक्त राष्ट्र की अपनी सीमाएं हैं और अक्सर वह ऐसे युद्धों को रोकने में कारगर नहीं हो पाता। बड़ी समस्या यह नहीं है कि इजरायल-ईरान का तनाव बढ़ रहा है और कभी भी आग के भड़क उठने की आशंकाएं हैं, समस्या यह है कि यह सब ऐसे मोड़ पर हो रहा है, जहां पहुंचने के लिए समझदारी के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले | 20 अप्रैल, 1949

प्रजातंत्री आयर

आयरलैण्ड जिसे संक्षेप में आयर भी कहते हैं, अब प्रजातंत्री राष्ट्र बन गया है। उसने ब्रिटेन के साथ अपने सदियों पुराने संबंधों को समाप्त कर दिया है। आयरिश प्रजा में स्वतंत्रता की तीव्र आकांक्षा थी, जिसने उसे उस समय तक बेचैन रखा, जब तक वह पूरी नहीं हो गई। आयर के लिए यह हर्ष का दिन है। उसके चिरस्वप्नों की आज पूर्ति हुई है और इसलिए आयरिश प्रजा ने जिस हर्ष और उल्लास के साथ उसका स्वागत किया, यह स्वाभाविक ही था। आयर के इतिहास में सन् १९१६ का ईस्टर स्मरणीय रहेगा; क्योंकि आयर के देशभक्तों ने ब्रिटेन के प्रभुत्व के विरुद्ध तब विद्रोह का झण्डा बुलन्द किया था। आयरिश प्रजा ने अपना स्वतंत्रता संग्राम जिस वीरता के साथ लड़ा और उसमें जो कुर्बानियां दीं, उनसे अनेक पराधीन देशों को प्रेरणा मिली और आगे भी मिलती रहेगी। भारत और आयर के बीच हमेशा प्रगाढ़ सहानुभूति के संबंध रहे हैं और भारतवासियों की इस अवसर पर यही कामना हो सकती है कि आयर फले-फूले और संसार के देशों में सम्मान का स्थान प्राप्त करे। आयर के लिए इस हर्ष के बीच विषाद की एक ही रेखा खिंची रही और वह यह कि उत्तरी आयरलैण्ड अब भी उससे पृथक बना हुआ है। आयरिश स्वाधीनता के अन्यतम योद्धा श्री डी वेलरा और उनकी पार्टी का हर्ष समारोहों से अलग रहना इसी असंतोष को प्रकट करता है। आयर के प्रधानमंत्री ने उत्तरी आयरलैण्ड वालों के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि यदि वे रक्षा और वैदेशिक मामले अखिल आयर सरकार के सुपुर्द कर दें, तो शासन की शेष सत्ता अभी की भांति उनके हाथों में रह सकती है। उत्तरी आयरलैण्ड वाले अपनी जिद पर डटे हुए हैं, इसलिए आयरलैण्ड का विभाजन बना रहेगा। किन्तु हमारी आशा है कि एक न एक दिन ऐसा अवश्य आयेगा, जब आयर पुनः संयुक्त होगा।

शिक्षा की समस्या- स्वतंत्र भारत को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनमें शिक्षा की समस्या असाधारण महत्व रखती है। देश का भविष्य आने वाली पीढ़ी पर जितना निर्भर करता है, उतना मौजूदा पीढ़ी पर नहीं। आने वाली पीढ़ी को अपने दायित्व का बोझ उठाने के लिए सक्षम बनाना उस शिक्षा पर निर्भर करता है जो आज दी जायेगी।

सड़क से सर्वोच्च न्यायालय तक ईवीएम और वीवीपैट की चर्चा है, पर एक वह भी समय था, जब लोग मतपत्र मतदान केंद्र से बाहर लाकर बेच देते थे और साल 1960 में चुनाव प्रक्रिया में बड़े सुधार की पहल हुई थी। उस साल 16 दिसंबर को संसद में हुई बहस आज भी प्रासंगिक है।

लोगों को सिखाएं कि अपना वोट नहीं बेचें

ए के सेन | तत्कालीन केंद्रीय विधि मंत्री

- मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारे देश के मतदाता इतने जाहिल हैं।
- गरीब मतदाता मतपत्रों को बाहर ले जाकर बेच देते थे। यह खतरनाक है।
- बहुत से लोग मतपत्र कहीं भी रखकर और नमस्कार करके लौट जाते हैं।

सभा को याद होगा कि निशान लगाकर मतदान की प्रणाली 1952 के सामान्य निर्वाचन के पहले प्रचलित थी। वास्तव में सन् 1945 के सामान्य निर्वाचन निशान लगाकर मतदान करने की प्रणाली के अंतर्गत ही हुए थे।... यह ठीक है कि इधर-उधर कुछ गलतियां भी हुईं। जब 20 करोड़ व्यक्ति मत देने आएंगे, तो कुछ गलतियां अवश्य ही होंगी, परंतु देश के आकार और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए हमने चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर जो चुनाव व्यवस्था निर्धारित की है, वह सर्वथा सफल सिद्ध हुई है...। निशान लगाकर मतदान के विरुद्ध केवल एक तर्क पेश किया गया है और वह यह कि जब संसद के माननीय सदस्य भी बटन ठीक से नहीं दबा सकते, तो अशिक्षित मतदाता मतपत्र पर सही निशान कैसे लगा सकते हैं? ...हमें स्वीकार करना चाहिए कि उसमें शिक्षा का विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि शिक्षित होने के बावजूद लोग गलतियां कर सकते हैं।...

पहले हम गांवों की बात करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे अधिकांश देशवासी गांवों में ही रहते हैं। अभी जो प्रणाली प्रचलित है तथा जो 1952 और 1957 में भी अपनाई गई थी, वह यह है कि एक कमरे में उतनी मतपेटियां रखी जाती हैं, जितने उम्मीदवार होते हैं और प्रत्येक पेटी पर एक उम्मीदवार का चुनाव-चिन्ह अंकित होता है। यदि दस उम्मीदवार होंगे, तो दस पेटियां होंगी। ...अब उसे अनेक मतपेटियां न देखकर एक कागज पर बने चुनाव चिन्हों में से एक चिन्ह चुनना होता है। ...मैं ऐसे अनेक मामले जानता हूं, जिनमें मतपेटियां इस प्रकार रख दी जाती हैं कि आदमी अपनी पसंद की पेटी नहीं तलाश कर पाता और मतपत्र को वहीं कहीं डाल देता है अथवा अपने साथ ही लेकर चला जाता है। मैं समझता हूं, जब एक व्यक्ति अनेक पेटियों में से चिन्ह देखकर अपनी पसंद की पेटी तलाश कर सकता है, तो कोई कारण नहीं कि वह मतपत्र पर भी वह चिन्ह न तलाश कर सके, जिस पर वह निशान लगाना चाहता है। ...वास्तव में मेरा तो विचार यह है कि जो प्रणाली हम अब अपनाने जा रहे हैं, वह पहले वाली प्रणाली से अधिक सरल है।...

मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हमारे मतदाता इतने जाहिल हैं। बात वास्तव में यह है कि हम उन्हें भली प्रकार समझाते नहीं हैं। शिक्षा का इससे कोई संबंध नहीं है। ...जिन बुराइयों के निराकरण के लिए यह प्रणाली निकाली गई थी, वे अनेक हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि गरीब मतदाता मतपत्रों को बाहर ले जाकर बेच देते थे। प्रजातंत्र के लिए इससे अधिक खतरनाक चीज कोई नहीं है। वर्तमान प्रणाली में मतदाता मतपत्र को बाहर नहीं ले जा सकेगा, क्योंकि मतपत्र निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में पेटी में डाला जाएगा। ...एक अन्य बात यह है कि बहुत से लोग मतपत्र लेकर उसे कहीं भी रखकर और नमस्कार करके चले जाते हैं। ...अब संसदीय सीट की मतगणना को ले लीजिए। बहुत से गणक मेज पर बैठते हैं और मतपेटियां फैला दी जाती हैं। प्रत्येक पेटी से मतपत्र निकालकर गिने जाते हैं। उस समय उनको एक-दूसरे में आसानी से मिलाया जा सकता है। एक बार उनके मिल जाने पर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा मतपत्र किसके लिए था। वर्तमान प्रणाली में यह दोष भी दूर हो जाएगा।

निशान लगाकर मतदान की नई प्रणाली को तुरंत क्रियान्वित करना संभव नहीं होगा। हम यह चुनाव आयुक्त पर छोड़ देंगे कि वह जिन क्षेत्रों को ठीक समझें, उनको नई प्रणाली लागू करने से छूट दे सकें। हम स्वयं निर्धारण नहीं करेंगे। ...आयुक्त के लिए नई प्रणाली को तुरंत लागू करना कठिन होगा। हमें याद रखना चाहिए कि आगामी वर्षों में हमारे देश में साक्षरता भी बहुत बढ़ जाएगी। अनुमान है, 1961 की जनगणना में 40 प्रतिशत साक्षरता हो जाएगी। इसलिए हमें ऐसी प्रणाली को यथाशीघ्र लागू करने का प्रयत्न करना चाहिए।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

आमने-सामने

सीखते, तो अभी तक सब सज्जन हो जाते

विभूति मिश्र | वरिष्ठ नेता व तत्कालीन सांसद

- संसद क्या जांच नहीं कर सकती कि मतदाता बुद्धिमान हैं या नहीं हैं?
- अमेरिका में मार्किंग सिस्टम है, मशीन का प्रयोग है, पर वहां भी गलती हुई है।
- यह कहना तकनीकी बात है कि तमाम लोगों को सिखाया जा सकता है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की तारीफ करता हूं कि ईमानदारी के साथ उन्होंने मार्किंग सिस्टम को जारी किया है, पर उन्होंने खुद ही अपने भाषण में इस बात को कबूल किया है कि जो दूरदराज के इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, वहां इस व्यवस्था को लागू नहीं किया जाना चाहिए। ... शहरों में वह इस व्यवस्था को लागू करने के हक में हैं, किंतु पिछड़े इलाकों में लागू करने के पक्ष में नहीं हैं और उनके लिए उन्होंने कहा कि सिंबल सिस्टम ही जारी रखा जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा है कि मतदाता बुद्धिमान हों। मैं कहना चाहता हूं कि यह संसद ही अगर इस बात की जांच नहीं कर सकती कि मतदाता बुद्धिमान हैं या नहीं, तो और कौन कर सकता है? ...यह कहा गया है कि मतगणना में गड़बड़ी होती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसमें कभी गड़बड़ी नहीं होती है। एक प्रत्याशी के पहले सारे मत गिन लिए जाते हैं और उसके बाद पेटी में बंद हो जाते हैं और उसके बाद ही दूसरे प्रत्याशी के मतों की गिनती होती है। मेरी इस बात का मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है कि 42 करोड़ बैलेट पेपर और 15 दिन के अंदर हिन्दुस्तान में सुरक्षा के साथ छपवाए जा सकते हैं या नहीं छपवाए जा सकते हैं। ...मैंने अमेरिका का उदाहरण दिया था। वहां मार्किंग सिस्टम है और वहां पर इस काम में मशीन को इस्तेमाल में लाया जाता है, पर वहां भी गलती हुई है।...

मैं नहीं कहता कि मार्किंग सिस्टम फेल होगा, पर फेल अगर होता है, तभी तो सुधार की बात कही जाती है। ...सुधार की बात सिंबल सिस्टम में भी और मार्किंग सिस्टम में भी, दोनों में लागू होती है। इस वास्ते क्यों न पुराने सिस्टम को सुधार करके चालू रखा जाए?

...गांव में आज दिन भी बड़े-बड़े लोग रहते हैं और उनके सामने जाकर गरीब आदमी को वोट देना होगा और वह बड़ा आदमी उसको डरा-धमकाकर जिसको चाहेगा, वोट दिलवा देगा और उसको कह देगा कि फलां बक्से में वोट डालो। उस गरीब आदमी को दिखलाना पड़ेगा कि वह उसको वोट दे रहा है या उसके कहने के मुताबिक वोट दे रहा है। ...गोपनीयता नहीं रह पाएगी।

आप कहते हैं कि मार्किंग सिस्टम में मतदाता को शिक्षित किया जाए और उसको कहा जाए कि वह अपना मत न बेचे। ...आप यह भी कहते हैं कि प्रत्याशी उनको बुद्धिमानी से शिक्षित करें। मैं पूछना चाहता हूं कि इस सदन में कितने माननीय सदस्य ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा जनसेवा में लगाया है?...

जहां तक इल्जाम लगाने का ताल्लुक है, वह कोई भी लगा सकता है। चाहे यहां धर्मराज भी आकर बैठ जाएं, तो उनके खिलाफ भी इल्जाम लगाए जाएंगे। ...हमारे यहां के चुनाव की आज दुनिया भर में साख है। पहले हमारे (सुकुमार) सेन साहब चुनाव आयुक्त थे..., उन्होंने ईमानदारी के साथ चुनाव करवाया...।

यहां कुछ लोगों का दिल्ली, कलकत्ता, बंबई आदि बड़े शहरों में रहने के कारण गांवों से संपर्क छूट गया है। ...केरल में जो उप-चुनाव हुआ, उसे कराने के लिए सारे हिन्दुस्तान की हर पार्टी के लोग गए थे और एक-एक वोटर को चार-चार आदमी सिखाने के लिए थे, तो केरल का चुनाव कोई उदाहरण नहीं है। ...जब आम चुनाव होंगे, तब सारे हिन्दुस्तान में एक साथ होंगे। उस समय हर एक अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में काम करेगा। जब अपनी दाढ़ी में आग लगेगी, तो कौन किसी और को देखेगा और दिखाएगा। यह कहना तो एक तकनीकी बात है कि लोगों को सिखाया जा सकता है। अगर ऐसा होता, तो आज सारे लोग सज्जन हो गए होते और धर्मात्मा हो गए होते। राजा रामचंद्र के राज में और युधिष्ठर के राज में भी यही कहा जाता था, पर लोग शिक्षित नहीं हो पाए। असलियत देखते हुए मैं कहता हूं कि सेन साहब या चुनाव आयुक्त हमारे साथ हिन्दुस्तान के देहात का पैदल दौरा करें, तब उन्हें सही स्थिति का ज्ञान हो सकेगा।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

ताकि वकील बनने के लिए भी लालायित हों योग्य युवा

हरिवंश चतुर्वेदी | शिक्षाविद, पूर्व निदेशक, बिमटेक

भारत के इंजीनियर, डॉक्टर और चिकित्सकों की दुनिया भर में मांग है, ठीक ऐसे ही विधि विशेषज्ञों की भी मांग होनी चाहिए। बार काउंसिल का प्रयास हमें इसी दिशा में ले जाता है।

विधि शिक्षा की नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था, 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया' ने सभी राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखकर विधि शिक्षा के अंधाधुंध विस्तार पर गहरी चिंता व्यक्त की है। बार काउंसिल ने विधि शिक्षा के अत्यधिक विस्तार पर अंकुश लगाने के अनुरोध की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया है। ध्यान रहे, विगत कुछ वर्षों में राज्य सरकारों ने 300 नए विधि महाविद्यालय खोलने की अनुमति दी है।

विधि शिक्षा हमारे देश की पूरी व्यवस्था की रीढ़ की तरह है। फिलहाल विधि महाविद्यालयों की संख्या 1,800 से अधिक है, जिनमें करीब 1,200 कॉलेज निजी क्षेत्र में, 500 से ज्यादा कॉलेज सरकारी क्षेत्र में और लगभग 100 कॉलेज अर्द्ध-सरकारी क्षेत्र में हैं। यूं तो भारत में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की कमी और आधारभूत मानकों की अवहेलना पर राष्ट्रीय स्तर की चर्चा होती रही है, किंतु विधि शिक्षा की गिरावट सभी हदों को तोड़ती रही है।

आज अगर सभी क्षेत्रों में गिरावट या कमी दिख रही है, तो इसकी एक बुनियादी वजह कमजोर विधि शिक्षा भी है। बार काउंसिल के नए प्रयास अगर साकार होते हैं, तो असर देश में सभी क्षेत्रों पर पड़ेगा। आज कोई भी शहर देख लीजिए, वकीलों की दयनीय स्थिति कई बार मजाक का विषय बन जाती है। विधि शिक्षा के महत्व को आज उच्च प्राथमिकता देने की जरूरत है। इसे हम अपने गणतंत्र, संसदीय व्यवस्था, संविधानवाद, नागरिकों के मूलभूत अधिकार, स्वाधीनता, बालिग मताधिकार और सब प्रकार के भेदभाव पर सांविधानिक निषेध से जोड़कर देख सकते हैं। जरा सोचिए, उपरोक्त व्यवस्थाओं को निर्मित करने वाले हमारे राष्ट्र निर्माता कौन थे और वे किस पेशे से जुड़े थे और कौन-सी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी? महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव आंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और सी राजगोपालाचारी जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने कानून की बेहतरीन शिक्षा ली थी और वकालत के पेशे से जुड़े थे। क्या आज स्तरहीन कानून की शिक्षा लेकर वकील बनने वाले लोग हमारे सांविधानिक ढांचे की उचित रखवाली और कानून के शासन के व्याख्याता बन सकते हैं? यही कारण है कि यहां बार काउंसिल की चिंताएं समीचीन जान पड़ती हैं। हम 2047 तक एक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। क्या कानूनी शिक्षा की मौजूदा हालत को सुधारे बिना और वकालत के पेशे को सुदृढ़ किए बिना विकसित भारत : 2047 का सपना साकार किया जा सकता है? हमें उन चुनौतियों से रूबरू होना पड़ेगा, जिनका सामना आज कानूनी शिक्षा और वकालत का पेशा कर रहा है।

इंजीनियरिंग में आईआईटी, प्रबंधन में आईआईएम और चिकित्सा में एम्स की तरह विधि शिक्षा में उच्च मानक स्थापित करने के लिए 1990 के दशक में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों की संख्या अब 27 हो चुकी है। चूंकि इनकी स्थापना सरकारों द्वारा विधिवत समुचित संसाधनों से की गई, अतः आज ये चमकते सितारे बन चुके हैं। इनके स्नातकों की मांग देश-विदेश में बढ़ती जा रही है। इनकी प्रसिद्धि का एक कारण तीन वर्ष की लॉ डिग्री न देकर पांच वर्षीय एकीकृत डिग्री देना भी रहा है। क्या इन राष्ट्रीय संस्थानों जैसी गुणवत्ता देश के सभी 1,800 विधि संस्थानों में बहाल की जा सकती है?

भारत के इंजीनियर, डॉक्टर और प्रबंधकों की दुनिया भर में मांग है, ठीक ऐसे ही विधि विशेषज्ञों की भी मांग होनी चाहिए। आने वाले समय में विश्व स्तर पर अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए भी गुणवत्ता वाले लाखों वकीलों की जरूरत पड़ेगी। कुछ निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों ने जो उल्लेखनीय मानक स्थापित किए हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अभी हाल ही में जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत को क्यूएस रैंकिंग में एशिया के स्तर पर प्रथम स्थान मिला है, जो निस्संदेह सराहनीय है। इससे अन्य संस्थानों को भी प्रेरणा मिलनी चाहिए।

आज डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक बनने के लिए प्रतिभाशाली युवाओं के बीच भेड़चाल दिखाई देती है। अगर हम विधि शिक्षा के लिए भी प्रतिभावान युवाओं में आकर्षण पैदा कर सके, तो सबको लाभ होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

उदारता क्यों जरूरी

जीवन में जब-जब तुम रुकावट महसूस करते हो, तुम्हारा विकास नहीं हो रहा, तुम इच्छाओं से घिरे हो, तुम्हें रूखापन महसूस होता है, तब तुम्हें क्या करना चाहिए? इसका सरल समाधान है- उदार बनो। कल नहीं, अभी, इसी क्षण। राजा हो या भिखारी, दोनों उदारता महसूस कर सकते हैं। उदारता चित्त की विशेषता है। जब तुम उदार महसूस करते हो, तुम्हारा जीवन समृद्ध होता है- अनुकंपा और प्रेम से परिपूर्ण होता है।

कई बार लोग पूछते हैं, क्या उदारता और कृतज्ञता एक ही है? नहीं, कृतज्ञता में ध्यान खुद पर होता है। तुम कृतज्ञ क्यों हो? इसलिए कि तुम्हारे पास कुछ है या तुम्हें कुछ मिला है। उदारता एक अभिव्यक्ति है, जो बाहरी परिस्थितियों से विमुक्त है। कोई अन्य तुम्हें उदार नहीं महसूस करा सकता। इसे तुम्हें स्वयं महसूस करना है। वास्तव में, उदारता कोई कृत्य नहीं, चेतना की अवस्था है, परंतु इसकी अभिव्यक्ति हमेशा कृत्य द्वारा ही होती है। एक बात हमेशा याद रखो, आसक्ति अभाव को दर्शाती है, अनासक्ति समृद्धि है। उदारता के बिना अनासक्ति स्वार्थी बनाती है, रूखापन लाती है। भूतकाल में की गई उदारता को याद करने से केवल कर्तापन आता है। इसे छोड़ो और केवल उदार महसूस करो।

समय को अपनी मौजूदगी का उत्सव मनाने दो। प्रायः तुम उत्सव में खो जाते हो। जब तुम काल को अपना उत्सव मनाने देते हो, तब उत्सव के बीच भी तुम साक्षी बनकर रहते हो। जब तुम संसार के लिए जीते हो, तो संसार सौभाग्यशाली बनता है। तुम अपने लिए नहीं जी रहे, संसार के लिए जी रहे हो। जो कुछ भी संसार को चाहिए, जो उसे जरूरत है, तुम उसकी पूर्ति के लिए हो।

श्री श्री रविशंकर

डॉ एसवाई कुरैशी | पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

यूरोप के 86 प्रतिशत देशों में राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए राज्य से धन दिए जाने की व्यवस्था है। यदि वहां पर यह प्रणाली अच्छा काम कर सकती है, तो भारत में क्यों नहीं करेगी?

ब्रिटिश सांसदों की अनुचित हरकत

ब्रिटेन के 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' में विंचेस्टर से प्रतिनिधि लॉर्ड बिशप ने भारत में धार्मिक आजादी व मणिपुर हिंसा को लेकर सवाल उठाया और ऋषि सुनक सरकार से जवाब-तलब किया। यह पहली बार नहीं है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के अंदरूनी मामले पर बात की गई और एक तरह से हमें कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। इसके पहले भी किसान आंदोलन के दौरान भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसदों ने भारत सरकार की कार्रवाई पर 'हाउस ऑफ कॉमन्स' में बहसबाजी की थी। ब्रिटिश सांसदों की यह बेजा हरकत है और हमारी सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। यह हमारे आंतरिक मामले पर टिप्पणी है।

ब्रिटेन के राजनेता भारत में धार्मिक आजादी पर उंगली उठाते हैं, मगर खुद वहां पर हमारे राजनयिक जब गुरुद्वारा जाना चाहते हैं, तो असामाजिक तत्वों द्वारा उनके साथ अभद्रता की जाती है और ब्रिटिश पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है। भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी के साथ स्कॉटलैंड में क्या हुआ था, क्या यह याद दिलाने की जरूरत है? वहां मंदिरों की दीवारों को विकृत कर, उन पर नफरत फैलाने वाले नारे लिखकर अपराधी मजे से निकल जाते हैं और अपनी व्यवस्था पर इतराने वाली ब्रिटिश पार्लियामेंट इसके बारे में कोई चिंता नहीं जताती। यह दोमुंहापन नहीं, तो और क्या है? दरअसल, जब से भारतीय अर्थव्यवस्था ने पश्चिमी देशों को पीछे छोड़ना शुरू किया है, तभी से भारत की तरक्की उन्हें पच नहीं रही। वे गाहे-बगाहे भारत की छवि को दागदार बनाने के लिए ऐसी हरकतें करते रहते हैं, ताकि दुनिया को जता सकें कि भारतीय लोग आज भी असभ्य हैं। लेकिन संयोग से अब उनकी राय की बहुत परवाह न नई दिल्ली को है और न शेष दुनिया को, क्योंकि पश्चिम की श्रेष्ठता-ग्रंथि के पीछे छिपी कुंठा को उसने देख लिया है।

म्यांमार की तरफ से लगातार जारी घुसपैठ मणिपुर में हिंसा की बड़ी वजह है और इस तथ्य से अंग्रेजों से बेहतर कौन अवगत होगा? मगर जान-बूझकर अपने घरेलू मामलों से ध्यान भटकाने के लिए ब्रिटिश राजनेता ऐसी हरकतें करते हैं। हमें इस प्रवृत्ति की हर मंच से निंदा करनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की सराहना करनी चाहिए कि अमेरिकी टिप्पणी हो या यूरोप के किसी देश का बयान, ऐसी हरकतों का वह फौरन जोरदार जवाब देते हैं। भारत के पास विशाल बाजार है, प्रतिभा है और सबसे बड़ी युवा आबादी है। इसलिए इसकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ब्रिटेन को ही भारी पड़ेगी।

राहुल सिंह, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

मणिपुर हिंसा

दुनिया को हम भला किस मुंह से रोकें

पहले सिर्फ पाकिस्तान अपनी संसद में जब-तब कश्मीर का खटराग अलापता रहता था, अब मणिपुर को लेकर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी टिप्पणियां की जा रही हैं। निस्संदेह, इससे हमारे देश की छवि खराब होती है। हम भले कहते रहें कि यह हमारे घरेलू मामले में दखलंदाजी है, मगर हकीकत यह है कि हाल के वर्षों में हमारी सर्वधर्म समभाव वाली छवि खंडित हुई है। देश का बहुसंख्यक हिंदू शांतिप्रिय है। वह धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का समर्थक रहा है, मगर आठ-दस प्रतिशत लोगों की आक्रामकता ने सब कुछ संदिग्ध कर दिया है। जब हम दूसरे देशों के हिंदू नागरिकों के साथ ज्यादती को मानवाधिकार के बजाय धार्मिक नजरिये से देखेंगे, उनके हितों के लिए आवाज उठाएंगे, तब किस मुंह से ब्रिटिश संसद के किसी ईसाई धर्म के शुभचिंतक सदस्य की कार्रवाई का विरोध करेंगे?

लॉर्ड बिशप ने मणिपुर में चर्चों को जलाए जाने और ईसाई धर्मावलंबियों के साथ हिंसा को मुद्दा बनाया है। दरअसल, दुनिया को यह मौका हमने ही मुहैया कराया है। मणिपुर में हिंसा कोई अचानक नहीं भड़की। यह लंबे समय से वहां के समाज में घनीभूत होते तनाव की परिणति है। आखिर हमारी सरकारें या उनका गुप्तचर तंत्र कहां था? वे क्यों नहीं आकलन कर सके कि हालात किस कदर गंभीर रूप ले रहे हैं? मणिपुर तो आज भी दहक रहा है। मीडिया ने वहां की खबरों से मुंह फेर लिया है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वहां की स्थिति सामान्य हो गई है। वास्तविकता यह है कि राज्य में लोकसभा की दो सीटें हैं और चुनाव आयोग यह हिम्मत नहीं जुटा सका कि एक चरण में दोनों सीटों पर मतदान कराया जाए। सोचिए! तमिलनाडु में 39 सीटों पर एक चरण में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो जाते हैं और मणिपुर कहां है? हमें अपने सभी क्षेत्रों को लेकर समान रूप से संवेदनशील होने की जरूरत है। जम्मू-कश्मीर में फौज शांति ला सकती है, मगर मणिपुर में उसके हाथ बंधे हुए हैं।

हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, जहां दुनिया के किसी कोने में मानवाधिकारों के हनन पर कोई चिंता जता सकता है, वरना तो कोलंबो हमसे कहेगा, श्रीलंका के तमिलों के नरसंहार पर भारत को बोलने का अधिकार नहीं, मधेसियों के दमन पर नेपाल यही दलील पेश कर देगा। इसलिए बेहतर होगा कि टिप्पणियों से आहत होने के बजाय आईना दिखाने वाली कार्रवाई की जाए। भारत की प्रतिष्ठा दूसरे देशों के चंद स्वार्थी राजनेताओं की टिप्पणियों से काफी बड़ी है। उस पर इनसे कोई खरोंच नहीं आने वाली!

दिव्य प्रकाश तिवारी, टिप्पणीकार

https://t.me/AINewsPaperPdf

दैनिक जागरण

सफलता कोई गंतव्य न होकर अनवरत चलने वाली यात्रा है

कांग्रेस के सहयोगी दल

लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का पहला चरण संपन्न हो गया, लेकिन विपक्षी दलों के मोर्चे आइएनडीआइए में खटपट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न केवल यह घोषणा की कि कांग्रेस और वामदल आइएनडीआइए के घटक नहीं हैं, बल्कि यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस एवं माकपा ने भाजपा से गुप्त समझौता कर रखा है। उनके इस आरोप पर यकीन करना कठिन है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह बंगाल की जनता को यही संदेश देना चाहती हैं कि अन्य भाजपा विरोधी दलों पर भरोसा करना ठीक नहीं। इस सबसे आइएनडीआइए एक ऐसे समय अपनी एकजुटता का संदेश देने में नाकाम है, जब अभी मतदान के छह चरण शेष हैं। ममता ने इसके पहले भी आइएनडीआइए को तब झटका दिया था, जब उन्होंने बंगाल में अपने बलबूते सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। आइएनडीआइए के साथ यही व्यवहार केरल में वाम दलों ने भी किया। उन्होंने न केवल वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया, बल्कि उन्हें यह सलाह भी दी कि यदि वह भाजपा को हराना चाहते हैं तो उत्तर भारत में कहीं से चुनाव लड़ें। आइएनडीआइए के घटकों के बीच जम्मू-कश्मीर में भी कोई समझौता नहीं हो सका।

कांग्रेस का संकट यह है कि वह सहयोगी दलों के असहयोग भरे रवैये का ढंग से प्रतिरोध भी नहीं कर पा रही है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह जिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भाजपा की बी टीम यानी सहयोगी बताया करती थी, उन्हें हैदराबाद में समर्थन देने के लिए तैयार हो गई। कांग्रेस को बंगाल, केरल, जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त कुछ अन्य राज्यों में भी अपने सहयोगी दलों की बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है। वह दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पंजाब में उसके खिलाफ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वहां उसे कोई सीट देने को तैयार नहीं हुए। लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के पहले जनता दल-यू और राष्ट्रीय लोक दल के आइएनडीआइए से छिटकने से भी कांग्रेस को झटका लगा था। ध्यान रहे जद-यू नेता नीतीश कुमार ही आइएनडीआइए के सूत्रधार थे। आइएनडीआइए की एक समस्या यह भी है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के घोषणा पत्रों में कई मुद्दों पर आम राय नहीं दिख रही है। उलटे कुछ मुद्दों पर तो वे एक-दूसरे की आलोचना तक कर रहे हैं, जैसे माकपा ने सवाल किया है कि कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून पर चुप क्यों है? कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं कि क्या वह परमाणु हथियार खत्म करने और क्वाड से बाहर निकलने की माकपा की घोषणा से सहमत है? उसे इस पर भी मौन धारण करना पड़ा है कि क्या वह भाकपा की राज्यपाल पद खत्म करने की घोषणा का समर्थन करती है?

पुलिस की लापरवाही

गैंगस्टरों के विरुद्ध पंजाब पुलिस अभियान चला रही है, वहीं इस प्रदेश के तरनतारन में पुलिस की ओर से बड़ी लापरवाही सामने आना हैरान करने वाला मामला है। गोइंदवाल साहिब जेल से सिविल अस्पताल लाए गए ए कैटेगरी के गैंगस्टर का फरार हो जाना गंभीर मामला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस विभाग के अधिकारियों को जब पता था कि गैंगस्टर के खिलाफ नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसने बैंक में लूट की कोशिश के दौरान एएसआइ को गोली मारी थी, तब सुरक्षा व्यवस्था में कोताही क्यों बरती गई। आखिर तीन पुलिस कर्मचारियों में से दो अस्पताल से घर क्यों चले गए। अस्पताल में जो कांस्टेबल उपस्थित था उसने अपनी ओर से घर जाने के लिए कहा या फिर दोनों पुलिस कर्मचारियों ने किसी अधिकारी से अनुमति ली थी, यह बात सामने आनी चाहिए। एक सवाल यह भी है कि अभी तक लापरवाह पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। इस तरह के मामलों से पुलिस की छवि पर असर पड़ना स्वाभाविक है। ऐसी लापरवाही का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपित एक गैंगस्टर भी पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति यदि होती रही तो स्वाभाविक है कि पुलिस के ऊपर से लोगों का भरोसा कम होगा। राज्य की कानून व्यवस्था के लिए भी इस तरह की घटनाएं ठीक नहीं हैं। खास करके तब जब आए दिन गैंगस्टर फोन करके व्यापारियों से रंगदारी मांगते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। गैंगस्टर के फरार होने के मामले की गहन जांच होनी चाहिए और इसके साथ ही कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए।

जेल से अस्पताल लाए गए ए कैटेगरी के गैंगस्टर का पुलिस हिरासत से फरार हो जाना गंभीर मामला है

पश्चिम एशिया का खत्म न होने वाला टकराव

दिव्य कुमार सोती

इजरायल-ईरान की तनातनी धीरे-धीरे और उग्र रूप धारण कर विश्व के लिए संकट बन सकती है

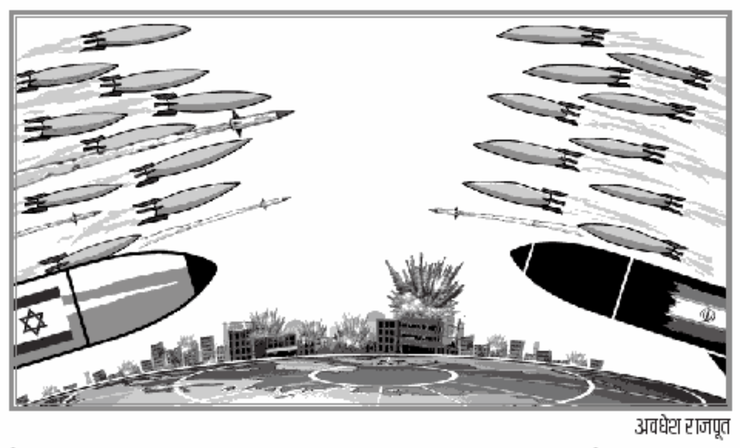

अवधेश राजपूत

इजरायल ने ईरान में सैन्य कार्रवाई की तो है, लेकिन न तो वह कुछ खुलकर कह रहा और न ही ईरान आधिकारिक रूप से यह स्वीकारना चाहता है कि उसे इजरायल ने निशाना बनाया। इजरायल-ईरान में टकराव की जड़ में हमास द्वारा इजरायल पर गत 7 अक्टूबर को किया गया वह भीषण आतंकी हमला है, जिसमें एक हजार से अधिक इजरायली और अन्य देशों के लोग मारे गए थे। उसके बाद शुरू हुआ गाजा का संघर्ष इजरायल-ईरान युद्ध के कगार पर आकर खड़ा हो गया। यह आसानी से नहीं टलेगा। पिछले सप्ताह ईरान ने इजरायल पर करीब 185 ड्रोन और 150 क्रूज एवं बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, क्योंकि इजरायली सेना ने सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास में ईरानी जनरलों को निशाना बनाया था। इसके बाद ईरान सरकार, जो इजरायल को धरती से मिटाने की कसमें खाती है, के पास हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसी बीच इजरायली सेना ने गाजा में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया के तीन बेटे मार गिराए, इसलिए ईरान बौखला गया। यदि वह इजरायल को निशाना न बनाता तो अपने समर्थकों के बीच साख गंवा देता।

सीरिया में ईरानी दूतावास पर बमबारी कर इजरायल ने जिन ईरानी जनरलों को आतंकी साजिश रचने का जिम्मेदार बताते हुए मारा, उन पर दूतावास के बाहर भी हमला किया जा सकता था, परंतु उन्हें दूतावास में ही निशाना बनाया गया। इजरायल अच्छे से जानता था कि ऐसा करना कूटनीतिक प्रोटोकाल और अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन होगा। फिर भी उसने संभवतः ऐसा इसलिए किया, क्योंकि 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के बाद उसने ठान लिया था कि सही समय पर हमास की हरकत के लिए ईरान की जवाबदेही तय की जाएगी। ईरान दशकों से हमास और हिजबुल्ला जैसे आतंकी संगठनों के जरिये इजरायल पर हमले कराता आया है-ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तानी फौज लश्कर, जैश जैसे संगठनों के जरिये भारत पर आतंकी हमले कराती रही है। अभी तक इजरायल ईरान समर्थित आतंकी संगठनों पर ही जवाबी कार्रवाई करता था, न कि उनके नियंत्रक ईरान पर। हमास के आतंकी हमले के बाद इजरायल का विचार बदला। पूर्व इजरायली पीएम नफ्ताली बैनेट का कहना था कि हमसे यह गलती हुई कि हम आतंक रूपी आक्टोपस के पैरों यानी हमास, हिजबुल्ला से लड़ते रहे, परंतु उसके सिर यानी ईरान को कुचलने की कभी कोशिश नहीं की। सीरिया में अपने दूतावास पर इजरायली हमले के बाद ईरान के पास भी यह विकल्प था कि वह किसी और देश में उसके ठिकानों को निशाना बनाता, लेकिन ईरान के कट्टरपंथी शासक इजरायल को नक्शे से मिटाने के सपने अपने समर्थकों को दिखा रहे थे, इसलिए उनके पास उस पर सीधे हमले के अलावा और उपाय न था।

इजरायल पर ईरान के हमले ने उसके मिसाइल कार्यक्रम की कमजोरी ही उजागर की। इजरायल पर दागी गईं 150 मिसाइलों में से मात्र सात ही निशाने पर लगीं। हमले के समय इजरायल की सुरक्षा में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं एक साथ काम कर रही थीं। आधी से ज्यादा ईरानी मिसाइलों को मार गिराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वे इजरायली सीमा में प्रवेश करने से पहले ही गिर गईं। जो सात मिसाइलें लक्ष्य तक पहुंचीं, वे भी इजरायल के एक सैन्य हवाई अड्डे का मामूली नुकसान कर पाईं। इसके बाद भी इस हमले ने इजरायली जनता के सामने ईरानी खतरे को मूर्त रूप दे दिया और दोनों देशों के बीच प्रतिरोधक क्षमता का संतुलन भी गड़बड़ा दिया। यदि इजरायल इस हमले का जवाब न देता तो भविष्य के लिए संकेत जाता कि ईरान सीधे उस पर बमबारी कर सकता है और फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस समय पश्चिम एशिया में तनाव के चलते अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि की सेनाएं तैनात हैं और ईरानी हमले को विफल करने में उन्होंने इजरायल की पूरी सहायता की, परंतु यह स्थिति हमेशा नहीं रहेगी, इसलिए इजरायल के लिए ईरान पर जवाबी कार्रवाई कर शक्ति संतुलन बहाल करना जरूरी था, ताकि भविष्य में ईरानी हमले नियमित न हो जाएं। खास बात यह है कि इजरायल ने ईरान पर हमला उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के जन्मदिन के मौके पर किया।

इजरायल के अंदर एक धड़ा है, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना चाहता है, क्योंकि यदि वह परमाणु बम बनाने में सफल हो गया तो वह पाकिस्तान की तरह परमाणु युद्ध की धमकी की आड़ में इजरायल के विरुद्ध व्यापक आतंकी युद्ध चलाता रह सकता है। इस धड़े को सऊदी अरब समेत कई सुन्नी देशों का मौन समर्थन है। वे नहीं चाहते कि शिया देश ईरान के पास परमाणु बम हो। जार्डन की वायुसेना ने तो ईरानी हमले को विफल करने में इजरायल की मदद भी की। माना जाता है कि इजरायली खुफिया एजेंसियां लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए ईरानी वैज्ञानिकों को निशाना बनाने के साथ अन्य विध्वंसक कार्रवाई करती आई हैं।

गत दिवस इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीधा निशाना तो नहीं बनाया, पर उन शहरों के सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की, जहां उसके परमाणु संयंत्र भी हैं। ईरानी सूत्र इस हमले को एक छोटा और विफल ड्रोन हमला बता रहे हैं, क्योंकि सच स्वीकारने पर ईरान को फिर से इजराइल पर मिसाइल हमले करने होंगे, जो पहले की तरह विफल कर दिए जाएंगे और उसकी कमजोरी की पोल पुनः खुल जाएगी। ईरान का व्यवहार बालाकोट में भारत के हमले के बाद पाकिस्तान जैसा है। इजरायल ने शायद इसलिए ईरान पर हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली, क्योंकि ऐसा करना रूसी वायुसेना को ईरान में आने का बहाना दे सकता था, जैसा सीरिया में देखा जा चुका है और अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। पश्चिम एशिया में ईरान-इजरायल का टकराव पहले ही यूक्रेन में अमेरिका समर्थित प्रतिरोध की धार कुंद कर रहा है। इन दोनों देशों का टकराव विश्व शांति को संकट में डालने वाला हो सकता है, जिसकी जद में ईरानी परमाणु कार्यक्रम भी आ सकता है। चूंकि यह साफ है कि पश्चिम एशिया में शांति के आसार नहीं, इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा।

(लेखक काउंसिल आफ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप का खतरा

शशि शेखर वेम्पति

बाहरी संस्थाएं अन्य देशों में चुनावों को प्रभावित करने के बाद भारत पर भी नजर टेढ़ी किए हुए हैं

पिछले कुछ हफ्तों में लोकसभा चुनाव से जुड़े विषय फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग, अल-जजीरा, यूके गार्जियन और इकोनमिस्ट जैसे वैश्विक मीडिया संस्थान की कवरेज के केंद्र-बिंदु बन गए हैं। इन मीडिया संस्थानों की कवरेज और लेखों के स्वर एवं भाव लगभग एक जैसे हैं और इनकी वजह से भारतीय लोकतंत्र के कमजोर होने से लेकर उसके भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ने की भविष्यवाणियां की जा रही हैं। विशेष रूप से चिंता की बात यह है कि वैश्विक मीडिया संस्थानों की कवरेज ने भारत में राजनीतिक मतभेदों को और बढ़ाने की कोशिश की है। उत्तर-दक्षिण विभाजन की कल्पना से लेकर न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग जैसे स्वायत्त संवैधानिक निकायों की विश्वसनीयता को कम करने तक, ऐसी विदेशी कवरेज ने पहले वोट डाले जाने के पूर्व ही चुनावी नतीजों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने के प्रयास किए हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि भारत परिष्कृत विदेशी हस्तक्षेप अभियानों का लक्ष्य बन गया है, जो इंटरनेट की व्यापक पहुंच और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की ताकत का लाभ उठा रहे हैं। इसमें भारत अकेला नहीं है। ऐसे कई विदेशी अभियानों ने दुनिया भर में चुनावी प्रक्रियाओं की पवित्रता को खतरे में डाल दिया है। उदाहरण के तौर पर कनाडा और आस्ट्रेलिया ने ऐसे अभियानों का सामना किया है, जिनके बारे में चीनी प्रभाव वाले फंडिंग अभियानों और प्रचार-प्रसार से जुड़े लगभग सिद्ध हो चुके मामले मौजूद हैं। माइक्रोसाफ्ट ने डीपफेक और एआइ के दुर्भावनापूर्ण उपयोग के माध्यम से चीन की ओर से भारतीय चुनावों को लेकर खतरों के प्रति आगाह भी किया है। कनाडा में प्रवासी भारतीयों और राजनीतिक हस्तियों को प्रभावित करने के गुप्त प्रयासों की रिपोर्टों ने चिंता पैदा की है। इसी तरह, आस्ट्रेलिया अपनी राजनीतिक संप्रभुता पर विदेशी हस्तक्षेप के प्रभाव से जूझ रहा है, जिसके कारण महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किए गए हैं तथा जासूसी और विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ कानूनों को मजबूत बनाया गया है।

विभिन्न प्रमाणों से यह स्पष्ट हुआ है कि परोक्ष तरीके से भेजी जाने वाली चीनी फंडिंग ने भारतीय मीडिया प्रतिष्ठानों में अपना रास्ता बना लिया है,

विदेशी मीडिया के निशाने पर भी हैं आम चुनाव। फाइल

जो सूक्ष्मता से धारणाओं को बदलने के साथ ही जनता की राय को प्रभावित कर रहा है। न्यूजक्लिक को विदेशी फंडिंग और चीन से जुड़े व्यवसायियों के साथ उसके संबंध का हालिया मामला इसका उदाहरण है। इससे भी अधिक घातक तरीके से, इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों को फर्जी वीडियो एवं डीपफेक कंटेंट को प्रसारित करने का हथियार बनाया गया है, जिससे सच्चाई एवं मनगढ़ंत कहानियों के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई हैं और पीएम मोदी तक ऐसे डीपफेक का शिकार हो गए हैं। वाट्सएप जैसे व्यक्तिगत मैसेजिंग एप्लिकेशन के जरिये गलत जानकारियों के प्रसार ने चुनावी प्रक्रिया में भरोसे को कम करते हुए मतदाताओं को गुमराह करने वाली रणनीति का पता लगाना कठिन बना दिया है।

भारतीय राजनीति पर ऐसी हरकतों के परिणाम दूरगामी होंगे। सूचना इकोसिस्टम में हेरफेर करने के अलावा विदेशी शक्तियां घरेलू तत्वों की पक्षपातपूर्ण राजनीतिक बयानबाजी का सहारा लेकर भारत में सामाजिक भेद को बढ़ा रही हैं। हताश राजनीतिक दल और नेता इस 'घातक' रणनीति का सहारा ले रहे हैं। उन्हें इस बात का जरा भी भान नहीं है कि भारतीय लोकतंत्र के बारे में उनकी अनावश्यक और अतिरंजित घोषणाओं का विदेशी शक्तियों द्वारा भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने के उद्देश्य से दोहन किया जा रहा है। यह लोकतंत्र के मूल सार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के नतीजे में विश्वास को खतरे में डाल रहा है। भारत की चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सीमा पार बैठे एजेंटों की ओर से प्रौद्योगिकी के दुर्भावनापूर्ण उपयोग के जरिये उत्पन्न होने वाले खतरों को देखते हुए, यह तत्काल निर्णय लेने और कार्रवाई करने का समय है। सूचनाओं के प्रसार में व्याप्त कमजोरियों को दूर करने और चुनावी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए सुरक्षात्मक उपाय किए जाने की जरूरत है। भारत निर्वाचन आयोग को अन्य सरकारी और गैर-सरकारी हितधारकों के साथ मिलकर इन कमजोरियों को दूर करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

भारत निर्वाचन आयोग की अहम भूमिका के तहत फोकस अन्य बातों के बजाय मुख्यतः आदर्श आचार संहिता को लागू करने पर केंद्रित रहा है, जबकि इस प्रक्रिया में हो रहे विदेशी हस्तक्षेप पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। दरअसल, चुनाव प्रक्रिया में हो रहे विदेशी हस्तक्षेप और इसके साथ ही गलत सूचनाओं से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को अपने अभियानों से परे जाकर मतदाताओं को जागरूक करने की जरूरत है, ताकि फर्जी खबरों, दुर्भावनापूर्ण वीडियो और डीपफेक मीडिया की सक्रिय रूप से पहचान की जा सके और उन्हें तत्काल हटाया जा सके। इसी तरह सरकार की फैक्ट्स चेक यूनिट्स को प्रभावकारी उपकरणों या साधनों और व्यापक क्षमता से लैस करके उन्हें सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है, तभी चुनाव आयोग दृढ़ता के साथ इस दिशा में ठोस कदम उठा सकता है। वास्तव में, यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपने भविष्य को अक्षुण्ण रखने के लिए हर हाल में जीतना ही होगा। यह हमारे लोकतंत्र के मजबूत आधार की रक्षा के लिए सतर्कता बरतने, एकता सुनिश्चित करने और सक्रिय उपायों का आह्वान करने का सही समय है। अब इस मोर्चे पर ठोस कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ना आवश्यक हो गया है।

(लेखक प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सत्य की महत्ता

इस समय संसार में असत्य और कपट का बोलबाला बढ़ रहा है। ऐसे में सत्य की महत्ता को समझना और भी आवश्यक हो गया है। गौतम बुद्ध ने इस संबंध में कहा है कि सत्य को छोड़कर जो असत्य बोलता है, धर्म का उल्लंघन करता है, परलोक की जिसे चिंता नहीं है, वह आदमी बड़े से बड़ा पाप कर सकता है। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में संकोच नहीं, वह कोई भी अनर्थ कर सकता है। इसलिए कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित न करें और न ही झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहन दें। असत्य का पूर्ण रूप से परित्याग कर देना चाहिए।

सत्य को कितने भी पर्दों में क्यों न छुपाकर रख दिया जाए, एक न एक दिन वह प्रकट हो ही जाता है। हमारे मनीषियों ने यथार्थ ही कहा है कि 'मनसा वाचा कर्मणा' यानी मन, वचन और कर्म से सत्य बोलना चाहिए। जो विचार मन में हो वही वाणी में भी होने चाहिए और उसी के अनुरूप ही मनुष्य का व्यवहार भी होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि मन, वचन और कर्म से अलग रहने वाले पूर्णरूपेण सत्य का आचरण नहीं कर सकते। चूंकि सत्य सदैव कड़वा होता है तो सत्य बोलने वाले समाज में कुछ अलोकप्रिय भी हो जाते हैं।

गांधीजी ने कहा कि सत्य केवल शब्दों की सत्यता ही नहीं, विचारों की सत्यता भी है। हमारी अवधारणा का सापेक्षिक सत्य ही नहीं, बल्कि निरपेक्ष सत्य भी है, जो ईश्वर ही है। गांधीजी सत्य को निरपेक्ष सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं। सत्य को ईश्वर का पर्यायवाची मानते हैं। हमारे अस्तित्व का एकमात्र औचित्य यही हो कि हमारी समस्त गतिविधि सत्य पर केंद्रित रहे। सत्य ही हमारे जीवन का प्राण तत्व होना चाहिए, क्योंकि सत्य के बिना व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। संभव है कि सत्य के बिना भी उसे सफलता मिल जाए, किंतु आंतरिक शांति एवं समग्र संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होगी।

नृपेंद्र अभिषेक नृप

एनीमिया से मुक्त होगा भारत!

गीता यादव

एक इंजेक्शन के सफल परीक्षण से देश को एनीमिया मुक्त बनाने की जगी उम्मीद

आयरन की कमी के कारण भारत का हर तीसरा बच्चा जन्म के समय कम वजन का होता है। लगभग 70 प्रतिशत भारतीय महिलाओं और बच्चों में आयरन, जिंक एवं कैल्शियम जैसे पौष्टिक तत्वों की गंभीर कमी पाई गई है। भारत में प्रसव के दौरान होने वाली 20 से 40 प्रतिशत मौतें एनीमिया के चलते होती हैं। पूरी दुनिया में इस कारण जितनी मौतें होती हैं, उनका आधा केवल भारत में होता है। एनीमिया से सबसे ज्यादा पीड़ित गर्भवती महिलाएं होती हैं। आयरन की कमी एनीमिया का सबसे बड़ा कारण है। हालांकि अन्य स्थितियां जैसे विटामिन बी-12 और विटामिन-ए की कमी, पुराना सूजन, परजीवी संक्रमण और आनुवंशिक विकार आदि भी एनीमिया का कारण हो सकते हैं। देश में गर्भावस्था से जुड़ा एनीमिया स्वास्थ्य से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है, जो न केवल मां, बल्कि विकसित हो रहे भ्रूण दोनों पर बुरा असर डालता है। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है, जिसमें रक्त में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में ही एनीमिया मुक्त भारत की रणनीति बनाई थी। इस अभियान का उद्देश्य पोषण अभियान, टेस्टिंग, डिजिटल तरीके और देखभाल के तरीकों का उपयोग करके एनीमिया का इलाज और सरकार द्वारा वित्त पोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के जरिये जागरूकता बढ़ाना है। केंद्र सरकार ने देश को 2047 तक एनीमिया से मुक्ति का लक्ष्य रखा है।

हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली के चिकित्सकों को इस दिशा में एक बड़ी कामयाबी मिली है। एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के एक प्रोफेसर का कहना है कि गंभीर एनीमिया होने पर रोगी को रक्त चढ़ाना पड़ता है या गर्भवती महिलाओं को आयरन के पांच से छह इंजेक्शन देने पड़ते हैं। हर सप्ताह एक इंजेक्शन लगता है। लेकिन कई गर्भवती महिलाएं सभी इंजेक्शन नहीं ले पातीं। विदेश में फेरी कार्बोक्सी इसका माल्टोज (एफसीएम) इंजेक्शन किडनी व कैंसर मरीजों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। उसकी कीमत तीन से चार हजार रुपये है। यहां गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की बड़ी समस्या को ध्यान में रखकर उन पर इसका ट्रायल किया गया, जिसमें यह इंजेक्शन गर्भवती महिलाओं के लिए भी सुरक्षित और असरदार पाया गया। इसके बाद मालिक्यूल में थोड़ा बदलाव करके जेनेरिक स्वदेशी इंजेक्शन तैयार कर लिया गया है। इसकी कीमत भी करीब तीन सौ रुपये है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे एनीमिया मुक्त भारत के वर्ष 2024 के निर्देश में शामिल कर लिया गया है। उम्मीद है कि छह माह में मध्यम से गंभीर एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को यह निःशुल्क मिलने लगेगा। अब दूसरे अस्पतालों में भी गंभीर मरीजों पर इसका उपयोग किया जाएगा और एनीमिया मुक्त भारत का सपना साकार हो सकता है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

वंशवादी राजनीति पर लगे विराम

'लोकतंत्र पर ही सवाल है वंशवाद' शीर्षक से लिखे आलेख में राज कुमार सिंह ने वंशवादी राजनीति के दम पर उम्मीदवारी हासिल करने वाले नेताओं की विस्तारपूर्वक लंबी सूची प्रस्तुत की है। सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी राजनीति की काट क्या है? इस तरह की राजनीति से देशवासियों को छुटकारा कैसे मिले? जिस राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से हुई थी, उसकी गिरफ्त में कमोबेश सभी पार्टियां कैसे आ गईं? दुखद है कि ऐसी राजनीति का विरोध करने वाले सबसे अधिक इसमें डूबे नजर आ रहे हैं। बस, भाजपा और अन्य पार्टियों में यह फर्क बचा है कि भाजपा किसी परिवार विशेष की पार्टी नहीं रह गई है, जबकि बाकी लगभग सभी परिवार की पार्टी बनकर रह गई हैं। मानो पार्टी न होकर कोई निजी कंपनी हो। ऐसे में अगर लोकतंत्र को बचाए रखना है, नए लोगों में राजनीति के प्रति आकर्षण पैदा करना है, तब कुछ न कुछ उपाय तो ढूंढ़ने ही पड़ेंगे। क्या देशवासी यह उम्मीद करें कि वह अपने तीसरे कार्यकाल में इस बुराई का कोई उपयुक्त समाधान दे पाएंगे, क्योंकि देश की जनता को यह भान है कि प्रधानमंत्री में वह माद्दा है जो सामाजिक सुधार के जरिये राजनीति की दशा-दिशा में सुधार कर सकते हैं।

मुकेश कुमार मनन, पटना

वादों की परख करने वाले चुनाव

प्रो. निरंजन कुमार का आलेख 'वादों की परख करने वाले चुनाव' अत्यंत सटीक है। यह चुनाव अनेक प्रकार से अलग है। 18 से 35 वर्ष की आयु वाले 60 करोड़ युवा मतदाता हैं। चीन को छोड़कर इतनी तो किसी देश की जनसंख्या भी नहीं है। यही 60 करोड़ युवा चुनाव परिणाम में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। बेशक रोटी, कपड़ा, मकान आदि की समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन कम अवश्य हुई हैं और चुनाव में बड़ा मुद्दा भी नहीं हैं। ये 60 करोड़ युवा अमेरीकी ड्रीम की तरह अपना एक विशिष्ट सपना संजोए हुए हैं। भारतीय ड्रीम में आर्थिक समृद्धि के अतिरिक्त विरासत, संस्कृति, धर्म को लेकर भी सजगता है। यही कारण है कि श्रीराम मंदिर उद्घाटन इतना बड़ा देशव्यापी मुद्दा बन गया। अधिकतर युवा समझ चुके हैं कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। इसीलिए युवा स्टार्टअप, स्वरोजगार तथा प्राइवेट सेक्टर में अच्छे करियर के लिए प्रयासरत हैं। लाखों युवा तो रोजगार देने वाले बन चुके हैं। क्षेत्रीय दल आमतौर पर लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसलिए आम मतदाता के समक्ष दो ही प्रभावी विकल्प हैं, भाजपा वाला एनडीए तथा कांग्रेस व बचा-खुचा आइएनडीआइए। वोटर को इनके वादे पूरे करने का रिकार्ड मालूम है। वोटर इसे ध्यान में रखते हुए तथा आगे के लिए किए गए वादों को देखकर वोट डालेगा। मोदी सरकार की विकास उन्मुख राजनीति ने जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति को पीछे छोड़ दिया है। मोदी सरकार ने 2014 तथा 2019 में किए अधिकतर वादे पूरे किए हैं। मुश्किल वादे अनुच्छेद-370 की समाप्ति, तीन तलाक की समाप्ति, श्रीराम मंदिर निर्माण, आतंकवाद की समाप्ति व नक्सलवाद का उन्मूलन भी काफी हद तक पूरे किए हैं। संक्षेप में पिछले वादों की पूर्ति, उपलब्धियां तथा भविष्य के वादों को पूरा कर ही मतदान होगा।

सीपी बंसल, दिल्ली

हम अपनी सीमाओं को समझें

धर्म कुछ मर्यादाएं प्रस्तुत करता है। कुछ व्यक्ति उनका ठीक अर्थ नहीं समझकर, उनकी आलोचना कर बैठते हैं। ऐसा समझते हैं, मानो धर्म के माध्यम से हमें बंधनों में डाला जा रहा है, किंतु यह सत्य नहीं है। धर्म मर्यादा के रूप में कोई बंधन नहीं डालता है। वह तो व्यक्ति को अपनी सीमा का ज्ञान कराता है। यद्यपि विश्व में भोग्य पदार्थ अनंत है, किंतु मानव के पास उनके उपभोग की शक्ति सीमित है। अपनी सीमित शक्ति को पहचान उपभोग को मर्यादित करना बंधन नहीं है। अपितु उपभोग की यह एक रचनात्मक दृष्टि है। व्यक्ति अपनी सीमा को पहचाने बिना उपभोग की तरफ बढ़ता रहेगा तो उसे असफलता और पश्चताप ही प्राप्त होंगे।

कांतिलाल मांडोत नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

सफलता कोई गंतव्य न होकर अनवरत चलने वाली यात्रा है

कांग्रेस के सहयोगी दल

लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का पहला चरण संपन्न हो गया, लेकिन विपक्षी दलों के मोर्चे आइएनडीआइए में खटपट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न केवल यह घोषणा की कि कांग्रेस और वामदल आइएनडीआइए के घटक नहीं हैं, बल्कि यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस एवं माकपा ने भाजपा से गुप्त समझौता कर रखा है। उनके इस आरोप पर यकीन करना कठिन है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह बंगाल की जनता को यही संदेश देना चाहती हैं कि अन्य भाजपा विरोधी दलों पर भरोसा करना ठीक नहीं। इस सबसे आइएनडीआइए एक ऐसे समय अपनी एकजुटता का संदेश देने में नाकाम है, जब अभी मतदान के छह चरण शेष हैं। ममता ने इसके पहले भी आइएनडीआइए को तब झटका दिया था, जब उन्होंने बंगाल में अपने बलबूते सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। आइएनडीआइए के साथ यही व्यवहार केरल में वाम दलों ने भी किया। उन्होंने न केवल वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया, बल्कि उन्हें यह सलाह भी दी कि यदि वह भाजपा को हराना चाहते हैं तो उत्तर भारत में कहीं से चुनाव लड़ें। आइएनडीआइए के घटकों के बीच जम्मू-कश्मीर में भी कोई समझौता नहीं हो सका। कांग्रेस का संकट यह है कि वह सहयोगी दलों के असहयोग भरे रवैये का ढंग से प्रतिरोध भी नहीं कर पा रही है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह जिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भाजपा की बी टीम यानी सहयोगी बताया करती थी, उन्हें हैदराबाद में समर्थन देने के लिए तैयार हो गई। कांग्रेस को बंगाल, केरल, जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त कुछ अन्य राज्यों में भी अपने सहयोगी दलों की बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है। वह दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पंजाब में उसके खिलाफ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वहां उसे कोई सीट देने को तैयार नहीं हुए। लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के पहले जनता दल-यू और राष्ट्रीय लोक दल के आइएनडीआइए से छिटकने से भी कांग्रेस को झटका लगा था। ध्यान रहे जद-यू नेता नीतीश कुमार ही आइएनडीआइए के सूत्रधार थे। आइएनडीआइए की एक समस्या यह भी है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के घोषणा पत्रों में कई मुद्दों पर आम राय नहीं दिख रही है। उलटे कुछ मुद्दों पर तो वे एक-दूसरे की आलोचना तक कर रहे हैं, जैसे माकपा ने सवाल किया है कि कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून पर चुप क्यों है? कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं कि क्या वह परमाणु हथियार खत्म करने और क्वाड से बाहर निकलने की माकपा की घोषणा से सहमत है? उसे इस पर भी मौन धारण करना पड़ा है कि क्या वह भाकपा की राज्यपाल पद खत्म करने की घोषणा का समर्थन करती है?

दलीय आस्था का सच

चुनावी मौसम में जो दल बदल होता है, उसे देखें और विचार करें तो यही निष्कर्ष निकलता है कि दलीय आस्था सिर्फ कहने के लिए है। असली आस्था ऊपर या नीचे के सदन में जगह के प्रति है, जिसे प्राप्त करने के लिए मन हो तो सुबह-दोपहर-शाम दल बदल कर लिया जाता है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य में कई बड़े कहे जाने वाले नेताओं ने दल बदल किया है। कई बार जिस दल ने सांसद बनाया, दल में रहते उसका गुणगान किया, बेटिकट होने के बाद उसी दल में सौ खोट निकाल लेने का उपक्रम कोई नेता ही कर सकता है। ऐसी प्रवृत्ति किसी एक दल के नेता में नहीं है। सभी दलों के नेताओं में है। पिता एक दल में हैं। टिकट के लिए उनके पुत्र दूसरे दल में चले जाते हैं। मतलब पुत्र की नजर में वह दल ठीक नहीं है, जिसमें उसके पिता पदधारक हैं। दो भाई हैं। दोनों की एक दल में गुंजाइश नहीं है। दोनों परस्पर विरोधी दल में चले जाते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को लगता है कि जनता उनके असली लक्ष्य से अनजान है। बात दूसरी है। असल में आम जनता को उपलब्ध उम्मीदवारों के बीच में से ही किसी का चयन करना होता है। मतदान के समय उसके पास अधिक विकल्प नहीं रहता है। इसलिए घूम फिर कर वही चेहरे कभी इस दल से तो कभी उस दल से सदन की शोभा बढ़ाते रहते हैं। नेताओं की दल बदल नीति ने कुछ नई प्रवृत्ति को भी जन्म दिया है। उनमें से एक यह है कि लोग उम्मीदवार के बदले दल को वोट देने लगे हैं। इसने दलीय नेतृत्व को बहुत हद तक निरंकुश बना दिया है। एकल नेतृत्व वाले क्षेत्रीय दल इस तरह की निरंकुशता का पूरा आनंद उठाते हैं। कुछ कहिए, राजनीति के इस घपले का असली शिकार आम आदमी हो रहा है। स्थिति ऐसी बनी है कि जैसे-तैसे टिकट लेकर जन प्रतिनिधि बने लोग आम जन के प्रति जवाबदेह नहीं बन पाते हैं।

राजनीति के इस घपले का असली शिकार आम आदमी हो रहा है

कह के रहेंगे

माधव जोशी

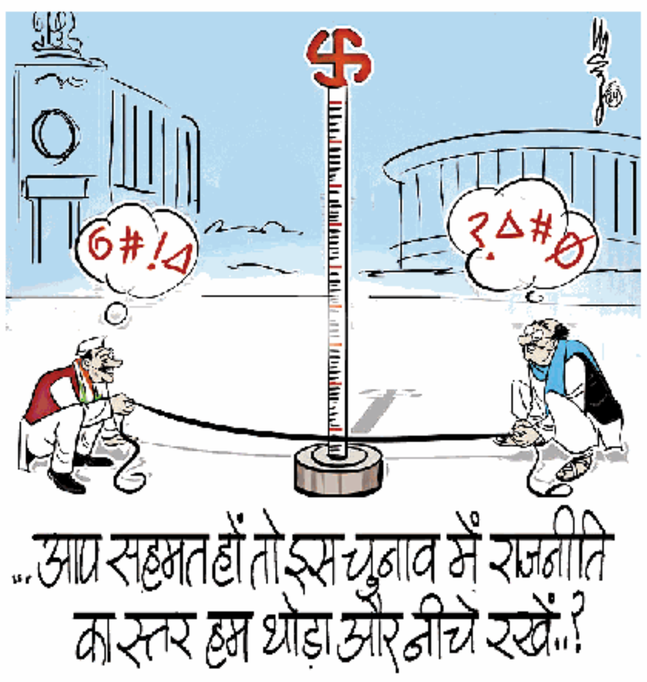

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने से उत्तर भारत में कांग्रेस को लाभ मिलेगा?

आज का सवाल

क्या रोहित शर्मा का यह कहना सही है कि इंपैक्ट प्लेयर नियम से आलराउंडर खिलाड़ियों की महत्ता घटी है?

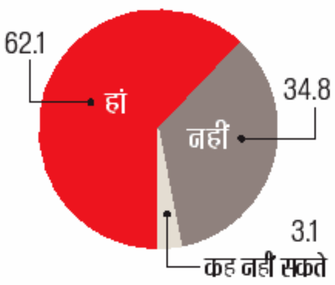

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

पश्चिम एशिया का खत्म न होने वाला टकराव

दिव्य कुमार सोती

इजरायल-ईरान की तनातनी धीरे-धीरे और उग्र रूप धारण कर विश्व के लिए संकट बन सकती है

इजरायल ने ईरान में सैन्य कार्रवाई की तो है, लेकिन न तो वह कुछ खुलकर कह रहा और न ही ईरान आधिकारिक रूप से यह स्वीकारना चाहता है कि उसे इजरायल ने निशाना बनाया। इजरायल-ईरान में टकराव की जड़ में हमास द्वारा इजरायल पर गत 7 अक्टूबर को किया गया वह भीषण आतंकी हमला है, जिसमें एक हजार से अधिक इजरायली और अन्य देशों के लोग मारे गए थे। उसके बाद शुरू हुआ गाजा का संघर्ष इजरायल-ईरान युद्ध के कगार पर आकर खड़ा हो गया। यह आसानी से नहीं टलेगा। पिछले सप्ताह ईरान ने इजरायल पर करीब 185 ड्रोन और 150 क्रूज एवं बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, क्योंकि इजरायली सेना ने सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास में ईरानी जनरलों को निशाना बनाया था। इसके बाद ईरान सरकार, जो इजरायल को धरती से मिटाने की कसमें खाती है, के पास हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसी बीच इजरायली सेना ने गाजा में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया के तीन बेटे मार गिराए, इसलिए ईरान बौखला गया। यदि वह इजरायल को निशाना न बनाता तो पूरे विश्व में अपने कट्टरपंथी समर्थकों के बीच साख गंवा देता।

सीरिया में ईरानी दूतावास पर बमबारी कर इजरायल ने जिन ईरानी जनरलों को आतंकी साजिश रचने का जिम्मेदार बताते हुए मारा, उन पर दूतावास के बाहर भी हमला किया जा सकता था, परंतु उन्हें दूतावास में ही निशाना बनाया गया। इजरायल अच्छे से जानता था कि ऐसा करना कूटनीतिक प्रोटोकाल और अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन होगा। फिर भी उसने संभवतः ऐसा इसलिए किया, क्योंकि 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के बाद उसने ठान लिया था कि सही समय पर हमास की हरकत के लिए ईरान की जवाबदेही तय की जाएगी। ईरान दशकों से हमास और हिजबुल्ला जैसे आतंकी संगठनों के जरिये इजरायल पर हमले कराता आया है-ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तानी फौज लश्कर, जैश जैसे संगठनों के जरिये भारत पर आतंकी हमले कराती रही है। अभी तक इजरायल ईरान समर्थित आतंकी संगठनों पर ही जवाबी कार्रवाई करता था, न कि उनके नियंत्रक ईरान पर। हमास के आतंकी हमले के बाद इजरायल का विचार बदला। पूर्व इजरायली पीएम नफ्ताली बैनेट का कहना था कि हमसे यह गलती हुई कि हम आतंक रूपी आक्टोपस के पैरों यानी हमास, हिजबुल्ला से लड़ते रहे, परंतु उसके सिर यानी ईरान को कुचलने की कभी कोशिश नहीं की। सीरिया में अपने दूतावास पर इजरायली हमले के बाद ईरान के पास भी यह विकल्प था कि वह किसी और देश में उसके ठिकानों को निशाना बनाता, लेकिन ईरान के कट्टरपंथी

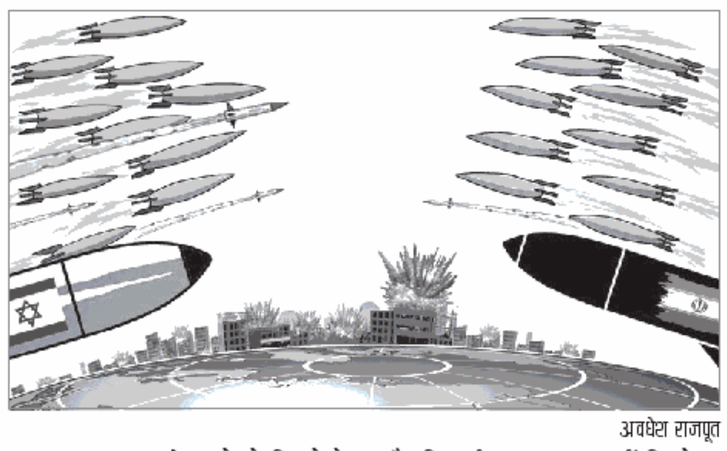

अवधेश राजपूत

शासक इजरायल को नक्शे से मिटाने के सपने अपने समर्थकों को दिखा रहे थे, इसलिए उनके पास उस पर सीधे हमले के अलावा और उपाय न था।

इजरायल पर ईरान के हमले ने उसके मिसाइल कार्यक्रम की कमजोरी ही उजागर की। इजरायल पर दागी गईं 150 मिसाइलों में से मात्र सात ही निशाने पर लगीं। हमले के समय इजरायल की सुरक्षा में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं एक साथ काम कर रही थीं। आधी से ज्यादा ईरानी मिसाइलों को मार गिराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वे इजरायली सीमा में प्रवेश करने से पहले ही गिर गईं। जो सात मिसाइलें लक्ष्य तक पहुंचीं, वे भी इजरायल के एक सैन्य हवाई अड्डे का मामूली नुकसान कर पाईं। इसके बाद भी इस हमले ने इजरायली जनता के सामने ईरानी खतरे को मूर्त रूप दे दिया और दोनों देशों के बीच प्रतिरोधक क्षमता का संतुलन भी गड़बड़ा दिया। यदि इजरायल इस हमले का जवाब न देता तो भविष्य के लिए संकेत जाता कि ईरान सीधे उस पर बमबारी कर सकता है और फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस समय पश्चिम एशिया में तनाव के चलते अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि की सेनाएं तैनात हैं और ईरानी हमले को विफल करने में उन्होंने इजरायल की पूरी सहायता की, परंतु यह स्थिति हमेशा नहीं रहेगी, इसलिए इजरायल के लिए ईरान पर जवाबी कार्रवाई कर शक्ति संतुलन बहाल करना जरूरी था, ताकि भविष्य में ईरानी हमले नियमित न हो जाएं। खास बात यह है कि इजरायल ने ईरान पर हमला उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के जन्मदिन के मौके पर किया।

एक तरह से इजरायल और ईरान ने इतिहास में पहली बार एक-दूसरे पर सीधे सैन्य हमले किए। इजरायल के अंदर एक धड़ा है, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना चाहता है, क्योंकि यदि वह परमाणु बम बनाने में सफल हो गया तो वह पाकिस्तान की तरह परमाणु युद्ध की धमकी की आड़ में इजरायल के विरुद्ध व्यापक आतंकी युद्ध चलाता रह सकता है। इस धड़े को सऊदी अरब समेत कई सुन्नी देशों का मौन समर्थन है। वे नहीं चाहते कि शिया देश ईरान के पास परमाणु बम हो। जार्डन की वायुसेना ने तो ईरानी हमले को विफल करने में इजरायल की मदद भी की। माना जाता है कि इजरायली खुफिया एजेंसियां लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए ईरानी वैज्ञानिकों को निशाना बनाने के साथ अन्य विध्वंसक कार्रवाई करती आई हैं।

गत दिवस इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीधा निशाना तो नहीं बनाया, पर उन शहरों के सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की, जहां उसके परमाणु संयंत्र भी हैं। ईरानी सूत्र इस हमले को एक छोटा और विफल ड्रोन हमला बता रहे हैं, क्योंकि सच स्वीकारने पर ईरान को फिर से इजराइल पर मिसाइल हमले करने होंगे, जो पहले की तरह विफल कर दिए जाएंगे और उसकी कमजोरी की पोल पुनः खुल जाएगी। ईरान का व्यवहार बालाकोट में भारत के हमले के बाद पाकिस्तान जैसा है। इजरायल ने शायद इसलिए ईरान पर हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली, क्योंकि ऐसा करना रूसी वायुसेना को ईरान में आने का बहाना दे सकता था, जैसा सीरिया में देखा जा चुका है और अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। पश्चिम एशिया में ईरान-इजरायल का टकराव पहले ही यूक्रेन में अमेरिका समर्थित प्रतिरोध की धार कुंद कर रहा है। ऐसे में इन दोनों देशों का टकराव धीरे-धीरे तेजी पकड़ने और विश्व शांति को संकट में डालने वाला हो सकता है, जिसकी जद में देर-सबेर ईरानी परमाणु कार्यक्रम भी आ सकता है। चूंकि यह साफ है कि पश्चिम एशिया में शांति के आसार नहीं, इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा।

(लेखक काउंसिल आफ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप का खतरा

शशि शेखर वेम्पति

बाहरी संस्थाएं अन्य देशों में चुनावों को प्रभावित करने के बाद भारत पर भी नजर टेढ़ी किए हुए हैं

विदेशी मीडिया के निशाने पर भी हैं आम चुनाव ● फाइल

पिछले कुछ हफ्तों में लोकसभा चुनाव से जुड़े विषय फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग, अल-जजीरा, यूके गार्जियन और इकोनमिस्ट जैसे वैश्विक मीडिया संस्थान की कवरेज के केंद्र-बिंदु बन गए हैं। इन मीडिया संस्थानों की कवरेज और लेखों के स्वर एवं भाव लगभग एक जैसे हैं और इनकी वजह से भारतीय लोकतंत्र के कमजोर होने से लेकर उसके भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ने की भविष्यवाणियां की जा रही हैं। विशेष रूप से चिंता की बात यह है कि वैश्विक मीडिया संस्थानों की कवरेज ने भारत में राजनीतिक मतभेदों को और बढ़ाने की कोशिश की है। उत्तर-दक्षिण विभाजन की कल्पना से लेकर न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग जैसे स्वायत्त संवैधानिक निकायों की विश्वसनीयता को कम करने तक, ऐसी विदेशी कवरेज ने पहले वोट डाले जाने के पूर्व ही चुनावी नतीजों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने के प्रयास किए हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि भारत परिष्कृत विदेशी हस्तक्षेप अभियानों का लक्ष्य बन गया है, जो इंटरनेट की व्यापक पहुंच और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की ताकत का लाभ उठा रहे हैं। इसमें भारत अकेला नहीं है। ऐसे कई विदेशी अभियानों ने दुनिया भर में चुनावी प्रक्रियाओं की पवित्रता को खतरे में डाल दिया है। उदाहरण के तौर पर कनाडा और आस्ट्रेलिया ने ऐसे अभियानों का सामना किया है, जिनके बारे में चीनी प्रभाव वाले फंडिंग अभियानों और प्रचार-प्रसार से जुड़े लगभग सिद्ध हो चुके मामले मौजूद हैं। माइक्रोसाफ्ट ने डीपफेक और एआइ के दुर्भावनापूर्ण उपयोग के माध्यम से चीन की ओर से भारतीय चुनावों को लेकर खतरों के प्रति आगाह भी किया है। कनाडा में प्रवासी भारतीयों और राजनीतिक हस्तियों को प्रभावित करने के गुप्त प्रयासों की रिपोर्टों ने चिंता पैदा की है। इसी तरह, आस्ट्रेलिया अपनी राजनीतिक संप्रभुता पर विदेशी हस्तक्षेप के प्रभाव से जूझ रहा है, जिसके कारण महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किए गए हैं तथा जासूसी और विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ कानूनों को मजबूत बनाया गया है।

विभिन्न प्रमाणों से यह स्पष्ट हुआ है कि परोक्ष तरीके से भेजी जाने वाली चीनी फंडिंग ने भारतीय मीडिया प्रतिष्ठानों में अपना रास्ता बना लिया है, जो सूक्ष्मता से धारणाओं को बदलने के साथ ही जनता की राय को प्रभावित कर रहा है। न्यूजक्लिक को विदेशी फंडिंग और चीन से जुड़े व्यवसायियों के साथ उसके संबंध का हालिया मामला इसका उदाहरण है। इससे भी अधिक घातक तरीके से, इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों को फर्जी वीडियो एवं डीपफेक कंटेंट को प्रसारित करने का हथियार बनाया गया है, जिससे सच्चाई एवं मनगढ़ंत कहानियों के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई हैं और प्रधानमंत्री मोदी तक ऐसे डीपफेक का शिकार हो गए हैं। वाट्सएप जैसे व्यक्तिगत मैसेजिंग एप्लिकेशन के जरिये गलत जानकारियों के अत्यधिक प्रसार ने चुनावी प्रक्रिया में भरोसे को कम करते हुए मतदाताओं को गुमराह करने वाली रणनीति का पता लगाना कठिन बना दिया है।

भारतीय राजनीति पर ऐसी हरकतों के परिणाम दूरगामी होंगे। सूचना इकोसिस्टम में हेरफेर करने के अलावा विदेशी शक्तियां घरेलू तत्वों की पक्षपातपूर्ण राजनीतिक बयानबाजी का सहारा लेकर भारत में सामाजिक भेद को बढ़ा रही हैं। हताश राजनीतिक दल और नेता इस 'घातक' रणनीति का सहारा ले रहे हैं। उन्हें इस बात का जरा भी भान नहीं है कि भारतीय लोकतंत्र के बारे में उनकी अनावश्यक और अतिरंजित घोषणाओं का विदेशी शक्तियों द्वारा भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने के उद्देश्य से दोहन किया जा रहा है। यह लोकतंत्र के मूल सार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के नतीजे में विश्वास को खतरे में डाल रहा है। भारत की चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सीमा पार बैठे एजेंटों की ओर से प्रौद्योगिकी के दुर्भावनापूर्ण उपयोग के जरिये उत्पन्न होने वाले अभूतपूर्व खतरों को देखते हुए, यह तत्काल निर्णय लेने और कार्रवाई करने का समय है। सूचनाओं के प्रसार में व्याप्त कमजोरियों को दूर करने और चुनावी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए सुरक्षात्मक उपाय किए जाने की जरूरत है। भारत निर्वाचन आयोग को अन्य सरकारी और गैर-सरकारी हितधारकों के साथ मिलकर इन कमजोरियों को दूर करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए।

भारत निर्वाचन आयोग की अहम भूमिका के तहत फोकस अन्य बातों के बजाय मुख्यतः आदर्श आचार संहिता को लागू करने पर केंद्रित रहा है, जबकि इस प्रक्रिया में हो रहे विदेशी हस्तक्षेप पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। दरअसल, चुनाव प्रक्रिया में हो रहे विदेशी हस्तक्षेप और इसके साथ ही गलत सूचनाओं से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को अपने अभियानों से परे जाकर मतदाताओं को जागरूक करने की जरूरत है, ताकि फर्जी खबरों, दुर्भावनापूर्ण वीडियो और डीपफेक मीडिया की सक्रिय रूप से पहचान की जा सके और उन्हें तत्काल हटाया जा सके। इसी तरह सरकार की फैक्ट्स चेक यूनिट्स को प्रभावकारी उपकरणों या साधनों और व्यापक क्षमता से लैस करके उन्हें सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है, तभी चुनाव आयोग दृढ़ता के साथ इस दिशा में ठोस कदम उठा सकता है। वास्तव में, यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपने भविष्य को अक्षुण्ण रखने के लिए हर हाल में जीतना ही होगा। यह हमारे लोकतंत्र के मजबूत आधार की रक्षा के लिए सतर्कता बरतने, एकता सुनिश्चित करने और सक्रिय उपायों का आह्वान करने का सही समय है। अब इस मोर्चे पर ठोस कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ना आवश्यक हो गया है।

(लेखक प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सत्य की महत्ता

इस समय संसार में असत्य और कपट का बोलबाला बढ़ रहा है। ऐसे में सत्य की महत्ता को समझना और भी आवश्यक हो गया है। गौतम बुद्ध ने इस संबंध में कहा है कि सत्य को छोड़कर जो असत्य बोलता है, धर्म का उल्लंघन करता है, परलोक की जिसे चिंता नहीं है, वह आदमी बड़े से बड़ा पाप कर सकता है। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में संकोच नहीं, वह कोई भी अनर्थ कर सकता है। इसलिए कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित न करें और न ही झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहन दें। असत्य का पूर्ण रूप से परित्याग कर देना चाहिए।

सत्य को कितने भी पर्दों में क्यों न छुपाकर रख दिया जाए, एक न एक दिन वह प्रकट हो ही जाता है। हमारे मनीषियों ने यथार्थ ही कहा है कि 'मनसा वाचा कर्मणा' यानी मन, वचन और कर्म से सत्य बोलना चाहिए। जो विचार मन में हो वही वाणी में भी होने चाहिए और उसी के अनुरूप ही मनुष्य का व्यवहार भी होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि मन, वचन और कर्म से अलग रहने वाले पूर्णरूपेण सत्य का आचरण नहीं कर सकते। चूंकि सत्य सदैव कड़वा होता है तो सत्य बोलने वाले समाज में कुछ अलोकप्रिय भी हो जाते हैं।

सत्य के महत्व पर गांधीजी ने कहा है कि सत्य केवल शब्दों की सत्यता ही नहीं, बल्कि विचारों की सत्यता भी है। हमारी अवधारणा का सापेक्षिक सत्य ही नहीं, बल्कि निरपेक्ष सत्य भी है, जो ईश्वर ही है। गांधीजी सत्य को निरपेक्ष सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं। सत्य को ईश्वर का पर्यायवाची मानते हैं। इसी सत्य के प्रति निष्ठा है। हमारे अस्तित्व का एकमात्र औचित्य यही हो कि हमारी समस्त गतिविधि सत्य पर केंद्रित रहे। सत्य ही हमारे जीवन का प्राण तत्व होना चाहिए, क्योंकि सत्य के बिना व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। संभव है कि सत्य के बिना भी उसे सफलता मिल जाए, किंतु आंतरिक शांति एवं समग्र संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होगी।

नृपेंद्र अभिषेक नृप

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

वंशवादी राजनीति पर लगे विराम

'लोकतंत्र पर ही सवाल है वंशवाद' शीर्षक से लिखे आलेख में राज कुमार सिंह ने वंशवादी राजनीति के दम पर उम्मीदवारी हासिल करने वाले नेताओं की विस्तारपूर्वक लंबी सूची प्रस्तुत की है। सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी राजनीति की काट क्या है? इस तरह की राजनीति से देशवासियों को छुटकारा कैसे मिले? जिस राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से हुई थी, उसकी गिरफ्त में कमोबेश सभी पार्टियां कैसे आ गईं? दुखद है कि ऐसी राजनीति का विरोध करने वाले सबसे अधिक इसमें डूबे नजर आ रहे हैं। बस, भाजपा और अन्य पार्टियों में यह फर्क बचा है कि भाजपा किसी परिवार विशेष की पार्टी नहीं रह गई है, जबकि बाकी लगभग सभी परिवार की पार्टी बनकर रह गई हैं। मानो पार्टी न होकर कोई निजी कंपनी हो। ऐसे में अगर लोकतंत्र को बचाए रखना है, नए लोगों में राजनीति के प्रति आकर्षण पैदा करना है, तब कुछ न कुछ उपाय तो ढूंढ़ने ही पड़ेंगे। बाकायदा इस बुराई के खराब परिणाम से प्रधानमंत्री देशवासियों को अवगत कराते रहते हैं। क्या देशवासी यह उम्मीद करें कि वह अपने तीसरे कार्यकाल में इस बुराई का कोई उपयुक्त समाधान दे पाएंगे, क्योंकि देश की जनता को यह भान है कि प्रधानमंत्री में वह माद्दा है जो सामाजिक सुधार के जरिये राजनीति की दशा-दिशा में सुधार कर सकते हैं। किसी अन्य में यह सामर्थ्य नहीं है। ऐसा विगत 10 वर्षों में उनके द्वारा लिए गए फैसलों से स्वाभाविक रूप से जाहिर भी होता है।

मुकेश कुमार मनन, पटना

महिला लोको पायलट की समस्याएं

रेलगाड़ियों में अब महिलाएं लोको पायलट का काम करने लगी हैं, लेकिन रेल मंत्रालय का ध्यान इनके कार्यस्थल की परेशानियों पर नहीं गया। सोचने की बात है कि अगर किसी व्यक्ति को चार-पांच घंटे या उससे ज्यादा देर तक लगातार काम करते रहना पड़े और आवश्यकता पड़ने पर भी उसके लिए शौचालय की सुविधा न हो तो उसकी स्थिति की कल्पना की जा सकती है। ऐसी ही समस्या चौक चौराहों पर तैनात महिला पुलिस के साथ भी है। काम का दबाव और इंजन में टायलेट की सुविधा नहीं होने के कारण महिला लोको पायलट कम पानी पीती हैं, ताकि उन्हें शौचालय की जरूरत ही नहीं पड़े। सवारी गाड़ी में स्टेशन पर रुकने पर महिला लोको पायलट बोगी के शौचालय का प्रयोग कर सकती हैं, परंतु मालगाड़ी में स्थिति विकट हो जाती है। अगर महिला लोको पायलट के सहयोग में पुरुष हो, तो स्थिति और असहज हो जाती है। यही वजह है कि महिला लोको पायलट के एक समूह ने रेलवे बोर्ड से आग्रह किया है कि या तो उनके कामकाज की दयनीय परिस्थितियों में सुधार किया जाए या फिर उन्हें अन्य विभागों में स्थानांतरित कर दिया जाए। रेल के व्यापक तंत्र में तमाम समस्याओं पर बात होती रही है, उनमें सुधार के लिए काम होते रहे हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेवा बनाने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, निकट भविष्य में बुलेट ट्रेन भी चलाई जाएंगी। ट्रेन को चलाने एवं गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी जिन चालकों पर होती है, उनकी सुविधा पर कम बात होती है। मंत्रालय को इनकी समस्या के निदान के लिए शीघ्र कदम उठाने की जरूरत है।

प्रसिद्ध यादव, बाबूचक, पटना

भारत से सौतेलापन

संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित 'दोयम दर्जे के उत्पाद' पढ़ा। अगर आप अपने नौनिहालों को पौष्टिक आहार या पेय जूस के तौर पर नामी गिरामी ब्रांड के उत्पाद देते हैं तो सावधान हो जाइए। एक जांच में बताया गया है कि ये सभी शिशुओं के पोषण में सक्षम नहीं है, अपितु जायका बदलने के लिए पर्याप्त है। इन आहारों एवं पौष्टिक पदार्थ को बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां पश्चिम देशों की तुलना में भारत से सौतेला व्यवहार करती है। ये कंपनियां पश्चिम देशों के लिए उच्च गुणवत्ता तथा भारत के लिए निम्न गुणवत्ता के उत्पाद बनाती हैं। रिपोर्ट के अनुसार नेस्ले भारत सहित कम समृद्ध देशों में बेचे जाने वाले शिशु के दूध में चीनी मिलाती है। यह रहस्योद्घाटन तब सामने आया जब स्विस जांच संगठन 'पब्लिक आई' और आईबीएफएएन (इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क) ने कंपनी के एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में विपणन किए जाने वाले शिशु खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए बेल्जियम की प्रयोगशाला में भेजे। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने देश में कार्यरत सभी ई कामर्स कंपनियों को पत्र जारी कर कहा है कि एनसीपीसीआर की जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि एफएसएस एक्ट 2006 के तहत कोई भी ड्रिंक हेल्थ ड्रिंक के तौर पर परिभाषित नहीं है। पत्र में ई कामर्स वेबसाइट्स और प्लेटफार्म को आदेश दिया गया है कि सभी को हेल्थ ड्रिंक की श्रेणी से हटाएं। नेस्ले इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, गुणवत्ता अनुपालन नेस्ले इंडिया की एक अनिवार्य विशेषता है।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

पोस्ट

कम्युनिस्टों को ऐसे ही भारत की जनता संदेह की दृष्टि से नहीं देखती। माकपा का घोषणा पत्र तो एक उदाहरण भर है, जिसमें देश के परमाणु हथियारों और सैन्य ठिकानों को खत्म करने की बात कही गई है।

सुशांत झा@jhasushant

मेरी समझ में इस चुनाव में कारोबारी तबका वैश्विक अवसरों के लिए वोट करेगा। मध्यवर्ग जीवन की सुरक्षा और अराजकता की आशंका को ध्यान में रखकर मतदान करेगा। हाशिए पर खड़ा समाज सत्ता से जीवन में समृद्धि की आस में वोट करेगा। ऐसे कम ही लोग हैं जो जाति के आधार पर वोट करेंगे। जबकि अल्पसंख्यकों का रुझान तो सार्वजनिक है।

सुमंत@sumantkabir

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो गई। दक्षिण कोरिया से लेकर इजरायल तक भारत जैसा कोई अनूठा लोकतंत्र नहीं। कम से कम विशाल लोकतंत्रों में तो ऐसा कोई भी नहीं है। यहां सत्ता का हस्तांतरण बहुत सुगम तरीके से होता आया है। तमाम आंतरिक कलह लोकतांत्रिक मुकाबले में समाहित हो जाती हैं और हम पहले की तुलना में और अधिक सुरक्षित होते जाते हैं।

हर्ष मधुसूदन@harshmadhusudan

जनपथ

गरजे जाय विदेश में अब अपना ब्रह्मोस,
देखि पड़ोसी देश को आएगा कुछ होश।
आएगा कुछ होश रहे ना बस आयातक,
अब हम क्षमतावान कहे जाते निर्यातक।
यही वोट का मूल्य इसे यदि जनता सिरजे,
फिर तो शीश उठाय विश्व में भारत गरजे!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्र, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 9

****

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का 75 निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक स्थापना वर्ष : 1948

सबसे बड़ा साहसिक कार्य जो आप कर सकते हैं, वह है अपने सपनों का जीवन जीना। -ओपरा विन्फ्रे

पहले बॉर्नवीटा और अब नेस्ले के प्रकरण से सवाल उठता है कि आखिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंतरराष्ट्रीय मानक विकासशील देशों में कमजोर क्यों हो जाते हैं? ब्रांड के नाम से आकर्षित होकर ही उपभोक्ता चयन करते हैं, लेकिन अगर ब्रांड ही अपनी प्रामाणिकता पर खरे न उतरें, तो संदेह गहराता है।

प्रामाणिकता का सवाल

केंद्र सरकार द्वारा ई-कॉमर्स कंपनियों को बॉर्नवीटा जैसे पेयों को स्वास्थ्य पेय की श्रेणी से हटाने के निर्देश दिए जाने के कुछ ही दिनों के भीतर अब शिशु आहार से जुड़ी कंपनी नेस्ले जिस तरह विवादों में घिरी है, उससे बच्चों के स्वास्थ्य के नाम पर परोसे जा रहे इन उत्पादों पर प्रश्नचिह्न तो लगता ही है, यह सवाल भी पैदा होता है कि आखिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंतरराष्ट्रीय मानक विकासशील देशों में कमजोर क्यों हो जाते हैं? उल्लेखनीय है कि स्विट्जरलैंड की जांच एजेंसी 'पब्लिक आई' और अंतरराष्ट्रीय शिशु आहार एक्शन नेटवर्क ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बेचे जा रहे नेस्ले के शिशु आहार उत्पादों के नमूने जब बेल्जियम की एक प्रयोगशाला में भेजे, तब पाया गया कि अल्प विकसित बाजारों में भेजे जा रहे शिशुओं के दूध में यूरोपीय बाजारों की तुलना में चीनी की मात्रा ज्यादा है। बावजूद इसके कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही नवजात शिशुओं की खुराक में अतिरिक्त चीनी से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसानों को लेकर चेतावनी दे चुका है, रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर सेरेलेक उत्पाद में प्रति खुराक 2.7 ग्राम चीनी थी, जबकि इथियोपिया में यह पांच ग्राम से ज्यादा और थाईलैंड में तो छह ग्राम तक पाई गई। उल्लेखनीय है कि कुछ साल पहले नेस्ले के ही एक दूसरे लोकप्रिय उत्पाद मैगी में भी हानिकारक पदार्थों की मौजूदगी के आरोप लगे थे। बात सिर्फ नेस्ले की नहीं है, चाहे सौंदर्य प्रसाधन हों या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, बहुराष्ट्रीय कंपनियां गुणवत्ता के मामले में विकासशील देशों के साथ दोहरा मापदंड दिखाती ही हैं, तो क्या यह व्यवस्था का मामला है या हम ही ध्यान नहीं देते या ये कंपनियां ही हमें द्वितीयक श्रेणी का मानती हैं? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फिलहाल रिपोर्ट की जांच कर रहा है और अगर रिपोर्ट में जरा भी सच्चाई निकलती है, तो यह स्थिति कड़े कदम उठाने की मांग करती है, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस नेस्ले-प्रकरण के बाद

पैकेज्ड या जंक फूड के बरक्स परंपरागत खाद्य पदार्थों की ओर लौटने की बहस तेज होगी, इसमें संदेह नहीं। पर बढ़ती मांग, घटती उपलब्धता और पर्यावरण के अंधाधुंध शोषण से अनाज, फल और दूध ही भला कितने शुद्ध बचे हैं। इसलिए मुद्दा पारंपरिक बनाम पैकेज्ड का उतना नहीं है, जितना खाद्य पदार्थों की सतत जांच का है। फिर जो चीजें बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी हैं, उनकी गहन जांच तो और भी जरूरी है। अगर हम पश्चिम का ही उदाहरण लें, तो खान-पान की शुद्धता के जो मानक उन्होंने बना रखे हैं, वे हमसे उन्नत हैं। हर चीज में पश्चिम की नकल करने वाले हम इस मामले में उनसे कोई सीख क्यों नहीं लेते!

पुनर्जागरण की राजनीति

ट्रंप की लोकप्रियता के बावजूद, उनकी शैली के चलते 'ट्रंपवाद' बेशक तेजी से विकसित न हो पा रहा हो, लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी दक्षिणपंथ का एक नया ही प्रयोग कर रहे हैं। वह विचारधारा के पुराने तर्कों और सांस्कृतिक पुरुखों को तवज्जो देने के साथ भविष्य से संवाद भी कर रहे हैं।

राष्ट्र को विवादित भावनाओं में बांट देना चुनावों के दौरान आम है। लेकिन राष्ट्रीय आत्मा का संघर्ष वह होता है, जब राजनेता सत्ता की व्यर्थ लड़ाई के जरिये देशभक्ति की बहाली के लिए प्रयास करते हैं। 21वीं सदी में इस विचार के सबसे परिचित खिलाड़ी असंतोष व स्वदेशीवाद का शोर मचाने वाले हलकों से आते हैं, और वे गौरवशाली अतीत की ओर वापसी को महानता की पूर्व शर्त बनाते हैं। यही वह पक्ष है, जो आमतौर पर धोखे के शिकार राष्ट्र और उसके निर्वाचित सहयोगियों के खिलाफ जीतता है। ब्रेग्जिट से प्रभावित ब्रिटेन और 'ट्रंपवाद' से प्रभावित अमेरिका इसके सटीक उदाहरण हैं कि कैसे एक काल्पनिक राष्ट्र वर्तमान दुर्दशा के खिलाफ विद्रोह का योग्य गंतव्य बन जाता है।

एस प्रसन्नराजन
संपादक, ओपन मैगजीन

ब्रेग्जिट और ट्रंपवाद, दोनों आज खंडित विरासत हैं। ब्रेग्जिट के उत्तराधिकारी राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए वोट का प्रबंधन करने में विफल रहे हैं; उन्होंने जो हासिल किया है, वह आर्थिक ठहराव और राजनीतिक अस्थिरता है। दुखद है कि राष्ट्रीय आत्मा के लिए संघर्ष राजनीतिक नश्वरता के विरुद्ध संघर्ष बन गया है। और ट्रंप की लोकप्रियता में वृद्धि के बावजूद ट्रंपवाद मजबूत नहीं हुआ। एक बार सत्ता में आने के बाद, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था में उनकी सफलता उनकी व्यक्तिगत शैली के नीचे दब गई। हार के बाद वह अमेरिकी राष्ट्रपति के इतिहास में साजिश के सर्वोच्च दूत बन गए। जैसा कि दूसरी बार सत्ता में उनका आना अपरिहार्य लग रहा है, ट्रंप अब भी बिगड़ैल सांड की भूमिका निभा रहे हैं। ट्रंप के रहते ट्रंपवाद के विचार के विकास की कोई संभावना नहीं दिखती। ये उदाहरण लोकप्रिय भावना और राजनीतिक यथार्थवाद के बीच के अंतर को सामने लाते हैं।

राष्ट्रीय आत्मा के लिए संघर्ष मुक्ति की त्रुटिपूर्ण राजनीति के रूप में समाप्त होता है। मूल आदर्श की मृत्यु के बाद राष्ट्र के झूठे पुनर्स्थापकों का उदय होता है। लेकिन अगर भारतीय राजनीति पर नजर डालें, तो यह पैटर्न टूट जाता है। यहां राष्ट्रीय आत्मा का संघर्ष अपने दूसरे दशक में प्रवेश करता है। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी ने आम चुनाव को राष्ट्रवाद की बहाली के जनमत संग्रह में बदल दिया। उन्होंने कभी भी खुद को दूसरे प्रधानमंत्री उम्मीदवारों के रूप में नहीं देखा, जिनकी सीमा अगले पांच वर्षों से आगे नहीं बढ़ती। मोदी ने भारत को आधुनिक रूप देने वाले और राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने वाले नेता के रूप में चुनाव जीता और अपना लक्ष्य काल्पनिक अतीत में नहीं खोजा, बल्कि भविष्य से संवाद किया।

यह सांस्कृतिक तर्क है, जिसमें दक्षिणपंथ आम तौर पर हार जाता है, पर मोदी के लिए यह तर्क भी नहीं है। यह होने की स्थिति है। राष्ट्रीय आधुनिकीकरण की अपनी परियोजना को सबसे स्थायी क्षेत्र यानी भारत के गरीबों तक ले जाने के लिए उन्हें कभी भी हिंदू विशेषण की जरूरत महसूस नहीं हुई। भारत के सांस्कृतिक पुरखों को बार-बार याद करने की जरूरत नहीं थी, और यह केवल उन लोगों के लिए विवाद का विषय था, जो अब भी मूल राष्ट्र निर्माताओं के उपदेशों में डूबे हुए थे। मोदी ने राष्ट्र को सीमित करने वाले स्थापत्यों को नष्ट करना अभी खत्म नहीं किया है, और इसलिए 2024 में उनकी लड़ाई राष्ट्र की पुनर्स्थापना के लिए है।

विकल्प में एक गठबंधन है, जिसे अपनी भारतीयता को रेखांकित करने के लिए एक संक्षिप्त नाम की जरूरत है। जब वे लुप्तप्राय भारत का रोना रोते हैं, तो अनिवार्य रूप से उनका मतलब ऐसे भारत से होता है, जो भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, उप-राष्ट्रवाद और वंशानुगत शक्ति में संलिप्त था-एक ऐसा भारत, जहां धर्मनिरपेक्ष आदर्श का मुख्य आकर्षण अल्पसंख्यक बस्तियां और राष्ट्रीय निषेध है। महागठबंधन का प्रत्येक सदस्य एक ऐसे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जो योग्यता और आधुनिकता पर बने समाज के आवेगों और दृष्टिकोण से बहुत दूर है।

लुप्तप्राय भारत के उनके रुदन को बौद्धिक समर्थन मिलता है, और ऐसे समय में, जब असहमति किसी कारण की तलाश में हो, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जो शायद यह बताता है कि असहमत लोगों के एक वर्ग के लिए अघोषित आपातकाल का आह्वान स्वाभाविक क्यों है। यह असहिष्णुता या वैचारिक हिंसा की किसी भी अभिव्यक्ति का विरोध करने के लिए फासीवाद शब्द का इस्तेमाल करने जितना ही अनैतिहासिक है। काले अतीत का इस तरह आकस्मिक सहारा अमानवीयता की यादों को कमतर कर देता है। अघोषित आपातकाल की साझा चिंता भारत की सांविधानिकता का सबसे निर्लज्ज उल्लंघन है।

भारत उन लोगों के लिए एक चुनावी निरंकुश शासन है, जो ताकत और दृढ़ संकल्प दिखाने वाली मोदी की दृढ़ विश्वास की राजनीति को गलत समझते हैं। वे अपना हाई कमान स्वयं हैं और अपने इस विश्वास के लिए लड़ते हैं कि सत्ता ही परिवर्तन लाती है। यह अपने आप में एक ऐसे देश में बड़ा सांस्कृतिक बदलाव है, जो सत्ता के लिए संघर्ष को नैतिक महत्व देता है, जिसे सत्ता के खिलाफ संघर्ष से कमतर बना दिया गया है।

जो लोग मोदी के भारत पर संविधानेतर होने का आरोप लगाते हैं, वे इसे निरंकुशता मानने की गलती करते हैं। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को ही लीजिए, जिसे अब भी कुछ लोग बहुसंख्यकवादी अपराध मानते हैं। हम इसे राष्ट्रीय एकता के उच्च उद्देश्य के लिए क्रूर सांविधानिकता के रूप में क्यों नहीं देख सकते? यदि भारत में जल्द ही समान नागरिक संहिता बनने जा रही है, तो यह केवल सांविधानिक समानता के आदर्शों पर खरा उतरने के लिए होगा। संस्थानों को कमजोर किए जाने की बात भी गलत है। भारत में न्यायाधीशों का चयन भी तो न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है। पूछा जा रहा है कि एक विपक्षी मुख्यमंत्री को जांच और कारावास क्यों दिया गया? क्या हम इसके बजाय 'आप' की अराजनीतिक राजनीति की मजबूर करने वाली कहानी नहीं बता सकते। गांधीवादी प्रतिरोध की कोख से जन्मा आंदोलन कैसे भ्रष्ट लोगों का संघ बन गया है? ऐसा लगता है कि लुप्तप्राय भारत में हितधारकों का एक अलग समूह है, और मोदी निश्चित रूप से उनमें नहीं हैं।

शायद यह अब राष्ट्रीय आत्मा की लड़ाई भी नहीं रही। क्या वह लड़ाई पहले ही नहीं जीती जा चुकी है? और विजेता अब भी लोकतंत्र में सबसे बड़े विश्वास मत का लाभ उठाता है, क्योंकि सत्ता ने भविष्य के लिए अभियान को और तेज कर दिया है। शुक्र है कि अतीत की याद दिलाता इंडिया (INDIA) केवल संक्षिप्त शब्द है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

आचार्य महाप्रज्ञ

ज्ञान के बाद आता है दर्शन। ज्ञान के आधार पर एक दृष्टिकोण निर्मित होता है। उसके बाद आचरण और व्यवहार की बात आती है। ज्ञान और आचरण के बीच एक दूरी है श्रद्धा और विश्वास की।

ज्ञान, दर्शन और चरित्र में सामंजस्य ही उद्देश्य

__जीवन__ का प्रवाह नदी के प्रवाह की भांति अनादिकाल से बहता आ रहा है। पूछा जाए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो कहना होगा कुछ भी नहीं। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता। जीवन नियति का एक बंधन है। यदि जीवन का कोई उद्देश्य होता, तो वनस्पति, कीड़े-मकोड़ों, पशुओं और मनुष्यों का भी होता। किंतु किसी का कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य होता नहीं, उद्देश्य बनाया जाता है। उसका निर्माण किया जाता है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है। उसने बुद्धि का विकास किया है। उसमें चिंतन, मनन, प्रज्ञा, मेधा और धारणा है। इसलिए वह अपने उद्देश्य का निर्धारण करता है।

जीवन का कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमें क्षमता मिली है, विवेक मिला है, इसलिए हम उद्देश्य का निर्माण कर सकते हैं। यदि दर्शन के संदर्भ में सोचें कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो मैं एक छोटा-सा उत्तर दूंगा। ज्ञान, दर्शन और चरित्र में सामंजस्य-यह होना चाहिए जीवन का उद्देश्य। जीवन को संचालित करने वाली यह त्रयी बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं, देखते हैं, आस्था और श्रद्धा रखते हैं, आकर्षण उत्पन्न करते हैं और आचरण करते हैं। जैसे मस्तिष्क, हृदय और हाथ-पैर हैं, वैसे ही ज्ञान, दर्शन और चरित्र हैं। ज्ञान हमारा मस्तिष्क है, दर्शन हमारा हृदय है और चरित्र हमारे हाथ-पैर हैं। शारीरिक स्तर पर तीनों का योग है और तीनों समन्वित रूप से कार्य करते हैं। किंतु ज्ञान, दर्शन और चरित्र-इस त्रयी में संगति नहीं है। इसलिए आदमी का जीवन विसंगतियों से भरा है। उन विसंगतियों को मिटाना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए।

आज आदमी की कथनी और करनी में बहुत दूरी है। यह स्वाभाविक है। जानना ज्ञान का काम है, पर ज्ञान हो जाने पर विसंगति नहीं मिटती। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, जो बड़े विद्वान और पंडित हैं, किंतु आचार और व्यवहार की दृष्टि से शून्य हैं। उनका व्यवहार इतना रूखा और कटु होता है कि दूसरा कोई भी व्यक्ति उनके साथ रहना नहीं चाहता। उनमें निम्नतर वृत्तियां पाई जाती हैं। ज्ञान का काम व्यवहार का परिष्कार करना नहीं है।

कहा जाता है, ज्ञान जीवन में प्रकाश भरता है। ज्ञान एक दीप है, एक सूर्य है। ज्ञान केवल प्रकाश दे सकता है, क्रिया नहीं दे सकता। प्रकाश देना एक बात है और उसके अनुसार आचरण करना दूसरी बात है। दीया जला दिया, पर आंखों में मोतियाबिंद है, तो दीया क्या करेगा? उसमें मूर्च्छा के परमाणु इतने सक्रिय हो गए कि ज्ञान का काम समाप्त हो गया है।

ज्ञान के बाद आता है दर्शन। ज्ञान के आधार पर एक दृष्टिकोण निर्मित होता है। आदमी पहले किसी चीज के बारे में जानता है, फिर अपनी दृष्टि बनाता है। उसके बाद आचरण और व्यवहार की बात आती है। ज्ञान और आचरण के बीच एक दूरी है श्रद्धा और विश्वास की।

सफलता के लिए...

सूत्र

मोहनीय कर्म ज्ञानावरण को प्रभावित नहीं कर सकता। ज्ञान को प्रभावित करता है ज्ञानावरण कर्म, और दृष्टि तथा आचरण को प्रभावित करता है मोहनीय कर्म, मूर्च्छा के परमाणु। जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है ज्ञान, दर्शन और चरित्र की दूरी को मिटाना, उनमें सामंजस्य स्थापित करना।

दूसरा पहलू

यूक्रेन में कई लोग ऐसे हैं, जो पूर्वी मोर्चे पर लड़ने जाने के बजाय तैरकर नदी पार करने का विकल्प चुन रहे हैं।

अपनी जान बचाएं या देश की आन

नदी के भंवर बेहद खतरनाक हैं। नदी के किनारे खड़े और फिसलन भरे हैं, जबकि नदी के अंदर बड़े-बड़े पत्थर हैं। इन सबके बावजूद यूक्रेन के सीमा प्रहरी त्यासा नदी के आसपास गश्त करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि लोग इस खतरनाक नदी को पार कर वहां पहुंचना चाहते हैं, जहां रोमानिया की सीमा है। यूक्रेन के एक गश्ती सैनिक ने हाल ही में नदी पार करने की कोशिश करते एक व्यक्ति को पकड़ लिया था। वह पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए जाना चाह रहा था, जो दो साल से किसी यूरोपीय देश में रह रहे हैं। यूक्रेन के आम नागरिकों को अब युद्ध के मोर्चे पर लगाना पड़ रहा है।

एंड्रयू ई क्रेमर

रोमानिया के सरकारी आंकड़े के अनुसार, अब तक यूक्रेन के 6,000 से अधिक लोग त्यासा नदी पार कर उनके यहां शरण लेने पहुंचे हैं। जबकि 22 लोग नदी पार करते हुए मर चुके हैं।

ऐसे में, कई लोग ऐसे हैं, जो पूर्वी मोर्चे पर लड़ने जाने के बजाय तैरकर नदी पार करने का विकल्प चुन रहे हैं। 'हम इन लोगों के बारे में कोई फैसला नहीं ले सकते, जो नदी पार करने का जोखिम उठाते हैं। लेकिन अगर सभी लोग इसी तरह सोचें, तो यूक्रेन की रक्षा कौन करेगा', एक गश्ती सैनिक कहता है। रोमानिया के सरकारी आंकड़े के अनुसार, अब तक यूक्रेन के 6,000 से अधिक लोग त्यासा नदी पार कर उनके यहां शरण लेने पहुंचे हैं। जबकि 22 लोग नदी पार करते हुए मर चुके हैं। हालांकि डूबकर मरने वालों का आंकड़ा इससे अधिक होगा।

चूंकि युद्ध खत्म नहीं हो रहा और हताहतों की संख्या भी बढ़ रही है, इसलिए कई यूक्रेनी लड़ने के बजाय देश छोड़ने का रास्ता अपना रहे हैं।

चूंकि हाल के कुछ महीनों में रूस ने युद्धक्षेत्र में सफलता हासिल की है, ऐसे में, यूक्रेन के सामने जहां हथियारों का भंडार भरने की चुनौती है, जो उसके मित्र देशों के सहयोग पर निर्भर है, वहीं बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती की भी जरूरत है। इससे राष्ट्रपति जेलेंस्की की चुनौती भी बढ़ गई है। सैनिकों की भर्ती इतनी आसान भी नहीं है। महीनों की जद्दोजहद के बाद यूक्रेन की संसद ने पिछले दिनों सैन्य भर्ती कानून में संशोधन किया। इसके तहत न सिर्फ भर्ती की आयु घटाकर पच्चीस कर दी गई है, बल्कि मेडिकल जांच समेत कुछ और अनिवार्यताएं भी खत्म कर दी गई हैं।

यूक्रेन के सैन्य जनरल भी मानते हैं कि सैनिकों की कमी एक बड़ी समस्या है। युद्ध शुरू होने के बाद जिन लोगों ने स्वेच्छा से सेना में योगदान शुरू किया था, उनमें से ज्यादातर अब भी मोर्चे पर हैं। उन्हें साल में सिर्फ दो महीने की छुट्टी मिलती है। चूंकि युद्ध खत्म होने तक मोर्चे पर डटे रहना पड़ेगा, और हताहतों की संख्या भी बढ़ रही है, इसी कारण कई यूक्रेनी हथियार पकड़ने के बजाय देश छोड़ने का रास्ता अपना रहे हैं। अपने प्राण और देश-दोनों की रस्साकशी में स्वाभाविक ही यह मुश्किल पेश आती है।

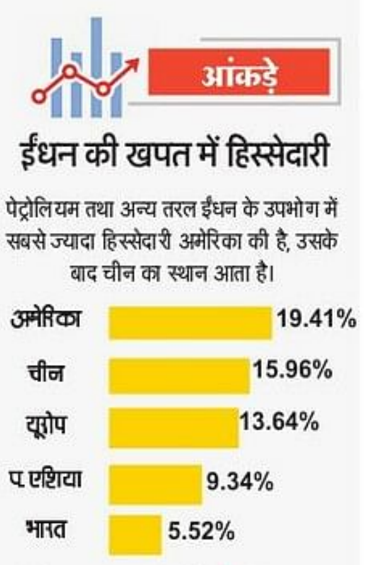

©The New York Times 2024

आंकड़े

ईंधन की खपत में हिस्सेदारी

पेट्रोलियम तथा अन्य तरल ईंधन के उपभोग में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी अमेरिका की है, उसके बाद चीन का स्थान आता है।

अमेरिका	19.41%
चीन	15.96%
यूरोप	13.64%
प. एशिया	9.34%
भारत	5.52%

आंकड़े 2024 की प्रथम तिमाही के | स्रोत: U.S EIA; TII

निम्न जाति तो उसकी होती है, जो दुर्व्यसनी और अपराधी होता है। स्वामी जी ने उसके हाथ से लोटा लेकर पानी ग्रहण किया।

भेदभाव पर प्रहार

अंतर्यात्रा
संकलित

उस समय स्वामी विवेकानंद नए-नए संन्यासी बने थे। तब तक उन्होंने प्राणिमात्र में समान भाव से ईश्वर के दर्शन के संदेश का गंभीर अध्ययन नहीं किया था। वह काफी समय तक ग्रामीण अंचलों का भ्रमण करने में लगे रहे और लोगों को सदाचारी बनने का उपदेश दिया करते थे।

एक दिन वह गर्मी में किसी गांव से गुजर रहे थे। एक व्यक्ति को मेड़ पर बैठे पानी पीते देखा, तो उन्हें भी प्यास लग गई। उन्होंने उस ग्रामीण से कहा, भैया, मुझे भी थोड़ा पानी पिला दो। उस ग्रामीण ने भगवा वस्त्रधारी साधु को देखकर सिर झुकाया और बोला, महाराज, मैं निम्न जाति का व्यक्ति आपको अपने हाथ से पानी पिलाकर पाप नहीं ले सकता।

यह सुनकर स्वामी जी आगे बढ़ गए। कुछ देर चलने के बाद उन्हें लगा कि मैंने साधु बनने के लिए जाति को त्याग दिया, तो फिर आग्रह करके उस ग्रामीण का पानी क्यों नहीं पिया? यह तो अधर्म हो गया। वह तुरंत उसके पास लौटकर बोले, भैया, मुझे क्षमा करना। मैंने तुम जैसे निश्छल व्यक्ति के हाथों से पानी न पीकर घोर पाप किया है। निम्न जाति तो उसकी होती है, जो दुर्व्यसनी और अपराधी होता है। स्वामी जी ने उसके हाथ से पानी ग्रहण किया। बाद में वह जीवन भर ऊंच-नीच की भावना पर प्रहार करते रहे।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला पुराने पन्नों से — 1 मई, 1992

दिल्ली विस्फोट कांड में मृतकों की संख्या 34 हुई

दिल्ली विस्फोट कांड में मृतक ३४ हुए
आतंकी कार्रवाई की आशंका नहीं

पुरानी दिल्ली में नया बाजार क्षेत्र में हुए भीषण विस्फोटों और उसके बाद तीन इमारतों के ढहने से मरने वालों की संख्या 34 पहुंच गई है। इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अभी मलबा निकालने का काम जारी है।

भ्रामक विज्ञापनों का विज्ञान

वर्तमान समय में जिस प्रकार से भ्रामक विज्ञापनों की बाढ़-सी आई है, यह समाज के लिए समाधान कम, समस्या ज्यादा बनते जा रहे हैं।

के सी त्यागी | बाजार

वर्तमान समय में विज्ञापन बाजार की दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में वैश्विक विज्ञापन बाजार का आकार 615.2 अरब अमेरिकी डॉलर था, जिसके आगामी कुछ वर्षों में 800 अरब डॉलर होने का अनुमान है। आंकड़ों के अनुसार, औसत व्यक्ति प्रतिदिन 200 से 300 विज्ञापन तक देखता है। विज्ञापन लोगों को सूचना देने और उत्पादों आदि के बारे में जागरूक करने का एक प्रभावी माध्यम है। लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से भ्रामक विज्ञापनों की बाढ़-सी आई है, यह समाज के लिए समाधान कम, समस्या ज्यादा बनते जा रहे हैं।

विज्ञापनदाता का इरादा मनोवैज्ञानिक रूप से आपको प्रभावित करते हुए आपके विचारों और निर्णयों को प्रभावित करना होता है। सिर्फ पांच दिनों में काले से गोरा करने, या मात्र एक खुशबू वाले डियोड्रेंट के स्प्रे मात्र से महिलाओं को आपके प्रति आकर्षित करने का दावा करने वाले विज्ञापन आपने खूब देखे होंगे।

अभी कुछ दिन पहले साइंस जर्नल 'मेडिसिन' ने भारत में बेचे जाने वाले और उपभोग किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय प्रोटीन पाउडर के 36 विभिन्न ब्रांडों पर किए गए विश्लेषण के निष्कर्ष प्रकाशित किए थे। विश्लेषण से पता चला कि 36 पूरकों में से लगभग 70 प्रतिशत में प्रोटीन की गलत जानकारी थी, कुछ ब्रांड अपने दावे का केवल आधा हिस्सा ही पेश कर रहे थे। इसके अलावा, लगभग 14 प्रतिशत नमूनों में हानिकारक फंगस थे, जबकि 8 प्रतिशत में कीटनाशकों के अवशेष दिखाई दिए। ये नतीजे भ्रामक जानकारी, पारदर्शिता की कमी और ऐसे उत्पादों से उत्पन्न संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में बढ़ती चिंता को दर्शाते हैं।

पर्यावरणीय स्थिरता और सचेत उपभोग के बारे में चिंतित दुनिया में ग्रीनवाशिंग एक बढ़ती हुई चिंता बन गई है। ग्रीनवॉशिंग, जिसे उत्पादों या सेवाओं के बारे में भ्रामक पर्यावरणीय दावे के रूप में परिभाषित किया गया है, ने नियामकों, उपभोक्ताओं और वकालत समूहों का समान रूप से ध्यान आकर्षित किया है। हाल ही में, यूरोपीय संसद और भारतीय न्यायपालिका, दोनों ने इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए निर्णायक कदम उठाए, जो सख्त नियमों और विपणन प्रथाओं में अधिक जवाबदेही की ओर वैश्विक बदलाव का संकेत है। इसी तरह, भारतीय न्यायपालिका द्वारा उत्पादों की प्रभावकारिता के बारे में भ्रामक और निराधार दावे करने के लिए पतंजलि समूह की निंदा करना कंपनियों को उनकी मार्केटिंग के प्रति जवाबदेह बनाने के महत्व को रेखांकित करता है। न्यायपालिका का निर्णय उपभोक्ताओं को गलत जानकारी के आधार पर विकल्प चुनने से बचाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनियां अपने विपणन संचार में नैतिक मानकों का पालन करें।

ग्रीनवाशिंग या भ्रामक विज्ञापन न केवल उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं, बल्कि टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के प्रयासों को भी कमजोर करते हैं। भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कस कर नियामक कंपनियों को अधिक जिम्मेदार और पारदर्शी विपणन रणनीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

भ्रामक विज्ञापनों को संबोधित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें नियामकों, उद्योग हितधारकों, उपभोक्ता वकालत समूहों और जनता के बीच सहयोग शामिल होता है। नियामक यह सुनिश्चित करते हुए कि कंपनियां विज्ञापन में सच्चाई का पालन करती हैं, पर्यावरणीय दावों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और मानक स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यवसायों और व्यापार संघों सहित उद्योग हितधारकों की नैतिक विपणन प्रथाओं को बनाए रखने और उपभोक्ताओं को सटीक जानकारी देने की जिम्मेदारी है। उपभोक्ता वकालत समूह भ्रामक प्रचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भ्रामक विपणन रणनीति के लिए कंपनियों को जिम्मेदार ठहराने में भूमिका निभा सकते हैं।

इसके अलावा, उपभोक्ता स्वयं टिकाऊ उपभोग प्रथाओं के बारे में खुद को शिक्षित करके और पर्यावरणीय प्रबंधन के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने वाले ब्रांडों का समर्थन करके ग्रीनवॉशिंग के खिलाफ लड़ाई में योगदान दे सकते हैं। नियमों को मजबूत बनाने, जागरूकता बढ़ाने और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है, केवल तभी हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उपभोक्ताओं के पास सटीक जानकारी पहुंच रही है, ताकि वे अपनी प्राथमिकताओं और मूल्यों के अनुरूप विकल्प चुन सकें।

साथ में बिशन नेहवाल।

कल्पमेधा

हम तितली की सुंदरता का आनंद लेते हैं, लेकिन बहुत कम उन परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं, जिनसे गुजर कर तितली को यह सुंदरता हासिल होती है।

– माया एंजेलो

चुनाव में हिंसा

आम चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। ज्यादातर इलाकों में तेज गर्मी के बावजूद लोगों में मतदान को लेकर उत्साह देखा गया। हालांकि कुछ जगहों पर हिंसक घटनाओं ने जरूर लोकतंत्र के इस उत्सव को बदरंग करने की कोशिश की, पर अच्छी बात है कि उनसे मतदाताओं और मतदान की प्रक्रिया पर बहुत नकारात्मक असर नहीं देखा गया। मणिपुर लंबे समय से जातीय हिंसा की चपेट में है और वहां पहले से चुनाव के विरोध का स्वर उभर रहा था। इसलिए अगर कुछ मतदान केंद्रों पर उपद्रव की घटनाएं हुईं, तो इसकी वजहें समझी जा सकती हैं। वहां चुनाव कराना निर्वाचन आयोग के सामने बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक मतदान केंद्र के पास नक्सलियों ने विस्फोट किया। यह भी कोई अनपेक्षित घटना नहीं थी, क्योंकि मतदान से दो दिन पहले ही वहां सुरक्षाबलों ने उनतीस नक्सलियों को मार गिराया था। उस घटना की प्रतिक्रिया में हमले की आशंका पहले से थी। हालांकि वहां भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और मतदान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न नहीं हुई। मगर पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसा देखी गई, वह जरूर चिंता पैदा करती है।

पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में हिंसा की आशंका बनी रहती है। पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता छोटी-छोटी बातों को लेकर गुत्थमगुत्था होते और हिंसक घटनाएं करते देखे जाते रहे हैं, उसमें इस चुनाव में भी व्यापक हिंसा की आशंका पहले से जताई जा रही है। उसकी शुरुआत कूचबिहार में देखी गई। वहां भाजपा के प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि राज्य के सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता लोगों को धमकाने और मतदान से रोकने का प्रयास करते रहे। यही आरोप तृणमूल कांग्रेस ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाए। उपद्रवियों की धर-पकड़ और हिंसा पर काबू पाने के क्रम में की गई तलाशी में कई बम भी बरामद किए गए। जाहिर है, हिंसा की तैयारियां वहां पहले से की गई थीं। पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में निर्वाचन आयोग अतिरिक्त रूप से सतर्क रहता है। इसलिए भी कूचबिहार में किसी बड़ी घटना की साजिशों को रोकने में कामयाबी मिल गई। मगर अभी वहां बाकी चरणों के चुनाव होने हैं, जिनमें हिंसा की आशंका बनी हुई है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में निर्वाचन आयोग का सहयोग करे।

यह ठीक है कि राजनीतिक दल अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। मगर इसका लोकतांत्रिक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि प्रतिद्वंद्वी दल के कार्यकर्ताओं पर हिंसक हमले करके उन्हें मतदान से रोका और अपने पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कराने का प्रयास किया जाए। अगर कोई राजनीतिक दल अपने कामकाज और सैद्धांतिक प्रभाव से मतदाता का विश्वास अर्जित नहीं कर पाता, तो उसे जीत का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता। मगर कुछ समय से धनबल और बाहुबल के जरिए चुनाव को अपने पक्ष में करने की अनैतिक कोशिशें बढ़ी हैं। लोकतंत्र मतदाता के भरोसे और विश्वास पर टिका होता है, अनैतिक तरीकों से मत अर्जित कर सत्ता में पहुंचे लोगों से लोकतंत्र की सुरक्षा की उम्मीद नहीं की जाती। जब तक राजनीतिक दल हिंसा के जरिए सत्ता में पहुंचने या बने रहने का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, तब तक सही अर्थों में चुनाव लोकतंत्र का उत्सव नहीं बन पाएंगे।

गहराता संकट

ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर इस्फहान पर इजराइल के हमले की खबर के बाद लगने लगा है कि युद्ध को टालने की कोशिशें अब नाकाम साबित हो रही हैं। स्थिति और नाजुक हो रही है। अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान पर नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। जाहिर है, ईरान के सामने अगर मुश्किलें पेश आएंगी तो उसकी प्रतिक्रिया भी शायद संतुलित न रहे। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में सीरिया में ईरान के दूतावास को इजराइल ने ड्रोन हमले से ध्वस्त कर दिया था। उसमें ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के दो जनरल समेत कुछ अन्य लोग मारे गए थे। उसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। इसके बाद से ही इजराइल के जवाबी कार्रवाई की आशंका बनी हुई थी। अब इस्फहान पर इजराइली ड्रोन हमले की खबर से साफ है कि हालात नाजुक हो सकते हैं। हालांकि ईरान ने ऐसे किसी हमले से इनकार किया है। उसने कहा है कि वह सिर्फ ड्रोन उड़ाने की कोशिश थी, जिसे मार गिराया गया। अगर इतना भी हुआ है, तो इससे टकराव और तनाव गहरा ही होगा। यह रास्ता कहां जाता है, छिपा नहीं है।

विडंबना है कि इसमें शामिल सभी सक्रिय पक्षों को पता है कि किसी भी समस्या या विवाद का आखिरी हल बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है। इसके बावजूद पहले सैन्य क्षमताओं की आजमाइश और टकराव को ही अकेला रास्ता माना जा रहा है। सवाल है कि अगर इजराइल और ईरान एक-दूसरे के ठिकानों पर हमला करते हैं, तो इससे नुकसान किसका होगा और कौन लोग नाहक मारे जाएंगे! इस टकराव के शुरुआती चरण में ही जिस तरह अलग-अलग ध्रुव बनते दिखने लगे हैं, उससे साफ है कि अगर इसका दायरा फैला तो यह तीसरे विश्वयुद्ध की शक्ल भी ले सकता है। अब तक के दो विश्वयुद्धों के जो अनुभव रहे हैं, उसमें तत्काल इस बात की जरूरत है कि संयुक्त राष्ट्र और महाशक्ति माने जाने वाले देश दखल देकर संबंधित पक्षों को बातचीत की मेज पर लाएं। युद्ध की आग और भड़की तो अत्याधुनिक तकनीकों और घातक हथियारों के इस युग में इसके नतीजे भयावह होंगे।

धरती के नीचे पसरा महासागर

वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के नीचे मौजूद महासागर में पृथ्वी की सतह के सभी महासागरों से तीन गुना अधिक पानी मौजूद हो सकता है।

रंजना मिश्रा

अब एक नया तथ्य सामने आया है कि पृथ्वी के अंदर सतह से सात सौ किलोमीटर नीचे एक विशाल महासागर छिपा हुआ है। यह महासागर 'रिंगवुडाइट' नामक खनिज में स्थित है, जो पृथ्वी की ऊपरी 'मेंटल' में पाया जाता है। 'मेंटल' पृथ्वी की सतह के नीचे पैंतीस किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रिंगवुडाइट की क्रिस्टल संरचना में हाइड्राक्साइड आयन होते हैं। यह स्पंज की तरह होता है, जो पानी को अपने अंदर सोखने की क्षमता रखता है। रिंगवुडाइट एक अत्यंत घना खनिज है, जो पृथ्वी के गहरे भागों में उच्च दबाव और तापमान के कारण बनता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के नीचे मौजूद महासागर में पृथ्वी की सतह के सभी महासागरों से तीन गुना अधिक पानी मौजूद हो सकता है। प्रसिद्ध भूविज्ञानी स्टीव जैकबसेन ने यह रोमांचक खोज की है।

वैज्ञानिक कई दशक से गहरे पानी की तलाश कर रहे हैं। यह खोज उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह खोज अमेरिका में दो हजार से अधिक भूकम्पमापी संयंत्रों की मदद से की गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पानी पृथ्वी के अंदर ही बना है। यह ज्वालामुखी विस्फोटों और अन्य भूवैज्ञानिक गतिविधियों के माध्यम से सतह पर आता है। यह खोज बेहद महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह पृथ्वी के जल चक्र को समझने में हमारी मदद कर सकती है। इससे यह समझने में भी मदद मिल सकती है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ और पृथ्वी की प्लेटें कैसे गति करती हैं, भूकम्प कैसे आते हैं। हालांकि यह खोज अभी शुरुआती चरण में है और वैज्ञानिकों को बहुत शोध करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक यह भी अध्ययन कर रहे हैं कि इस पानी का पृथ्वी के जलचक्र और जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है।

यह संभव है कि यह महासागर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का स्रोत हो और यह हमें अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में भी मदद कर सकता है। हालांकि, इस महासागर का अध्ययन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यह पृथ्वी की सतह से बहुत गहराई में स्थित है। वैज्ञानिकों को भूकंपीय तरंगों का उपयोग करके ही इस महासागर का अध्ययन करना होगा और यह एक धीमी और जटिल प्रक्रिया है। यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि इस महासागर में पानी किस रूप में मौजूद है। यह तरल पानी, बर्फ या किसी अन्य रूप में हो सकता है। वैज्ञानिकों को यह भी पता लगाना होगा कि यह महासागर पृथ्वी के अन्य भागों से कैसे जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक यह भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या इस पानी का उपयोग किया जा सकता है। यह खोज हमें भविष्य में पानी की कमी से निपटने में भी मदद कर सकती है।

वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर पानी लगभग 4.6 अरब साल पहले आया था। पृथ्वी की सतह का लगभग 71 फीसद हिस्सा पानी से ढका है। अधिकतर पानी खारा है, जो पीने या खेती योग्य नहीं है। पृथ्वी का केवल तीन फीसद पानी ताजा है, जो पीने और खेती के लिए उपयोगी है। पृथ्वी की सतह पर पानी की उत्पत्ति को लेकर कई सिद्धांत हैं। प्लेट

टेक्टोनिक्स सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की सतह लगातार गतिमान है और टकरा रही है। इस गति के कारण, पृथ्वी के मेंटल में मौजूद पानी क्रस्ट में दरारों के माध्यम से सतह पर आ सकता है। ज्वालामुखी सिद्धांत के अनुसार, ज्वालामुखी विस्फोटों के माध्यम से पृथ्वी के मेंटल से पानी

> **संभव है कि यह महासागर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का स्रोत हो और यह हमें अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में भी मदद करे। हालांकि इस महासागर का अध्ययन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यह पृथ्वी की सतह से बहुत गहराई में स्थित है। वैज्ञानिकों को भूकम्पीय तरंगों का उपयोग करके ही इस महासागर का अध्ययन करना होगा और यह एक धीमी और जटिल प्रक्रिया है। यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि इस महासागर में पानी किस रूप में मौजूद है। यह तरल पानी, बर्फ या किसी अन्य रूप में हो सकता है।**

सतह पर आ सकता है। दरअसल, ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलने वाली गैसों में जल वाष्प भी शामिल होता है, जो बाद में वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिर जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं के पृथ्वी से टकराने के बाद उसके प्रभाव से पानी उत्पन्न हुआ होगा। एक और सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी पर पानी रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बना था। पृथ्वी के शुरुआती वायुमंडल में हाइड्रोजन और आक्सीजन गैसें मौजूद थीं और इनकी प्रतिक्रिया से पानी का निर्माण हुआ। अब भी इस विषय पर शोध जारी है और यह पता लगाया जाना है कि किस सिद्धांत ने सबसे बड़ा योगदान दिया है।

वैज्ञानिक जैकबसेन के अनुसार, पृथ्वी की सतह के नीचे मिले महासागर के पानी का पृथ्वी के अंदर रहना ही ठीक है। अगर इतना पानी धरती पर आ गया तो पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी और पहाड़ों की चोटियों के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। अब दुनिया के वैज्ञानिक भूकम्पीय डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं, जिससे पानी की समझ को और मजबूत किया जा सके। इस खोज के बाद अब यह संभावना जताई जा रही है कि शायद समय के साथ पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद महासागर से ही समुद्र बाहर निकले होंगे।

2014 में प्रकाशित 'डिहाइड्रेशन मेल्टिंग ऐट द टाप आफ लोअर मेंटल' नामक शोध पत्र निचले मेंटल के शीर्ष पर खनिजों के निर्जलीकरण से उत्पन्न पिघलने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। निचले मेंटल के शीर्ष पर निर्जलीकरण और पिघलना एक जटिल प्रक्रिया है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रक्रिया भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट और प्लेट विवर्तनिकी जैसी घटनाओं को प्रभावित करती है। दरअसल, पिघला हुआ मैग्मा कम घनत्व वाला होता है और ऊपर की ओर उठता है, जिससे मेंटल में संवहन धाराएं बनती हैं। ये धाराएं प्लेट विवर्तनिकी को चलाने में मदद करती हैं। पिघला हुआ मैग्मा ज्वालामुखी विस्फोटों का स्रोत भी हो सकता है। मैग्मा के पिघलने से चट्टान कमजोर हो सकती है, जिससे भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा, पिघले हुए मैग्मा में विद्युत प्रवाहकता होती है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने में योगदान देती है।

इस शोध में रिंगवुडाइट नामक खनिज के गुणों पर भी प्रकाश डाला गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकम्पीय डेटा का अध्ययन कर-के पृथ्वी के अंदर मौजूद पानी के बारे में हमारी समझ को और बेहतर बना सकते हैं। यह ज्ञान हमें भविष्य में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने और उनसे बचाव के लिए बेहतर तरीके विकसित करने में मदद कर सकता है।

यह खोज पृथ्वी के जलवायु को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करेगी। दरअसल, गहरे पानी में मौजूद खनिज और रसायन हमें पृथ्वी के जलवायु इतिहास के बारे में जानकारी दे सकते हैं। यह जानकारी हमें भविष्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने और भविष्यवाणी करने में मदद कर सकती है। गहरे पानी में खनिज और ऊर्जा के नए स्रोत हो सकते हैं। इन संसाधनों की खोज हमें ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। गहरे पानी में मौजूद सूक्ष्मजीव हमें जीवन की उत्पत्ति और विकास के बारे में जानकारी दे सकते हैं। यह खोज निश्चित रूप से वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इसमें मानव जाति के लिए कई संभावित लाभ हैं।

दुनिया मेरे आगे

सुर और संवाद

कृष्ण कुमार रत्तू

यह जीवन निरंतर गतिशील है और यही समय का सच है। जिंदगी की गतिशीलता बनी रहे तो आने वाली नस्लों के लिए श्रेष्ठ संस्कृतियों के इतिहास की विरासत संरक्षित रहती है। किन्हीं वजहों से यह थम जाए तो शेष स्मृतियों में विरासत और इतिहास का पन्नों में दर्ज रहता है। इस कालचक्र में संवाद जिंदगी की सांसें हैं और ये निरंतर चलती रहनी चाहिए। बदलते समय और नई सूचना प्रौद्योगिकी के युग में समूचे विश्व में भागमभाग और चकाचौंध के बीच मानवीय मूल्य की नई पहचान हमारे सामने एक नया इतिहास रच रही है। पिछले दशकों में विज्ञान के नए तौर-तरीकों और नई सूचना संप्रेषण क्रांति की त्वरित गति ने आज के समाज में हर उम्र के बाशिंदे को पूरी तरह बदल दिया है और यह बदलाव अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इसी के साथ हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए अपनी विरासत को सहेज कर रखना होगा।

इन दिनों जिस तरह के परिदृश्य और बदलते परिवेश में महानगरों से दूर गांव की जिंदगी में हमने बदलावों को आमंत्रित किया है, वे समय की आवश्यकता हैं, लेकिन अगर हमने अपनी विरासत, इतिहास और पुरखों की पहचान को नष्ट कर दिया तो फिर अगली पीढ़ी और हम भविष्य में अपनी जो पहचान दुनिया के सामने बनाएंगे, वह कुछ अलग तरह की होगी। हमारी उस बदली हुई पहचान में भारतीयता नहीं होगी और सद्भाव और अपनापन कहीं गायब हो चुका होगा। एक वृत्त चित्र 'द लास्ट रिपेयर शाप' में स्मृतियों और संस्कृति की पहचान के पीछे एक गहरा संवेदनशील बदलाव दिखाया गया है। उसमें एक हारमोनियम की दुकान बंद होती दिखाई जाती है। उसके दुकानदार असल में मरम्मत करने वाले होते हैं, जिसके एक पात्र के संवाद पूरी दुनिया के इतिहास और बदलाव को एक नई दृष्टि देते हैं। उसकी जिंदगी बदल सकती है। मगर यह जिंदगी की उन नकारात्मक पहलुओं को भी दिखाती है कि किस तरह से मरम्मत की एक दुकान बंद होने से सुर-संवाद सब कुछ पीछे छूट जाता है।

यह उम्मीद से भरी एक कहानी है, जिसके साथ-साथ सुर-संवाद जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि यह समाज को जोड़ता है। इसको जब वर्तमान समाज के बदलते हुए परिवेश के साथ जोड़ कर देखा जाए तो लगता है कि हम सबने सुर संवाद की मरम्मत की अनेक दुकानों को ताले लगा दिए हैं। अपनी पहचान को हमने दफ्न कर दिया है। आज हमारे पुराने संगीत के साजों की दुकानें बीते हुए कल की बात बन गई है और नए सामान में किसी की रुचि नहीं है। नया संगीत शोर संगीत का अभिप्राय और उसकी पहचान बन गया है। वह रूह को भिगो देने वाले संगीत के संवाद की पहचान की प्रतिस्पर्धा में कहां रहेगा?

यही आदमी के विकास से रुकने की एक नई कहानी है। यह भी सच है कि आज संगीत के साथ-साथ संवाद के अन्य माध्यम हमारे सोशल मीडिया के कारण ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि त्वरित गति से संदेश आजकल कहीं भी पहुंच जाते हैं और एक बड़े दायरे से लोगों को जोड़ देते हैं। इस समय यह एक नया चलन है। अब संगीत और सुर का स्थान कहां है? हमने वह जगह ही खत्म कर दी है, जिसमें संगीत के स्वर से भावनात्मक संवाद यानी पारिवारिक पृष्ठभूमि का एक नया मंजर था।

यह परिदृश्य सौहार्द और प्रेम का एक उदाहरण था। यह ठीक वैसे ही है, जैसे हमने चिट्ठियां लिखनी छोड़ दी और भावनात्मक संबंधों से वाट्सएप और अन्य माध्यमों से वीडियो काल के जरिए बात हो जाती है, लेकिन संवेदना का सच और स्नेह जो हस्तलिखित में लिखे हुए अक्षरों के साथ किसी अपने के पास पहुंचता है, वह स्मृतियों में रूह से दिल का सफर करता है। यह दिल आजकल बदल गया है। एक सच यह भी है कि हमने अपनी रचनात्मकता को शून्य कर दिया है, यानी छोड़ दिया है। हमने प्रेम की परिभाषा ही बदल दी है, जो समाज को जोड़ती थी।

> **आज संगीत के साथ-साथ संवाद के अन्य माध्यम हमारे सोशल मीडिया के कारण ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि त्वरित गति से संदेश आजकल कहीं भी पहुंच जाते हैं और एक बड़े दायरे से लोगों को जोड़ देते हैं। इस समय यह एक नया चलन है। अब संगीत और सुर का स्थान कहां है?**

हम अब मुसीबत में मुस्कुराते नहीं हैं, सोशल मीडिया की शरण में चले जाते हैं। मगर जिंदगी और संवाद में वह ताकत है जो संकट में सारी शक्ति और ताकत को इकट्ठा करके रख सकता है। दूसरी ओर, पानी रुक जाए तो उसके बहाव में शुद्धता खत्म हो जाती है और यह इसी प्रकार से है कि संवाद का समय एक सुख जीवन की नई परिपाटी को लेकर आता है।

इन दिनों तकनीक की दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमता यानी एआइ और आभासी दुनिया में गुम नई नस्ल अपनी आभासी मुस्कान में ही मुग्ध होती दिख रही है। यह अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले दिन पहचान के लिए वैसे दिन होंगे जब आभासी दुनिया की एआइ तकनीक से 'डीपफेक' का शिकार होकर कोई व्यक्ति एक विकृत कृति में बदल जाएगा। इंसान का सच सुर-संगीत, सहज मन और शांति के साथ जीने की उस संस्कृति का नाम है, जिसमें जिंदगी मुस्कुराती रहे और जिंदगी फूलों से हर सुबह एक नया संदेश दे। यही इंसान का जिंदा और रूह में भीगा हुआ सुर और संवाद है। इसे बचाने के लिए हमें आभासी दुनिया से बाहर निकल कर प्रकृति के साथ जीना होगा और और संवाद का आनंद उठाना होगा। यह जिंदगी चार दिन की है, पता नहीं कब बीत जाए।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

मतदाता का रुख

जैसे-जैसे चुनाव नतीजों की तारीखें नजदीक आ रही हैं, मतदाताओं में उत्साह बढ़ रहा है। एक ओर राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए दिन-रात एक कर दिए हैं, वहीं मतदाता भी प्रत्याशियों के दमखम को परख रहा है। मतदाताओं की खामोशी प्रत्याशियों के लिए बेचैनी बन रही है, क्योंकि इससे चुनावी रणनीति बनाने में सुविधा होती। यों हर प्रत्याशी अपनी जीत को पक्का बता रहा है, लेकिन मतदाता खुलकर अभी किसी भी प्रत्याशी का साथ नहीं दे रहा है। वैसे मतदाता अब काफी हद तक जागरूक व सचेत हो चुका है कि किसे वोट देना है और किस नहीं देना है। इसके बारे में बहुत ही गहनता से विचार करने लगा है। अब मतदाता सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास की बात नहीं करता, बल्कि देश के विकास को भी महत्त्व देने लगा है, क्योंकि उसे पता है कि लोकसभा का चुनाव सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दों के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों के साथ भी लड़ा जा रहा है। ऐसे में कोई भी प्रत्याशी या पार्टी मतदाता को अब बरगलाने का काम नहीं कर सकती। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह अच्छी पहल है। ऐसा होना भी चाहिए।

– स्वर्णिम सक्सेना, लखनऊ

शोर की कीमत

'कानों में कहर बरपाती आवाजें' (लेख, 13 अप्रैल) में उल्लेख है कि ध्वनि प्रदूषण से आनंद कम और दूसरे को परेशानी ज्यादा होती है। कान में हेडफोन लगाने से पीछे की आवाज नहीं आती है और साथ ही मस्तिष्क और कान दोनों खराब होते हैं। ध्वनि प्रदूषण रक्तचाप में गड़बड़ी, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, कमजोर दिल और अनावश्यक झड़प पैदा करवाता है। हालांकि जुलूस में निर्धारित से ज्यादा आवाज होने पर छह माह का कारावास और जुर्माना दोनों है, लेकिन धार्मिक जुलूस, बारात, चुनावी जुलूस, रैली, प्रचार आदि में न्यायिक प्रतिबंधों का पालन नहीं हो रहा है। तेज हार्न, फटे साइलेंसर आदि की आवाज व्यक्ति की नींद को उड़ाती है और इसकी वजह से बढ़ता तनाव रोगियों की संख्या बढ़ा रहा है। जल और वायु प्रदूषण से शारीरिक रोग पैदा होते हैं, जबकि ध्वनि प्रदूषण मानसिक रोगी बढ़ा रहा है। ज्यादा खतरनाक होने से पहले ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को प्राथमिकता देनी होगी।

– बीएल शर्मा 'अकिंचन', उज्जैन

धरोहर की फिक्र

भारत ऐतिहासिक धरोहरों के मामले में एक समृद्ध राष्ट्र है। ये धरोहरें न सिर्फ देखने वालों का ध्यान आकर्षित करती है, बल्कि विस्तृत इतिहास से भी परिचित कराती हैं। पुरातात्त्विक धरोहर भारतीय संस्कृति को दर्शाते हैं। भारत के कई स्थलों को विश्व धरोहरों की सूची में शामिल किया गया है। धरोहरें किसी भी देश और शहर की पहचान होती हैं, जिसे देखने काफी पर्यटक आते हैं और देश की संस्कृति और इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। पर्यटन का केंद्र होने की वजह से ये धरोहरें आर्थिक रूप से भी देश को मजबूती प्रदान करते हैं। स्थानीय स्तर पर कई लोगों की आय का साधन भी बन जाता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि धरोहरों का रखरखाव अच्छे तरीके से किया जाए और कहीं कोई कमी हो तो उसका सुधार किया जाए। इन्हें संरक्षित करने के ठोस उपाय हो।

– साजिद अली, इंदौर

शत्रुता का हासिल

भारत ने ईरान-इजराइल के बीच शत्रुता बढ़ने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और तत्काल तनाव कम करने का आह्वान किया है। कोई भी संघर्ष फैलता है, तो वह इस क्षेत्र में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए खतरा पैदा कर देगा। पश्चिम एशिया क्षेत्र भारत की अस्सी फीसद तेल आपूर्ति में योगदान देता है, जिस पर संभावित संघर्ष का प्रभाव पड़ेगा। भारत रियायती कीमतों पर रूसी तेल खरीदकर रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण तेल की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में सक्षम है, लेकिन नए संघर्ष का या इसका दायरा फैलने का ऊर्जा कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारत ने प्रमुख अरब देशों, ईरान और इजराइल के साथ रणनीतिक संबंधों में निवेश किया है और मध्य-पूर्व और यूरोप आर्थिक गलियारे पर जोर दे रहा है, जिसके रणनीतिक और आर्थिक लाभ भी हैं। अब अगर टकराव बढ़ता है तो भारत के लिए दुविधा की स्थिति होगी।

– रवि रंजन, नई दिल्ली

https://t.me/AllNewsPaperPaid
www.readwhere.com

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

लोकतंत्र में मतदाताओं की परिपक्वता के संकेत

लोकतंत्र के महापर्व का पहला चरण शांतिपूर्वक सम्पन्न होना यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि देश का मतदाता अब परिपक्व हो चुका है। तीन दशक पहले तक पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तरप्रदेश और बिहार में चुनाव का मतलब हिंसा ही समझा जाता था। इस दौरान हिंसा में बड़ी संख्या में लोगों के मरने और मतदान केंद्रों पर कब्जे की खबरें आया करती थीं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में माहौल बदला है। इस बार लोकसभा चुनाव के पहले चरण में छिटपुट हिंसा को छोड़ मतदान का सुचारू चलना तो अहम रहा ही, संतोष इस बात का भी है कि मतदाताओं ने बड़ी संख्या में इस पर्व पर अपने मत की आहुति दी। यह तथ्य इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिका देशों में कोई भी ऐसा दूसरा देश नहीं है जिसकी आबादी भारतीय मतदाताओं के बराबर हो। इसके बावजूद देश के विभिन्न स्थानों पर व्यवस्थित तरीके से चुनाव होना भारतीय व्यवस्था की सफलता है। अलग-अलग धर्म, जाति, खानपान और भौगोलिक विषमताओं वाले देश में शांति से होने वाले चुनाव हमारे लिए जहां गर्व का विषय है, वहीं दूसरे देशों के लिए आश्चर्य।

दो महीने पहले पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में जो हुआ, वह किसी से छिपा नहीं है। चुनाव में बाजी किसके हाथ लगेगी, सिर्फ अनुमान लगाए जा सकते हैं, जीते कोई भी। यह कहना होगा कि भारतीय लोकतंत्र और मजबूत होने की तरफ अग्रसर हो रहा है। इतना जरूर है कि हमारे यहां भी चुनाव को लेकर पक्ष-विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। यह भी लोकतंत्र की खूबी है। लोकतंत्र के मायने सिर्फ पांच साल में चुनाव होना भर नहीं है। लोकतंत्र का सच्चा अर्थ अभिव्यक्ति की आजादी भी है। एक आम नागरिक सरकारों और शासन चलाने वालों के बारे में खुलकर बोल सके, यह भी लोकतंत्र ही है। पड़ोसी देश चीन में हालत यह है कि जनता लोकतंत्र की ऐसी महक महसूस नहीं कर पा रही है। वहीं लोकतंत्र सवाल भी खड़े करता है। राजनीतिक दलों के लिए भी और जनता लिए भी। राजनीतिक दलों के लिए सवाल यह है कि 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने के बाद भी राजनीति में घुस आई अनेक बुराइयों को वे दूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि आपराधिक छवि के लोग भी संसद में पहुंच रहे हैं और दलबदलू भी। चुनाव जीतने के लिए अंधाधुंध पैसा बहाया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह भी कि क्या इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता? चुनाव पर खर्च हो रहा पैसा आखिर निकलता तो जनता की जेब से ही है।

जनता से भी सवाल है कि राजनीतिक दल अगर दागी और दल-बदलुओं को टिकट देते हैं तो जनता उन्हें जिताती क्यों है? देश में चुनाव जातिवाद व परिवारवाद से मुक्त हो। राजनीति के नाम पर नफरत और टकराव का माहौल खत्म हो। मतदान के छह चरण और होने हैं। उम्मीद यही की जाती है कि हम हर मायने में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनकर दिखाएंगे।

सभी देवियां स्वयं में कुछ नहीं हैं। अपने-अपने देवता की शक्तियों का स्वरूप हैं। स्थूल सृष्टि में दोनों अलग दिखाई देते हैं। अति सूक्ष्म सृष्टि तक पहुंचते-पहुंचते दूसरा लुप्त हो जाता है। हमारी कठिनाई यह है कि हम दोनों को एक मानकर नहीं जी सकते।

संस्कार आत्मा का विषय है

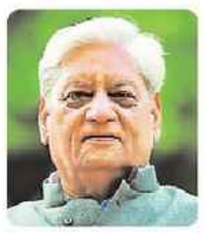

गुलाब कोठारी
प्रधान संपादक
पत्रिका समूह
@patrika.com

शरीर ही ब्रह्माण्ड

एक स्थान सातों लोकों में ऐसा होना चाहिए जहां चारों सूक्ष्म स्वरूप में मिल सकें। एक-दूसरे में आहूत हो सकें। सृष्टि सातों लोकों में उपस्थित है। प्रत्येक लोक के योषा-वृषा के स्वरूप-आकृतियां भिन्न हैं। फिर भी चारों को मिलना है।

यह एक तथ्य है कि जीवन पिछले कर्मों के फल भोगने के लिए मिला है। इसका अर्थ है कि मन में जो इच्छाएं स्वतः पैदा होती हैं, वे इन फलों को भोगने के लिए ही उठती हैं अथवा प्रकृति पैदा करती है। प्रश्न यह है कि दैनिक जीवन में निर्णय लेते समय क्या हमको याद रहता है? मन में इच्छा उठी और हम पूरा करने में जुट जाते हैं। प्रकृति की इच्छा का एक स्वरूप है और पुरुष (जीवात्मा) की इच्छा का दूसरा स्वरूप है। दोनों मिलकर सृष्टि का संचालन करते हैं। प्रकृति का कार्य त्रिगुणी-सत्व, रज और तम रूप होता है। शरीर-मन-बुद्धि तीनों पुरुष के साधन हैं। तीनों ही त्रिगुणी हैं। स्वयं प्रकृति त्रिगुणी है। प्रकृति स्वभाव को कहते हैं। अतः प्रकृति पुरुष से भिन्न नहीं है। माया भी ब्रह्म ही है। तब क्या माया का कोई स्वतंत्र अस्तित्व हो सकता है?

जीवन के रंगमंच का यह सबसे बड़ा नाटक है। सृष्टि में पुरुष-प्रकृति युगल रूप में दो दिखाई तो देते हैं, किन्तु वास्तव में ऐसा है नहीं। पुरुष मात्र अकेला है। उसके स्वभाव- इच्छा की दिशा को ही प्रकृति कह दिया है। सभी देवियां स्वयं में कुछ नहीं हैं। अपने-अपने देवता की शक्तियों का स्वरूप हैं। स्थूल सृष्टि में दोनों अलग दिखाई देते हैं। अति सूक्ष्म सृष्टि तक पहुंचते-पहुंचते दूसरा लुप्त हो जाता है। हमारी कठिनाई यह है कि हम दोनों को एक मानकर नहीं जी सकते। प्रकृति में अग्नि ही सोम बन जाता है, सोम ही अग्नि बन जाता है। तत्त्व तो मूल में एक ही है-वही ब्रह्म है। वही योषा है, वही वृषा है। वहां भी अर्द्धनारीश्वर की भांति दोनों में दोनों होते हैं। स्त्री भी भीतर पुरुष है, पुरुष भी भीतर स्त्री है। उसके बाद भी सिद्धान्त यह है कि सृष्टि पुरुषमय है, स्त्री वहां है ही नहीं। पुरुष सातों लोकों में एक ही है। उसके बीज का स्वरूप नहीं बदलता है। चूंकि सृष्टि में कुल योनियां 84 लाख कही गई हैं, अतः माताएं 84 लाख प्रकार की होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पुरुष भिन्न आकृति वाला होगा। पुरुष की प्रत्येक आकृति में शुक्र तो एक ही रहता है। उसी को शायद गॉड पार्टिकल कह रहे हैं।

ब्रह्म के विस्तार में आकृति का भेद स्थूल देहमात्र का है। इससे तो जीवात्मा के शरीर का निर्माण (आकृति) होगा। शरीर स्थूल-क्षर सृष्टि है। जीवात्मा सूक्ष्म-अक्षर सृष्टि है। पुरुष शुक्र जीवात्मा का वाहक है। उसे स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित भी करना है और दोनों का सूत्र बन्धन भी करना है। शुक्र जल रूप है। जिस प्रकार जल से आठ अवस्थाओं में पृथ्वी का निर्माण होता है वैसे ही शुक्र रूप जल से पृथ्वी रूप शरीर का निर्माण होता है। स्त्री शोणित आग्नेय होता है। अग्नि के तीन स्तर होते हैं-घन-तरल और विरल। इनको ही क्रमशः अग्नि-यम-आदित्य कहते हैं। सोम भी घन, तरल और विरल रूप तीन स्तरों में अप्-वायु तथा सोम रूप में कार्य करता है। प्रत्येक प्राणी के भी तीन शरीर होते हैं-स्थूल-सूक्ष्म व कारण। स्त्री-पुरुष शरीरों का वही धरातल होता है जो अप् और अग्नि का होता है।

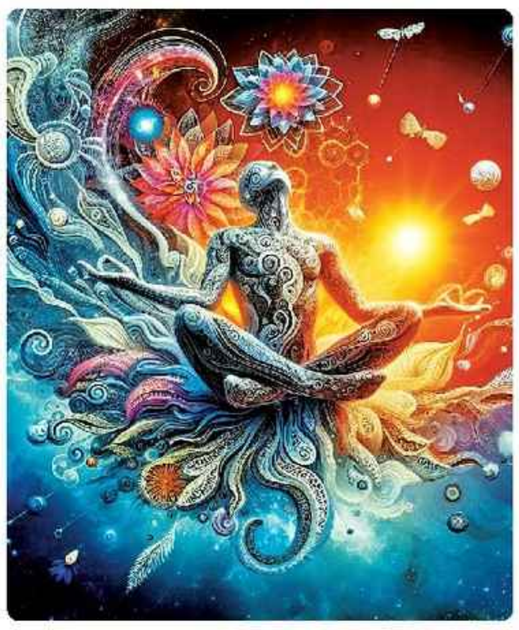

चारों स्थूल स्तर पर हैं। सृष्टि के लिए चारों को सूक्ष्म/कारण स्तर तक उठना होगा। यज्ञ की आहुतियां होंगी और पुनः जीवात्मा के साथ स्थूल देह में आ जाना होगा।

एक स्थान सातों लोकों में ऐसा होना चाहिए जहां चारों सूक्ष्म स्वरूप में मिल सकें। एक-दूसरे में आहूत हो सकें। सृष्टि सातों लोकों में उपस्थित है। प्रत्येक लोक के योषा-वृषा के स्वरूप-आकृतियां भिन्न हैं। फिर भी चारों को मिलना है। 'यथाण्डे तथा पिण्डे' का सिद्धान्त यही कहता है। इसका उत्तर गीता में कृष्ण दे रहे हैं-

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्।
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत।। (14.3)

-मेरी योनि महद् ब्रह्म है, जिसमें गर्भ की स्थापना करता हूं। उसी से सारे भूतों की उत्पत्ति होती है। अर्थात्-सातों लोकों में उत्पन्न प्राणिमात्र की उत्पत्ति होती है। महद् लोक चौथा लोक है, केन्द्र है। लय-प्रलय का भी यही स्थान है। इसके ऊपर तीन अमृत लोक हैं। सूर्य आधा अमृत-आधा मृत्यु लोक है। चन्द्रमा-पृथ्वी मृत्युलोक है।

प्रजापति ब्रह्मा के आग्नेय ऋषि प्राणों तथा परमेष्ठी के सौम्य पितर प्राणों की आहुति से महद् लोक में प्रथम बीजारोपण होता है सृष्टि का। सूर्य ही प्रथम सत्य रूप प्रकट होता है। यही षोडशी पुरुष रूप सृष्टि का पिता बनता है। सोम अंधकार युक्त होने से परमेष्ठी को 'ब्लेक होल' कह सकते हैं। महद् लोक में आते-आते दोनों अग्नि और सोम सत्य रूप में आ जाते हैं। ऋत से सृष्टि नहीं होती। आपोलोक (परमेष्ठी) का अंगिरा-भृगु ही वृषा-योषा का रूप लेकर यजन करते हैं। परमेष्ठी शुद्ध सोम लोक है। विष्णुलोक है। सोम से ही सारे पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अतः यही लक्ष्मी है, विष्णु पत्नी है। सृष्टि के लिए अग्नि रूप प्रकट हुआ। सोम अग्नि में आहूत होगा, तभी यज्ञ होगा।

महद् लोक में उत्पन्न जीव अति सूक्ष्म भाव में रहता है। जैसे-जैसे सृष्टि आगे बढ़ेगी जीवात्मा के शरीर की स्थूलता बढ़ती जाएगी। आकृतियां बदलेंगी, आकार बदलेंगे। आकृतियां माता के शरीर में बनती हैं। शरीर के अंग-प्रत्यंगों का खाका रेत में उपलब्ध रहता है। रेत पूरे शरीर में आत्मा के साथ व्याप्त रहता है। यही एकत्र होकर-शरीर के मानचित्र सहित- अग्नि में आहूत होता है। जिसका विभाजन गर्भ में होता हैं।

ब्रह्म के विवर्त में रेत नहीं बदलता। इस रेत को अग्नि उपलब्ध कराने के लिए योषा की आवश्यकता पड़ती है। यहां योषा के लिए योनि के अनुरूप ही स्त्री शरीर होता है। हर एक आकृति में महद् लोक की स्थिति भिन्न होती है। वहां अग्नि का प्रज्वलन-प्रक्रिया भी भिन्न होगी। हर योनि में स्त्री भिन्न-भिन्न प्रक्रिया से महद्लोक उपलब्ध कराती है। रेत वही रहता है, यज्ञ वेदी बदलती जाती है। महद्लोक का सिद्धान्त नहीं बदलता। यज्ञ प्रक्रिया नहीं बदलती। युगल सृष्टि में स्त्री शरीर की यही जटिलता है।

आहुति काल में दोनों सूक्ष्म-कारण शरीरों का एकाकार होना भी हृदय की विरलता ही है। शरीर का भान छूट जाए, ईश्वर से नए जीव का आह्वान करें, प्रार्थना में खो जाएं, आहुतियों को मंत्रों की ध्वनि से जोड़ सकें, तब यज्ञ में सभी 33 देवता उपस्थित हो जाएंगे। एक ही यज्ञ में पहले ईश्वर आत्मा तथा बाद में जीवात्मा आहूत होते हैं। भीतर दोनों को साथ रहना है। दोनों का सामंजस्य बना रहे, निर्मल भाव बने रहे, इसके लिए दोनों आत्माओं का एकाकार होकर यज्ञ सम्पन्न करना जरूरी है। इसके बिना जीव शरीर धारण करके तो बाहर आ जाएगा, किन्तु संस्कार नहीं मिलेंगे। पहले भी पशु था, आगे भी मानव शरीर में पशु संस्कारों के साथ ही जीता रहेगा। संस्कार औरत नहीं, स्त्री ही देती है। शरीर से नहीं, संस्कार आत्मा से आते हैं। पुरुष में आहूत होकर स्त्री यह क्षमता प्राप्त करती है।

क्रमशः

gulabkothari@epatrika.com

क्यूआर कोड को स्कैन कर आप आलेख सुन भी सकते हैं।

आर्ट एंड कल्चर

सभी संस्कृति के सरोकारों से जुड़ें

डॉ. राजेश कुमार व्यास
कला समीक्षक
@patrika.com

उत्सव शब्द का शाब्दिक अर्थ है, 'विशेष अवसर'। आगमों में उत्सव शब्द धार्मिक से अधिक समाज के साथ जश्न मनाने के अर्थ में, प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के प्रति कृतज्ञता के लिए प्रयुक्त हुआ है। लोकसभा चुनाव लोकतंत्र का ऐसा ही बड़ा उत्सव है। जनता जनार्दन के मत की ताकत से होने वाले परिवर्तन से जुड़ा यह उल्लास पर्व है।

हमारी संस्कृति में भी लोकतंत्र के बीज आरंभ से ही रहे हैं। चीन, इंग्लैंड आदि देशों में एकाधिकार शासन की प्रवृत्ति रही है। सम्राट, महारानी आदि नियामक रहे हैं। भारत में ऐसा नहीं रहा। हमारे यहां राजा राज जरूर करता था पर वह नियामक नहीं होता था। नियामक हमारे धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, आदर्श परंपराएं रही हैं। राजा की सहमति में सभासदों की असहमति की संभावना सदा बनी रहती थी। धर्म च्युत होने पर राजा को अपदस्थ होने का भय भी बना रहता था।

हिटलर ने अपना राज कायम रखने किए किताबें जलवा दीं। इस तरह बख्तियार खिलजी ने नालंदा पुस्तकालय में आग लगवा दी। मंशा यही थी कि इससे लोग सोचने-समझने की शक्ति से दूर हो जाएंगे। पर ऐसा कहां हुआ! संस्कृति को नष्ट नहीं किया जा सकता। भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह समय इसके सांस्कृतिकरण का है। राजनीति शक्ति देती है, पर बल के साथ विवेक नहीं है तो सब व्यर्थ है। कला-संस्कृति यह विवेक देती है। संस्कृति के लोकतंत्रीकरण की ओर भी हम प्रेरित हों। शासन में संस्कृति के प्रति आस्था बढ़े। देश की भाषाएं, क्षेत्रीय कलाएं जीवंत रखने के लिए संवाद के अवसर बढ़ें। इस लोकतंत्र उत्सव में हम उम्मीद करें, देश की एक सांस्कृतिक नीति की ओर भी हम आगे बढ़ेंगे। सांस्कृतिक संस्थाएं, संस्कृति के सरोकारों की उपस्थिति से ही असमानताएं पूरी तरह से मिट सकती हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए, भारत के विकासमान भविष्य के लिए यही प्राथमिकता रहे।

पत्रिका साक्षात्कार : नक्सल समस्या पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से बातचीत

आदिवासियों की सुरक्षा है प्राथमिकता

छत्तीसगढ़ के बस्तर में लोकसभा के लिए पहले चरण के मतदान के दो दिन पहले कांकेर में नक्सलियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों की ऐतिहासिक सफलता करार दिया है। उनका कहना है कि हमारे जवानों ने अराजक तत्वों के कुचक्रों को कुचलकर रख दिया है। यह ऐतिहासिक सफलता है। देश नक्सल समस्या से मुक्ति की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस मुठभेड़ में शामिल सभी जवान और सुरक्षा अधिकारी बधाई के पात्र हैं। कांकेर की मुठभेड़ और नक्सली गतिविधियों को केंद्र में रखकर पत्रिका की ***मीनाकुमारी*** *ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बातचीत की। बातचीत के मुख्य अंश-*

Q पहले चरण के मतदान से ऐन पहले सुरक्षा बलों की नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को किस रूप में लेते हैं?

मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के नक्सल मामलों के इतिहास की यह सबसे बड़ी सफलता है। यह बात सभी को पता है कि देश में सक्रिय माओवादी लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते और हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हिंसात्मक गतिविधियों से प्रभावित करते हैं। चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की साजिश को हमारे जवानों ने विफल किया है। इसके लिए हमारे जवान बधाई के पात्र हैं।

Q चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने से आपका तात्पर्य?

इसमें दो मुख्य बातें हैं। एक यह कि बस्तर में पड़ा हर वोट लोकतंत्र के बारे में नक्सलियों द्वारा गढ़े गए झूठे नैरेटिव व दुष्प्रचार को ध्वस्त करता है। हालत यह है कि माओवादी मतदान करने पर लगाई जाने वाली स्याही लगी अंगुलियों को काट देने का फरमान तक जारी करते हैं। इसके बावजूद हमारे आदिवासी भाई-बहन जम कर वोट करते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे विधायक भीमा मंडावी की हत्या कर दी गई थी। दिवंगत विधायक का परिवार फिर भी वोट डालने के लिए कतार में खड़ा था। यह समर्पण है लोकतंत्र के प्रति बस्तर के आदिवासियों का। हम सभी जानते हैं कि आज देश भर में भाजपा के पक्ष में सबसे अधिक संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी हम सभी 11 लोकसभा सीटें जीतने के प्रति आश्वस्त हैं। ऐसे में नक्सली किसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है।

Q सुरक्षा बलों ने जान पर खेलकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। उधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसे फर्जी करार दे रहे हैं?

कांग्रेसियों का चरित्र ही है ऐसा है कि वे हर सही काम पर सवाल उठाते हैं। वे सुरक्षा बलों के शौर्य पर सवाल दागते हैं। इस बार वे मुठभेड़ का सबूत मांग रहे हैं या इसे फर्जी करार दे रहे हैं, जो नई बात नहीं है। फिर भी मैं विपक्ष के लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कुछ जगह राजनीति नहीं करनी चाहिए। नक्सल विचारधारा पूरे समाज के लिए घातक है। आदिवासी भाई-बहनों की जान, उनके जंगल और जमीन की रक्षा हम हर कीमत पर करेंगे।

Q छत्तीसगढ़ जल्द से जल्द नक्सल मुक्त हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?

हम नक्सलियों से सदैव अपील करते रहे हैं कि बंदूक छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो जाओ। हम सदैव बातचीत के लिए तैयार हैं पर बात होगी शांति, विकास व समाज के सरोकार की। हमारी सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई विकास योजनाएं चलाती हैं। हमने 'नियद नेल्ला नार' अर्थात आपका अच्छा गांव योजना प्रारंभ की है जिसमें हमारे 'विकास कैम्प' के आसपास के गांवों तक हम शासकीय सुविधाओं और योजनाओं को पहुंचा रहे हैं।

Q फिर भी हिंसा की घटनाएं क्यों होती रहती हैं?

यह भी किसी को गलतफहमी न हो कि हम हिंसा को सहन कर लेंगे। हम हर तरह की हिंसा से कड़ाई से निपटेंगे। हम प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप इस समस्या के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध हैं। जैसा कि भारत के गृहमंत्री ने भी कहा है कि हमारी प्राथमिकता बस्तर को नक्सल मुक्त करने की है। हम सब उसी दिशा में काम कर रहे हैं।

Q आज छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की क्या स्थिति है? कितने जिले इससे प्रभावित हैं और कितने मुक्त हुए?

लगभग सौ दिनों में 63 मुठभेड़ों में 54 नक्सलियों के शव, 77 हथियार और 135 विस्फोटक बरामद किए गए हैं। 304 माओवादियों को गिरफ्तार करने में भी सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। 165 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सल संबंधी कुल 26 प्रकरणों को देश की प्रमुख जांच एजेंसी एनआइए को सौंपा है। गौरतलब है कि विगत 4 माह के दौरान 24 फॉरवर्ड सुरक्षा कैम्पों की स्थापना की गई है। निकट भविष्य में 29 नए बेस कैम्पों की स्थापना प्रस्तावित है।

पश्चिम बंगाल : तृणमूल कांग्रेस और भाजपा ने लगाया पूरा दम

भाजपा को पीएम मोदी के करिश्मे पर भरोसा

कोलकाता
विनीत शर्मा

इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के लिए निर्णायक साबित होने जा रहा है। भाजपा को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तूफानी दौरों का सहारा है, तृणमूल कांग्रेस की कोशिश मुस्लिम और बंगाली भद्रजनों की जुगलबंदी को अपने पक्ष में बनाए रखने की है। भद्रजन अगर छिटके तो तृणमूल की राह मुश्किल हो सकती है। उधर, भाजपा के तीन सौ पार के पुराने रेकॉर्ड को कायम रखने में पश्चिम बंगाल की भूमिका अहम रह सकती है। जानकारों की नजर प्रदेश की करीब दो दर्जन ऐसी सीटों पर है, जहां एक से तीन फीसदी का स्विंग भाजपा या तृणमूल कांग्रेस के लिए सुनामी बन सकता है।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की छोटी पार्टनर रही भाजपा आज उसी के लिए चुनौती बन गई है। भाजपा की कोशिश जहां 2019 के आंकड़े को पार करने की है, टीएमसी प्रदेश में नंबर एक पार्टी होने के तमगे को खोना नहीं चाहती। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जानती हैं कि यदि भाजपा प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो उनकी सरकार का कार्यकाल पूरा करना भी आसान नहीं होगा। दोनों ही पक्ष सधी चाल से अपने मोहरे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदू, मुस्लिम के साथ ही एक तीसरा धड़ा बंगाली मतदाताओं का है। बंगाली मतदाता इस बार भी निर्णायक हो सकते हैं।

भाजपा नेताओं को उम्मीद

भाजपा को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व से पश्चिम बंगाल उसकी झोली में आ जाएगा। चुनाव जीतने के लिए ट्रिपल एम स्ट्रेटेजी यानी मीडियम, मैसेंजर और मैसेज को अहम माना जाता है। भाजपा के लिए मोदी का नाम ही जीत की गारंटी माना जा रहा है। असली बात तो परिणाम के बाद ही पता चलेगी।

महावीर जयंती कल : हर जीव अपना कर्ता, नियंता और विधाता है

आध्यात्मिक लोकतंत्र के शास्ता महावीर

प्रवीण चन्द्र छाबड़ा, वरिष्ठ पत्रकार

भगवान महावीर का जन्म उत्तरी बिहार में वैशाली के लिच्छवी जाति की गणतंत्रीय व्यवस्था में हुआ। वैशाली उस समय लिच्छवी जाति के क्षत्रियों का गौरवशाली गणतंत्र था। मतदान के लिए काले और लाल रंग की शलाकाओं का प्रयोग होता था। बहुमत का निर्णय स्वीकार कर उसे सर्वसम्मति से क्रियान्वित कर दिया जाता था। यही कारण है कि महावीर के अंतःकरण पर गण की गरिमा व महिमा का गहरा प्रभाव रहा।

महावीर आध्यात्मिक लोकतंत्र के शास्ता हैं। जहां समग्रता प्रथम चरण है। वे मनुष्य थे और मनुष्यत्व की संपूर्णता के लिए उन्होंने वह सब कुछ छोड़ा जिससे लोग ऐसे चिपके रहना चाहते हैं जैसे आज के राजनीतिज्ञ सत्ता व पद से। वे जानते थे कि लोकतंत्र में लोक दृष्टा हैं, जो

दिखाई भी देते हैं और दिखने वाले भी होते हैं। दोनों ही लोक हैं। दोनों का ही साध्य, साधन में छिपा है। महावीर की सत्ता सर्वसाधारण की है, जहां विकास में सब भागीदार होते हैं तो त्याग में भी। महावीर के साथ मनुष्य जीवन का नया अध्याय शुरू होता है जिसमें हर जीवन संपूर्ण होता है। अपना स्वामी स्वयं होता है। उन्होंने ईश्वर का भी जनतंत्रीकरण कर दिया। ईश्वर की सार्वभौम सत्ता के साथ उनके सृष्टा या नियंता की जगह उन्होंने सर्वहितकारी, प्रियकारी व शिवकारी बना दिया। महावीर की अवधारणा में हर जीव अपना कर्ता, नियंता और विधाता है। उसके स्वयं के कर्म उसे उन्नत करते हैं या गिराते हैं। जीवन सरल नहीं है, वह कठिन है, जहां निरंतर परीक्षा है। एक समय का प्रमाद समूचे जीवन को निगल जाता है। इसलिए जीवन से भागना पलायन है। वे कहते हैं- भागो मत, अपने को बदलो। व्याख्या या विश्लेषण मत करो। सुनो-सुनो और अपने में गुणते जाओ। सत्य बाहर नहीं होता भीतर ही होता है।

भगवान महावीर का जीवन बोध अनवत प्रेरणा है। हर जीव जीना चाहता है। महावीर इस भाव को ही प्राणवान करते हैं। हर जीव को आत्मवत समझने को जीवन का आधार बनाते हैं। वे किसी भी प्रकार के स्वामित्व को हिंसा मानकर नकारते हैं।

आपकी बात

शरीर में पानी की कमी न हो

गर्मी में शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। घर से बाहर निकलते समय हमेशा पानी साथ में रखें। आंखों पर चश्मा व सिर को ढक कर रखें, जिससे लू न लगे। ढीले-ढाले व आरामदायक कपड़े पहनें। बाहर ठेले पर खाने की चीजों से न ललचाएं। इन तरह की सावधानियों से बीमारियों से बचाव हो सकता है।

- प्रहलाद यादव, महू, मध्यप्रदेश

पहनावे के प्रति भी रहें सावधान

शरीर में ऊर्जा को बनाए रखने के लिए भोजन के साथ मौसमी फलों का सेवन जरूर करना चाहिए। दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक और फ्रिज में रखे हुए अत्यधिक ठंडे खाद्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही तेज धूप से बचें। इन दिनों कपड़े भी ढीले पहनने चाहिए।

- उमराव सिंह वर्मा, सेमरिया, बेमेतरा, छत्तीसगढ़

आज का सवाल

अपराधों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है?

कल का सवाल था: गर्मी में बीमारियों से बचाव कैसे हो सकता है?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

दोपहर में बाहर जाने से बचें

गर्मियों में बीमारियों से बचाव के लिए निरन्तर व कम अन्तराल में पानी पीते रहना चाहिए। हल्का भोजन लेना चाहिए । हल्के रंग के कपड़े पहनें। शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। लू से बचने के लिए दोपहर बाहर निकलने से बचना चाहिए। बीमार होने पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

- देवीसिंह गिराब, बाड़मेर

खान-पान का रखें ध्यान

गर्मी के मौसम में सब्जी, फल सहित अन्य खानपान की वस्तुएं जल्दी खराब हो जाती हैं। इनसे कई तरह की बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है। फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द, टाइफाइड और पीलिया जैसी अन्य बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए इस मौसम में सेहत का अधिक ध्यान रखना चाहिए। रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जरूरत है।

-प्रकाश भगत, कुचामन सिटी, नागौर

https://t.me/epaperpdf

चिंतन

विकासशील से विकसित की ओर तेजी से बढ़ रहा देश

नए वर्ष पर देश को आर्थिक मोर्चे पर एक के बाद एक अनेक शुभ संकेत मिले हैं। शेयर मार्केट नए शिखर पर पहुंच गया, सोना भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड पर और भारत का मार्केट कैप पहली बार 400 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है और जल्दी ही हम जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन सकते हैं। आईटी और ऑटो शेयरों में भारी खरीदारी के दम पर बीएसई सेंसेक्स पहली बार 75,000 अंक के पार पहुंच गया जबकि निफ्टी भी 22,765 अंक के नए स्तर को छू गया। निफ्टी के 50 शेयरों में से 35 तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे। इससे पहले सोमवार को भारत का मार्केट कैप पहली बार 400 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। पिछले नौ महीने में इसमें 100 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। पिछले साल पांच जुलाई को भारत का मार्केट कैप 300 लाख करोड़ रुपये पहुंचा था। उसके बाद से निफ्टी में 16 प्रतिशत तेजी आई है। भारत का मार्केट कैप 2007 में 50 लाख करोड़ पहुंचा था जबकि 2014 में यह पहली बार 100 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा था। इसमें 200 लाख करोड़ रुपये का स्तर फरवरी 2021 में छुआ था। देसी बाजार का अब अगला बड़ा पड़ाव 5 लाख करोड़ डॉलर बाजार पूंजीकरण हासिल करना होगा, जिससे अभी वह करीब 4 फीसदी पीछे है। बाजार के भागीदारों ने कहा कि घरेलू मोर्चे पर वृहद आर्थिक मजबूती और विदेशी निवेश के निरंतर प्रवाह से शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला बना हुआ है। शेयर बाजार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को मापने का पैमाना होता है। यही बताता है कि देश के उद्योग किस गति से आगे बढ़ रहे हैं, आम आदमी किस तरह निवेश और खर्च कर रहा है। बाजार को देखने का एक और मानक होता है सोना। वह भी नव वर्ष के दिन नई बुलंदी पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 71,150 रुपये हो गई। सोमवार को इसमें करीब 1400 रुपये की तेजी आई थी और मंगलवार को 240 रुपये की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ महीनों से सोने की कीमत में भारी तेजी देखी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ महीनों में यह 75,000 रुपये तक जा सकता है। अर्थव्यवस्था को देखने के लिए किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार को भी परखा जाता है। इस क्षेत्र में भी भारत नित नए सोपान छू रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। 29 मार्च 2024 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 2.951 अरब डॉलर की शानदार बढ़ोतरी हुई और यह 645.583 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। पिछले कई महीनों से भारत अपना गोल्ड रिजर्व भी बढ़ा रहा है और ताजा आंकड़ों के मुताबिक यह 817 टन पहुंच गया है। ये सारे संकेत बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था की सेहत न केवल ठीक है बल्कि नई बुलंदी की ओर बढ़ रही है। भारत बड़ी इकॉनमीज में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। आईएमएफ के मुताबिक अगले दो साल तक भारत सबसे तेज इकॉनमी बना रहेगा। यूरोपियन पार्लियामेंट के थिंक टैंक एक्सपर्ट का कहना है कि भारत की इकॉनमी चीन से ज्यादा तेज गति से बढ़ रही है और आगे भी यही स्थिति रहेगी। 2023 में भारत की एवरेज ग्रोथ 7.5 फीसदी से ऊपर रहने की संभावना है, जबकि चीन के मामले में 5.2 फीसदी रहने का अनुमान है। माना जा रहा है कि भारत जल्दी ही जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। सारे संकेत बताते हैं कि हम विकासशील से विकसित की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी अनेक क्षेत्र ऐसे भी हैं, जिनमें बहुत कुछ किया जाना शेष है। अगर हैप्पीनेस इंडेक्स को देखे तो हम पड़ोसी पाकिस्तान से भी पीछे हैं। हमें वो उपाय करने होंगे, जिससे हर देशवासी में उल्लास का संचार हो। उसे अपने भविष्य का सुखद अहसास हो। ऐसी ही हालात हंगर इंडेक्स की है। यह बताता है कि देश तो बुलंदी छू रहा है, लेकिन एक तबका आज भी दो रोटी की जंग लड़ रहा है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। सेहत, शिक्षा और रोजगार तीन ऐसे पैमाने हैं, जो विकसित होने की गारंटी कहे जाते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में जल्द से जल्द आमूल-चूल बदलाव की जरूरत है। तभी हम दुनिया में अव्वल राष्ट्र कहला पाएंगे।

दिवस विशेष
योगेश कुमार गोयल

गैर विषैले और दुष्प्रभावों से मुक्त हैं होम्योपैथिक उपचार

प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को 'होम्योपैथी' के जनक माने जाने वाले जर्मन मूल के चिकित्सक, महान विद्वान, शोधकर्ता, भाषाविद् और उत्कृष्ट वैज्ञानिक डा. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिवस के अवसर पर 'विश्व होम्योपैथी दिवस' मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य चिकित्सा की इस अलग प्रणाली के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी पहुंच की सफलता दर को बेहतर बनाना है। 10 अप्रैल 1755 को जन्मे डा. हैनीमैन के पास एमडी की डिग्री थी, लेकिन उन्होंने बाद में अनुवादक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी, फ्रांसीसी, इतालवी, ग्रीक, लैटिन इत्यादि कई भाषाओं में चिकित्सा, वैज्ञानिक पाठ्य पुस्तकों को सीखा। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, जो औषधियों तथा उनके अनुप्रयोग पर आधारित है। विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है और इस वर्ष यह दिवस 'होम्योपैथीः अनुसंधान को सशक्त बनाना, दक्षता बढ़ाना' थीम के साथ मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मानना है कि वैकल्पिक और परम्परागत औषधियों को बढ़ावा दिए बगैर सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में विश्व में होम्योपैथी का प्रमुख स्थान है। होम्योपैथी ग्रीक शब्द 'होमियो' से बना है, जिसका अर्थ है 'समान' और 'पाथोस', जिसका अर्थ है पीड़ा या बीमारी। होम्योपैथी को चिंता, अवसाद, एडीएचडी और ओसीडी सहित कई प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों, एलर्जी और पुराने दर्द सहित कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में प्रभावी पाया गया है। होम्योपैथिक उपचार सुरक्षित, गैर विषैले और दुष्प्रभावों से मुक्त हैं, जो उन्हें ऐसी पारम्परिक मनोरोग चिकित्सा का आकर्षक विकल्प बनाते हैं, जो प्रायः कई अप्रिय दुष्प्रभावों को साथ लाती है। होम्योपैथी अत्यधिक तनुकृत पदार्थों के उपयोग पर आधारित ऐसा उपचार है, जिसके बारे में चिकित्सकों का दावा है कि यह शरीर को स्वस्थ रख सकता है। केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के अनुसार चिकित्सा का ही एक वैकल्पिक रूप है होम्योपैथी, जो 'समः समम शमयति' अथवा 'समरूपता' दवा सिद्धांत पर आधारित है, जो दवाओं द्वारा रोगी का उपचार करने की ऐसी विधि है, जिसमें किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्राकृतिक रोग का अनुरूपण करके समान लक्षण उत्पन्न किया जाता है, जिससे रोगग्रस्त व्यक्ति का उपचार किया जा सकता है।

दिखने में भले ही होम्योपैथी दवाएं एक जैसी लगती हैं, किन्तु वास्तव में विश्वभर में होम्योपैथी की चार हजार से भी ज्यादा तरह की दवाएं हैं। होम्योपैथी के संस्थापक माने जाने वाले सैमुअल हैनीमैन का कहना था कि इलाज का उच्चतम आदर्श सबसे भरोसेमंद और कम से कम हानिकारक तरीके से स्वास्थ्य की तेज, कोमल और स्थायी बहाली है। चूंकि बहुत सारी होम्योपैथी दवाओं का असर रोगी पर कुछ धीमी गति से होता है, जबकि एलोपैथी दवाएं रोगी पर तुरंत असर दिखाती हैं, इसीलिए हाम्योपैथी भले ही एलोपैथी जितनी लोकप्रिय नहीं है, लेकिन दुनियाभर में यह उपचार के सबसे लोकप्रिय वैकल्पिक रूप में मौजूद हैं। दरअसल होम्योपैथिक उपचार सबसे सरल उपचार है, जो शरीर को अधिक प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया की अनुमति देता है। होम्योपैथी दवाएं चिकित्सा का एक सुरक्षित और प्राकृतिक विकल्प प्रदान करती हैं, जो बिना किसी दुष्प्रभाव अथवा दवा के परस्पर क्रिया का कारण बनता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

देश के लिए संकट बनते खर्चीले चुनाव

विश्लेषण
प्रमोद भार्गव

चुनाव आयोग ने लोकसभा उम्मीदवार को 95 लाख रुपये तक खर्च करने की छूट दी हुई है, लेकिन हम सब जानते हैं कि करीब आठ विधानसभाओं में लड़े जाने वाले इस चुनाव में यह राशि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। वास्तविक खर्च इससे कई गुना अधिक होता है। प्रत्याशी और दल तो चुनाव में धन खर्च करते ही हैं, सरकार को भी चुनाव कराने में बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है, इसलिए खर्च के इस छुटकारे का उपाय एक साथ चुनाव बनाम संयुक्त चुनाव में देखे जा रहे हैं। यदि लोकसभा, विधानसभा, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ होते हैं तो लंबी चुनाव प्रक्रिया के चलते मतदाता में जो उदासीनता छा जाती है, वह दूर होगी।

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 'उनके पास चुनाव लड़ने के लिए धन नहीं है।' साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 'मुझे इस बात को लेकर भी मलाल है कि चुनाव में समुदाय व धर्म जैसी चीजों को जीत तय करने का आधार बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है।' सीतारमण कई बार लोकसभा का चुनाव लड़ने के अनुभव से गुजर चुकी हैं, इसलिए वे जो कह रही हैं उसमें निश्चित सच्चाई है। हम देख भी रहे हैं कि अनैतिक रूप से कमाए गए धन और आवारा पूंजी ने चुनावी खर्च इतना बढ़ा दिया है कि आम आदमी तो छोड़िए मध्यमवर्गीय व्यक्ति का भी चुनाव लड़ना मुश्किल है। वैसे चुनाव आयोग ने लोकसभा उम्मीदवार को 95 लाख रुपये तक खर्च करने की छूट दी हुई है, लेकिन हम सब जानते हैं कि करीब आठ विधानसभाओं में लड़े जाने वाले इस चुनाव में यह राशि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। वास्तविक खर्च इससे कई गुना अधिक होता है। प्रत्याशी और दल तो चुनाव में धन खर्च करते ही हैं, सरकार को भी चुनाव कराने में बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है, इसलिए खर्च के इस छुटकारे का उपाय एक साथ चुनाव बनाम संयुक्त चुनाव में देखे जा रहे हैं। संभव है 2029 का चुनाव इसी प्रणाली से हो?

यदि लोकसभा, विधानसभा, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ होते हैं तो लंबी चुनाव प्रक्रिया के चलते मतदाता में जो उदासीनता छा जाती है, वह दूर होगी। एक साथ चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाता को एक ही बार घर से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचना होगा, अतएव मतदान का प्रतिशत बढ़ जाएगा। यदि यह स्थिति बनती है तो चुनाव में होने वाले सरकारी खर्च कम होगा। 2019 के आम चुनाव में करीब 60,000 करोड़ खर्च हुए थे, जबकि 2014 में इसके आधे 30 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2024 के चुनाव में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने की उम्मीद है। गैर-लाभकारी संगठन सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस) के अध्ययन के अनुसार 2019 का आम चुनाव दुनिया में सबसे महंगा चुनाव रहा है। इस चुनाव में औसतन प्रति लोकसभा क्षेत्र 100 करोड़ रुपये खर्च हुए। एक तरह से यह खर्च एक मत के लिए 700 रुपये बैठता है। यह खर्च केवल चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद का है। कई उम्मीदवार जिनका लड़ना तय होता है, वह साल-छह माह पहले से ही चुनाव की तैयारियों में लग जाते हैं। इस खर्च को अध्ययन में शामिल नहीं किया गया है। यदि लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 75 से 80 सीटें ऐसी थीं, जहां प्रत्याशी विशेष ने 40 करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च किए। यह चुनाव आयोग द्वारा प्रत्याशी के लिए तय खर्च की अधिकतम सीमा से 50 गुना से भी अधिक है। 2019 में खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपये थी।

यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दल और प्रत्याशी को भी कम धन खर्च करना होगा। दरअसल अलग-अलग चुनाव होने पर हारने वाले कई प्रत्याशी एक बार फिर किस्मत आजमाने के मूड में आ जाते हैं,

वहीं विधायकों को भी लोकसभा चुनाव लड़ा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जो सीट खाली होती है, उसे फिर से छह माह के भीतर भरने की संवैधानिक बाध्यता के चलते चुनाव कराना पड़ता है। नतीजतन जनता के साथ-साथ प्रत्याशी को भी चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी उदासीनता झेलनी पड़ती है। इस कारण सरकारी मशीनरी की जहां कार्य संस्कृति प्रभावित होती है, वहीं मानव संसाधन का भी ह्रास होता है।

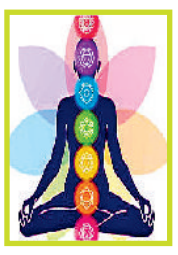

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सात चरणों में करीब ढाई माह चुनाव प्रक्रिया चलेगी। भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप चुनाव को देखें तो उत्तर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक और पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व में सुंदर वन के मैंग्रोव जंगल के इलाके भी चुनाव प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। इनमें अनेक मतदान केंद्र ऐसे होते हैं, जहां मतदानकर्मियों को पालतू मवेशियों और नावों में चुनाव सामग्री लादकर ले जानी पड़ती है। ऐसे में प्रति मतदाता चुनाव का औसत खर्च 700 रुपये तक बैठता है। जबकि देश की साठ फीसदी आबादी बमुश्किल औसतन 250 रुपये प्रतिदिन कमा पाती है। ऐसे में बार-बार चुनाव में खर्च निश्चित ही एक चिंता का विषय है। सरकारी खर्च के अलावा प्रत्याशियों को टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया और अखबारों में विज्ञापन पर बड़ा खर्च करना होता है। वाहन, भोजन, पोस्टर-बैनर और नेताओं के लिए जुलूस व आम सभाओं पर भी बड़ा खर्च होता है। यदि इन प्रत्यक्ष खर्चों के अलावा अप्रत्यक्ष खर्चों को देखें तो शराब, वोट के बदले नोट और उपहार के रूप में कोई वस्तु देने पर भी बड़ा खर्च प्रत्याशियों को उठाना पड़ता है। चुनाव में होने वाली खर्च की बड़ी राशि को सार्वजनिक नहीं किया जाता, क्योंकि ज्यादा खर्च दिखाना तय राशि का उल्लंघन माना जाएगा। इसके बावजूद हम देखते हैं कि उम्मीदवार और दल बेहिसाब धन खर्च करते हैं। निर्वाचन आयोग में पंजीबद्ध दलों के प्रत्याशी चुनावी सुविधाओं के लिए डमी उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े करते हैं। इन पर भी बड़ी राशि खर्च होती है। प्रत्येक चुनाव में जातीय और धर्म आधारित समुदायों के ध्रुवीकरण पर भी बड़ी राशि खर्च होती है। अब धनी उम्मीदवार जातिवार सभाएं करके उनके भोजन-पानी का भी इंजमाम करते हैं। हालांकि राजनीतिक दल के लिए खर्च करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इसी तरह विधानससभा चुनाव के लिए प्रत्याशी अधिकतम चालीस लाख रुपये खर्च कर सकता है। वहीं छोटे राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में लोकसभा उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा 75 लाख रुपये और विधानसभा उम्मीदवार के लिए 28 लाख रुपये है।

ऐसे में एक साथ सभी चुनावों को संयुक्त रूप में करा दिया जाए तो एक प्रत्याशी को कई सीटों से या बार-बार चुनाव लड़ने के विकल्प समाप्त हो जाएंगे और धन की बर्बादी नहीं होगी। चूंकि संविधान के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग इकाइयां हैं। इस परिप्रेक्ष्य में संविधान में समानांतर किंतु भिन्न-भिन्न अनुच्छेद हैं। इनमें स्पष्ट उल्लेख है कि इनके चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष के भीतर होने चाहिए। लोकसभा या विधानसभा जिस दिन से गठित होती है, उसी दिन से पांच साल के कार्यकाल की गिनती शुरू हो जाती है। इस लिहाज से संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि एक साथ चुनाव के लिए कम से कम 18 अनुच्छेदों में संशोधन किया जाना जरूरी होगा। विधि आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग और संविधान समीक्षा आयोग तक इस मुद्दे के पक्ष में अपनी राय दे चुके हैं। ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। केंद्र सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। यदि विपक्षी दल सहमत हो जाते हैं तो दो तिहाई बहुमत से होने वाले ये संशोधन कठिन कार्य नहीं हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

आध्यात्मिक चेतना आखिर क्या है?

संकलित
दर्शन

आज मनुष्य अत्यधिक भौतिकवादी तथा लालची हो गया है। बलिदान, त्याग, संतोष, प्रज्ञा, चिंतन-मनन, मुक्ति और मोक्ष जैसे शब्द हमारे शब्दकोश से धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, जो कि आध्यात्मिक मूल्यों के द्योतक रहे हैं। व्यापक उपभोगवादी संस्कृति तथा भोग-विलास से पोषित भौतिकवाद की नई उभरी संस्कृति ने आध्यात्मिक चेतना पर पर्दा डाल दिया है। धन-अर्जन, सत्ता तथा प्रसिद्धि की लालसा और सुखवादी जीवन-प्रणाली आज जीवन का परम लक्ष्य है। सभी धर्मों ने लालच को महापाप कहा है, परंतु आज लालच ही मुख्य प्रेरणा-द्वार है। ऋषि-मुनि आध्यात्मिक मूल्यों को सर्वोच्च महत्व देते हैं। हिंदू धर्म के आध्यात्मिक मूल्यों का अनुक्रम है-धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। अर्थ तथा काम संसारिक मूल्य हैं, जबकि धर्म तथा मोक्ष आध्यात्मिक मूल्य हैं, परंतु धर्म का स्थान सर्वदा प्रथम है। यह अर्थ तथा काम दोनों का प्रेरक तथा नियंत्रक है। जीवन के हिंदू दृष्टिकोण के अनुसार, सात्विक सर्वाधिक ऊंचा आदर्श है। इसके बाद राजसी का स्थान है, जो एक आदर्श नहीं, परंतु सामाजिक आवश्यकता है। तामसिक सबसे अधिक अपमानजनक वृत्ति है, जिससे सभी बुद्धिमान दूर रहते हैं। मनु की पद्धति में सतत्व को न्याय की संज्ञा दी गई है, राजस को आकांक्षा की तथा तमस को इच्छाओं की। महापुरुषों ने चिंतन-मनन को मनुष्य के परम आनंद के रूप में देखा। आंतरिक शांति तथा आध्यात्मिक ज्ञान के लिए समर्पित जीवन ही मानव गतिविधियों का सवरेत्तम रूप है।

मूर्ख साधू और ठग

संकलित
प्रेरणा

किसी गाँव के मंदिर में देव शर्मा नाम का एक प्रतिष्ठित साधू रहता था। उसे अपने भक्तों से दान में तरह- तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे मिलते थे। उन वस्त्रों को बेचकर साधू ने काफी धन जमा कर लिया था। वह अपने धन को एक पोटली में रखता था और उसे हमेशा अपने साथ लेकर ही चलता था। उसी गाँव में एक ठग रहता था। ठग हमेशा साधू का पीछा किया करता था, लेकिन साधू उस गठरी को कभी अपने से अलग नहीं होने देता। उसने साधू से मिन्नत की कि वह उसे अपना शिष्य बना ले क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। साधू तैयार हो गया और इस तरह से वह ठग साधू के साथ ही मंदिर में रहने लगा। ठग मंदिर की साफ सफाई से लेकर अन्य सभी कार्य भी करता था। एक दिन साधू को पास के गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया, साधू ने वह आमंत्रण स्वीकार किया और निश्चित दिन साधू अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी और साधू ने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। उसने पैसों की गठरी को एक कम्बल के भीतर रखा और उसे नदी के किनारे रख दिया। उसने ठग से सामान की रखवाली करने को कहा और खुद नहाने चला गया। ठग को तो कब से इसी पल का इंतज़ार था। जैसे ही साधू नदी में डुबकी लगाने गया, वह रुपयों की गठरी लेकर चम्पत हो गया। शिक्षाः किसी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ही उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए।

गुड़ी पड़वा

मुंबई के गिरगांव में मंगलवार को गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्रीयन नव वर्ष के अवसर पर पारंपरिक पोशाक पहने लोग एक रैली में भाग लेते हुए।

आज की पाती

इजरायल पर हमला हमास को महंगा पड़ा

हमास के आतंकियों ने इजरायल पर हमला कर निर्दोष लोगों की जान ही नही ली,बल्कि अनेक लोगों को बन्दक बना कर ले गए। आज का मंजर भयानक है। गाज़ा पट्टी को तहस नहस करने की ठान चुके इजराइल ने अब तक 33 हजार से ज्यादा लोगो को मौत की नींद सुला दिया। आतंकवाद का नामोनिशान मिटाने का दृढ़ संकल्प ले चुके इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की भी नही सुन रहे है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि इजराइल को धमकाने की जगह अमेरिका हमास पर दबाव क्यो नही बनाता। खंडहर में तब्दील गाजापट्टी वीरान दिखाई दे रही है। – **कांतिलाल मांडोत**, सूरत

ट्रेंड

युद्ध के आघात को बढ़ाया

सूचना युद्ध ने गाजा में युद्ध के आघात को और बढ़ा दिया है-तथ्यों को छिपाना और दोषारोपण करना। अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों को गाजा में प्रवेश से वंचित करना दुष्प्रचार और झूठी कहानियों को पनपने की इजाजत दे रहा है।
-एंटोनियो गुतरेस, यूएन महासचिव

सम्मानजनक अंत्येष्टि

डब्ल्यूएचओ नेअल-शिफा अस्पताल परिसर में अज्ञात शवों के लिए सम्मानजनक अंत्येष्टि के आयोजन में आज गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का समर्थन किया। शव पहले गंदगी या प्लास्टिक की चादर के नीचे पड़े रहते थे।
-टेड्रोस, डब्ल्यूउचओ महानिदेशक

हिंदू-मुस्लिम करने में लगे

10 साल सरकार चलाने के बाद जब देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है तो पीएम मोदी अपनी घिसी-पिटी स्क्रिप्ट पर आ गए हैं, बजाए अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के हिंदू-मुस्लिम करने में लगे हैं। पीएम मोदी बौखलाए हुए हैं, उनके सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी का 180 पार नहीं हो रहा।
-सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस नेता

अच्छा लगता है

मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई दूसरा मैदान है जहां भीड़ लगभग मैच के बाद की प्रस्तुति का हिस्सा बन जाती है। मुझे इसे यहां करना अच्छा लगता है।
-हर्षा भोगले, क्रिकेट एक्सपर्ट

करंट अफेयर

इंपीरियल कॉलेज लंदन ने 'यूनिवर्सिटी चैलेंज' जीता

ब्रिटेन में इंपीरियल कॉलेज लंदन की क्विज़ टीम ने 'यूनिवर्सिटी चैलेंज' की चैंपियन ट्रॉफी जीती है। इस टीम में कोलकाता के कम्प्यूटेशनल विज्ञान स्नातक सौरजीत देबनाथ शामिल हैं। ब्रिटेन के टेलीविज़न का सबसे कठिन 'क्विज़ टूर्नामेंट' बताए जाने वाले कार्यक्रम में 31 वर्षीय देबनाथ ने अंतिम दौर में कई मुश्किल सवालों का जवाब दिया और पिछली टीम के 'अद्वितीय मार्गदर्शन' ने इस साल प्रभावशाली अंतर से जीत दर्ज करने में योगदान दिया। यह कार्यक्रम सोमवार रात को बीबीसी पर प्रसारित किया गया जिसमें लंदन स्थित विश्वविद्यालय, कार्यक्रम के इतिहास में सबसे कामयाब विश्वविद्यालयों में शामिल हो गया है। देबनाथ ने कहा, 'मैं ब्रिटिश क्विज़ का हिस्सा बनकर काफी खुश हूं और आभारी हूं कि हमारी टीम को इंपीरियल का प्रतिनिधित्व करते हुए खिताब जीतने का अवसर मिला।' ब्रिटिश-भारतीय प्रस्तोता अमोल राजन ने बीबीसी के लोकप्रिय कार्यक्रम की मेज़बानी की। उन्होंने इंपीरियल कॉलेज की जीत को उल्लेखनीय बताया। टीम को इंपीरियल कॉलेज लंदन के साउथ केन्सिंग्टन परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में राजन और जाने माने नाटककार सर टॉम स्टॉपर्ड ने 'यूनिवर्सिटी चैलेंज' ट्रॉफी से सम्मानित किया।

ऑफ बीट

अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ अपने न्यूनतम स्तर पर

दक्षिणी गर्मियों के अंत में, अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ अपने वार्षिक न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई। कम से कम एक माप से, जो समुद्र के उस क्षेत्र को ट्रैक करता है जिसमें कम से कम 15% समुद्री बर्फ है, यह 2023 के रिकॉर्ड निचले स्तर से थोड़ा ऊपर था। उस समय, मैं इतालवी आइसब्रेकर लौरा बस्सी पर सवार था, विडंबना यह है कि केप हैलेट से लगभग 10 किमी दूर समुद्री बर्फ से घिरा हुआ था और अभियान के नमूना स्थलों में से एक तक जाने में असमर्थ था। यहां तक कि सिर्फ एक दशक पहले तक, समुद्री बर्फ हर सर्दियों में मज़बूती से खुद को फिर से बना लेती थी। लेकिन दक्षिणी महासागर के काम करने के तरीके में कुछ बदलाव आया है और समुद्री बर्फ से ढका क्षेत्र नाटकीय रूप से कम हो गया है। हमारा उद्देश्य अंटार्कटिका के आसपास समुद्र में होने वाले परिवर्तनों को ट्रैक करना और उन कुछ प्रक्रियाओं का पता लगाना था जिनके बारे में हमें लगता है कि वे समुद्री बर्फ के इस नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे अधिक संभावना है, यह महासागरों के गर्म होने का परिणाम है और इसलिए हमने उन रास्तों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया है जिनके जरिए गर्म समुद्री जल और बर्फ को पिघलाने निकल सकता है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से **aapkepatra.haribhoomi@gmail.com** पर भेज सकते हैं।